राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 187

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 15 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड मामलों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट >> 13

सरोकार

कभी गरजती थीं बंदूकें, अब फसल लहलहाती है...

औरैया : उप्र औरैया जिले का का मई मानपुर गांव। जहां कभी बंदूकें गरजती थीं, वहां अब समृद्धि की फसल लहलहा रही है। शराब की जगह दूध की नदियां बह रही हैं। अब स्कूलों में सन्नाटा नहीं ककहरा गूंजता है। यह संभव हुआ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन से। (पेज-11)

रविवार विशेष

बनारस की गंगा आरती का दीदार करा रहा 'डिंगी'

वाराणसी : आइआइटी बीएचयू के पूर्व छात्र का स्टार्टअप 'डिंगी एप' काशी में चर्चा में है। देश-विदेश के सैलानियों को यहां गंगा में नौकाविहार के लिए जहां बुकिंग का आसान प्लेटफार्म मुहैया हो गया है, वहीं नाविकों को बेहतर रोजगार। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सीबीआइ ने लीला सैमसन के खिलाफ मामला दर्ज किया

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने चेन्नई स्थित कलाक्षेत्र फाउंडेशन के कुथंबलम सभागार के पुनरुद्धार की 7.02 करोड़ रुपये की परियोजना में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना लीला सैमसन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पद्मश्री से सम्मानित सैमसन संगीत नाटक अकादमी और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पीएसए के तहत मार्च तक टली फारूक अब्दुल्ला की रिहाई

श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर के सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला की रिहाई फिलहाल टल गई है। सामान्य हालात में अब वह अगले तीन माह तक रिहा नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत उनकी कैद को फिर तीन माह के लिए और बढ़ा दिया है। जन सुरक्षा अधिनियम 1978 को डॉ. फारूक के पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही लागू किया था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

जीएसटी कंपेंसेशन पर बढ़ रही राज्यों की नाराजगी

नई दिल्ली : जीएसटी कंपेंसेशन (वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति) के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। अगले सप्ताह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथ ही राज्य अब केंद्र सरकार पर कंपेंसेशन की अवधि को पांच साल और बढ़ाने का दबाव बना सकते हैं। राज्यों का कहना है कि कंपेंसेशन की अवधि 2021-22 में समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब तक रेवेन्यू (राजस्व) वृद्धि की अपेक्षित रफ्तार हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

नमामि गंगे से फूटेगी अब 'अर्थ' की धारा : मोदी

समीक्षा बैठक ▶ राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में खींचा आय का खाका

परिषद हुई और मजबूत, मिला सभी निर्णय लेने का अधिकार

जागरण संवाददाता, कानपुर

'नमामि गंगा' के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करने शनिवार को कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अविरल-निर्मल गंगा के सहारे विकास का खाका खींचा, बल्कि यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यह योजना आय का सबसे बड़ा जरिया बनने की जा रही है। उन्होंने कहा-'नमामि गंगे की धारा अब अर्थ गंगा की ओर मुड़ने जा रही है।' स्पष्ट खाका भी खींचा कि अविरल-निर्मल धारा कैसे किसानों और सामान्य जनों के लिए आय का बड़ा साधन बनेगी।

प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में अब तक हुए विकास कार्यों की पूरी जानकारी ली और जीरो बजट खेती, ईको-एडवेंचर टूरिज्म, रिवर फ्रंट बेसिन का विकास और डॉल्फिन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि आय का साधन बढ़ाने के लिए गंगा के किनारे फलदार वृक्ष लगाएं, नर्सरी बनाएं। इसमें महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों व पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दें। गंगा किनारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, वाकिंग पाथ-वे की व्यवस्था करें। गंगा में जलयान यानी क्रूज टूरिज्म का रोमांच दें।

प्रधानमंत्री ने परिषद को और मजबूत करते हुए उसे गंगा व सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए सभी निर्णय लेने के अधिकार दिए। कहा, सभी विभाग और मंत्रालय गंगा केंद्रित सोच के साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे। नीति आयोग व जलशक्ति मंत्रालय जिलावार निगरानी करेगा। उन्हें डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए हर रोज शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का डाटा मिलेगा। सीएसए में तय समय से डेढ़ घंटा अधिक रुके पीएम ने कहा, गंगा का कायाकल्प करना वर्षों की चुनौती है। 2014 में नमामि गंगे शुरू होने के बाद सरकार ने बहुत कुछ किया है। पेपर मिलों को जीरो डिस्चार्ज किया गया है तो टेनरी के प्रदूषण में भी कमी आई है। अभी भी काफी कुछ करना बाकी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कानपुर में वोट से भ्रमण कर गंगा का हाल जाना। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी (योगी के पीछे), उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत (बाएं) भी साथ थे। मो. आरिफ

मोटर बोट से गंगा में भ्रमण

प्रधानमंत्री ने मोटर बोट से गंगा का भ्रमण किया। वह सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ अटल घाट से 128 साल पुराने सीसामऊ नाला तक गए और निरीक्षण किया।

20 हजार करोड़ खर्च करने वाली पहली सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन पांच राज्यों से गंगा होकर बहती है, वहां जल प्रवाह को ठीक बनाए रखने के लिए 2015-20 के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने वाली यह पहली केंद्र सरकार है। अब तक नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 7,700 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। उन्होंने जिला गंगा समितियों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए क्लीन गंगा फंड बनाया हुआ है। इसमें व्यक्तिगत, एनआरआइ, कारपोरेट संस्थाएं योगदान कर सकती हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2014 से अब तक मिले उपहारों की नीलामी और सियोल शांति पुरस्कार से प्राप्त धनराशि से 16.53 करोड़ रुपये इस फंड में दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रस्तुत की कार्यों की रिपोर्ट पेज>>5

असम शांत, बंगाल में बढ़ा बवाल

सीएए के विरोध में बंगाल में दूसरे दिन भी जमकर उपद्रव व आगजनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ कई बसों में भी लगाई आग
- गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में ढील, नगालैंड में बंद का आयोजन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने में आगे रहे पूर्वोत्तर के राज्यों में शनिवार को शांति रही। इसी के चलते असम के गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलांग में कर्फ्यू में ढील दी गई। नगालैंड में छह घंटे का बंद आयोजित किया गया। जबकि बंगाल दूसरे दिन भी जलता रहा। शुक्रवार की घटनाओं से रेल प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, लिहाजा दूसरे दिन भी रेलवे को ही सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग लगाने के अलावा रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की, फर्नीचर को ट्रैक पर डालकर आग लगा दी, टिकट काउंटरों पर तोड़फोड़ और लूटपाट की, खाली खड़ी चार ट्रेनों और मालगाड़ी के इंजन को आग के हवाले कर दिया गया। जान बचाने के लिए रेल कर्मचारी स्टेशनों को छोड़कर भाग खड़े हुए। लिहाजा 40 से अधिक ईएमयू और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद कर दिया गया। सात ट्रेनों को रास्ते में ही समाप्त कर दिया गया। जबकि पांच ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया गया। उधर, नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पांच जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है और सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन अंतर्गत कई स्टेशनों को निशाना बनाया। मुर्शिदाबाद के सुजनीपाड़ा स्टेशन को तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। कृष्णपुर स्टेशन पर खाली खड़ी चार ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। लालगोला, जियागंज स्टेशनों में भी तोड़फोड़ की गई। स्टेशनों के फर्नीचर को ट्रैक पर डालकर आग लगा दी गई, इससे लालगोला-कृष्णानगर सेक्शन पर संचालन पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने दूसरे दिन भी बेलडांगा स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी की। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी को भी आग लगा दी गई। हारुआ रोड स्टेशन के पास और सोनदलिया-लेबुतला स्टेशन के बीच लेवल क्रासिंग तोड़ दिया गया। ट्रेनों पर भी जमकर पथराव किया गया। भीड़ के तेवर देख आरपीएफ और जीआरपी के साथ ही रेल कर्मचारी भी भाग खड़े हुए।

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने सांकराइल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर कक्ष के पैनल बोर्ड, टिकट काउंटर, प्लेटफार्म और लेवल क्रासिंग गेट को तोड़ दिया। टिकट काउंटरों पर लूटपाट व आगजनी भी की गई। नलपुर व चंगेल स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की। बाउरिया स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी गई। जगह-जगह रेल पटरी पर टायर जलाकर ट्रेन संचालन ठप कर दिया गया। मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारियों को पीटा। मालदा डिवीजन के हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई।

प्रदर्शनकारियों ने बसों और अन्य वाहनों को भी निशाना बनाया। कोना एक्सप्रेस वे पर 25 सरकारी व निजी बसों को आग लगा दी गई। मालदा व मुर्शिदाबाद जिलों में कई बसों को आग लगाए जाने की खबर है। टोल प्लाजा को भी आग लगा दी। यहां यात्रियों को जबरन बस से उतार दिया गया। जिले में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हावड़ा, दोमजुर बगनान के साथ ही बीरभम जिले में टायर जलाकर सड़कों को ब्लॉक कर दिया और कई दुकानों में भी आग लगा दी।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शनिवार को हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव किया और कई जगह आगजनी की। पथराव से बचने की कोशिश करते सुरक्षा बल। प्रेट्र

राजनाथ बोले, शरणार्थियों को पक्की नागरिकता देगी सरकार पेज>>5
राष्ट्रीयता का राष्ट्र धर्म ! (मुद्दा) पेज>>7

उन्नाव के बाद अब फतेहपुर में दरिंदगी, दुष्कर्म कर युवती को केरोसिन डाल कर जलाया

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

- पड़ोसी ने दिया घटना को अंजाम, युवती 90 फीसद झुलसी
- जिला अस्पताल में बयान लेने के बाद किया गया कानपुर रेफर

उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्नाव के बाद अब फतेहपुर में दरिंदगी की वारदात सामने आई है। शनिवार सुबह हुसेनगंज क्षेत्र के एक गांव में दरिंदे ने घर में घुसकर 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर केरोसिन उड़ेलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। चीखती युवती बाहर की ओर भागी। पड़ोसियों ने आग बुझाकर उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। 90 फीसद झुलसी पीड़िता को हैलट अस्-कानपुर रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया। एडीजी सुजीत पांडेय समेत कई अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया।

सुबह करीब नौ बजे पड़ोस में रहने वाला चाचा घर में युवती को अकेला पाकर घुस आया और दुष्कर्म किया। युवती ने जब स्वजनों को जानकारी देने की बात कही तो आरोपित ने उसके शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। वह चीखते हुए घर के बाहर भागकर आ गई। आग बुझाने के बाद पड़ोसी ने पास के नर्सिंगहोम में उसका प्राथमिक उपचार कराया। बाद में सदर अस्पताल लेकर आए। डॉ. नरेश विशाल ने बताया कि युवती 90 फीसद से अधिक झुलस गई है। हालत बेहद गंभीर होने पर उसे कानपुर भेज दिया गया। पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर देकर बताया कि स्वजन मजदूरी करने गए थे। घर में बहन अकेली थी, तभी पड़ोसी घुस आया और दुष्कर्म कर उसे जला दिया। एसपी के मुताबिक, आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म कर जानलेवा हमले के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देर शाम गांव पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

ट्रॉमा सेंटर में मजिस्ट्रेटी बयान : नायब तहसीलदार संतराज ने सीओ सिटी कपिलदेव मिश्र, महिला थाना प्रभारी नमिता सिंह आदि की मौजूदगी ट्रॉमा सेंटर में युवती के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने बयान में कहा कि युवक ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।

प्रेम प्रसंग की बात

डीएम संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता व आरोपित के बीच दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवारों के बीच पंचायत में युवक को युवती की शादी होने तक गांव से बाहर रहने की हिदायत दी गई थी। जिससे क्षुब्ध होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है।

वाहन चालकों को नेशनल हाईवे पर फास्टैग से एक माह की राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- टोल प्लाजा की एक-चौथाई लेन में चालकों से कैश भी होगा स्वीकार
- फास्टैग की कमी को देखते हुए सरकार ने एनएचएआइ के आग्रह पर दी राहत

सरकार ने वाहन चालकों को फास्टैग खरीदने और बिना जुर्माने के टोल प्लाजा से निकलने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे दी है, लेकिन एनएच पर स्थित सभी टोल प्लाजा की तैयारी के लिहाज से फास्टैग का उपयोग रविवार से अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग मिलने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने चालकों को एक माह की मोहलत दी है। इस दौरान वे टोल प्लाजा की चौथाई लेन में कैश भुगतान कर गुजर सकेंगे। टोल प्लाजा को रविवार से कम से कम तीन-चौथाई लेन में फास्टैग की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया करानी होगी।

सरकार ने एनएचएआइ से कहा है कि वह एक माह तक कम से कम एक-चौथाई लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की व्यवस्था करे। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी टोल प्लाजा में आठ लेन हैं तो वहां दो लेन में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के अलावा कैश भुगतान भी स्वीकार होंगे। जहां 12 लेन हैं वहां तीन लेन कैश के लिए भी खुली होंगी। अभी तक केवल एक लेन में ही कैश भुगतान की सुविधा होने से लंबी कतारें लग जाती थीं। सड़क मंत्रालय ने एनएचएआइ से कहा है कि वाहन चालकों को सुविधा देने के साथ-साथ उसका प्रयास हाइब्रिड लेन की संख्या को कम से कम रखने का होना चाहिए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी फास्टैग लेने का प्रयास करें। किसी भी हालत में फास्टैग लेन 75 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।

इससे पहले एनएचएआइ ने मुश्किलें गिनाते हुए सड़क मंत्रालय से फास्टैग अनिवार्यता की तारीख बढ़ाने अथवा 45 दिनो तक एक से अधिक लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की अनुमति मांगी थी। एनएचएआइ का कहना था कि देश में चिप का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से फास्टैग की आपूर्ति काफी कम है। बीती छह दिसंबर तक देश में रोजाना 1.96 लाख फास्टैग जारी हो रहे थे। फास्टैग में आयातित चिप के उपयोग और उसकी बढ़ती मांग को देखते हुए एनएचएआइ ने पांच-छह दिसंबर को टैग निर्माताओं तथा बैंकों के साथ स्थिति की समीक्षा की। अभी फास्टैग निर्माताओं की कुल दैनिक उत्पादन क्षमता 50 हजार टैग बनाने की ही है। निर्माताओं के पास पहले से 18 लाख फास्टैग आपूर्ति के ऑर्डर पड़े हुए हैं। एनएचएआइ के अनुरोध पर सड़क मंत्रालय ने फास्टैग अनिवार्यता की तारीख को पहली दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर किया था।

राहुल बोले, मैं सावरकर नहीं, शिवसेना ने कहा-मत करें अनादर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बोले-माफी नहीं मांगूंगा, मोदी और अमित शाह को मांगनी चाहिए माफी
- दोनों नेताओं पर लगाया अर्थव्यवस्था तबाह करने का आरोप

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं मर जाऊंगा, पर माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा है, सच कहा है। वैसे भी मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। माफी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह को मांगनी चाहिए, जिन्होंने देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। एक दिन पहले ही रेप इन इंडिया बयान पर घिर चुके राहुल गांधी द्वारा इस तरह सावरकर का नाम लिए जाने का शिवसेना ने तत्काल प्रतिवाद किया। हाल ही में कांग्रेस की सहयोगी बनी पार्टी ने कहा कि हिंदुत्व के प्रतीक का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया कि वीर विनायक दामोदर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए देवतुल्य हैं। हम गांधी और नेहरू का सम्मान करते हैं। आपको सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते राहुल गांधी। ध्रुव कुमार

कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, भाजपा के लोग उनके बयान पर उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन, वह कभी माफी नहीं मांगेंगे। यहां बता दें कि राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान से खफा भाजपा ने शुक्रवार को संसद के भीतर और बाहर माफी मांगने की मांग की। राहुल ने कहा, पूरी दुनिया पहले भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर देखती थी, लेकिन, पीएम मोदी की चोट से अर्थव्यवस्था अब तक उबर नहीं पाई है। जीडीपी चार फीसद पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान के सारे दुश्मन चाहते थे, कि इसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए, लेकिन, वह काम दुश्मन ने नहीं, मोदी ने किया है। राहुल ने कहा, यह सरकार एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ा रही है। पूरे पूर्वोत्तर की स्थिति खराब है। कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाते हुए कहा, इस देश को डराया और दबाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर और शेरनियां है, वह किसी से डरने वाला नहीं है।

सावरकर का नाम राष्ट्र और स्वयं के बारे में गौरव को दर्शाता है। गांधी और नेहरू की तरह सावरकर ने भी देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन सबका देवों की तरह सम्मान किया जाना चाहिए। इससे कोई समझौता नहीं होगा।

- संजय राउत, शिवसेना सांसद

भाजपा ने कहा, इनका नाम तो राहुल जिन्ना होना चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र : राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, कांग्रेस नेता के लिए उपयुक्त नाम 'राहुल जिन्ना' है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें पाक के संस्थापक का उत्तराधिकारी बनाती है। ज्ञात हो, भाजपा सावरकर को काफी ऊंचा दर्जा देती है, लेकिन, विरोधी सावरकर पर ब्रिटिश शासन से माफी मांगने का आरोप लगाते हैं।

देश की आत्मा को तार-तार कर देगा नागरिकता कानून : सोनिया पेज>>3

इनसे मिलिए

22 साल के हसन सफिन 23 दिसंबर को संभालने जा रहे जामनगर एएसपी का पदभार, गुजरात के बनासकांठा में हीरा तराशने के कारखाने में श्रमिक हैं हसन के माता-पिता, बेटे की पढ़ाई में बाधा न आए इसलिए मां ने रेस्त्रां में खाना बनाने का भी किया काम

हीरा तराशने वाले माता-पिता का बेटा निकला कोहिनूर

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

बनासकांठा (गुजरात) निवासी 22 वर्षीय हसन सफिन 23 दिसंबर को जामनगर में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में पदभार संभालने जा रहे हैं। देश के सबसे युवा आइपीएस अधिकारी हसन का कहना है कि देश और समाज की सेवा में हरसंभव योगदान उनकी प्राथमिकता है, जिससे प्रेरित होकर ही उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा को करियर के रूप में अपनाया।

गत वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने वाले सफिन की इस कामयाबी के पीछे उनके माता-पिता के कठोर संघर्ष का योगदान रहा है। बनासकांठा के पालनपुर क्षेत्र के गांव कणोदर में सफिन का घर है। यहीं उनकी परवरिश हुई। पिता मुस्तफा हसन और मां नसीमबानु नजदीक स्थित एक कारखाने में हीरे तराशने का काम करते। हसन बचपन से मेधावी थे, लिहाजा माता-पिता ने इस बात का हरसंभव प्रयास किया कि बेटे की शिक्षा में गरीबी आड़े न आने पाए। जब पैसों की कमी पड़ने लगी तो मां नसीमबानु ने दोहरी भूमिका निभाई। रेस्त्रां और विवाह समारोह आदि में रोटी-पूड़ी बेलने का काम भी करने लगीं। इधर, सफिन ने भी जमकर मेहनत की। माता-पिता की मेहनत को जल्द से जल्द सफलता में परिणत करने का जज्बा उनके लिए प्रेरणा का काम कर रहा था। सहायक पुलिस अधीक्षक, जामनगर का पदभार संभालते हुए वह भारत में सबसे कम उम्र के आइपीएस अधिकारी होंगे।

सफिन कहते हैं, मैंने आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) को लक्ष्य बनाया था, लेकिन 570वीं रैंक आई और आइपीएस का विकल्प सामने था। मैं दोबारा परीक्षा देकर रैंक सुधारने के बारे में सोच सकता था, लेकिन फिर तय किया कि अब आइपीएस के रूप में ही देश और समाज की सेवा करूंगा... । वह बताते हैं कि बचपन में अपनी मौसी के साथ एक स्कूल में गए थे, वहां समारोह में पहुंचे कलेक्टर की बातें सुन और उनका रुतबा देख बेहद प्रभावित हुए। मौसी से पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह आइएएस अधिकारी हैं और जिले के मुखिया हैं। उसी दिन उन्होंने आइएएस अधिकारी बनने की ठान ली। गांव कणोदर में प्राथमिक शिक्षा के बाद हसन ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास की और पढ़ाई के लिए सूरत चले गए। फिर स्नातक के बाद गुजरात लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर जिला रजिस्ट्रार बन गए, लेकिन मन में आइएएस या आइपीएस बनने की इच्छा थी। गुजरात कैडर से आइपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब वह पदभार ग्रहण करेंगे।

सफिन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, फेसबुक पेज पर उनके करीब 80 हजार से अधिक फॉलोअर हैं। पिता मुस्तफा और मां नसीमबानु बेहद खुश हैं, कहते हैं बेटे ने जो ठाना वह कर दिखाया। हमारा सपना साकार हो गया।

हसन सफिन। (सौ. परिजन)

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्रों ने किया हमला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कार का शीशा तोड़ा, टीचर फेडरेशन ने की जांच की मांग, छात्र संघ ने कहा-सिर्फ छात्रावास के मुद्दे पर किया था सवाल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति पर शनिवार को छात्रों ने हमला किया। जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने दावा किया है कि उन पर 10 से 15 छात्रों ने हमला किया। जेएनयू टीचर फेडरेशन (जेएनयूटीएफ) ने इस मामले की प्रशासनिक जांच और आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति के आरोपों से इन्कार किया है।

कुलपति ने कहा, शनिवार को वह जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में कुछ काम के सिलसिले में गए थे। वहां 10 से 15 छात्रों ने उन्हें घेरकर गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छात्र उन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ने किसी तरह उन्हें बचाया। इस दौरान उनकी कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। जेएनयूटीएफ से जुड़े शिक्षकों ने कहा है कि कुलपति के साथ छात्रों द्वारा किए गए हमले की हम निंदा करते हैं। कुलपति की कार के शीशे भी छात्रों ने ही तोड़े हैं। उनके कार्यालय के गेट को भी तोड़ा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जेएनयू के कुलपति, रजिस्ट्रार को सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए हैं। पुलिस इन्हें सुरक्षा मुहैया कराए।

वहीं छात्र संघ ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि कुलपति स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पहुंचे थे। कुछ छात्रों ने उनसे छात्रावास के मुद्दे पर सवाल किया तो वह बिना जवाब दिए ही वहां से चल दिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव के जरिये चुने गए छात्र संघ के प्रतिनिधियों से छात्रावास के मुद्दे पर कुलपति बात करें।

163 रहा शनिवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की रफ्तार कम होने और मौसम में बनी नमी के चलते रविवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच सकती है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 15 दिसंबर 2019

आप को मिला प्रशांत किशोर का साथ

तैयारी ▶ केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, विधानसभा चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, अबकी बार 67 पार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आइ-पैक) अब दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कहा कि अबकी बार 67 पार। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होगा।

अपने आठ साल के चुनावी प्रबंधन के दौरान 90 फीसद से अधिक सफलता हासिल करने वाले प्रशांत किशोर बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। आई-पैक ने भी ट्वीट किया है कि पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद हमने 'आप' को अभी तक के अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकार किया। केजरीवाल और आप के साथ आकर खुश हैं।

सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल की बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही थी। दोनों ने ऐसे समय में औपचारिक रूप से हाथ मिलाया है, जब वह नागरिकता संशोधन कानून पर व्यक्तिगत

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। (फाइल)

रूप से विरोध कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी जनता दल (यू) इसके समर्थन में है।

2011 में पीके गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी से जुड़े : अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर वर्ष 2011 में पीके गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े थे। उसी साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की तीसरी बार वापसी हुई तो उसका कुछ क्रेडिट प्रशांत किशोर को भी मिला। उनका नाम तब तेजी से चर्चा में आया जब वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई। मगर चुनाव बाद मतभेदों के चलते प्रशांत किशोर ने भाजपा से दूरी बना ली और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) से जुड़ गए। नीतीश को चुनाव में सफलता मिली। हालांकि वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी दुर्गति का उन पर दाग भी है। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनको सफलता मिली।

चड्ढा बोले, वॉलेंटियर के तौर पर सेवाएं देंगे पीके

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) ने साफ किया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सेवाएं देने के लिए प्रशांत किशोर कोई पैसा नहीं लेंगे। आप के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि वह वॉलेंटियर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में यह पूछे जाने पर कि प्रशांत की बड़ी कंपनी है, जाहिर है कि वह पैसा लेते होंगे, वह कितने के पैकेज में आप के साथ आ रहे हैं? इस पर चड्ढा ने कहा कि आप के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, वे सभी वॉलेंटियर के तौर पर जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि आज देश के लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल को राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। बहुत से लोग साथ जुड़कर हमारे चुनावी अभियान को और मजबूत करने के लिए साथ आ रहे हैं। वह इस चुनाव रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते

आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा। जागरण

हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आइ-पैक का बहुत-बहुत स्वागत है। पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी? इस पर उन्होंने कहा कि वह चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उनकी क्या भूमिका होगी उनके बारे में भविष्य में बताया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रशांत किशोर ने उनसे संपर्क किया या आप ने उनसे संपर्क किया? इस पर उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या वह आप में शामिल होंगे या केवल सेवाएं देंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह आप के लिए चुनाव प्रचार अभियान संभालेंगे।

बिल्डिंग में आग लगने से तीन महिलाओं की मौत

जासं, नई दिल्ली : शालीमार बाग इलाके में शनिवार शाम बहुमंजिला इमारत में आग लगने से तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान कांता देवी (75), किरन शर्मा (65) व सोमवती (42) के रूप में की गई। घायलों में लाजवंती (68), इना (28), अक्षित (16) व वंशिका (14) शामिल हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौत का कारण धुएं के कारण दम घुटने को बताया जा रहा है।

शालीमार बाग बीक्यू ब्लॉक में बहुमंजिला इमारत है। इसके भूतल पर पार्किंग है और उसके ऊपर चार मंजिल बनी हुई हैं। इनमें अलग-अलग परिवार रहते हैं। शाम करीब छह बजे पहली मंजिल में अचानक आग लग गई। घटना के समय इस मंजिल पर कोई मौजूद नहीं था। इस कारण ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को पता नहीं चल सका और कुछ ही देर में आग ने पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि आग लगने के बाद बिल्डिंग के अंदर फंसे कुछ लोग बाहर आ गए, लेकिन बुजुर्ग महिलाएं सहित कुछ लोग अंदर ही फंसे रह गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस व अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पुलिस टीम व दमकल की नौ गाड़ियां पहुंचीं। करीब एक घंटे में दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इसके बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। दमकलकर्मियों ने कुल सात लोगों को बाहर निकाल कर शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पातल पहुंचाया, वहां तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया।

आप ने शुरू किया 'मेरा वोट काम को' अभियान

'मेरा वोट काम को' अभियान चलाते हुए जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया। सौ. : आम आदमी पार्टी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीसरी बार दमखम के साथ उतरने जा रही आम आदमी पार्टी (आप) ने अब नया अभियान शुरू किया है। इसे 'मेरा वोट काम को' नाम दिया गया है। इसके तहत सभी विधायक और पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सरकार के कार्यों के नाम पर वोट मांगेंगे।

गत सितंबर से आप विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है। इनमें पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय, राज्यसभा संजय सिंह और पार्टी के नेता दिलीप पांडेय अलग-अलग जन संवाद अभियान चला चुके हैं। अब पार्टी का निर्देश है कि विधायक अपने अपने इलाके में अभियान चलाकर सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएं।

> मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निर्देश है कि विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएं। उन्हें बताएं कि उनकी सरकार ने जनता के लिए क्या-क्या कार्य कराए हैं। इसे दिल्ली भर में चलाया जा रहा है। अलग-अलग इलाकों में विधायक जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में राय ले रहे हैं। जनता खुश है और खूब समर्थन मिल रहा है।
>
> **-दिनेश मोहनिया, उपाध्यक्ष, जल बोर्ड**

न्यूज गैलरी

दो यात्रियों के पास से 25 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने 25 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा के साथ दो भारतीय तस्कर को दबोचा है। दोनों दुबई जाने की जुगत में थे। तस्करों की पहचान फरहान खान और मोहम्मद आमिर अंसारी के रूप में हुई है। दोनों आरोपितों को एयरपोर्ट कस्टम के हवाले कर दिया गया है। सीआइएसएफ के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह बल की निगरानी टीम के जवानों ने दो संदिग्ध यात्रियों को आइजीआइ एयरपोर्ट टर्मिनल-3 के चेक-इन एरिया में घूमते हुए देखा था। यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों के देखते हुए जवान उनकी निगरानी करते रहे। जैसे ही दोनों सिक्योरिटी होल्ड एरिया (एसएचए) में पहुंचे उनसे पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि उनका नाम फरहान खान और मोहम्मद आमिर अंसारी है। वे दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनका स्पाइस जेट की उड़ान का टिकट बना हुआ था। तलाशी लेने पर फरहान के बैग से एक लाख सऊदी रियाल और चार हजार कतर रियाल जबकि मो. आमिर के बैग से तीन हजार ओमानी रियाल बरामद हुए। पूछताछ करने पर वे विदेशी मुद्रा के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और ना यह बता पाए कि वे इतनी संख्या में विदेशी मुद्रा देश से बाहर क्यों ले जा रहे थे। (जासं)

शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, रद हुई नियुक्ति

नई दिल्ली : शिक्षा निदेशालय ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद कर दी है। निदेशालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की सूचना पर यह कार्रवाई की। निदेशालय के मुताबिक हाल ही में भर्ती किए गए 15 सहायक शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा मिलने के चलते यह कदम उठाया गया। डीएसएसएसबी ने नवंबर 2018 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद पास हुए अभ्यर्थियों को बीते जून में नियुक्ति देने के साथ अक्टूबर से स्कूल आंवटित किए थे। डीएसएसएसबी ने नियुक्ति के बाद की जांच में 15 अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक डाटा में फर्जीवाड़ा पाया। इन 15 शिक्षकों की जगह अन्य लोग परीक्षा में बैठे थे। फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। बोर्ड ने हाल ही में नौ अभ्यर्थियों को चिह्नित किया था। इनमें से दो अभ्यर्थी एक ही पद के लिए अलग-अलग चरणों में हुई परीक्षा में दो बार बैठे थे, जबकि सात अभ्यर्थी ऐसे थे, जिनकी जगह किसी अन्य ने परीक्षा दी थी। इनमें से तीन अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे, जबकि चार असफल रहे। (जासं)

'फांसी' करीब आने से सदमे में दोषियों के परिजन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया कांड

- दोषी युवकों के परिजनों ने मीडियाकर्मियों से भी बनाई दूरी
- कॉलोनी के लोग बोले, फांसी लगने से ही धुलेगा दाग

निर्भया मामले में चारों दोषियों के परिजन फांसी की तिथि करीब आने से सदमे में हैं। उन्होंने पड़ोसियों से भी बात करना बंद कर दिया है। इनमें से तीन दोषियों पवन, विनय और मुकेश के घर आरकेपुरम के सेक्टर-3 में रविदास कैंप स्थित झुग्गी में हैं। पवन और विनय के परिजन यहीं रहते हैं, जबकि मुकेश के परिजन दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी झुग्गी में ताला लगा रखा है। अक्षय का परिवार दूसरे इलाके में रहता है।

निर्भया मामले में कुल छह दोषियों में से मुकेश और राम सिंह सगे भाई हैं। राम सिंह आत्महत्या कर चुका है। फिलहाल पवन और विनय के परिजन मीडियाकर्मियों से मिल तो रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वह क्या बात करें। बहुत बात कर चुके, घर पर मौजूद पवन की बहन ने कहा कि घरवालों ने किसी से भी बातचीत करने से मना किया है। अगर कोई बात करता है, तो मां उसे घर के पास खड़ा नहीं होने देती हैं। इतना कह कर उसने भी घर का दरवाजा बंद कर लिया। पवन के पिता हीरालाल और मां आरकेपुरम के सेक्टर-1 में फलों का ठेला लगाते हैं।

विनय के पिता हरीराम शर्मा ने कहा कि वह तो अब 18 तारीख को कोर्ट में ही बात करेंगे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वहीं, रविदास कैंप कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों का कहना था कि दोषियों को जल्द फांसी मिलनी चाहिए। इनकी वजह से कॉलोनी का नाम बदनाम हुआ है। इनको फांसी के बाद दाग धुल जाएगा। चारों दोषियों को जल्द फांसी देने की याचिका पर 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।

तमिलनाडु पुलिस के हवाले फांसी घर, सुरक्षा बढ़ी

निर्भया के दोषियों पर जेल प्रशासन की निगरानी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को दोषियों से मुलाकात और फांसी घर के निरीक्षण के बाद सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया गया। जेल अधिकारियों ने फांसी घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तमिलनाडु पुलिस को सौंप दी है। इसके आसपास कैदियों को जाने की इजाजत नहीं है। कर्मचारियों को भी सुरक्षा जांच के बाद ही वहां जाने दिया जा रहा है। पिछले चार दिनों से फांसी घर में डमी को फंदे पर लटकाने का अभ्यास किया जा रहा था। शुक्रवार को जेल अधिकारी ने सारी प्रक्रिया देखी और तकनीकी पहलुओं को देखने के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। सूत्रों का कहना है कि दोबारा डमी को लटकाने की प्रक्रिया तब शुरू होगी, जब निर्भया के गुनहगारों का डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर गुनहगारों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। तमिलनाडु पुलिस के एक जवान हर समय उनके साथ रहता है। उनके हावभाव पर जेल प्रशासन नजर रख रहा है। जेल नंबर-दो में पवन, मुकेश व अक्षय बंद है, वहीं विनय जेल नंबर-चार में है। जेल सूत्रों ने बताया कि ये अब अपने बैरक से पहले के मुकाबले काफी कम बाहर निकल रहे हैं। जेल अधिकारी इनसे बात करने के लिए जा रहे हैं। दिन में दो बार उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है।

निर्भया के दोषी पवन के पिता की अर्जी पर सुनवाई

जासं, नई दिल्ली : निर्भया के साथ दुष्कर्म और हत्या के अलावा हत्या के एक और मामले में दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरा लाल की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट अदालत ने कहा कि गवाह को शपथ दिलाकर बयान लिया जाता है। बाहर वह क्या कहता है, इससे अदालत उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकती। हीरा लाल ने अर्जी में कहा कि निर्भया मामले में गवाह ने कई टीवी चैनलों से पैसा लेकर बयान दिए। उसके बयानों की वजह से मीडिया ट्रायल बन गया और इसका असर केस पर पड़ा। गवाह पर केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने गलत बयानबाजी की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उनकी शिकायत में क्या संज्ञेय अपराध पाया गया है? अदालत 20 को तय करेगी कि इस अर्जी पर आगे सुनवाई करनी है या नहीं।

मालिकाना हक का चुनावी फल पाने की कवायद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक देने के फैसले का चुनावी लाभ हासिल करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत ताकत झोक दी है। 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए रैली आयोजित की जा रही है जिसमें इन कॉलोनियों से भीड़ जुटाने की तैयारी है। रैली में प्रधानमंत्री को 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराकर सौंपे जाएंगे। इसके लिए शनिवार से अनधिकृत कॉलोनियों में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली और पदयात्रा निकालने की भी तैयारी है।

अनधिकृत कॉलोनियों में प्रत्येक घर तक पहुंचकर कार्यकर्ता इस योजना से होने वाले लाभ की जानकारी देंगे। यह भी बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर उनके साथ धोखा करती रही हैं। साथ ही मोदी को धन्यवाद करने करने के लिए लोगों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि 11 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य है।

17 दिसंबर को रामलीला मैदान में भूमि पूजन के साथ रैली के लिए पंडाल

झुग्गियों में गोयल चलाएंगे जागरूकता अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल के निवास पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें दिल्लीवासियों के लाखों लोगों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई। गोयल ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के बाद अब केंद्र सरकार ने 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को आशियाना उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे लगभग 20 लाख लोगों को अपना घर मिल जाएगा।

विजय गोयल। (फाइल)

उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं और आरडब्ल्यू प्रतिनिधियों से झुग्गियों में जाकर लोगों को इसकी जानकारी देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक झुग्गीवाले को इस योजना की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वे इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 32 झुग्गी बस्तियों में सर्वे का काम पूरा कर लिया है। 160 झुग्गी बस्तियों में चल रहा है। जैसे ही यह काम पूरा होगा, लोगों को बहुत कम पैसे में फ्लैट दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2006 से पहले की बनी झुग्गी बस्तियों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। इन झुग्गियों में एक जनवरी 2015 के पहले से रह रहे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप की सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया था। पक्का मकान देना तो दूर आप सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू नहीं होने दी है।

बनाने का काम शुरू हो जाएगा। उसी दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर बाइक रैली निकालेंगे। 18 से 20 दिसंबर तक 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही साढ़े तीन सौ स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों के जरिये लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनसे रैली में पहुंचकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने का आह्वान किया जाएगा।

तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को अपने मकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से शिविर लगाए जा रहे हैं। 25 शिविर लग चुके हैं और 18 दिसंबर तक 25 और लगेंगे। इन शिविरों में लोगों की सहायता के लिए भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। प्रेसवार्ता में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य नेता मौजूद थे।

दिल्ली में ठंड के साथ अब बढ़ेगा कोहरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रिकार्डतोड़ बारिश के बाद दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड तो बढ़ ही रही है, अब कोहरे में भी इजाफा होगा। रविवार और सोमवार की सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार से बर्फीली हवा भी दिल्लीवासियों की कंपकंपी छुड़ाएगी।

शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा। 14 दिसंबर को यह बीते आठ सालों में सबसे कम तापमान है। सुबह के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। खासतौर पर रविवार की सुबह घने कोहरे की संभावना है। इससे दृश्यता का स्तर भी प्रभावित होगा। जबकि सोमवार को दिन में मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन के समय आसमान पर हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को पहाड़ों की ठंडी हवा राजधानी पहुंचेगी।

शिमला के लिए फ्लाइट को करना होगा इंतजार

सौरभ पांडेय, साहिबाबाद

पिथौरागढ़ और हुबली के बाद अब यात्रियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से शिमला के लिए विमान सेवा का कुछ और इंतजार करना होगा। 2020 की शुरुआत में शिमला के लिए उड़ान सेवा देने की योजना बना रही कंपनी ने इसे करीब दो माह के लिए टाल दिया है। अब अगले वर्ष फरवरी-मार्च में ही शिमला के लिए उड़ान शुरू हो सकेगी। शिमला और पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे भारी हिमपात को देखते हुए सेवा को करीब दो माह टालने का निर्णय लिया गया है।

मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 11 अक्टूबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए यहां से उड़ान शुरू कर दी गई है। छह नवंबर से कर्नाटक के हुबली के लिए भी लोगों को विमान सेवा मिलने लगी है। पिथौरागढ़ और हुबली के बाद अब हिंडन से शिमला भी विमान के जरिये जुड़ जाएगा। पिथौरागढ़ के लिए उड़ान सेवा दे रही कंपनी हेरिटेज एविएशन ही शिमला के लिए भी उड़ान शुरू करेगी। बीस सीटर विमान में यह सुविधा मिलेगी।

> हुबली के बाद अब शिमला के लिए भी उड़ान की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 2020 की शुरुआत में ही शिमला के लिए उड़ान की तिथि घोषित कर दी जाएगी। हेरिटेज एविएशन ही इस फ्लाइट का संचालन करेगी। मौसम ठीक होने के बाद ही शिमला के लिए संचालन शुरू किया जा सकेगा।
>
> **-शोभा भारद्वाज, डायरेक्टर हिंडन एयरपोर्ट।**

हिंडन एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने मार्च में किया था उद्घाटन। यहां से पिथौरागढ़ व हुबली के लिए उड़ान उपलब्ध है। (फाइल)

अमेरिका से आ रहा है विमान, फरवरी-मार्च में मिलेगी सेवा : एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार हेरिटेज एविएशन ने अमेरिका की एक कंपनी का विमान लीज पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीस सीटर विमान को हिंडन से शिमला के बीच उड़ाया जाएगा। शुरुआत में दिन में एक ही फ्लाइट होगी। माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसी विमान को अन्य रूटों पर भी उड़ाया जा सकता है। हालांकि पहले इसे जनवरी में ही उड़ाने की योजना थी। यात्रियों को उम्मीद थी कि हिमपात के सीजन में वे फ्लाइट से आसानी से शिमला पहुंच सकेंगे। कंपनी ने अब योजना को फरवरी के अंत अथवा मार्च की शुरुआत तक के लिए टाल दिया है। अधिकारियों की माने तो खराब मौसम की वजह से पिछले दिनों पिथौरागढ़ की फ्लाइट कई दिन रद रही थी। ऐसे में एविएशन कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके चलते शिमला के लिए भी देरी से उड़ान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

आयोजन

जश्न ए रेख्ता के दूसरे दिन आयोजित विशेष सत्र में गीतकार जावेद अख्तर ने साहिर लुधियानवी के जीवन के कई पहलुओं पर बात की

छोटी-छोटी बातों की भी मां से इजाजत लेते थे साहिर : जावेद अख्तर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जश्न ए रेख्ता के दूसरे दिन साहिर लुधियानवी पर आयोजित सत्र 'पल दो पल का शायर हूं' में गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि अपनी कविताओं के जरिये सच्चाई बयां करने और सही बात के लिए लड़ते समय कई बार उग्र रवैये के लिए पहचाने जाने वाले साहिर असल जिंदगी में बिल्कुल विपरीत थे। अख्तर ने कहा कि वह विरोधाभासी व्यक्तित्व वाले इंसान थे। यदि मैं कहूं कि वह अच्छे व्यक्ति थे, तो उनके बारे में इससे अधिक उबाऊ बात और कोई नहीं हो सकती। जब वह अच्छे होते थे तो उनकी अच्छाई की कोई सीमा नहीं थी और जब वह किसी से गुस्सा होते थे, तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होती थी।

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित जश्न-ए-रेख्ता में जावेद अख्तर ने कहा साहिर एक अमीर जमींदार की इकलौती संतान थे। साहिर जब बच्चे थे तभी उनके माता-पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ रहे

जश्न ए रेख्ता कार्यक्रम में बोलते कवि व गीतकार जावेद अख्तर (दाएं)। साथ में लेखक सैफ महमूद। जागरण

और उन्होंने एक सफल कवि एवं गीतकार बनने से पहले गरीबी में जीवन बिताया। लुधियानवी ने जीवन में जो कुछ सहा, उसे देखकर यह सोचना गलत होगा कि इतने सफल कवि का जीवन आसान रहा होगा। अख्तर ने कहा, क्या आपको लगता है कि एक आसान जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी पुस्तक का नाम 'तल्खियां' रखता, यह संभव नहीं है। अख्तर ने बताया कि लुधियानवी का अपनी मां के साथ जो लगाव और रिश्ता था, वैसा मां-बेटा का रिश्ता उन्होंने कहीं नहीं देखा। उन्होंने बताया कि लुधियानवी कहीं भी मुशायरे के लिए कार से जाते थे तो अपनी मां को भी ले जाते थे। लुधियानवी मंत्रियों को झिड़क सकते थे, निर्देशकों, निर्माताओं एवं संगीतकारों से लड़ सकते थे, लेकिन दूसरी ही तरफ वह छोटी-छोटी बातों के लिए अपनी मां की मंजूरी लेते थे। उन्होंने कहा, वह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, उनके भीतर कई इंसान रहते थे।

आजकल के गानों में प्रकृति की मौजूदगी संबंधी एक सवाल के जवाब में जावेद ने कहा कि प्रकृति को लोग भूल गए हैं। जरा दिमाग पर जोर देकर अपने आप से ही पूछिये कि आखिरी बार कब चौदहवीं का चांद देखा था। झरने के पास आखें बंद कर कब बैठे। पेड़ों की छांव में कब हवाओं को महसूस किया। दरअसल, अब इन्सान सीमेंट के जंगल में रहता है। प्रदूषण इतना है कि चांदनी भी नहीं दिखती। इसका असर संगीत पर भी पड़ा है क्योंकि गीत-संगीत समाज का ही हिस्सा है। साहिर के ताजमहल पर लिखी एक नज्म पर चर्चा के दौरान जावेद ने कहा कि इस नज्म को लिखने से पहले उन्होंने ताजमहल का कभी दीदार नहीं किया था।

मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी ने साझा किया मुशायरे का सफर : 'मुशायरा और हम' सत्र में शायर मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी ने मुशायरे के सफर पर विस्तार से दर्शकों से अनुभव साझा किए। राहत इंदौरी ने जौन एलिया से जुड़े कई प्रसंग साझा किए। हिंदी प्रकाशकों द्वारा उर्दू शायरों की किताबें बड़े पैमाने पर छापे जाने का दोनों ही शायरों ने स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत की गंगा-जमुनी तहजीब को पुख्ता करता है।

स्वाति की सेहत बिगड़ी, अनशन खत्म करने की सलाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आंध्र में पारित 'दिशा बिल' को पूरे देश में लागू करने की मांग

दुष्कर्म मामले में सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर राजघाट पर अनशन कर रहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद की सेहत 12वें दिन और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें अनशन खत्म करने की सलाह दी है।

डॉक्टरों ने शनिवार को बताया कि स्वाति का वजन 7-8 किलो तक कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी सामान्य से कम बना हुआ है। यूरिक एसिड 10.1 है, जो सामान्य से बहुत अधिक है। यह खतरे का संकेत हैं। इसमें वृद्धि के कारण किडनी खराब हो सकती है। स्वाति ने अनशन के 12वें दिन आंध्र सरकार को बधाई देते हुए 'दिशा बिल' की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बिल जब एक राज्य में पास हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जा सकता। इस बिल की सारे देश की जरूरत है। स्वाति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा। खत में स्वाति ने दुख जताया कि 12 दिन बाद भी सरकार ने उनकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा।

उन्होंने बताया कि उनका वजन 6-7 किलो कम चुका है। तबीयत भी थोड़ी खराब है लेकिन उनके हौसले मजबूत हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश की सरकार की तर्ज पर दिशा बिल पूरे देश में लागू करने की मांग की। स्वाति ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को पत्र लिखकर दिशा बिल को लाने के लिए बधाई दी। स्वाति ने कहा कि उन्हें दुख है कि सांसदों ने इस सत्र का समय दुष्कर्म के ऊपर बयानबाजी में खराब कर दिया। यदि यही समय दुष्कर्म के खिलाफ एक कानून बनाने और मुद्दों पर बहस करने में लगाया होता तो देश मे कुछ बदलाव आता।

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आदर्शों व अनुपालन में अंतर'

- किशोर अपराधों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने साझा किए विचार
- जिन बच्चों को अपराधी के रूप में देखा जाता है दरअसल वे इस कारोबार के पीड़ित हैं : जस्टिस चंद्रचूड़
- न्यायाधीश ने कहा, किशोर अपराध को रोकने के लिए अभावों व गरीबी पर ध्यान देने की जरूरत
- बोले, हालात धकेलती हैं नाबालिगों को मादक द्रव्यों के सेवन व हिंसा की ओर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आदर्शों और उसके अनुपालन में काफी अंतर है। किशोर अपराधों को रोकने के लिए अभावों और गरीबी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ही नाबालिगों को मादक द्रव्यों के सेवन और हिंसा की ओर धकेलती हैं।

राष्ट्रीय किशोर न्याय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कानून के उल्लंघन में फंसे बच्चे सिर्फ अपराधी नहीं होते बल्कि कई मामलों में उन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, 'हमारे पास अद्भुत कानून हैं, लेकिन कानून के आदर्शों और उनके अनुपालन में अंतर है... बच्चों को कई बार अपराध विरासत में मिलते हैं। वे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में पैदा हुए होते हैं जो उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन और हिंसा की ओर धकेल देती हैं।'

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह विषय उनके लिए निजी है क्योंकि वह और उनकी पत्नी दो दिव्यांग युवा बच्चियों के पालक माता-पिता हैं जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बड़ी हुईं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि संस्थाओं के मानक बरकरार रखा जाना बेहद अहम हैं। इस क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर और पनवेल आश्रय गृहों का उदाहरण दिया जहां नाबालिग बच्चियों का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था।

मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को अपराधी के रूप में देखा जाता है दरअसल वे इस कारोबार के पीड़ित हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्थिक संसाधनों के अभाव और किशोर अपराधों में गहरा संबंध है।

डीवाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 42.39 फीसद किशोर अपराधियों की पारिवारिक आय 25,000 रुपये से कम थी। वहीं, 28 फीसद बाल अपराधियों की पारिवारिक आय 25,000 से 50,000 के बीच थी। केवल दो से तीन फीसद बाल अपराधी उच्च आय वर्ग के थे। चंद्रचूड़ ने कहा, इस बारे में सामने आए आंकड़े खुद ब खुद तस्वीर को पेश कर रहे हैं।

योजनाएं लागू न हों तो उन पर कागज बर्बाद न करें : जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) कानून, 2000' को बनाए जाने के 19 साल बाद भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। अभी तक बच्चों के लिए आश्रय गृहों का पंजीकरण नहीं किया गया है। इसी वजह से यौन उत्पीड़न, तस्करी, मादक द्रव्यों और कई अन्य मामले होते हैं। उच्चाधिकारियों का दायित्व है कि वे कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जस्टिस लोकुर ने कहा कि योजनाओं पर कागज बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है अगर उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है।

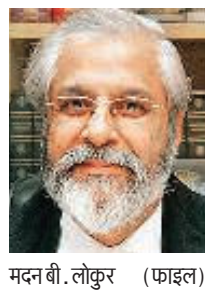
मदन बी. लोकुर (फाइल)

खत्म कर दी जाएं जुवेनाइल जस्टिस कमेटियां : दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने भी कहा, 'बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत सारे कानून हैं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जमीनी स्तर पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बच्चों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है।' इस समस्या का समाधान सुझाते हुए उन्होंने कहा, बच्चों को आश्रय गृहों में भेजे जाने के बजाय उन्हें वैकल्पिक देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हर बच्चे को उसके अपने माहौल में पलने का अधिकार है। लिहाजा मकसद संस्थाकरण कम करने का होना चाहिए। गुप्ता ने सुझाव दिया कि आश्रय गृहों का कंप्यूटरीकृत प्रणाली से प्रबंधन किया जाना चाहिए। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस कमेटियों को खत्म कर दिया जाना चाहिए और उनका काम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को करना चाहिए ताकि बच्चों के वो संरक्षण दिया जा सके जिसके वे अधिकारी हैं।

सीबीआइ ने लीला सैमसन के खिलाफ मामला दर्ज किया

- 7.02 करोड़ रुपये की परियोजना में अनियमितताओं का मामला
- संगीत नाटक अकादमी, फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं

लीला सैमसन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने चेन्नई स्थित कलाक्षेत्र फाउंडेशन के कुथंबलम सभागार के पुनरुद्धार की 7.02 करोड़ रुपये की परियोजना में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना लीला सैमसन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पद्मश्री से सम्मानित सैमसन संगीत नाटक अकादमी और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सैमसन के अलावा फाउंडेशन के तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी टीएस मूर्ति, लेखा अधिकारी एस रामचंद्रन, इंजीनियरिंग अधिकारी वी श्रीनिवासन और 'सीएआरडी' के मालिक और चेन्नई के इंजीनियरों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सीबीआइ ने आरोपितों के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि फाउंडेशन के अधिकारियों ने सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए 'सीएआरडी' के साथ पुनरुद्धार कार्य के लिए अनुबंध किया था। मंत्रालय ने 2016 में जांच के बाद आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने 7.02 करोड़ की परियोजना के अनुमानित मूल्य से 62.20 लाख रुपये ज्यादा खर्च किए। इस सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए आकलन के मुताबिक यह ठेका अपेक्षाकृत ज्यादा कीमत पर दिया गया और इसी के अनुरूप ठेकेदारों को भुगतान किया गया। सैमसन छह मई, 2005 से 30 अप्रैल, 2012 के बीच फाउंडेशन की निदेशक रही थीं। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा 1985 में बनाए गए सभागार के पुनरुद्धार की जरूरत 2006 में महसूस की गई।

मंत्रालय ने शिकायत में आरोप लगाया कि ठेके देने में खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्राथमिकी में कहा गया कि खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं करने की वजह से फाउंडेशन को हुए नुकसान के लिए सैमसन कथित तौर पर जिम्मेदार थीं।

देश की आत्मा को तार-तार कर देगा नागरिकता कानून : सोनिया

तीखा हमला ▶ पूछा, जिस काले धन के लिए नोटबंदी की गई वह किसके पास है, मनमोहन बोले-सरकार ने जनता से की वादाखिलाफी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कानून देश की आत्मा को तार-तार कर देगा। हालांकि मोदी और शाह को इसकी परवाह नहीं है। उनका एक ही संकीर्ण एजेंडा है। लोगों को आपस में लड़वाओ और असली मुद्दों को छिपाओ। लेकिन, नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराध है। इसके लिए संघर्ष करना होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष शनिवार को रामलीला मैदान पर पार्टी की 'भारत बचाओ रैली' को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बताएं, क्या वह संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं? इस पर भीड़ ने तैयार होने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून भेदभाव से भरा है। हमारे देश का बुनियादी स्वभाव ऐसे कदमों की इजाजत नहीं देता है। लेकिन, मैं विश्वास दिलाती हूं, जिनके साथ अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।

नई दिल्ली में शनिवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली के दौरान लोगों का अभिवादन करतीं, बाएं से, पार्टी नेता प्रियंका वाड्रा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ध्रुव कुमार

सोनिया ने मौजूदा सरकार को 'अंधेर नगरी चौपट राजा' बताते हुए कहा कि देश के ऐसे ही हालात हैं। अर्थव्यवस्था सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई है। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है।

किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर सबका साथ-सबका विकास की बात कहां गई? जिस काले धन के लिए नोटबंदी की गई, वह किसके पास है? इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान संसद के काम-काज पर भी सवाल उठाए और कहा कि संसदीय समितियों में बगैर चर्चा के विधेयकों को पास कराया जा रहा है।

रैली को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी संबोधित किया और सरकार पर जनता से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छह साल पहले सरकार ने जनता से काफी लुभावने वादे किए थे। लेकिन, उनका क्या हुआ, यह सभी को पता है।

उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाएं, ताकि हम देश को सही रास्ते पर आगे ले जा सकें। वहीं रैली को संबोधित करने हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि अब भी हम चुप रहे, तो डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के जो हालात हैं, ऐसे में अभी जो न्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा, उसे कायर कहा जाएगा।

रैली को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि ने भी संबोधित किया। रैली की भारी भीड़ देखकर कमलनाथ गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि भीड़ को देखकर मेरा ढाई सौ ग्राम खून बढ़ गया है। उन्होंने मोदी से पूछा वह राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन क्या बताएंगे कि भाजपा के कितने नेताओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया?

राहुल गांधी की पार्टी में फिर से ताजपोशी की तैयार हुई जमीन

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' वैसे तो केंद्र की नीतियों के खिलाफ थी। लेकिन, इसमें जिस तरह पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी का जिक्र किया और उनके मुद्दों को प्रासंगिक बताने की कोशिश की, वह इस बात के साफ संकेत है कि उनका फिर से पार्टी अध्यक्ष बनना तय है। शनिवार की यह रैली भी इसकी जमीन तैयार करने का हिस्सा थी। पार्टी ने इसका संदेश देशभर से आए कार्यकर्ताओं के जरिये दे दिया है। साथ ही यह भी बता दिया कि राहुल ही पार्टी के नेता हैं और आगे भी रहेंगे।

पार्टी के भीतर हालांकि राहुल की फिर से ताजपोशी की चर्चा उनके इस्तीफे के बाद से ही लगातार चल रही है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग-अलग मंचों से उन्हें ही फिर से पार्टी की कमान दिए जाने की वकालत कर चुके हैं। लेकिन, शनिवार को पार्टी की बड़ी रैली में सबको यह संदेश देने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ही 'मेरे नेता राहुलजी' से की। इसके बाद भी उन्होंने अपने भाषण में कई बार राहुल गांधी का जिक्र किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह साफ संकेत था। खासकर उन लोगों के लिए जो प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान देने की वकालत करते दिखते हैं। इस बात को मजबूती तब मिली, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल की जोरदार पैरवी की। उन्होंने कहा कि 'चुनाव हारना और जीतना एक अलग बात है। सभी को पता है कि कैसे राष्ट्रवाद और सेना के शौर्य के दम पर चुनाव जीता गया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दे चुनाव के दौरान उठाए थे, वह आज भी प्रासंगिक हैं। देश की अर्थव्यवस्था दिनो-दिन खराब हो रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है।' छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राहुल का जिक्र किया। हालांकि वह पहले भी राहुल की फिर से ताजपोशी की वकालत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने उनको ही भविष्य का नेता बताया था। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी को पूरा तवज्जो देते दिखे।

प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई, मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है। कैबिनेट मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों पर प्रजेंटेशन (प्रस्तुतिकरण) देने के लिए भी कहा गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव (संगठन) बीएल संतोष बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधित मंत्रालयों के चल रहे प्रोजेक्टों पर चर्चा कर सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, फेरबदल होने पर मोदी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई फेरबदल नहीं किया है। पिछली सरकार में छह महीने के भीतर ही उन्होंने नौ नवंबर 2014 को मंत्रिमंडल में बदलाव किया था।

बंद हो चुके सेना के डेयरी फार्मों की जमीन का ब्योरा पहुंचा रक्षा मंत्रालय

दीपक बहल, अंबाला

- डेयरी फार्मों की भूमि के बेहतर इस्तेमाल की तैयारी में सरकार
- अंबाला से 847.71 एकड़ जमीन की भेजी गई रिपोर्ट

कभी भारतीय फौज की खुराक को पूरा करने का जिम्मा उठाने वाले बंद हो चुके डेयरी फार्मों की खाली पड़ी जमीन पर अब रक्षा मंत्रालय की निगाहें टिकी हैं। अंबाला सहित 39 छावनी क्षेत्रों में हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन खाली पड़ी है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट मंगा ली है। उसकी योजना इस जमीन का बेहतर उपयोग करने की है। अंबाला में जहां राफेल की तैनाती होनी है, वहीं थल सेना भी अपनी तैयारियां पुख्ता करने की योजना बना रही है।

आवश्यकता के अनुसार यह जमीन वायु सेना, थल सेना अथवा किसी अन्य मंत्रालय को ट्रांसफर की जा सकती है। फिलहाल अंबाला में एयरफोर्स को करीब 51 एकड़ जमीन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान से करीब 220 किलोमीटर (एरियल रूट) दूरी पर अंबाला स्थित है। यह जमीन राफेल के लिए स्थानांतरित की जा रही है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी सेना की जरूरत के मुताबिक इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

अंबाला से 847.71 एकड़ जमीन की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। महत्वपूर्ण है कि यह जमीन डिफेंस एस्टेट आफिस के पास है। इस जमीन पर न तो कोई अतिक्रमण है और न ही कोई कोर्ट केस।

ब्रिटिशकालीन हैं डेयरी फार्म : खानपान की वस्तुओं की कमी के चलते 1889 में यह सैन्य डेयरी फार्म अस्तित्व में आए थे। यहां पर सेना के लिए जहां दुग्ध उत्पादन किया गया, वहीं फल व सब्जियां भी उगाई गईं थीं। अंबाला में करीब 847.71 एकड़ जमीन पर डेयरी फार्म बनाया गया था।

रक्षा मंत्रालय ने करीब दो साल पहले देशभर में डेयरी फार्म बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जमीन को लेकर रक्षा मंत्रालय ने देशभर से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद डिफेंस एस्टेट कार्यालय ने जांच कि जमीन पर किसी का कब्जा या फिर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन तो नहीं है।

देश भर में डेयरी फार्म की जमीन : बिनागुरी 217.36 एकड़, गुवाहाटी 88.92 एकड़, दीमापुर में 34.53 एकड़, जोरहट 11.11 एकड़, पानागढ़ 766.68 एकड़, पानीटोला 112.65 एकड़, तेंगा 20.54 एकड़, कोलकाता 20.97 एकड़, मिसामरी 40.00 एकड़, बेंगडुबी 248.97 एकड़, कारू 1390 एकड़, कारगिल 1442 एकड़, श्रीनगर 20.81 एकड़, नौशेरा 47.50 एकड़, उधमपुर 21.03 एकड़, जम्मू 13.37 एकड़, अहमदनगर 4234.77 एकड़, बेलगांव 96.94 एकड़, देवलाली 95.44 एकड़, ग्वालियर 80.52 एकड़, झांसी 683.46 एकड़, पिंपरी 387.76 एकड़, सिकंदराबाद 3978.64 एकड़, आगरा 307.08 एकड़, इलाहाबाद 536.31 एकड़, कानपुर 599.98 एकड़, रानीखेत 8.33 एकड़, बरेली 489.84 एकड़, लखनऊ 1308.42 एकड़, नामकुम 376.17 एकड़, जबलपुर 1118.56 एकड़, महू 1502.99 एकड़, मेरठ 959.74 एकड़, फिरोजपुर 895.13 एकड़, पठानकोट 33.43 एकड़, योल 15.37 एकड़, डगशाई 14.16 एकड़, अंबाला 847.71 व जालंधर 569.50 एकड़।

विद्युतीकरण के कारण रेलवे के लिए सिरदर्द हैं डीजल इंजन

संजय सिंह, नई दिल्ली

- 1,500 डीजल लोको का नहीं हो रहा उपयोग, दो साल में हो जाएंगे 4,000
- डीजल इंजनों को कबाड़ में बेचने की नौबत, निर्यात पर हो रहा विचार

रेलवे के डीजल इंजन, जो अब धीरे-धीरे चलन से बाहर हो रहे हैं। प्रतीकात्मक

68,500 किमी रूट लाइन हैं रेलवे की देशभर में

30 हजार रूट किलोमीटर अर्थात 43 फीसद लाइनें विद्युतीकृत हैं

10-12 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं रेलवे को एक डीजल इंजन के निर्माण पर

25-30 लाख रुपये में बिकेगा कबाड़ में एक इंजन

शत-प्रतिशत विद्युतीकरण परियोजना ने रेलवे के आगे डीजल इंजनों के निपटान की एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस समय रेलवे के तकरीबन डेढ़ हजार डीजल इंजन बिना उपयोग के खड़े हैं। अगले दो वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 4,000 हजार हो जाने वाली है। ऐसे में रेलवे को समझ नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए।

रेलवे ने दो वर्ष पहले शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसके तहत पांच वर्ष के भीतर देश की सभी रेलवे लाइनों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। इस योजना पर तेजी से अमल हो रहा है और 2016-17 के 2013 रूट किलोमीटर के मुकाबले 2017-18 में दोगुनी से ज्यादा अर्थात 4087 रूट किलोमीटर लाइनों का विद्युतीकरण किया गया। अभी रेलवे की कुल 68,500 रूट किलोमीटर लाइनों में से 30 हजार रूट किलोमीटर अर्थात 43 फीसद लाइनें विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2022-23 तक शत-प्रतिशत लाइनें विद्युतीकृत होनी हैं।

विद्युतीकरण में ज्यों-ज्यों तेजी आ रही है, डीजल इंजनों का उपयोग कम होता जा रहा है। विद्युतीकरण के कारण पिछले दो साल में तकरीबन डेढ़ हजार डीजल इंजन उपयोग से बाहर हो चुके हैं। जबकि अगले दो साल में ऐसे इंजनों की संख्या बढ़कर चार हजार हो जाने की अनुमान है। ऐसे में रेलवे के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इन बेकार इंजनों का क्या किया जाए। क्योंकि ये इंजन उपयोग से बाहर अवश्य हुए हैं, परंतु बेकार नहीं हैं। ये न केवल बखूबी काम कर रहे हैं, बल्कि सामान्य ट्रेन संचालन के लिए बिलकुल उपयुक्त हैं।

इन अप्रयुक्त डीजल इंजनों में अधिकांश का निर्माण वाराणसी की डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप में हुआ है। जहां ऐसे प्रत्येक इंजन के निर्माण पर 10-12 करोड़ रुपये की लागत आती है। चूंकि यह एक बड़ी राशि है, लिहाजा रेलवे इन इंजनों को कबाड़ के भाव नहीं बेचना चाहता। कबाड़ में एक इंजन ज्यादा से ज्यादा 25-30 लाख रुपये में बिकेगा। ऐसे में इन इंजनों के निर्यात की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों का अनुमान है कि पड़ोसी देशों को निर्यात से प्रत्येक इंजन से दो-ढाई करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है। माना जाता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में, जहां अभी भी डीजल ट्रेनों का संचालन होता है, इन इंजनों के लिए बाजार मिल सकता है।

मार्च, 2018 तक रेलवे के पास कुल 6,086 डीजल और 5,639 इलेक्ट्रिक इंजन थे। हर साल करीब 650 पुराने इंजन सेवा से बाहर होते हैं जिनकी प्रतिपूर्ति नए इंजनों से की जाती है। इसके लिए रेलवे के लोको कारखाने हर साल 650-700 लोको बनाते रहे हैं। जिनमें 55 फीसद डीजल और 45 फीसद इलेक्ट्रिक होते थे। परंतु विद्युतीकरण परियोजना के कारण इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन बढ़ने से ये अनुपात उलट गया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्लू) के अलावा वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्लू) में भी डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक लोको के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा मढौरा में जीई के सहयोग से डीजल इंजन कारखाना लगाए जाने के कारण हुआ है, जहां दस वर्ष में 1,000 डीजल इंजन बनेंगे। दूसरी ओर अल्स्टॉम के सहयोग से मधेपुरा में लगने वाला इलेक्ट्रिक लोको कारखाना हैवी इलेक्ट्रिक इंजनों की कमी पूरी करेगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी

रणनीतिक हित

टू प्लस टू वार्ता से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्पर का बड़ा बयान, 18 दिसंबर को होने वाली वार्ता की मेजबानी की तैयारी में जुटा अमेरिका

अमेरिका के लिए भारत का बड़ा महत्व : एस्पर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका का रणनीतिक हित भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आने वाले वर्षों में अमेरिका के लिए रूस के साथ चीन दूसरी बड़ी चुनौती बनने वाला है। यह बात अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कही है। 18 दिसंबर को अमेरिका भारत के साथ टू प्लस टू मंत्री स्तर की वार्ता की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की यह वार्षिक बैठक दूसरी बार होगी। इससे दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होने की संभावना है।

थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में एस्पर ने कहा, पेंटागन में उनकी भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद वह और राजनाथ सिंह विदेश मंत्रालय के मुख्यालय फॉगी बॉटम जाएंगे, वहां पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के साथ टू प्लस टू वार्ता होगी। एस्पर ने कहा कि हम हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में बेरोक-टोक आवागमन के पक्षधर हैं। इसके लिए हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय नियमों से जुड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए अमेरिका सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके लिए कई नए और महत्वपूर्ण रास्ते भी बनाए जा रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम शक्तिशाली मुकाबले के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें चीन हमारे लिए पहली और रूस दूसरे नंबर की चुनौती है। दोनों देश अपनी सेनाओं को लगातार आधुनिक बना रहे हैं, स्पेस और साइबर क्षेत्र में अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। इसके लिए दोनों ही देश न केवल छोटे देशों की संप्रभुता खत्म कर रहे हैं बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों-कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड अभियान के जरिये चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। इसके जरिये वह अपनी सेनाओं की वहां तक पहुंच बना रहा है। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे को लेकर चीन छोटे पड़ोसी देशों को धमका रहा है, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। रूस का क्रीमिया पर कब्जा और यूक्रेन के साथ विवाद देशों की संप्रभुता के उल्लंघन का उदाहरण है। उसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो को नीचा दिखाना है।

मार्क एस्पर फाइल फोटो

इराक पर हमले के लिए ईरान को कड़ी चेतावनी : माइक पोंपियो

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने इराक पर ईरानी हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और ईरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। कहा है कि इराकी ठिकानों पर ईरान के रॉकेट हमलों पर हम गंभीर हैं। इनमें अमेरिकी नागरिकों, सहयोगियों या हितों पर चोट होगी तो करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए ईरान पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करे। (पेज-13 देखें)

हाई कोर्ट पहुंची रणजीत हत्या केस में जज बदलने की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ चल रहे रणजीत हत्या मामले में सीबीआइ जज को बदलने की मांग लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। सीबीआइ की पंचकूला कोर्ट इस मांग को खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

इस मामले में आरोपित कृष्ण लाल ने अपील में कहा है कि सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह पहले भी गुरमीत सिंह के खिलाफ दो मामलों में फैसला सुना चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले से अलग किया जाए।

DR. RAMASWAMY IAS ACADEMY
FREE COACHING
IAS, SSC, JUDICIARY AND GROUP-A, B & C
SC/ST /EWS/OBC DELHI RESIDENCE ONLY
9350933144, 9958589406
Centre-1 1418, Dr. Mukherjee Nagar, 4th Floor, Main Road, New Delhi-09
Centre-2 4-A/17, Old Rajendra Nagar Main Market, New Delhi-110060

लोगों को उकसाकर दंगे भड़का रही कांग्रेस : अमित शाह

प्रचार ▶ अनुच्छेद 370, राम मंदिर, एनआरसी व सर्जिकल स्ट्राइक से टटोली मतदाताओं की नब्ज

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

कांग्रेस पर लगाया दुष्प्रचार कर देश की जनता को बांटने का आरोप

जागरण संवाददाता, धनबाद

केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर कांग्रेस देशभर में लोगों को उकसाकर दंगे भड़का रही है। आज तक हिंदू-मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई कांग्रेस का चेहरा अब बेनकाब हो गया है। वह लगातार दुष्प्रचार कर लोगों को बांटने में लगी है। यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। वह शनिवार को धनबाद, गिरिडीह और देवघर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि राहुल बाबा 55 साल का हिसाब नहीं देते और मोदी सरकार जब तीन तलाक, अनुच्छेद 370 पर कानून बनाती है, तो उन्हें दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के राम मंदिर के फैसले पर भी उनकी जुबान सिल जाती है। राम मंदिर की

- कहा-अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण चार माह के भीतर शुरू हो जाएगा
- पिछड़ों का बढ़ेगा आरक्षण, दलितों-आदिवासियों के आरक्षण में नहीं होगी कोई कटौती

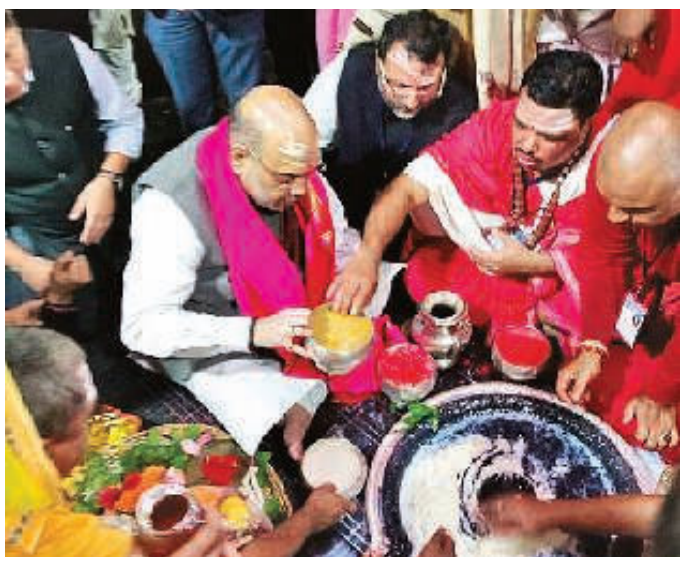

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की और इसके बाद चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। जागरण

चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण चार माह के भीतर शुरू हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे मुस्लिम विरोधी बता रही है जबकि यह कहीं से भी मुस्लिम विरोधी नहीं है। उत्तर-पूर्व के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी और सरकार उनके हितों की हर हाल में रक्षा होगी। इसके अलावा उन्होंने मेघालय के सीएम से बात होने की जानकारी भी मंच से ही दी। स्पष्ट किया कि एनआरसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का बिल है, उनकी नागरिकता छीनने का बिल नहीं है।

इस दौरान शाह ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की। पिछड़ों को रिझाने के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाने का आश्वासन दिया। साथ में यह भी कहा कि इससे दलितों और आदिवासियों का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। अनुच्छेद 370, श्रीराम मंदिर, एनआरसी और सर्जिकल स्ट्राइक पर जनता से सवाल भी किया कि यह जो भाजपा ने किया वह सही है या नहीं, जनता ने भी समर्थन की मुहर लगाई।

राहुल बताएं 55 साल में क्या किया

शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार की चार पीढ़ी और कांग्रेस ने देश में 55 साल राज किया। राहुल गांधी बताएं कि गरीबों के लिए क्या किया। उनको बिजली, चूल्हा, शौचालय, आवास मोदी ने दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल पहले क्या था, सब जानते हैं हमारी सरकार गरीबों के हित में आयुष्मान योजना लाई। राहुल व हेमंत बताएं की उन्होंने क्या किया, इस पर वह बहस करने के लिए तैयार हैं।

देश की सुरक्षा से समझौता नहीं

शाह यहीं नहीं रुके, मनमोहन सिंह पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और जवानों का सिर काटकर ले जाते थे। प्रधानमंत्री उफ तक नहीं करते थे। अब ऐसा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक और अब एयर स्ट्राइक से पुलवामा का बदला लेकर हमने स्पष्ट कर दिया है कि अब देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा।

लक्ष्मी कमल पर बैठकर आती हैं, तीर-धनुष पर नहीं : स्मृति

जागरण संवाददाता, सुरही (बेरमो)

घर में लक्ष्मी कमल पर बैठकर आती हैं। वह तीर-धनुष पर बैठकर नहीं आती हैं। ये बातें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को तेलो के बाजारटांड़ में डुमरी के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप साहू के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीते पंद्रह सालों में तीर-धनुष वालों ने राज्य को केवल लूटने का काम किया है। अब डुमरी को तीर-कमान से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। कहा कि भाजपा अनुशासन एवं मर्यादा का ख्याल रखती है।

उन्होंने विकास के दीप जलाने की अपील करते हुए कहा कि जनता का भला तीर-धनुष ने नहीं हो सकता है। तीर-धनुष वाले लूटने और अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त हैं। उनके पास जनता के लिए समय कहां है। कहा कि महिलाओं को धुआं से मुक्ति दिलाते हुए डुमरी में उज्ज्वला

बेरमो में शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करती स्मृति ईरानी। जागरण

योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन दी गई। यही नहीं, सरकार ने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। यह मोदी ही हैं, जो गरीबों के दर्द को पहचानते हुए आयुष्मान योजना लेकर आए, ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। झारखंड के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहां के लोग मेहनती है।

देखते हैं पहले विराट डबल सेंचुरी मारता है या प्याज : तेजस्वी

जासं, मैथन (धनबाद) : बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को मैथन स्थित बीएसके कॉलेज मैदान में आयोजित चुनावी सभा में नागरिकता संशोधन कानून, प्याज के बढ़ते दाम, बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। यहां महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी अशोक मंडल के समर्थन में राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। भाजपा वाले भाई से भाई को लड़ा कर देश को तोड़ने में लगे हैं। बिहार में किसी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू नहीं होने देंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं, जो यहां से अल्पसंख्यकों को बाहर निकाल सके। सीएए पर 21 दिसंबर को राजद द्वारा बिहार बंद बुलाया गया है।

उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। प्याज का दाम आसमान छू रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देखते हैं प्याज पहले सेंचुरी मारता है या सचिन तेंदुलकर। लेकिन, अब मैं कह रहा हूं, देखता हूं विराट पहले डबल सेंचुरी मारता है या प्याज। अब तो लोग प्याज को सूंघ- सूंघ कर खाना खा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि 19 साल के झारखंड में 16 साल भाजपा के लोगों ने राज किया और कहते है कि झारखंड गरीब है। वे बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार देंगे। यहां तो एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध में लिप्त है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोग डरा कर शासन करना चाहते हैं।

मप्र भाजपा के मुखिया का मुकाबला दिलचस्प

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में लॉबिंग तेज हो गई है। अचानक बदले सियासी घटनाक्रम के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में शनिवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह से भेंट की। दोनों के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई और दोपहर का भोजन भी साथ किया। सियासी हल्कों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस लंच डिप्लोमेसी के बहाने दोनों ने गिले-शिकवे दूर कर लिए हैं। एक दिन पहले भी शिवराज दिल्ली गए थे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे।

दिल्ली में दो दिनों की उठापटक से कयास लगाए जा रहे हैं कि हाईकमान की मंशा को भांपकर ही अब प्रदेशाध्यक्ष के दावेदारों ने खंभ ठोकना बंद कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष को लेकर सारी सियासत का केंद्र भी अब भोपाल के बजाय दिल्ली हो गया है। गौरतलब है कि पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और विजय सोनकर शास्त्री से प्रदेशाध्यक्ष के दावेदार को लेकर बड़े नेताओं से रायशुमारी करवा ली है। आने वाले सप्ताह में भाजपा का मध्य प्रदेश का अगला मुखिया तय होने की संभावना है।

'नहीं चेते तो साड़ी, सिंदूर भी महंगा होगा'

जासं, शिकारीपाड़ा (दुमका)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को यहां चुनावी सभा में भाजपा पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नहीं चेते तो साड़ी, सिंदूर भी महंगा होगा। कहा कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद भी आदिवासी-मूलवासी अपने हर और अधिकार से वंचित हैं। जब तक झारखंड में महागठबंधन की आबुआ यानी हमारी सरकार नहीं बनती है, तो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य, बीज, साड़ी काफी महंगी हो गई है। प्याज 150 रुपये किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा कि झामुमो को समर्थन नहीं दिया, तो विस्थापित होना पड़ेगा। यह भी चेतावनी दी कि महागठबंधन के अलावा अन्य पार्टी जीती, तो वह भाजपा को समर्थन करेगी। इस दौरान उन्होंने भीड़ से पूछा क्या आप पारा शिक्षक व आंगनबाड़ी सेविकाओं को पीटने वाली सरकार को वोट देंगे, हमारी सरकार बनाएं। 100 यूनिट तक का बिजली बिल और किसानों का ऋण माफ कर देंगे। लड़कियों की सभी तरह की शिक्षा का खर्च

- कहा, महागठबंधन की सरकार बनी तो 100 यूनिट तक का बिजली बिल और किसानों का ऋण माफ करेंगे
- प्रदेश में जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनती, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी

हेमंत सोरेन। फाइल

सरकार उठाएगी। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का भी वादा किया।

रघुवर को सिकड़ में बांधकर भेजेंगे छत्तीसगढ़ के जंगल : हेमंत ने कहा कि इस बार रघुवर दास को सिकड़ में बांधकर छत्तीसगढ़ के जंगल में भेज देंगे। मसलिया के मोहनपुर फुटबॉल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने तीर धनुष पर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि झारखंड के समुचित विकास केवल झामुमो ही कर सकता है। आदिवासी मूलवासी परंपरा को बचाए रखने के लिए तीर धनुष पर वोट दे।

नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता : हेमंत

जासं, मंडरो (साहिबगंज) : झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को मंडरो के गडरा पंचायत स्थित तालेडीह में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि वर्तमान सरकार ने पढ़े लिखे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर झामुमो की सरकार राज्य में बनती है तो स्थानीय युवाओं को प्रदेश में होने वाली नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। इस सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश के किसान गलत नीतियों के कारण आत्महत्या को मजबूर हैं। प्रतिदिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इसी रोक पाने में सरकार पूरी तरह नाकाम है।

थम गया चौथे दौर के लिए प्रचार का शोर

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत चौथे दौर की 15 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए शनिवार को प्रचार अभियान खत्म हो गया। अब इन सीटों पर प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। इन सीटों पर 16 दिसंबर को सुबह सात बजे से मतदान होगा। नेताओं ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है।

इस दौर की 15 सीटों में दस सीटों पर शाम पांच बजे तक मतदान होना है, इसलिए वहां शाम पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हुआ। इनमें मधुपुर, देवघर, गांडेय, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया तथा बाघमारा शामिल हैं। वहीं, बगोदर, जमुआ, गिरिडीह, डुमरी और टुंडी में शाम तीन बजे ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन सीटों पर शाम तीन बजे तक ही मतदान होगा।

दो वर्तमान और सात पूर्व मंत्री की जुड़ी है प्रतिष्ठा : चौथे चरण के चुनाव से दो मंत्री, सात पूर्व मंत्री और वर्तमान 14 विधायकों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इस चरण में कुल 221 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 22 महिलाएं और 59 निर्दलीय हैं। सबसे अधिक कुल 25 प्रत्याशी बोकारो में तथा सबसे कम आठ निरसा में हैं।

राहुल की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा महिला मोर्चा

राज्य ब्यूरो, रांची

- गोड्डा की सभा में राहुल ने कहा था रेप इन इंडिया
- राहुल की चुनावी सभा पर रोक लगाने की मांग की, महिला आयोग में भी शिकायत

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गोड्डा की सभा में की गई टिप्पणी रांची से दिल्ली तक विवादों में बनी हुई है। शनिवार को राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया और उनकी शिकायत चुनाव आयोग के साथ-साथ राज्य महिला आयोग से भी की। बता दें कि गत 12 दिसंबर की गोड्डा की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि आज भारत मेक इन इंडिया के बजाय रेप इन इंडिया बन गया है। राहुल की इस टिप्पणी पर संसद में भी काफी हंगामा हुआ था।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा की गई इसी टिप्पणी को आधार बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग और महिला आयोग में शिकायत की। राहुल की टिप्पणी को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा, यह भी कहा कि राहुल गांधी के झारखंड में चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 12 दिसंबर 2019 को गोड्डा की चुनावी सभा में राहुल गांधी

राहुल गांधी। फाइल

ने अपमानजनक और शर्मसार करने वाला बयान दिया था। कहा था कि आज भारत मेक इन इंडिया के बजाय रेप इन इंडिया बन गया है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उन्होंने न केवल भारत में रहने वाली माताओं, बहनों एवं बेटियों को अपमानित किया है, बल्कि पूरे भारत को विश्व पटल पर भी शर्मिंदा किया है।

यमुना से लगती जमीन के विवाद सुलझने की बढ़ी उम्मीद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वर्षों पुराने विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए शानिवार को लखनऊ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वार्ता की टेबल पर बैठे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में कई अहम समझौते हुए हैं। बैठक में न केवल यमुना से लगती जमीन और नहरी पानी के विवादित मसलों को सुलझाने की कोशिश की गई, बल्कि राजस्व, सिंचाई, जल संसाधन, परिवहन तथा पीडब्ल्यूडी से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। अन्य मुद्दों के समाधान के लिए अगली बैठक इसी महीने आगरा में होगी।

वर्षों से लंबित द्विपक्षीय मामलों को हल करने की पहल में उस समय बड़ी सफलता मिली जब यमुना नदी पर तीन पुलों के निर्माण कार्य को आदित्यनाथ ने सहमति दे दी। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि पलवल के हसनपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले पुल का दोनों राज्य अपने-अपने हिस्से का निर्माण स्वयं करवाएंगे न कि 50-50 के अनुपात में। बैठक में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा के मामले में 14 फरवरी 1975 को दिए गए दीक्षित अवार्ड के अंतर्गत जो बुर्जियां मौके से गायब हैं, उनकी पुनः स्थापना के लिए निर्णय लिया गया कि यह कार्य सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से 31 मार्च, 2020 तक पूरा कराया जाएगा। इसपर 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दोनों राज्य 50-50 के अनुपात में यह राशि भी वहन करेंगे।

बैठक में पानीपत जिले में बिलासपुर को खोजकीपुर को जोड़ने वाले पुल तथा सड़क के निर्माण के लिए 70 मीटर भूमि उत्तर प्रदेश सरकार एक महीने में अधिग्रहीत करेगी। इसी प्रकार फरीदाबाद व ग्रेटर नोएडा वाया जसना-मंझवाली अट्टा गुजरांन के बीच यमुना नदी पर पुल के निर्माण पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है। इसी महीने भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे।यमुना नगर-रादौर (राज्यमार्ग-06) से नुकूर-सहारनपुर (एमडीआर-1472) सड़क पर यमुना नदी पर पुल के निर्माण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने अपने स्तर पर करने का आश्वासन दिया।

अकाली दल 2022 में सरकार बनाएगा जो 30 साल चलेगी : सुखबीर

जागरण संवाददाता, अमृतसर

सुखबीर सिंह बादल शनिवार को शिरोमणि अकाली दल के पांच वर्षों के लिए लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने कहा कि 2022 में पार्टी पंजाब में फिर सरकार बनाएगी और 30 साल तक सत्ता में बनी रहेगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मुख्यालय तेजा सिंह समुंद्री हाल में पार्टी की 99वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में 600 डेलीगेट्स ने अध्यक्ष का चुनाव किया। प्रकाश सिंह बादल को फिर पार्टी का सरपरस्त बनाया गया। सेहत ठीक न होने के कारण वह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।

सुखबीर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल टकसाली कांग्रेसियों के इशारों पर अकाली दल को कमजोर करने वाले साजिशकर्ताओं का ग्रुप है। पंथ व सिख संगत इन्हें नकार चुकी है। हम भविष्य में इतनी बड़ी लाइन खींच देंगे कि साजिशकर्ता यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत के संघीय ढांचे के लिए संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी ने इसके लिए 1962 में आवाज उठाई थी। अकाली दल शुरू से ही धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखता रहा है। पार्टी कभी भी देश को एक धर्म व एक विचारधारा वाला देश स्वीकार करने की बात नहीं मान सकती। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अकाली दल हमेशा अपनी जंग जारी रखेगा। अकाली दल शहीदों की और देश की पुरानी पार्टियों में से एक है। वह सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता है। सुखबीर ने कहा कि दुनिया में जहां भी सिखों को मुश्किल आई अकाली दल ने आवाज उठाई। अफगानिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी उसने ही आवाज उठाई है। नागरिकता संशोधन कानून में मुसलमानों को शामिल करने के लिए भी अकाली दल आवाज उठा रहा है। अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा के लिए वह हमेशा आवाज उठाता रहेगा।

कांग्रेस के पास इंटेलिजेंट मैनेजर नहीं : उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए कई संभावनाएं हैं। बस मैनेजर इंटेलिजेंट होना चाहिए। आज कांग्रेस के साथ कोई भी इंटेलिजेंट मैनेजर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा खजाना खाली होने का शोर मचाकर विकास में बाधा खड़ी की है, जबकि बादल सरकार ने विकास किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की कोई चिंता नहीं। वह जनता के प्रति समर्पित इंसान नहीं हैं।

मोदी ने दी बधाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अकाली दल की 99वीं वर्षगांठ पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश की पुरानी पार्टियों में से एक अकाली दल ने हमेशा समाज की सेवा की और लोगों के कल्याण के मुद्दे उठाए। भाजपा अपने सहयोगी अकाली दल पर गर्व करती है। यह गठबंधन सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि हमारी सरकार ने पंजाब में बहुत विकास किया है।

- अकाली दल के लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए सुखबीर, प्रकाश सिंह बादल फिर बने सरपरस्त

अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की 99वीं वर्षगांठ पर सुखबीर बादल को तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर उन्हें दस्तार भेंट कर सम्मानित किया गया। (बाएं से) पूर्व मंत्री जत्थेदार तोता सिंह, एसजीपीसी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल, पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुखबीर सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल व राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़। राघव शिकारपुरिया

शिअद व एसजीपीसी के अस्तित्व को बादल परिवार से बचांएगे : ढींडसा

अकाली दल बादल से नाराज होकर अकाली दल टकसाली के कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य सभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि वह भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह शिअद व एसजीपीसी के अस्तित्व को बादल परिवार से बचाने के लिए काम करेंगे। उनका बेटा परमिंदर सिंह ढींडसा भी जल्द ही शिअद टकसाली का हिस्सा बनेगा। उल्लेखनीय है कि परमिंदर बादल सरकार में वित्तमंत्री रहे हैं और इस समय विधानसभा में अकाली दल के नेता हैं।

फिर हुए सक्रिय

बदले हालात में अपनी राजनीतिक अहमियत साबित करने के लिए पुराने नेता फिर सक्रिय, पीडीपी से निष्कासित पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी के इर्दगिर्द बुना जा रहा सियासी तानाबाना

कश्मीर में नए मोर्चे के लिए पक रही सियासी खिचड़ी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

बदली परिस्थितियों में केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के सियासी मंच पर अपनी अहमियत साबित करने के लिए पुराने राजनीतिक नेता एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। यह नेता एक नया मोर्चा तैयार करना चाहते हैं, जो न सिर्फ घाटी में बल्कि जम्मू संभाग में भी पूरा प्रभाव रखे। संभावित मोर्चा तैयार करने में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के निष्कासित नेता जो पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों का दिल्ली में ही नहीं, विदेश में भी कुछ खास जगहों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। इनमें से एक नेता हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे हैं। नए सियासी संगठन को तैयार करने में जुटे यह लोग केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के नारे के साथ अपनी सियासत शुरू करने पर आपस मे सहमति बना रहे हैं।

अल्ताफ बुखारी। फाइल

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार मार्च-अप्रैल 2020 तक विधानसभा चुनाव कराना चाहती है। नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पांच अगस्त से पूर्व की जम्मू-कश्मीर की स्थिति की बहाली होने तक चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने का संकेत दिया है। इन दोनों दलों के सभी प्रमुख नेता नजरबंद हैं या फिर हिरासत में हैं। कांग्रेस भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। इसके अलावा बदले माहौल में क्षेत्रीय दलों के लिए जनता के समक्ष जाना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि वह जिन मुद्दों पर लोगों से वोट मांगते रहे हैं, वह पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने बीते चार माह के दौरान जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अपने स्तर पर कई उपाय किए जो अभी तक सफल होते नजर नहीं आए हैं।

कांग्रेस के पुराने नेता भी हाथ मिलाने को तैयार

सूत्रों ने बताया कि इस संभावित नए मोर्चे के साथ नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के कुछ पुराने नेता भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। हालांकि इनके राजनीतिक एजेंडे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस कवायद के साथ जुड़े लोगों की मानें तो यह सभी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के नारे के नाम पर अपना मोर्चा शुरू करेंगे।

पीडीपी से निष्कासित बुखारी का नाम सबसे ऊपर : पीडीपी के निष्कासित नेता अल्ताफ बुखारी का नाम उन लोगों में सबसे ऊपर लिया जा रहा है। वह कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे हैं। उनके साथ गत वर्ष की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा मंत्रिमंडल से निष्कासित किए गए गए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबु भी सक्रिय हैं। द्राबु दिल्ली के अलावा जम्मू संभाग में अपने परिचितों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। बुखारी ने कश्मीर में मोर्चा संभाल रखा है।

कारोबारी बुखारी के भाजपा नेताओं से भी अच्छे संबंध : कश्मीर की सियासत में बीते पांच साल से पूरी तरह सक्रिय सईद अल्ताफ बुखारी एक नामी कारोबारी हैं। वह खुद भी श्रीनगर में तीन से चार विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। उनके नेशनल कांफ्रेंस और भाजपा के कई नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

विशेष न्यायिक जांच आयोग ने शुरू की सुनवाई, ओजस्वी ने दर्ज कराया बयान

नईदुनिया, जगदलपुर

लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में नक्सल हमले में मारे गए तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी ने हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। श्यामगिरी नक्सल कांड की जांच कर रहे जस्टिस एसके अग्नहोत्री की अध्यक्षता में गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग की शनिवार को यहां कमिश्नर कार्यालय भवन में सुनवाई में ओजस्वी ने बयान दर्ज कराया।

जस्टिस एसके अग्निहोत्री ने उनसे जब यह पूछा कि उन्हें भीमा मंडावी की हत्या को लेकर किसी पर शंका है क्या? इस पर ओजस्वी ने किसी पर शंका जाहिर नहीं की लेकिन कहा राजनीतिक साजिश हो सकती है। जस्टिस ने पूछा क्या कभी भीमा मंडावी ने बताया था कि उन्हें जान का खतरा है? उनकी सुरक्षा में कमी थी क्या? आदि कई सवालों का जवाब देते ओजस्वी ने कहा कि सुरक्षा में कमी, जान का खतरा आदि के बारे में उन्होंने कभी चर्चा नहीं थी। प्रचार में निकलने के पहले बताया था कि वह गृहग्राम गदापाल जाने का मन बना रहे हैं पर बाद में वे गांव नहीं गए और प्रचार के लिए दूसरे क्षेत्रों में निकल गए। आयोग की पहली सुनवाई में ओजस्वी मंडावी के अलावा नंदलाल मुडामी, राकेश नाग, मनीष भट्टाचार्य, श्रवण कड़ती, धन्नूराम कोर्राम ने बयान दर्ज कराया। आयोग के सवालों का गवाहों ने जवाब दिया। इनमें अधिकांश का कहना था कि वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भीमा पार्टी के विधायक थे इसलिए अक्सर उनसे चर्चा होती रहती थी। वे सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे और क्षेत्र में सक्रिय रहकर काम करने वाले नेता थे। सुनवाई में आयोग के न्यायिक सचिव सुमीत कपूर, सचिव अरविंद एक्का और शासन पक्ष के अधिवक्ता रजनीश बघेल भी मौजूद थे।

27 करोड़ का नुकसान हुआ है रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा भूमि का पट्टा नया करने में देरी के चलते। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है।

काबू में आ रहा नागरिकता कानून विरोधी हिंसक आंदोलन

कार्रवाई ▶ इंटरनेट पर पाबंदी अगले दो दिन और बढ़ी, 85 अराजक तत्व गिरफ्तार, पूरे राज्य में गांधी के सत्याग्रह की तर्ज पर चलेगा आंदोलन

संजय मिश्र, गुवाहाटी

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आक्रोश में उबल रहा असम का हिंसक आंदोलन शनिवार को कुछ काबू में आता दिखाई दिया। बीते चार दिन से हिंसक हो चुके इस आंदोलन के चलते ठप गुवाहाटी शहर को शनिवार को जब कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू से छूट मिली तो हिंसा की कोई चिंताजनक घटना नहीं हुई। असम के दूसरे हिस्सों से भी विरोध की हिंसामुक्त रिपोर्ट आ रही हैं। हालांकि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) का आंदोलन अभी धीमा पड़ने के कोई संकेत नहीं हैं। आंदोलन को और हिंसक होने से रोकने के लिए असम में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी को अगले दो दिन और बढ़ा दिया गया है। असम पुलिस ने हिंसा और तोड़-फोड़ में शामिल करीब 85 अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया है।

गुवाहाटी के अलावा डिब्रूगढ़, जोरहाट, नयागांव और तिनसुकिया समेत कई दूसरे जिलों में हिंसा की घटनाएं थमी हैं। एहतियात के तौर पर गुवाहाटी में शनिवार को शाम चार बजे से कर्फ्यू फिर लागू हो गया। मगर इस दौरान सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती भी नजर आईं। शहर के कुछ चौराहों पर आवश्यक वस्तुओं की कुछ दुकानें भी खुली दिखीं। पुलिस कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने पर जोर देती हुई नहीं दिखी। नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन में अराजक तत्वों के हिंसा करने को लेकर पूछे जाने पर असम के डीजीपी ज्योति महंत ने 'दैनिक जागरण' को बताया कि ऐसे तत्वों की पहचान हो रही है और हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आंदोलन के वीडियो फुटेज से ऐसे तत्वों की पहचान की जा रही है।

नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आसू ने भी हिंसा की घटनाओं से अपना पल्ला झाड़ लिया है। आसू के चीफ एडवाइजर समुजल कुमार भट्टाचार्य ने साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन सुबह से लेकर शाम सात बजे तक ही होंगे। सूर्यास्त के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा और अंधेरे में आंदोलन के नाम पर कोई हिंसा करता है तो उससे आसू का कोई लेना देना नहीं है। आसू ने आंदोलन को हिंसा की बदनामी से बचाने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसक सत्याग्रह का स्वरूप देने का फैसला किया है। इसके तहत 16 दिसंबर से असम के सभी जिला मुख्यालयों में सड़कों पर लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। सत्याग्रह को वैचारिक मजबूती देने के लिए रविवार को गुवाहाटी में एक बड़े म्यूजिकल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय से लेकर सूबे के स्तर के कला और बौद्धिक जगत के लोग इकट्ठा होंगे और गीत संगीत के माध्यम से नागरिकता कानून में किए गए बदलाव को वापस लेने के लिए दिल्ली की सत्ता तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

मगर आंदोलनकारियों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ संगठित लंबी लड़ाई की ताल ठोककर राज्य प्रशासन की चिंता में और इजाफा किया है। हालांकि, अफरातफरी और हिंसा के साये में चार दिन के खौफ और परेशानी की झलक गुवाहाटी एयरपोर्ट से बाहर आते ही टैक्सी चालकों की बेचैनी से जाहिर हो जाती है। कई दिनों तक खाली बैठे टैक्सी चालक यात्रियों को अपनी टैक्सी में बिठाने के लिए आपस में ही भिड़ते नजर आए।

तो दूसरी ओर आंदोलन के जोखिम और परेशानी का सहारा लेते हुए दोगुना किराया भी वसूल रहे हैं। लेकिन हिंसक तत्वों की अराजकता को लोग गलत भी मान रहे हैं। निजी कंपनी में काम करने वाले गुवाहाटी के हाटीगांव इलाके से भास्कर शर्मा ने कहा कि आंदोलन से मुश्किल तो हो रही है मगर इस आंदोलन को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों के कारण ही आंदोलन को भय की नजर से देखा जा रहा है, जो सही नहीं है।

गुवाहाटी में शनिवार को कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोग सब्जी खरीदने बाजार पहुंच गए। एएनआइ

मोदी और शाह से मिलेंगे सोनोवाल

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ असम में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में एक टीम जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। असम के संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी ने बताया कि भाजपा विधायकों और सांसदों की बैठक में उक्त फैसला लिया गया।

चाय उत्पादन पर पड़ रहा असर

कोलकाता, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पूर्वोत्तर में हो रहे प्रदर्शन का असम में चाय उत्पादन पर असर पड़ने लगा है। राज्य के कई चाय बागानों में उत्पादन की प्रक्रिया बाधित हुई है। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र के जरिए होने वाली बिक्री भी घटी है। नार्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के सलाहकार विद्यानंद बरकाकोटी ने बताया-'यूं तो सर्दी चाय उत्पादन के लिहाज से व्यस्त मौसम नहीं है लेकिन विरोध-प्रदर्शन के कारण असम के विभिन्न बागानों में चाय की पत्तियों को तोड़ने के काम पर असर पड़ा है, जिससे चाय उत्पादन घटा है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार दिसंबर में मौसम अनुकूल रहा और उत्पादक बेहतर गुणवत्ता वाली चाय की पैदावार करने में सफल रहे लेकिन विरोध-प्रदर्शन के कारण इसकी प्रोसेसिंग पर असर पड़ रहा है।'

ऑल असम स्माल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन के महासचिव करुणा महंता ने कहा-'गत मंगलवार को चाय बागान बंद रहे, वहीं शुक्रवार को चाय की पत्तियां तोड़ने का काम तो हुआ लेकिन पूरी क्षमता पर नहीं। गाड़ियां नहीं चलने के कारण बहुत से श्रमिक काम पर नहीं पहुंच सके।' इस बीच चाय श्रमिकों की अनुपलब्धता को देखते हुए टी बोर्ड ने चाय की पत्तियां तोड़ने की अवधि 19 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

शरणार्थियों को पक्की नागरिकता देगी सरकार : राजनाथ

जासं, पाकुड़ : कांग्रेस के शासनकाल में देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने इस्लामिक देश घोषित कर रखा है। इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग अगर भारत में शरण लेते हैं तो प्रावधान के तहत सरकार उसे पक्की नागरिकता देगी। यह बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वह शनिवार को पाकुड़ के हरिणडांगा उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने नागरिकता संशोधन बिल और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को यह भी पता नहीं कि उसे किस बात का विरोध करना चाहिए और किस बात का समर्थन। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए राजनीति करती है। आगे कहा, भाजपा के अपने शासनकाल में किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। भाजपा शासन में ही कई भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान को भी नसीहत देते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश आतंक का सहारा लेकर भारत को तोड़ना चाहता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो भारत को तोड़ सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड विकास के मामले में आगे बढ़ा है। देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड व्यापार के मामले में सातवें पायदान पर पहुंच चुका है। खिचड़ी की सरकार बनने से रोकें और भाजपा की मजबूत और डबल इंजन की सरकार बनाएं।

एएमयू में गूंजे सावरकर और हिंदुत्व के खिलाफ नारे, मामला दर्ज

जासं, अलीगढ़ : एएमयू में जब से नागरिकता संशोधन बिल कानून का विरोध शुरू हुआ है, भाजपा और हिंदुत्व ही निशाने पर है। गुरुवार को बॉबे सैयद पर हुए प्रदर्शन में सावरकर, हिंदुत्व, भाजपा व जातिवाद की कब्र खोदने के नारे लगाए गए थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपितों की पहचान की जा रही है।

एएमयू में सबसे पहले बुधवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया था। उस दिन भी हिंदुत्व विरोधी नारे लगाए गए। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान मोदी-शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। गुरुवार को हुए प्रदर्शन में स्वराज पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव व गोरखपुर के डॉ. कफील खान शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने 'सावरकर, हिंदुत्व, बीजेपी व जातिवाद की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर' जैसे नारे लगाए। जेएनयू की तर्ज पर ढपली की धुन पर लगाए गए इन नारों का 19 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पूर्वोत्तर की यात्रा करने पर कई देशों ने दी नागरिकों को हिदायत

वॉशिंगटन, एजेंसियां : अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को पूर्वोत्तर भारत में यात्रा करते समय सावधान रहने के लिए कहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में इस समय चल रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए इन देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा एडवायजरी जारी की है। इससे पहले ब्रिटेन, इजरायल और फ्रांस अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही एडवायजरी जारी कर चुका है। अमेरिकी सरकार ने प्रदर्शन के मुख्य केंद्र असम के लिए आधिकारिक यात्राएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है।

यात्रा परामर्श में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को नागरिकता संशोधन कानून के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के चलते सावधान रहना चाहिए। कुछ इलाकों में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट और मोबाइल सेवा को भी बाधित किया जा सकता है। कई इलाकों में परिवहन पर इन प्रदर्शनों का असर पड़ सकता है। अमेरिकी दूतावास ने पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सावधानियों को सूचीबद्ध किया है। उनसे प्रदर्शनों एवं जन अशांति वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा है।

अमेरिका ने फिर छेड़ा नागरिकता कानून का राग

वॉशिंगटन, प्रेट्र : एक शीर्ष अमेरिकी राजयनयिक ने कहा है कि उनका देश भारत के नागरिकता संशोधन कानून के प्रभाव को लेकर चिंतित है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के राजदूत सैम ब्राउनबैक ने ट्वीट किया कि भारत की बड़ी ताकतों में एक उसका संविधान है। हम भारत की संस्थाओं का आदर करते हैं। लेकिन, नागरिकता संशोधन कानून के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। ब्राउनबैक ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टू प्लस टू वार्ता के लिए अगले सप्ताह ही वॉशिंगटन जाने वाले हैं।

धनखड़ ने बंगाल में हिंसा पर जताई चिंता

जासं, कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य भर में जारी हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में घट रही घटनाओं से व्यथित हूं। शपथ के अनुसार मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के प्रति विश्वास व सच्ची निष्ठा रखनी होगी।

मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा, मैं राज्यपाल के रूप में संविधान व कानून की रक्षा और बचाव की अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करूंगा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रदर्शन रोकने की विनती की और कहा कि ऐसा न करें। शांतिपूर्ण तरीके से भी बातें रखी जा सकती हैं। राज्यपाल की टिप्पणी पर बिफरीं मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहले स्वयं राज्यपाल अपने दायित्व को समझ लें। भाजपा ने कहा है कि बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का हाथ है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे।

प्रशांत किशोर ने किया दावा, एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं नीतीश कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना

जदयू में विवाद

- नागरिकता संशोधन कानून पर पार्टी से अलग राय रखने वाले पीके मुख्यमंत्री से मिले
- जदयू ने दोनों सदनों में किया था – नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन

नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग बयान देने वाले प्रशांत किशोर (पीके) ने शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और का नोटिस नहीं लेते हैं। उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री से कह दी है। उन्हें जो भी निर्णय लेना होगा, लेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर उन्हें जो कहना था, वह मैं खुल के कह चुका हूं और अपने स्टैंड पर कायम हूं। इसमें संशोधन का सवाल नहीं उठता।

इस्तीफा किया नामंजूर : पीके की सीएम से मुलाकात पहले से तय थी। इसीलिए दिल्ली से पटना आकर सीधे वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। पीके ने यह भी स्वीकार किया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश की थी, जिसे नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि आप जदयू में हैं और बने रहेंगे। पीके ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री भी एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून अगर एक साथ लागू होता है तो यह खतरनाक होगा। हालांकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पार्टी का पक्ष रखेंगे।

पार्टी लाइन से अलग दिया था बयान : उल्लेखनीय है कि पीके नागरिकता कानून के खिलाफ हैं, जबकि जदयू ने संसद के दोनों सदनों में इसका समर्थन किया है। इसी मुद्दे पर हफ्ते भर से जदयू में बयानबाजी जारी है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने खरी-खोटी भी सुना दी थी। अपने बारे में आरसीपी सिंह के बयान की याद दिलाने पर प्रशांत ने कहा कि आरसीपी बड़े नेता हैं। मुझपर जिसे जो आरोप लगाना है, लगाए। मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, सबका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी पूरी बात नीतीश कुमार के सामने रख दी है। उन्होंने कहा है कि यह सब मुझपर छोड़ दीजिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कुछ कह सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पीके ने जदयू के फैसले का खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने भी तेवर तल्ख कर लिए थे। आरसीपी ने यहां तक कह दिया था कि जिसे पार्टी का फैसला मंजूर नहीं वह बाहर का रास्ता देख सकता है।

फिसले, लड़खड़ाए और संभल गए मोदी

- ऊंची सीढ़ी से पांव टकराने के बाद अटल घाट पर हुई घटना
- कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश, कहा-सीढ़ी की ऊंचाई कम कराई जाएगी
- उसी सीढ़ी पर संभलकर चलने की चेतावनी भी लिखी थी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार को गंगा का जायजा लेकर लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अटल घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी एक सीढ़ी में पैर फंसने से उनका संतुलन बिगड़ गया। वीडियो ग्रैब

जागरण संवाददाता, कानपुर

कानपुर में गंगा का जायजा लेकर मोटरबोट से लौटे पीएम जब अटल घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक ऊंची सीढ़ी में पांव टकराने से उनका संतुलन बिगड़ गया। वह फौरन खड़े हुए और बगैर शिकन लाए लोगों का अभिवादन करते हुए कार की ओर बढ़ गए। इस बीच, पीछे चल रहे एसपीजी के जवानों ने उन्हें संभाला। गनीमत रही कि पीएम को कोई चोट नहीं आई। पीएम जहां फिसले, उस सीढ़ी पर संभलकर चलने की चेतावनी लिखी थी। घटना को लेकर कमिश्नर सुधीर एम बोबडे ने जांच का आदेश दिया है। बकौल कमिश्नर, एसपीजी को रात में ही बता दिया गया था कि अटल घाट पर एक सीढ़ी ज्यादा ऊंची है। एसपीजी ने पीएम को भी अवगत करा दिया था। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्माण एजेंसी से इसकी जांच कराई जाएगी और सीढ़ी की ऊंचाई भी कम कराई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रस्तुत की कार्यों की रिपोर्ट

प्रथम पृष्ठ का शेष

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्य में नमामि गंगे के तहत हुए कार्यों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि इस योजना में गंगा किनारे के 25 जिलों सहित 27 जिलों में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 102 करोड़ रुपये की वनीकरण परियोजनाएं चल रही हैं। 10341 करोड़ रुपये में 1292 करोड़ रुपये की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन और प्रक्रिया में हैं।

बंगाल और झारखंड का नहीं हुआ प्रतिनिधित्व

21 सदस्यीय परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आईं। वहीं विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के चलते झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवरदास भी नहीं पहुंचे। इसके साथ ही इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी नहीं आ सकीं।

निर्मल गंगा की 'प्रतिमा' देख मुग्ध हुए 'संगतराश' मोदी

जागरण संवाददाता, कानपुर

एक अनगढ़ पत्थर को खूबसूरत प्रतिमा का आकार देने में एक मूर्तिकार (संगतराश) बहुत मेहनत करता है, पसीना बहाता है। जब प्रतिमा साकार होती है, लोग उसे बखानते हैं तो उसका हृदय गदगद हो जाता है। कानपुर में गंगा की लहरों पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर संतोष के भाव उनके हृदय की यही खुशी बयान कर रहे थे, क्योंकि गंगा के उद्गम स्थल के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कानपुर में गंगा की निर्मलता की तारीफ कर रहे थे। यह खुशी तब और बढ़ती नजर आई, जब प्रधानमंत्री के जाने के बाद जनता वहां पहुंची और कहा, अभी तक ऐसी गंगा न देखी न सुनी।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में राष्ट्रीय गंगा परिषद की मैराथन बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी अटल घाट पर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी थे। घाट से कलकल बहती गंगा अपनी निर्मलता के प्रयासों को मुहरबंद कर रही थीं। मां गंगा का अभिवादन कर मोदी ने प्रयागराज से आई बोट पर यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें घाटों के बारे में जानकारी देते जा रहे थे। सभी ने कानपुर में गंगा के इस रूप को सराहा। सीसामऊ नाला जब करीब आया तो मुख्यमंत्री ने इशारा कर बताया कि यही वह 128 साल पुराना ऐतिहासिक नाला है, जिसे बंद कराने से ही निर्मल गंगा की राह आसान हुई है। प्रधानमंत्री पहले ही इस नाले के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। बोट किनारे लगी तो सबसे पहले पीएम यहां उतरे, फिर बाकी लोग। पीएम ने पहले इस नाले के पास खड़े होकर अकेले एक तस्वीर खिंचवाई। फिर सभी को इस नाले की जानकारी दी। यहां से बोट वापस अटल घाट के लिए रवाना हुई। रास्ते में मैगजीन घाट समेत कई जगह किनारे बंधे पर खड़े युवाओं ने मोदी-मोदी का जयघोष किया तो प्रधानमंत्री की नजरें बरबस उधर चली गईं। उन्होंने हाथ हिलाकर इनका अभिवादन किया। अटल घाट पर उतरने के बाद जब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठने लगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाया तो उनके चेहरे पर तसल्ली के भाव थे।

हनी ट्रैप मामले में फरार जीतू के भाई और भतीजे की फैक्ट्री ध्वस्त

इंदौर में फैक्ट्री को ढहाती निगम की टीम। राजू पवार

नईदुनिया, इंदौर

इंदौर में हनी ट्रैप से जुड़े मामले में फरार अखबार संचालक जीतू (जितेंद्र) सोनी के भाई महेंद्र सोनी और भतीजे जिग्नेश सोनी की फैक्ट्री को ढहा दिया गया। उद्योग विभाग और नगर निगम की जांच में फैक्ट्री में अवैध निर्माण बताया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत की गई। मालूम हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे।

हनी ट्रैप मामले में शनिवार को जिला कोर्ट में फरियादी और नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह के धारा 164 में बयान हुए। सिंह ने बंद कोर्ट में आपबीती सुनाई। करीब एक घंटे तक वह बताता रहा कि कैसे आरोपितों ने उसे ब्लैकमेल कर परेशान किया। इस मामले में पुलिस सोमवार को आरोपितों के खिलाफ चालान पेश करेगी।

मालूम हो, हरभजन ने 17 सितंबर को पलासिया थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि दो महिलाएं उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरती सिंह, मोनिका यादव, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, बरखा भटनागर और ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया था।

बर्फबारी रुकी, अब हिमस्खलन की चेतावनी

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत के तीनों पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तीन दिन से जारी बारिश और बर्फबारी के मौसम में शनिवार को सुधार हुआ। इसके बावजूद तीनों ही राज्यों के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान हिमस्खलन और बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी गई है कि मौसम के पूरी तरह से साफ होने तक घरों से बाहर न निकलें। इसके साथ ही उन्हें घरों की छतों पर बर्फ को जमा न होने देने को कहा है।

कश्मीर में नौवें दिन शुरू हुई हवाई सेवा : मौसम में सुधार होने और धुंध हटने के बाद नौवें दिन श्रीनगर एयरपोर्ट से हवाई सेवा भी शुरू हो गई। इससे कश्मीर में फंसे यात्रियों को राहत मिल गई है। वहीं, बर्फबारी के कारण आंशिक तौर पर प्रभावित हुई बनिहाल-बारामूला रेल सेवा भी सुचारू कर दी गई। इसके अलावा सभी मार्गों को बहाल करने का काम किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को छराबड़ा के समीप भारी बर्फबारी के कारण लंबे यातायात जाम में फंसे पर्यटक। जागरण

हिमाचल में ठंड से एक की मौत : हिमाचल में मौसम के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 15 और 16 दिसंबर को किन्नौर, कुल्लू व लाहुल स्पीति जिलों के कई क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। चंबा में एक व्यक्ति की मौत ठंड से होने की आशंका है। मृतक की पहचान चंबा के मोहल्ला लोअर जुलाहकड़ी निवासी 75 वर्षीय मलकीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं, प्रदेश में 431 सड़कें बंद रहीं, जहां करीब 54 बसें फंसी हैं।

- नौ दिन बाद श्रीनगर से हवाई उड़ानें शुरू, जम्मू-श्रीनगर, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद
- लोगों को घरों की छतों पर बर्फ न जमने देने और बाहर न निकलने की सलाह

उत्तराखंड में बर्फबारी से 300 गांव कटे, 80 संपर्क मार्ग भी बंद

उत्तराखंड में गुरुवार से जारी बारिश और बर्फबारी का दौर शनिवार सुबह थम गया, लेकिन दुश्वारियों का सिलसिला जारी है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 300 से ज्यादा गांव अलग-थलग पड़ गए हैं और 440 गांवों में बिजली आपूर्ति अभी तक ठप है। भारी बर्फबारी के बाद बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पिथौरागढ़ हाईवे के अलावा 80 से अधिक संपर्क मार्ग भी बंद हैं। वहीं, बर्फबारी का लुत्फ उठाने हर्षिल पहुंचे 25 पर्यटक गंगोत्री हाईवे बंद होने के कारण फंस गए हैं।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोष के लिए वेतन से कटौती पर बिफरे कर्मचारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

गलती भी मानी

- कार्मिकों के वेतन से प्रतिमाह 500 रुपये कटौती के आदेश पर हंगामा
- विरोध पर बस्ती के जिलाधिकारी ने वापस लिया आदेश

मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 500 रुपये कटौती करने के आदेश पर राज्य कर्मचारियों में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के आधार पर बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने भी अधीनस्थों को पत्र जारी कर दिया, लेकिन कर्मचारियों ने जब विरोध की चेतावनी दी तो शनिवार शाम तक डीएम ने संबंधित आदेश वापस लेकर गलती भी मान ली।

मामले पर बवाल डीएम बस्ती के 11 दिसंबर के उस पत्र से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के चार दिसंबर के पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के लिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के वेतन से पांच सौ रुपये की कटौती कर लखनऊ की एक बैंक में रकम जमा कराने की अपेक्षा अधीनस्थ अधिकारियों से जताई थी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि वाराणसी और चंदौली सहित कई अन्य जगहों से भी उन्हें शासन द्वारा ऐसा पत्र भेजे जाने की जानकारी मिली है। परिषद ने शनिवार को प्रदेशभर में संपर्क करने के बाद दोपहर में आपात बैठक बुलाई और इसे तुगलकी फरमान ठहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आदेश वापस लेने की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने इस कटौती से सरकार के पास हर महीने करीब 200 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान लगाया है।

राज्य कर्मचारियों द्वारा विरोध की चेतावनी के बाद बस्ती के जिलाधिकारी का एक और पत्र शनिवार शाम तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्होंने 500 रुपये की कटौती के आदेश को लिपिकीय त्रुटि ठहराते हुए आदेश वापस ले लिया। हालांकि इस पत्र में भी जिलाधिकारी ने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी स्वेच्छा से इसमें सहभागिता करना चाहते हों, वे अंशदान कर सकते हैं। निरंजन ने विभागीय कर्मियों से इस कोष की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने के प्रयास करने का भी आग्रह किया है। दूसरी तरफ संयुक्त परिषद ने दावा किया कि विरोध की चेतावनी के बस्ती डीएम ने बैकफुट पर आकर आदेश वापस लिया है। परिषद ने अब इस मामले को सोमवार को शासन स्तर पर ले जाने की तैयारी की है।

5117 स्कूल भवन बांस से बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। भूकंप जोन-चार में 528, जोन-पांच में 4513 स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। बांस से निर्मित एक भवन की लागत करीब 16.43 लाख आंकी जा रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 15 दिसंबर 2019

विचारों की धरती पर पनपा सार्थक संवाद

भारतेंदु नाट्य अकादमी में जागरण संवादी का दूसरा दिन, गहन चर्चाओं के बीच हर सत्र में लोकतंत्र, मुंबई से आए दोस्त ने सजाई शाम

दुर्गा शर्मा, लखनऊ

शनिवार को भारतेंदु नाट्य अकादमी में संवादी के दूसरे दिन दलित साहित्य का भविष्य विषय पर विचार रखते (बाएं से) विवेक कुमार, श्योराज सिंह बेचैन व भगवानदास मोरवाल। जागरण

सैंया मिले लरकइयां... गुनगुनाते श्रोता मालिनी अवस्थी का सुरमयी सत्र जेहन में लिए जब शनिवार को संवादी की दहलीज पर पहुंचे तो कुछ गंभीर विषय सामने थे। दलित साहित्य पर चिंतन के बाद धर्म की भाषा का मर्म समझना था। साहित्य के स्वर्ण युग से रूबरू होने के साथ ही उपन्यासकाल को भी टटोलना था। श्रोताओं ने संघ के भविष्य में भी झांका। वार्तालाप की खूबसूरती इसी में रही कि हर सत्र में 'लोकतंत्र' मौजूद रहा। चाहे दलित साहित्य के फलने से प्रजातंत्र के मजबूत होने की बात हो या धर्म की भाषा को लोक की भाषा मानने पर सहमति। वहीं, लेखनी के बढ़े दायरे और मंच को साहित्य का लोकतंत्रात्मक स्वरूप कहा गया।

अंकुरण के बाद जागरण संवादी का दूसरा दिन विचारों की धरती पर सार्थक संवाद के पनपने का अवसर था। यही वजह रही कि शुक्रवार से अभिव्यक्ति के सतरंगी उत्सव से साक्षात्कार कर रहे लोग उतने ही उत्साह और ऊर्जा के साथ पहुंचे। मंच ने जिज्ञासाओं को शांत किया तो दर्शक दीर्घा ने भी ज्वलंत मुद्दों पर सटीक और सुस्पष्ट राय रखी। संवादी की सफलता संवाद की सार्थकता में खिलखिलाती दिखी।

हॉल में धीरे-धीरे बढ़ रहे श्रोताओं के बीच शुरू दलित साहित्य का भविष्य सत्र विचारों के कुहासे को छांट गया। सार रहा कि दलित साहित्य का भविष्य उज्वल है। यह अहसास का साहित्य है, जो हमेशा बढ़ता जाएगा। अगले सत्र ने सवाल किया कि क्या धर्म की कोई भाषा होती है या होनी चाहिए? धर्म निरपेक्षता और संविधान भी कठघरे में थे। मंथन, विमर्श, सहमति-असहमति के बीच निष्कर्ष यह निकला कि धर्म की भाषा वही होनी चाहिए जिसका मर्म इंसानियत हो। धर्म की भाषा होती है पर परिस्थिति के अनुसार। जैसे अरबी कुरआन की शक्ल में और श्लोक संस्कृत के रूप में धर्म की भाषा है। एक संवेदनशील और गहमागहमी से भरे सत्र ने अब साहित्यिक रूप अख्तियार कर लिया। युवा कलम को अनुभव ने नसीहत दी कि कला और साहित्य की दुनिया मार्केटिंग से नहीं चलनी चाहिए। वरिष्ठों का सवाल था कि ये कैसा मंच है, जहां लेखन नहीं, लेखक जगमगा रहा है। वहीं, युवा लेखनी ने उलाहना दिया कि वरिष्ठ बिना पढ़े ही हमें खारिज कर रहे हैं, उन्हें अपनी भूमिका से न्याय करना चाहिए। चौथे सत्र ने उपन्यास के पन्ने खोले। वहीं, संघ का चेहरा बनकर आए सुनील आंबेकर की बात में भी संवाद की अहमियत साफ दिखी। उन्होंने कहा 21वीं सदी में भी संघ अपने मूल जीवन मूल्यों को लेकर चल रहा है। हम समाज के साथ न कल संवादहीन थे न आज हैं। ढलती शाम हजलगोई की खत्म होती रवायत से राब्ता करा गई तो 'मुंबई से आया दोस्त' श्रोताओं को अगले दिन भी संवादी में शामिल होने का न्योता दे गया।

अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उठाए सवाल

विकास शर्मा, चंडीगढ़

अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ बालाकोट पैनल में हिस्सा लेने आईं अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ क्रिस्टीन फेयर ने रिटायर्ड चीफ एयर मार्शल बीएस धनोआ के सामने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना मिग-21 से एफ-16 को गिराने की बात कह रही है, यह बात हजम होने के लायक नहीं है। एफ-16 की रफ्तार मिग-21 से कई गुना ज्यादा है, इसके अलावा एफ-16 गिराने के बाबत भारत जो सुबूत दे रहा है, वे पुख्ता नहीं हैं। अमेरिका की अलग-अलग एजेंसियों ने अपने स्तर पर जांच की लेकिन इस बाबत कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली।

मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत कर रहीं क्रिस्टीन फेयर के इस विवादित बयान से पहले रिटायर्ड एयर मार्शल बीएस धनोआ और विंग कमांडर समीर जोशी ने स्पेशल डिस्प्ले के साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक होने के तमाम तरह के सुबूत दिए। गौरतलब है कि गत 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज लड़ाकू विमानों से बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर वहां स्थित आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। इसी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपना एफ-16 विमान भारतीय सीमा में घुसा दिया था, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 से गिरा दिया था।

अगले बालाकोट के लिए तैयार है एयरफोर्स: विंग कमांडर समीर जोशी ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हमने अपनी तैयारियों को कई स्तर पर सुधारा है। अब हमारे हरेक एयरफोर्स स्टेशन से ऐसी स्ट्राइक हो सकती है। एयरफोर्स के रणनीतिकार हर स्तर पर लगातार सुधार कर रहे हैं, अगली बार एयर स्ट्राइक होगी तो हम कोशिश करेंगे कि पुख्ता सुबूत भी लाएं।

अभी इंटर लिंक्ड नहीं हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट: रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी ने बताया कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट अभी तक इंटर लिंक्ड नहीं हैं जबकि पाकिस्तान ने 10 से 15 साल पहले अपने फाइटर जेट को इंटर लिंक्ड कर दिया था। भारतीय सेना तभी अपनी तैयारियां करती है जब युद्ध छिड़ जाता है। आज देश की सीमाओं को कई मोर्चों पर एक साथ तैयारी करनी होगी। हमें जमीन पर, आकाश में, पानी में, साइबर युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की एकसाथ तैयारियां करनी होंगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना ने अपना बजट बढ़ाया है, उसके सैन्य अधिकारी हथियारों के लिए दुनियाभर में लॉबिंग कर रहे हैं।

सावरकर ने दी थी टू नेशन थ्योरी : मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हम भारतीय बहुत व्यस्त हैं। हमारे पास समय नहीं कि इतिहास की पुरानी किताबों में जाकर भारत की आजादी के बारे में जानें। इसका फायदा उठाते हैं नेता, जो कुछ भी बोलते हैं। इन नेताओं का गलत इतिहास देश का वर्तमान खराब कर रहा है। चर्चा में आरएसएस के देश रत्न निगम, सांसद महुआ मोइत्रा और सर मार्क टुली भी शामिल हुए।

पीएसए के तहत मार्च तक टली फारूक अब्दुल्ला की रिहाई

सख्त रुख ▶ नेकां अध्यक्ष पर लगाए गए पीएसए की अवधि तीन माह बढ़ी

इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई अधिकतम दो साल तक रखा जा सकता है बंदी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

फारूक अब्दुल्ला। फाइल

अपने ही घर में कैद हैं फारूक

82 वर्षीय डॉ. फारूक अब्दुल्ला बीमार हैं। उन्हें गुपकार स्थित उनके घर में ही कैद किया गया है। गृह विभाग ने उनके घर को एक उप जेल का दर्जा दे रखा है। डॉ. फारूक अब्दुल्ला के पुत्र और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी चार अगस्त को ही प्रशासन ने एहतियातन हिरासत में लिया था। उमर अपने पिता से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर हरि निवास में बंद हैं।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर के सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला की नए साल पर रिहाई की उम्मीद फिलहाल टल गई है। सामान्य परिस्थिति में अब वह अगले तीन महीने तक रिहा नहीं होंगे। क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत उनकी कैद को एक बार फिर तीन माह के लिए और बढ़ा दिया है।

जन सुरक्षा अधिनियम 1978 को डॉ. फारूक के पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही लागू किया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई अधिकतम दो साल तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है।

तीन बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके डॉ. फारूक अब्दुल्ला को पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने से एक दिन पहले प्रशासन ने एहतियातन उनके घर में नजरबंद कर दिया था। इसके बाद राज्य प्रशासन ने उन्हें शांति और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए 15 सितंबर को पीएसए के तहत बंदी बनाया था।

डॉ. फारूक अब्दुल्ला को शुरू में 12 दिन के लिए पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। इसके बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान उन पर पीएसए की अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया था। सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व जज जनक राज कोतवाल की अध्यक्षता वाले पीएसए समीक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर गृह विभाग ने उनकी पीएसए की अवधि को एक बार फिर तीन माह के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है।

पंजाब से नाना-नानी ने बनवाया था जाति प्रमाण पत्र : जजपाल

नईदुनिया, भोपाल: बार-बार जाति बदलकर चुनाव लड़ने वाले मध्य प्रदेश के अशोक नगर से कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी राज्यस्तरीय छानबीन समिति के समक्ष पेश हुए। समिति के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव विनोद कुमार ने सवाल किया कि जब आपके पास पंजाब से बना कीर जाति (अनुसूचित जाति) का प्रमाण पत्र था तो फिर नया प्रमाण पत्र नट जाति का क्यों बनवाया। जवाब में जज्जी ने कहा कि उसके नाना-नानी ने यह प्रमाण पत्र पंजाब से बनवाया था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बाद में मैंने मध्य प्रदेश से नट जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया।

मौखिक सवालों के जवाब में जज्जी ने कहा कि ओबीसी (अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग) की छानबीन समिति ने मुझे नट जाति का माना है। बताया जा रहा है कि छानबीन समिति के समक्ष तीसरी बार सुनवाई के बाद साक्ष्य और सवाल-जवाब का काम पूरा हो गया है। अब छानबीन समिति का निर्णय कभी भी आ सकता है। इससे पहले 2013 में छानबीन समिति ने जज्जी के प्रमाण पत्र को अमान्य करते हुए फर्जी करार दिया था।

जज्जी ने छानबीन समिति के समक्ष कहा कि मेरे पूर्वज पंजाब से आए थे और यहां रस्सी से करतब दिखाया करते थे। उन्होंने अपने खिलाफ शिकायतों को राजनीतिक रंजिश बताया।

कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया

जेएनएन, बारामुला

जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिला मुख्यालय से सटे जंगल में सुरक्षा बलों ने एक ऐसे आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें तीन से चार आतंकी छिप सकते थे। आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बलों को राशन और अन्य सामान मिला है। हालांकि आतंकी वहां से भाग निकले थे। वहीं, कोई हथियार भी नहीं मिला है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि सर्च ऑपरेशन की भनक लगते ही आतंकी भाग गए होंगे।

दरअसल, पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से पता चला था कि बारामुला के साथ सटे यनकरा जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं जो किसी बड़े हमले की तैयारी में हैं। इसके बाद पुलिस ने सेना की 46 आरआर और सीआरपीएफ की 53वीं वाहिनी के जवानों के साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नाले के पास बने आतंकी ठिकाने का पता लगा लिया। ठिकाने में आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद तीन जवान पूरे एहतियात के साथ ठिकाने में घुसे और अन्य बाहर खड़े रहे। ठिकाने के भीतर कोई आतंकी नहीं था। अलबत्ता, वहां कंबल और गैस सिलेंडर के अलावा भारी मात्रा में राशन व दवाएं थी। जवानों ने सामान को कब्जे में लेकर ठिकाने को नष्ट कर दिया।

बीएसएफ ने सीमा पर पकड़ी पाकिस्तानी नाव

जासं, अजनाला (अमृतसर): भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शनिवार तड़के रावी नदी में पाकिस्तान की तरफ से बहकर आ रही नाव पकड़ी है। इसमें कोई सवार नहीं था। आपत्तिजनक वस्तु भी नहीं मिली है। बीएसएफ जवान अंतरराष्ट्रीय सीमा की अजनाला की बीओपी (बार्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट) पंजगराइयां के पास शनिवार सुबह गश्त कर रहे थे। घने कोहरे के बीच करीब साढ़े छह बजे रावी नदी में पाकिस्तान की तरफ से एक नाव आती हुई दिखी। उस पर कोई सवार नहीं था। जवानों ने नाव को अपने कब्जे में ले लिया। नाव पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, जिसके बारे में जांच की जा रही है। अनुमान है कि उर्दू में नशा तस्करों के लिए कोई संदेश लिखा गया है।

उप्र में 500 शिक्षकों का जेल जाना तय

जासं, वाराणसी: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री पर परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन कर रहे करीब 500 शिक्षकों की उपाधि फर्जी होने का संदेह है। सूबे के विभिन्न जिलों के सत्यापन में अब तक चार सौ से अधिक अंकपत्र जाली मिले हैं। सत्यापन पूरा होते ही विश्वविद्यालय एसआइटी को रिपोर्ट सौंप देगा। वहीं एसआइटी ने फर्जीवाड़ा करने वाले अध्यापकों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों में हेराफेरी की जांच एसआइटी कर रही है। इसके तहत एसआइटी 65 जिलों में चयनित अध्यापकों के अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों का दोबारा सत्यापन करा रही है। विश्वविद्यालय 65 में से 42 जिलों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर चुकी है। अंकपत्रों के सत्यापन में लगभग चार सौ अध्यापकों के अंकपत्र जाली मिल चुके हैं। 23 जिलों के अध्यापकों के अंकपत्र व प्रमाणपत्रों का सत्यापन लंबित है। एसआइटी लंबित अंकपत्रों का सत्यापन इसी माह में पूरा करने का दबाव बनाए हुए है। बहरहाल एसआइटी के निर्देश पर विश्वविद्यालय अंकपत्रों का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास में है।

फोटो स्टेट सौंपने की तैयारी: एसआइटी ने 2004 से 2014 तक बीएड का टेबुलेशन रजिस्टर (टीआर) की फोटो काफी मांगी है। इसके अलावा कंप्यूटर में दर्ज रिकार्ड भी मांगे गए हैं।

ग्वालियर में बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गोशाला में दान करने होंगे 10 कंबल

नईदुनिया, ग्वालियर

- गायों को सर्दी से बचाने के लिए कलेक्टर ने दिए आदेश
- गोसेवकों एवं समाजसेवियों के साथ की थी बैठक

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल में बंदूक रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाना है। इसी चाहत को प्रशासन सेवाभाव की ओर ले जाने में लगा है। बंदूक (शस्त्र) के लाइसेंस के लिए पहले 10 पौधे लगाने की शर्त रखी थी। अब दूसरी शर्त गोशाला में 10 कंबल दान करने की है। यह आदेश ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शनिवार सुबह गोसेवकों एवं समाजसेवियों के साथ हुई बैठक में दिया।

मालूम हो, पिछले दिनों ग्वालियर में नगर निगम द्वारा संचालित मुकेश अग्रवाल रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल (मार्क) गोशाला में सर्दी से दो दिन में 14 गायों की मौत हो गई थी। इसके बाद कलेक्टर ने गायों को सर्दी से बचाने के लिए तीन लाख रुपये और अन्य समाजसेवियों से प्राप्त दो लाख रुपये के तिरपाल दान दिए गए थे। इसके बावजूद दो गोशालाओं में रहने वाली 9000 गायों को सर्दी से बचाने के इंतजाम पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसके चलते कलेक्टर ने आदर्श गोशाला में शनिवार सुबह गोसेवकों एवं समाजसेवियों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी से गायों को सर्दी से बचाने के सुझाव मांगे गए। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश दिया कि शनिवार से जो भी शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करेगा, उसे 10 कंबल दान करने होंगे।

लाइसेंसी हथियार रखने की है चाहत : ग्वालियर-चंबल संभाग में लाइसेंसी हथियार रखने का लोगों को बहुत शौक है। इससे ग्वालियर जिला भी अछूता नहीं है। वर्तमान में ग्वालियर जिले में 28500 शस्त्र लाइसेंस हैं। इसके बाद भी हर माह लगभग सौ आवेदन शस्त्र लाइसेंस के लिए आते हैं।

मध्य प्रदेश में दांत के डॉक्टरों को पीएचसी में तैनात करने की तैयारी

नईदुनिया, भोपाल

- डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार बना रही योजना
- छह माह के ब्रिज कोर्स के बाद की जाएगी तैनाती

प्रतीकात्मक

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के एलोपैथिक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। बिना डॉक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में दांत के डॉक्टर (डेंटिस्ट) को पदस्थ करने का प्रस्ताव है। नियुक्ति के पहले उन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। इसमें उन्हें कई बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, निमोनिया आदि के लक्षण, जांच व दवाओं के बारे में बताया जाएगा। पदस्थापना का निर्णय कैबिनेट से होने के बाद ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।

प्रदेश में 1199 पीएचसी में से 371 में डॉक्टर पदस्थ नहीं हैं। बाकी कर्मचारी व संसाधन होने के बाद भी डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। पीएचसी में डॉक्टर नहीं होने से सबसे बड़ा नुकसान आपातस्थिति के मरीजों को हो रहा है। तत्काल इलाज नहीं मिलने से उनकी हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर के पदस्थ होने पर उनका प्राथमिक इलाज कर जरूरत पर बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने पीएचसी में दांत के डॉक्टरों को पदस्थ किया है। कुछ जगह आयुष डॉक्टरों की पदस्थापना की गई है।

डेंटिस्ट और आयुष डॉक्टर सालों से पीएचसी में पदस्थापना की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान समेत कई विषय पाठ्यक्रम में एक से हैं। दवाइयों की पढ़ाई अलग-अलग हैं। आयुष या डेंटिस्ट डॉक्टरों की पीएचसी व सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) में पदस्थापना के लिए 2013 में तत्कालीन सरकार ने तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भी ब्रिज कोर्स के बाद आयुष या डेंटिस्टों को पीएचसी-सीएचसी में पदस्थ करने की सिफारिश की थी। हालांकि, इस पर अमल नहीं हो पाया था।

> प्रदेश में डॉक्टरों की लगातार भर्ती की जा रही है। कोई अस्पताल बिना डॉक्टर न रहे इसलिए दांत के डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स के बाद पीएचसी में नियुक्त करने का विचार है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
> -तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश

प्रदेश में डॉक्टरों की स्थिति

पदनाम	स्वीकृत	पदस्थ
विशेषज्ञ	3620	882
चिकित्सा अधिकारी	5097	3631

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दो बच्चियों को दी 'आवाज'

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- कश्मीर की दो मूक-बधिर बच्चियों का मुफ्त इलाज, दोनों बच्चियों के माता-पिता हैं खुश

आर्थिक रूप से कमजोर और मूक-बधिर कश्मीर की दो बच्चियों को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नई जिंदगी दी है। दोनों का श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निःशुल्क इलाज हुआ। श्रीनगर के खनयार और बेमिना की दोनों बच्चियों इकरा और सायरा को बचपन से न सुनाई देता था और न वे बोल पाती थीं। एक बच्ची के इलाज पर आठ से 10 लाख खर्च आया है।

इकरा की मां गुलशन ने बताया कि बेटी से 'अम्मी' शब्द सुन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार को उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका इलाज केवल लाखों की लागत वाला काकलेयर इम्प्लांट सर्जरी ही था। उनके पास इतने रुपये नहीं थे कि इलाज करवा पाते। इस दौरान उन्हें किसी ने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किसी ने जांच कराने को कहा। यहां डॉ. रोहन गुप्ता ने उनका दर्द समझा। उन्होंने हमारे केस को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भेज दिया। बोर्ड के सीईओ ने भी उनके केस को वित्तीय सहायता के लिए देरी नहीं की। आज उनकी बेटी भी बोल रही है। इससे बड़ा तोहफा एक मां के लिए और क्या होगा।

वहीं, सायरा के पिता एजाज अहमद डार का कहना है कि बोर्ड ने उनकी बेटी को नई जिंदगी दी है। हमारा पूरा परिवार बेहद खुश है। उन्होंने सर्जरी के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी आभार जताया। दोनों की सर्जरी पद्मश्री डॉ. जेएम हंस, डॉ. सुनील कोतवाल और डॉ. रोहन गुप्ता शामिल थे। डॉ. सरिता, डॉ. तिरुपति और डॉ. संतोष ने सहयोग किया। अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉ. मनमोहन हरजेई ने कहा कि पूरे जम्मू-कश्मीर में सिर्फ यही अस्पताल काकलेयर इम्प्लांट उपलब्ध करवाता है। उनका मकसद है कि किसी की जिंदगी में भी सूनापन न हो। आगे भी इस प्रकार के बच्चों की सहायता करने के लिए प्रयास होगा।

डॉ. हेस और डॉ. कोतवाल ने गरीब बच्चों को लाखों की लागत वाले यह इम्प्लांट उपलब्ध करवाने की सराहना की। डॉ. रोहन ने बताया कि अगर तीन साल की उम्र तक बच्चे का इलाज हो जाए तो वह पूरी तरह से सुन सकता है। देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर के बच्चों में यह समस्या बहुत है।

पंजाब का हाल

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों समेत स्कूल प्रमुख को लोन गारंटर नहीं बनने के जारी किए गए आदेश, बैंकों की रिकवरी टीम ने शिक्षा विभाग को भेजे नोटिस तो जारी करने पड़े आदेश

अध्यापक बड़ी संख्या में बैंकों के डिफॉल्टर

गौरव सूद, पटियाला

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) के अध्यापक बड़ी संख्या में बैंकों के डिफॉल्टर हो रहे हैं। ऐसे अध्यापकों पर कार्रवाई के लिए विभिन्न बैंकों ने अब शिक्षा विभाग से संपर्क साधा है। विभाग ने अध्यापकों के वेतन से कटौती करने के लिए बैंकों को तो साफ मना कर दिया, लेकिन सभी जिलों में शिक्षा अधिकारियों समेत स्कूल प्रमुखों से कहा कि वह किसी अध्यापक के लोन केस में गारंटर न बनें। इसके लिए बकायदा पत्र भी जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर चेतावनी दी कि आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और बाद में बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए वह व्यक्तिगत रूप से खुद जिम्मेदार होगा। विभाग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैंकों की रिकवरी टीम ने शिक्षा विभाग को भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। इन नोटिसों से विभाग के अधिकारी इस कद्र परेशान हो गए कि उसे जिला शिक्षा अफसर, प्रिंसिपल, स्कूल प्रमुखों और डिसबर्सिंग अधिकारियों को निर्देश जारी करने पड़े। जिला शिक्षा अधिकारी अमरजीत सिंह ने आदेशों की पुष्टि कर कहा कि आदेशों की कॉपी सभी स्कूल प्रमुखों को भेज दी गई है। उन्हें किसी भी कर्मचारी के ऋण संबंधी मामले में गारंटर न बनने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग की गारंटी पर दिया लोन इसलिए कर्ज वसूली में करें सहयोग: शिक्षा विभाग को जारी नोटिस में बैंक अधिकारियों ने रिकवरी में सहयोग करने की अपील की है। नोटिस के अनुसार, शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों की गारंटी पर ही बैंक ने संबंधित कर्मचारियों अथवा अध्यापकों को लोन दिया। अब कर्मचारी लंबे समय से लोन नहीं भर रहे तो उनके वेतन या पेंशन में से लोन की राशि रिकवर कर बैंक को लौटाई जाए। इन नोटिसों पर शिक्षा विभाग ने किसी भी तरह के सहयोग से साफ मना कर दिया। विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और अन्य मुनाफे सीधे उनके खाते में जाते हैं। इस कारण वह किसी भी तरह का सहयोग करने में असमर्थ है।

सैलरी स्लिप पर लिखें, लोन देने के लिए गारंटी न माना जाए

बैंक के नोटिसों से शिक्षा विभाग इस तरह परेशान हो गया कि उसने सैलरी स्लिप को लेकर भी खास हिदायत जारी की। अब स्लिप पर यह भी लिखा जाएगा कि लोन देने के लिए इसे गारंटी न माना जाए। इसके अलावा बैंक को रिकवरी संबंधी बांड में रिकवरी की गारंटी न दी जाए।

होम लोन लौटाने के मामले में विभाग पहले ही परेशानी में

शिक्षा विभाग ने करीब दो साल पहले एक स्कीम तहत अपने स्टाफ के होम लोन पास करवाए थे। उसमें विभाग ने गारंटर के तौर पर उनको बैंकों से लोन दिलवाया, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने रिटायरमेंट या मौत हो जाने के कारण ऋण नहीं लौटाया। अब बैंकों ने उस पैसों को वसूलने के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी है।

विदेशी पक्षियों का शो

कोलकाता में शनिवार को विदेश पक्षियों के 21 वें बर्ड शो के दौरान एक विदेशी तोते को हाथ पर बैठाए बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री कोनीनिका बनर्जी। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल विदेशी पक्षी प्रेमी एसोशिएशन द्वारा किया जाता है। इस शो में विभिन्न देशों से अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी प्रदर्शित किए जाते हैं। एएनआइ

ओडिशा में हाथियों ने मचाया उत्पात, ग्रामीण को मार डाला

नईदुनिया, जशपुरनगर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पंद्रह हाथियों के दल ने एक ग्रामीण का घर घेर लिया और बाहर निकलने पर सौ मीटर दूर ले जाकर कुचलकर मार डाला। हाथियों ने उसके घर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हाथी छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए। हाथियों ने कई गांवों में उत्पात मचाया।

सुंदरगढ़ जिले के ग्राम केंदूडीह में हाथियों का दल रात करीब पौने बारह बजे पहुंचा। प्रखीत गहीर और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा था। मकान में तोड़फोड़ की आवाज सुन प्रखीत उठा और दरवाजे से ही देखने लगा, तभी हाथी ने उसे सूंड़ में उठा लिया और दूर ले जाकर पटककर मार डाला। हाथियों ने उसके घर को तबाह कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों का यह दल बेहद आक्रामक है। सामने आने वाले हर वस्तु पर हमला कर रहे हैं।

भारत

साल	हिंदू	मुस्लिम
1951	84.1	9.8
2011	79.8	14.2

पाकिस्तान

साल	अल्पसंख्यक	मुस्लिम
1947	23.0	77.0
2011	3.7	96.3

बांग्लादेश

साल	अल्पसंख्यक	मुस्लिम
1947	22.0	78.0
2011	7.8	92.2

राष्ट्रीयता का राष्ट्र धर्म !

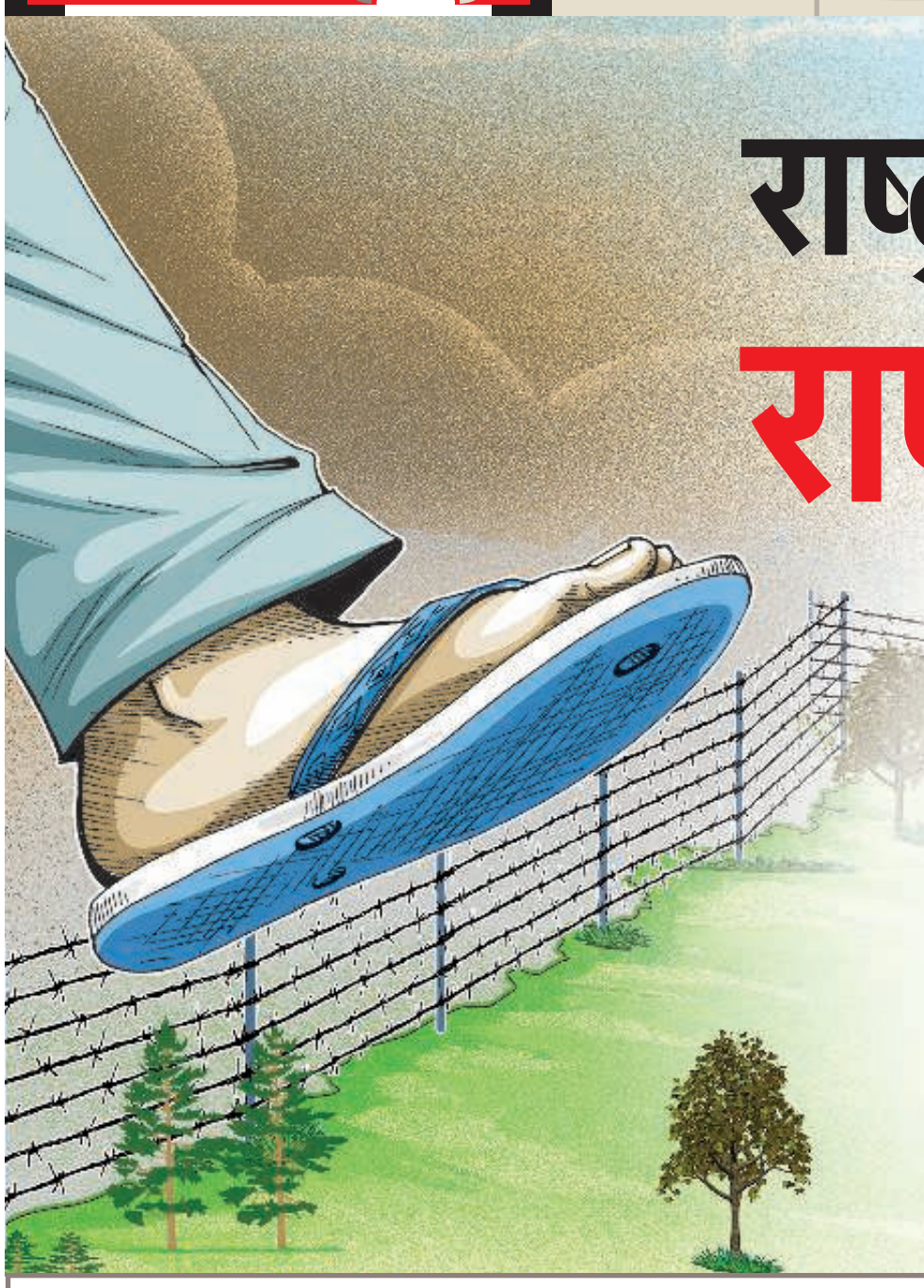

नागरिकता संशोधन कानून–2019 के तहत भारत सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की राह प्रशस्त करने जा रही है। उसकी सोच रही है कि अपने मूल देशों में सताए और प्रताड़ित किए जा रहे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देकर भारत न सिर्फ राष्ट्र धर्म का निर्वहन करेगा बल्कि आजादी के समय हुई ऐतिहासिक भूल को सुधारने का काम भी करेगा। दरअसल 1947 में जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, तब लाखों की संख्या में लोगों ने धर्म के आधार पर देश बदला। बहुत से मुसलमान भारत में ही रह गए और बहुत से हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध पाकिस्तान में बसे रहे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश बना ताकि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित समझें और उन्हें समान अधिकार मिलें। भारत ने अपने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बना दिया। यही कारण है कि विभाजन के बाद भारत में बचे 8 फीसद मुसलमान आज बढ़कर लगभग 14 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गए हैं लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की किस्मत भारतीय मुसलमानों जैसी न तब थी, न आज है। प्रगतिशील और उदारवादी विचारधारा को त्यागकर पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश बन गए और अल्पसंख्यकों का जीवन नर्क हो गया। तीन पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों के जीवन को बेहतर करने वाले सरकार के कदम पर विवाद भी छिड़ चुका है। कोई इसे वोटबैंक की राजनीति से जोड़ रहा है तो कोई समानता के अधिकार की दुहाई दे रहा है। दुष्प्रचार और अज्ञानता के चलते पूर्वोत्तर के हिस्सों में इसका हिंसक विरोध शुरू है। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दोनों पक्षों के मंसूबों की पड़ताल आज बड़ा मुद्दा है।

यहां लागू नहीं

पूरे अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम को नागरिकता कानून से अलग रखा गया है। लगभग पूरे मेघालय, वहीं असम और त्रिपुरा के इलाकों को भी अलग रखा है। हालांकि पूरा मणिपुर इसके दायरे में होगा।

अलग रखने की वजह

नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार, यह असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी इलाके में संविधान की छठी अनुसूची के चलते लागू नहीं होगा और यह क्षेत्र बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत 'इनर लाइन' में अधिसूचित है। इनर लाइन परमिट (आइएलपी) प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में लागू है।

आइएलपी का असर

आइएलपी भारत के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए एक विशेष परमिट है जो कि तीन राज्यों में जाने के लिए आवश्यक है। इसे ऑनलाइन या व्यक्तिगत आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही आइएलपी धारक द्वारा निश्चित तारीख को, निश्चित इलाकों की यात्रा की जा सकती है। जब इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत लागू किया तो उसका उद्देश्य राजा के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश शासन (भारतीय) को व्यापार करने से रोकना था। हालांकि 1950 में भारत सरकार ने स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए 'ब्रिटिश शासन' के स्थान पर 'भारत के नागरिक' कर दिया।

आइएलपी का फायदा

आइएलपी वाले राज्यों में भारत के दूसरे राज्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्रवासी निवास करते हैं। यह लोग यहां रहते हैं और काम करते हैं। इसके लिए लंबी अवधि की आइएलपी का नवीनीकरण कराते रहते हैं। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो क्या वह किसी अन्य भारतीय की तरह आइएलपी के लिए आवेदन कर सकता है और उस राज्य में काम कर सकता है। बाहरी लोगों (भारतीय नागरिक जो उस राज्य/क्षेत्र के बाहर के हैं) के इन राज्यों में आने और रहने को लेकर इनर लाइन प्रणाली या छठी अनुसूची के तहत कई तरह के नियम और प्रतिबंध हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मौजूदा नियम नई नागरिकता प्राप्त करने वाले पर भी समान रूप से लागू होंगे।

छठी अनुसूची और नागरिकता संशोधन कानून से मुक्त क्षेत्र

संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। साथ ही यह स्वायत्त जिला परिषद को विशेष शक्तियां उपलब्ध कराता है। इन परिषदों को विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां भी दी गई हैं, जिसका उद्देश्य आदिवासी इलाकों के विकास और आदिवासी समुदाय द्वारा स्वशासन को बढ़ावा देना है। मिजोरम आइएलपी शासन से सुरक्षित होता है। तीन अन्य प्रदेश के क्षेत्र छठी अनुसूची के तहत सुरक्षित होते हैं। आदिवासी बहुल मेघालय में शिलांग शहर के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर तीन परिषदें हैं जो पूरे राज्य को व्यावहारिक रूप से संभालती हैं। छठी अनुसूची के साथ असम में तीन और त्रिपुरा में एक परिषद है। मणिपुर और त्रिपुरा रियासतों का 1949 में भारत में विलय हुआ। 1972 में ये पूर्ण राज्य बने। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में छठी अनुसूची लागू है। जब त्रिपुरा को छठी अनुसूची के जरिए सुरक्षित किया गया तो केंद्र ने कहा कि जल्द ही इसे मणिपुर में भी लागू किया जाएगा, लेकिन यह अभी तक वास्तविकता नहीं बन सकी है। हालांकि राज्य सरकार तीन बार छठी अनुसूची की मांग कर चुकी है।

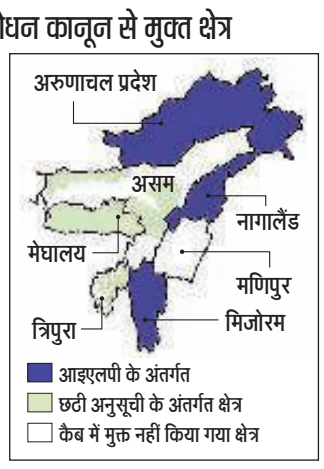

मणिपुर के आदिवासी इलाकों की स्थिति

मणिपुर में भौगोलिक रूप से दो अलग इलाके हैं। एक घाटी है, जहां इंफाल स्थित है। इस दस फीसद भौगोलिक क्षेत्र में करीब 60 फीसद जनसंख्या रहती है। शेष 90 फीसद इलाका पहाड़ी है, जो शेष 40 फीसद लोगों का घर है। यहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, जिनमें नगा और कुकीस शामिल हैं। यहां के लोगों का मानना है कि केंद्र ने जब से राज्य का दर्जा दिया है, तब से आदिवासियों के लिए समस्याएं खड़ी होने का अंदेशा था। इस कारण से अनुच्छेद 371(सी) को लाया गया।

पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में प्रावधान

इसी साल नवंबर में मेघालय कैबिनेट ने मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह कदम आइएलपी जैसे शासन को लागू करने की मांग की पृष्ठभूमि में सामने आया है। वहीं असम में भी आइएलपी शासन जैसे नियमों को लागू करने की मांग सामने आई है।

क्या है अनुच्छेद 371(सी)

संविधान के अनुच्छेद 371(सी) के तहत मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के आदेश से राज्य विधानसभा के सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है जिसमें पहाड़ी इलाके से चुने गए सदस्य भी शामिल होते हैं। यह लोग मिलकर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के बेहतर प्रबंध के लिए काम करते हैं। राष्ट्रपति के मांगने अथवा वार्षिक रूप से राज्यपाल मणिपुर के पहाड़ी इलाके के प्रबंध से जुड़ी रिपोर्ट भेजते हैं। इसके जरिए मणिपुर के आदिवासियों का हक विधानसभा में सुरक्षित करना है। मणिपुर (पहाड़ी इलाका) जिला परिषद कानून, 1971 संसद द्वारा पारित किया गया था। जिसने 1972 में मणिपुर में छह स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना को सुनिश्चित कर दिया। वहीं पिछले साल मणिपुर पीपुल बिल, 2018 विधानसभा ने पारित किया। जिसे राष्ट्रपति की अनुमति का इंतजार है। इसमें बाहरी और गैर मणिपुरी लोगों को लेकर कई नियम हैं।

भय की वजह भाषा

हरेंद्र प्रताप
पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद

असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के पीछे भाषाई अल्पसंख्यक होने का बैठा हुआ यही भय हैं। केंद्र सरकार को असम के लोगों के मन में जो भय व्याप्त है उसे दूर करना होगा।

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की दुहाई देते हुए इसे संविधान की धारा 14, 15, 21, 25 और 26 आदि का उल्लंघन करार दे रहे हैं। वे इस कानून में मुसलमानों को भी शामिल करने की मांग करते हुए देश विभाजन के लिए महान क्रांतिकारी वीर सावरकर को द्वि राष्ट्रवाद का जनक बता रहे हैं। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में दिए उनके भाषण का उल्लेख किया जा रहा है।

अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता से डरे अंग्रेजों ने षड़यंत्रपूर्वक मुसलमानों के संगठन मुस्लिम लीग को पैदा किया। देश विभाजन का बीजारोपण तो 1906 में ढाका मे हुए मुस्लिम लीग के सम्मेलन में ही हो गया था। हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए ही तुर्की के खलीफा का विषय लेकर कांग्रेस ने भारत में असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए 1924 में 21 दिन का अनशन भी किया फिर भी क्या वे देश का विभाजन रोक पाये?

सच्चाई यह है कि वीर सावरकर ने नहीं बल्कि सर्वप्रथम अलग पाकिस्तान की मांग उर्दू कवि इकबाल ने लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखी। 1933 में रहमत अली ने देश के दो भागों का नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक रख दिया। हिंदू-मुस्लिम एकता के सारे प्रयास मुस्लिम मानसिकता के कारण विफल हो गए और 1947 में देश बंट गया। मुस्लिम बहुल इलाका भारत से कट गया। इस विभाजन को द्वि राष्ट्रवाद का नाम भले दिया गया पर वास्तविक रूप में यह देश से मुसलमानों का विभाजन था क्योंकि देश का वही हिस्सा भारत से कटा जहां मुस्लिम बहुमत में थे। विभाजन के बाद भी भारत में रह गए मुसलमानों के साथ कोई भेद भाव हुआ हो या अपने उत्पीड़न के कारण उन्हें भारत छोड़ने को बाध्य होना पड़ा हो -ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता।

पाकिस्तान का जन्म ही गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत के आधार पर हुआ है। गैर मुस्लिमों के प्रति मुसलमानों का कैसा व्यवहार है, इसका प्रमाण है वहां गैर मुस्लिमों की घटती जनसंख्या। इस्लाम और मुस्लिम मानसिकता के बारे में आजादी के दौरान एनी बेसेंट ने 1922 में लिखी अपनी पुस्तक 'दि फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स' में लिखा है कि मुसलमान गैर मुसलमानों से नफरत करते हैं। 18 अप्रैल 1924 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में रवींद्रनाथ टैगोर का साक्षात्कार छपा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान पहले मुसलमान है फिर उसके बाद ही और कुछ है।

राजनीतिक नेतृत्व ने देश का बंटवारा किया पर उसका दंश पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गये गैर मुस्लिमों को भुगतना पड़ा। विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आने लगे थे। सदन में चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने 25 नवंबर 1947 के कांग्रेस कार्यसमिति और 26 सितंबर 1947 को गांधी जी के बयानों का हवाला देकर इसे देश के सामने भी रखा। नेहरू मंत्रिमंडल से डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए ही इस्तीफा दिया था। 13 फरवरी 1964 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने त्रिपुरा से एक तार मिलने का उल्लेख करते हुए कहा था-'कल रात मुझे एक तार मिला जिसमें यह उल्लेख है कि एक लाख शरणार्थी आ चुके हैं। रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे हैं।

पाकिस्तान-बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के ऊपर क्या-क्या कहर ढाए जा रहे हैं, यह बात एक बार छोड़ भी दें लेकिन भारत के मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीर में गैर मुस्लिमों पर हुए मुसलमानों के अत्याचार को कौन भूला सकता है। न केवल कश्मीर बल्कि मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से भी गैर मुस्लिमों का पलायन हो रहा है।

असम और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों और प्रखंडों से भी गैर मुस्लिम-मुस्लिम उत्पीड़न के कारण पलायन करने को बाध्य हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वालों को छोड़ दें तो असम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों के अलावा पूरे देश ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 का स्वागत ही किया है। भले ही भारत का विभाजन हिंदू -मुस्लिम के आधार पर हुआ पर पाकिस्तान का विभाजन 'बांग्ला भाषा' के आधार पर हुआ है। बांग्लादेश से आने वाले सभी लोगों की मातृभाषा बांग्ला है। 1991 में असम में 'असमिया' को अपनी मातृभाषा लिखने वालों की संख्या 57.81 प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना में घटकर 48.37 प्रतिशत हो गयी। असम में 1991 में बांग्ला मातृभाषी लोगों की संख्या 21.66 प्रतिशत 2011 में बढ़कर 28.91 प्रतिशत हो गयी है।

नागरिकता संशोधन कानून

तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करने वाला नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में कानून के सभी पहलुओं के साथ ही इसके फायदे को जानना भी हर भारतीय के लिए जरूरी है।

कौन है अप्रवासी

सहज रूप से अप्रवासी का अर्थ उन लोगों से है जो इन छह समूहों या समुदायों में से हो। इन समूहों के अतिरिक्त इन देशों से आने वाले लोग किसी भी तरह से नागरिकता के पात्र नहीं होंगे। यह विधेयक प्राकृतिक रूप से नागरिकता के प्रावधान में भी छूट देता है। साथ ही विधेयक तीन देशों के छह समुदायों के लोगों को 11 साल भारत में रहने की अवधि में भी छूट देता है। विधेयक में इसे घटाकर पांच साल किया गया है।

किसे करता है शामिल

यह विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अप्रवासियों को शामिल करता है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार, एक अवैध अप्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अवैध अप्रवासी का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारत में या तो वैध दस्तावेजों के बिना दाखिल हुआ है अथवा निर्धारित समय से अधिक भारत में रह रहा है। सरकार ने 2015 में इन तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में आने देने के लिए पासपोर्ट और विदेशी एक्ट में संशोधन किया था। यदि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो भी वह भारत में आ सकते हैं।

यह है कानून

नागरिकता संशोधन कानून 2019 संसद के दोनों से सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून बना। यह भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता का प्रस्ताव करता है।

विपक्ष का सवाल

प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक देश के करीब 15 फीसद मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हैं। वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे में उन्हें उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार दूसरे समुदायों की प्रार्थना पत्रों पर अलग-अलग मामले में गौर करेगी।

सरकार की दलील

1947 में भारत और पाकिस्तान के धार्मिक आधार पर विभाजन का तर्क देते हुए सरकार ने कहा कि अविभाजित भारत में रहने वाले लाखों लोग भिन्न मतों को मानते हुए 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान उन्हें विशिष्ट धार्मिक राज्य बनाता है। परिणामस्वरूप, इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के बहुत से लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलते हैं। इनमें से बहुत से लोग रोजमर्रा के जीवन में उत्पीड़न से डरते हैं। जहां उनका अपनी धार्मिक पद्धति, उसके पालन और आस्था रखना बाधित और वर्जित है। इनमें से बहुत से लोग भारत में शरण के लिए भाग आए और वे अब यहीं रहना चाहते हैं। यद्यपि उनके यात्रा दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है या वे अपूर्ण हैं अथवा उनके पास दस्तावेज नहीं हैं।

विधेयक की पृष्ठभूमि

एनडीए सरकार के चुनावी वादों में से यह एक है। आम चुनावों के ठीक पहले यह विधेयक अपनी शुरुआती अवस्था में जनवरी 2019 में पास हुआ था। इसमें छह गैर मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता मांगी गई। इसमें नागरिकता के लिए बारह साल भारत में निवास करने की आवश्यक शर्त को कम करके सात साल किया गया। यदि नागरिकता चाहने वाले के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो भी। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था, हालांकि यह बिल पास नहीं हो सका क्योंकि यह राज्यसभा में गिर गया था।

विधेयक के विपक्ष में

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद - 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और माकपा सहित अन्य कुछ प्रमुख राजनीतिक दल विधेयक का मुखर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में विधेयक के खिलाफ व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

इसलिए है विरोध

उत्तरपूर्वी राज्यों में विधेयक का भारी विरोध है। यहां पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग महसूस करते हैं कि अवैध प्रवासियों के स्थायी रूप से बसने के बाद स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साथ ही आगामी समय में संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा और पहले से यहां रह रहे लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। लोगों का एक बड़ा वर्ग और संगठन विधेयक का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि यह 1985 के असम समझौते को रद कर देगा। असम समझौते के अनुसार, 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए लोगों की पहचान कर बाहर निकाला जाए। अब नागरिकता संशोधन विधेयक में नई सीमा 2019 तय की गई है। अवैध प्रवासियों के निर्वासन की समय सीमा बढ़ाने से लोग नाराज हैं।

कितने लोग जुड़ेंगे

संसदीय समिति के अनुसार, दूसरे देशों के रहने वाले इन अल्पसंख्यक समुदायों के 31 हजार 313 लोग लंबी अवधि के वीसा पर रह रहे हैं। यह लोग धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर शरण मांग रहे हैं। इंटेलीजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, इन 31 हजार 313 लोगों में 25 हजार 447 हिंदू, 5 हजार 807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं।

जनमत

क्या नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत तीन पड़ोसी मुल्कों के गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का सरकार का प्रस्ताव उचित है?

हां 85% | नहीं 15%

क्या विपक्षी राजनीतिक दलों की यह मांग सही है कि नागरिक संशोधन विधेयक के दायरे में तीनों पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक भी आने चाहिए?

हां 05% | नहीं 95%

आपकी आवाज

जिन तीन पड़ोसी देशों की बात हो रही है, वहां अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं। अब उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसको लेकर बिना वजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। **क्षमा सिंह**

नागरिकता कानून से कुछ लोगों का का करुण कृंदन बेमतलब का है। क्योंकि कल तक यही लोग देश को असहिष्णु बताकर देश छोड़कर जा रहे थे। तो फिर अब भाईलोगों को नागरिकता क्यों चाहिए। **जुगल किशोर**

जमीन है फसाद की जड़

असम के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और राज्य लगातार जल रहा है, तो त्रिपुरा में भी ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा लेकिन इस पर न असमियों ने यकीन किया और न ही त्रिपुरा की जनजातियों ने। उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा क्योंकि वे अपनी पूरी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें भूमि, भाषा और संस्कृति शामिल है। इससे निपटने के बजाय नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) उन्हें धर्म और जनजातियों में बांटता है। इस विधेयक में सात आदिवासी जिलों को अलग रखा गया है। यह जिले छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वे पिछले कुछ दशकों में राज्य के शेष सोलह जिलों में भी भूमि खो चुके हैं। त्रिपुरा में आदिवासी इलाकों के दो जिलों को अलग रखा गया है, यह जिले छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। हालांकि पिछले सात दशकों में आदिवासी अब के बांग्लादेश के हिंदू बंगाली अप्रवासियों के हाथों अपनी 40 फीसद जमीन गंवा चुके हैं। वे मानते हैं कि जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, वे शरणार्थी नहीं हैं, बल्कि जमीन के भूखे अप्रवासी जमीन की तलाश में यहां आते हैं। राज्य के भूमि कानून को उनकी सुविधा के लिए बदला गया था और इस कानून के तहत उनकी बहुत सी जमीन हटाई गई थी। असम में आदिवासी और गैर आदिवासी जिलों की बहुत सी जमीन खो चुकी है।

नागरिकता संशोधन कानून असम के लोगों की भूमि और पहचान को लेकर उनके डर को नजरअंदाज करता है और नागरिकता को परिभाषित करने के लिए धर्म का उपयोग करता है। असम के लोग न खुद की नागरिकता का विरोध कर रहे हैं और न ही बाहर से आने वाले लोगों की नागरिकता का विरोध है। वे चाहते हैं कि उनकी भूमि को कब्जे से संरक्षित किया जाए और नए अधिनियमित नागरिकता कानून में यह बातें नहीं हैं। वे इस बात से अवगत हैं कि बंगाली हिंदू असम और त्रिपुरा में भूमि की तलाश में आए, धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं। असम के लोग ये महसूस करते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून अप्रवासियों को धर्म के नाम पर और अधिक प्रोत्साहित करता है और उनकी जमीनों को कब्जे से सुरक्षित नहीं करता है, जिसे हिंदू और मुस्लिम करते हैं। उदाहरण के लिए, 19 लाख लोगों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) में नागरिकता से हटाया गया है। इसमें 10 लाख मुस्लिम और पांच लाख बंगाली भाषी हिंदू हैं। शेष हिंदुओं में भिन्न भाषा बोलने वाले समूह जैसे हिंदी और नेपाली हैं। यहां तक की असमी बोलने वाले भी करीब एक लाख लोग हैं। वे चाहते हैं कि इस विसंगति को उचित दस्तावेजों की कानूनी प्रक्रिया के जरिए ठीक किया जाना चाहिए। धर्म के उपयोग को मानदंड मानकर उनकी क्षति को लौटाया नहीं जा सकता। सभी जनगणना को देखने के बाद यह दिखता है कि अप्रवासियों की 40 फीसद जनसंख्या बंगाली भाषी मुसलमानों की है। शेष हिंदी, बंगाली और नेपाली बोलने वाले हिंदू हैं। एनआरसी में हटाए गए हिंदुओं को कैब में नागरिकता मिल जाएगी। वे मानते हैं कि नियमित होना गैर भेदभावपूर्ण तरीका है।

प्रो वॉल्टर फर्नांडिस
सीनियर फेलो, नॉर्थ ईस्टर्न सोशल रिसर्च सेंटर, गुवाहाटी

असमी इस बात से डरे हैं कि यह कानून पड़ोसी मुल्कों के हिंदुओं को उत्तरपूर्व के राज्यों में भूमि की तलाश में आने और खुद को धार्मिक उत्पीड़न का शिकार घोषित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

भूमि से अलग असमी बोलने वालों को राज्य में अल्पसंख्यक होने का डर भी सता रहा है। त्रिपुरा में आदिवासी-बंगाली संघर्ष शुरू हुआ तब आदिवासियों ने बंगाली भाषी हिंदुओं के हाथों अपनी 40 फीसद जमीन खो दी। साथ ही वे जहां 1951 में 51.1 फीसद थे, वहीं 2001 की जनगणना के आधार पर 31.1 फीसद रह गए। कानून के बदलाव ने आदिवासियों को उस सार्वजनिक भूमि से वंचित कर दिया, जिस पर वे रहते थे। कानून असम के लिए भी अस्पष्ट है। केवल एक तिहाई भूमि का पट्टा है, इसमें भी ज्यादातर शहरी इलाका है। राज्य की शेष भूमि का विभिन्न कानूनों के जरिए ध्यान रखा जाता है। एक बाहरी के लिए किसी भी जमीन पर कब्जा करना और फिर रिश्वत देकर पट्टा हासिल करना बहुत आसान है। इस कानूनी असंगति से निपटने के बजाय कैब नागरिकता के लिए धार्मिक मापदंड तय कर देता है। असम भूमि और भाषा के आधार पर शासन चाहता है जो कि राज्य के सभी निवासियों को सुरक्षित करे और शरणार्थियों को धार्मिक उत्पीड़न के बहाने प्रोत्साहित न करें। वे किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं।

दैनिक जागरण

निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है

कांग्रेस की चिंताएं

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की भारत बचाओ रैली ने यही बताया कि पार्टी एक साथ कई मसलों पर मोदी सरकार को घेरना चाह रही थी। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह से लेकर पी चिदंबरम तक ने जिन तमाम मसलों पर अपनी चिंता जाहिर की उनमें नागरिकता कानून सर्वोपरि दिखा तो शायद इसी कारण कि उसके जरिये कुछ राजनीतिक लाभ मिलने की सूरत दिख रही है। देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। निःसंदेह इस पर भी निर्भर करेगा कि नागरिकता संबंधी इस संशोधित कानून को आम जनता किस रूप में ले रही है? भले ही पूर्वोत्तर में इस कानून का विरोध हो रहा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि कांग्रेस जो कह रही है वही सही है। इसमें संदेह है कि मोदी सरकार नागरिकता कानून पर कांग्रेस की आपत्ति को महत्व देने वाली है, लेकिन उसे अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर कांग्रेसी नेताओं की चिंता पर गंभीरता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक सुस्ती का माहौल एक सच्चाई है और उस पर विपक्ष को अपनी चिंता जताने और साथ ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अधिकार है। वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा है, क्योंकि आर्थिक सुस्ती के बीच महंगाई भी सिर उठाती दिख रही है। यह सही है कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है, लेकिन अभी हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं और इसी कारण विपक्ष को टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिल रहा है।

पता नहीं कांग्रेस इसका आकलन करेगी या नहीं कि भारत बचाओ रैली कितनी असरकारी रही, लेकिन उसे और खासकर राहुल गांधी को यह समझ आए तो बेहतर कि उन्हें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। यह साफ है कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधने के फेर में ऐसा कहा, लेकिन निशाना उस शिवसेना पर भी लगा जिसकी सरकार को कांग्रेस समर्थन दे रही है। राहुल गांधी ने भले ही सावरकर का उल्लेख यह जताने के लिए किया हो कि वह अपने किसी बयान के लिए माफी नहीं मांगने वाले, लेकिन सबको पता है कि राफेल मामले में वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिखित तौर पर माफी मांग चुके हैं। आखिर वह अपनी इस लिखित माफी को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि अगर आए दिन उनके बयान चर्चा में आ जाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपनी बातों से लोगों को आश्वस्त करने में सफल हो जाते हैं।

सार्थक कदम

उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के खाली पड़े परिसरों में अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी संचालित किया जा सकेगा। बंद पड़े प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के साथ में विद्यालयों के खाली पड़े परिसरों का भी इस कार्य के लिए उपयोग करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह फैसला सही और विभिन्न महकमों के संसाधनों को एक साथ बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में अच्छा कदम कहा जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग कर रहा है। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषकतत्वयुक्त भोजन के साथ ही प्री प्राइमरी शिक्षा इन केंद्रों में मुहैया कराई जा रही है। ये आंगनबाड़ी केंद्र नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में चलेंगे। इससे विद्यालयों को भी फायदा है। प्री प्राइमरी शिक्षा के बाद बच्चे इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला ले सकेंगे। वैसे भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है। शिक्षा महकमे को सेवित क्षेत्रों के बच्चों को दाखिला दिलाने को प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम संचालित करने पड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अपने सेवित क्षेत्रों के बच्चों के आंकड़े भी जुटाते हैं। ऐसे में इन केंद्रों के जरिये प्राथमिक विद्यालयों को भी मदद मिल सकेगी। हालांकि काफी लंबे समय से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में निजी विद्यालयों खासतौर पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर प्री प्राइमरी के रूप में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, लेकिन आर्थिक कारणों से इस पर अमल करने से गुरेज किया गया। वैसे भी शिक्षा महकमे के कुल बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ वेतन-भत्तों पर खर्च हो रहा है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा का रास्ता साफ होने जा रहा है। हालांकि पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में कुछ दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। इन क्षेत्रों में अधिकतर प्राथमिक विद्यालय गांव या आबादी क्षेत्र से हटकर हैं। छह साल से कम आयु के छोटे बच्चों को इन केंद्रों तक लाने-ले जाने की समस्या खड़ी हो सकती है। उक्त दोनों व्यवस्था साथ-साथ होने से इन समस्याओं के समाधान की राह भी निकलेगी। बावजूद इसके इस प्रयोग को यदि संजीदगी के साथ लागू किया गया तो इससे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की स्थिति में अधिक सुधार नजर आ सकता है। साथ ही विद्यालयों को ड्राप आउट की समस्या से निजात मिल सकेगी।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के पास अब प्री प्राइमरी शिक्षा से जुड़ने का मौका है। यह व्यवस्था कारगर रही तो विद्यालयों में बच्चों के दाखिले का संकट भी दूर होगा

नागरिकता कानून पर दुष्प्रचार

संजय गुप्त

समस्या केवल यह नहीं कि विपक्षी दल नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यह है कि वे उसे लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं

अवधेश राजपूत

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून का रूप ले लिया। मोदी सरकार ने इस विधेयक को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से जिस तरह पारित कराने में सफलता प्राप्त की उससे उसके राजनीतिक कौशल का पता चलता है। इस विधेयक को कानून का रूप देकर मोदी सरकार ने अपने एक और अहम वादे को पूरा किया। इसके पहले वह अनुच्छेद 370 को हटा चुकी है और अयोध्या मामले का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। नागरिकता विधेयक पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यह एक समस्या का निराकरण करने के लिए लाया गया विधेयक है और मोदी सरकार समस्याओं के समाधान के लिए ही सत्ता में आई है, न कि सत्ता सुख भोगने के लिए। जैसा पहले से स्पष्ट था, कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, फिर भी राज्यसभा में सरकार को इसलिए आसानी हुई, क्योंकि बीजद जैसे दलों ने विधेयक का समर्थन किया। शिवसेना का रवैया अजीब रहा। उसने लोकसभा में समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में उसके बहिष्कार पर उतर आई। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी उसका विरोध जारी है। विपक्षी दल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच अंतर करने के कारणों को समझने के लिए तैयार नहीं। हालांकि गृहमंत्री ने इन कारणों को बार-बार स्पष्ट किया, लेकिन विपक्ष इसी पर अड़ा है कि यह कानून संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और खासकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। साफ है कि वह इसकी अनदेखी कर रहा है कि नागरिकता कानून तीन पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों और वहां के बहुसंख्यकों में भेद करता है, न कि हिंदू-मुसलमानों के बीच। विपक्ष यह समझने को तैयार नहीं कि अनुच्छेद 14 तर्कसंगत विभेद आधारित कानून बनाने की अनुमति देता है। विपक्ष इस बात को भी ओझल कर रहा है कि गृहमंत्री साफ कर चुके हैं कि यदि उक्त तीन देशों के बहुसंख्यक यानी मुसलमान भारत की नागरिकता चाहेंगे तो उस पर विचार होगा।

समस्या केवल यह नहीं कि विपक्षी दल नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे उसे लेकर लोगों को बरगलाने और उकसाने का काम कर रहे हैं। उनकी ओर से यह प्रचारित किया जा रहा है कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। यह प्रचार तब हो रहा है जब इस कानून का किसी भी मजहब के भारतीय नागरिकों से कोई संबंध नहीं। जाहिर है कि एक संवेदनशील मसले पर दुष्प्रचार के कारण लोगों में गलत संदेश जा रहा है और वे आशंकित हो रहे हैं। इस आशंका को भुनाया जा रहा है। नागरिकता कानून पर गलत और उकसावे वाले प्रचार के कारण ही असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस विरोध का आधार यह अंदेशा है कि बाहरी लोगों को नागरिकता देकर उनके यहां बसा दिया जाएगा। असम के लोगों को लगता है कि इससे उनकी संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। असम आजादी के बाद से ही पहले पूर्वी पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का शिकार है। बांग्लादेश के करोड़ों लोग असम में बस चुके हैं। उनके चलते असम का सामाजिक और राजनीतिक माहौल बदल गया है। इसी कारण असमी लोग बांग्लादेश से आए बांग्ला भाषी हिंदुओं को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। असम में बाहरी लोगों के खिलाफ उग्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। उग्रवादी संगठन उल्फा इसी आंदोलन की उपज था। आज असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में नागरिकता कानून के विरोध में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वह क्षेत्रवाद की राजनीति का ही परिचायक है। क्षेत्रीयता का राष्ट्रीयता पर हावी होना एक विडंबना ही है। क्षेत्रवाद को हवा देने वाली राजनीति तमिलनाडु, बंगाल और महाराष्ट्र में भी जब-तब की जाती रही है। एक समय पंजाब में भी इसी राजनीति को हवा दी गई थी। केरल, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की ओर से यह जो कहा गया कि वे नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे वह केवल क्षेत्रवाद की शर्मनाक राजनीति ही नहीं, संघीय ढांचे का निरादर भी है।

नागरिकता कानून को लेकर असम में जो हिंसा जारी है उसका औचित्य इसलिए नहीं, क्योंकि यह कानून वहां के कुछ ही जिलों में लागू होगा। यही स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की है। कुछ राज्य तो इनर लाइन परमिट से पूरी तरह संरक्षित हैं। पूर्वोत्तर के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वे भी इस कानून से बाहर हैं ताकि उनकी मूल संस्कृति सुरक्षित रहे। पूर्वोत्तर के जो इलाके इस कानून के दायरे में हैं वे वही हैं जहां बाहरी लोग दशकों से रह रहे हैं और वहां के माहौल में घुलमिल गए हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि इनमें से पात्र लोगों को नागरिकता देकर वहीं बसाना बेहतर होगा। ऐसे इलाकों से संबंधित राज्य सरकारें सैद्धांतिक तौर पर इससे सहमत हैं, लेकिन राजनीतिक नुकसान के चलते वे ऐसा कहने से बच रही हैं। असम की भाजपा सरकार में असम गण परिषद एक प्रमुख घटक है, लेकिन उसके कुछ नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कुछ भाजपा नेता भी इसके खिलाफ हो सकते हैं। बेहतर होगा कि उन नेताओं से संपर्क-संवाद तेज किया जाए जो नागरिकता कानून को लेकर आशंकित हैं। कायदे से यह काम विधेयक पेश करने के पहले ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह तय था कि कुछ दल इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करेंगे। आज यही हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यह कह रहे हैं कि इस कानून से पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति को कोई खतरा पैदा नहीं होने दिया जाएगा।

राष्ट्रीय महत्व के मसलों को हिंसा के सहारे नहीं सुलझाया जा सकता। हिंसा से तो वैमनस्य ही बढ़ेगा, जबकि जरूरत सामंजस्य बढ़ाने की है। बाहर से आए जो लाखों लोग दशकों से पूर्वोत्तर में रह रहे हैं उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें नागरिक या शरणार्थी घोषित करने का काम करना ही होगा। इस मामले में एक सीमा तक ही उदारता दिखाई जा सकती है, क्योंकि भारत के पास इतने संसाधन नहीं कि वह हर किसी को देश में रहने का अधिकार दे दे। विपक्ष असम की तर्ज पर शेष देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा का भी विरोध कर रहा है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि हर देश को यह जानने का अधिकार है कि उसके यहां रह रहे लोगों में कौन उसके नागरिक हैं और कौन नहीं? अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने और दूसरे देश के नागरिकों की पहचान करनी होगी। दूसरे देशों की नागरिकों की पहचान करते समय यह भी देखना होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन शरणार्थी? इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम घुसपैठियों ने मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। वे भारतीय नागरिकों की तरह भारत के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। यह ठीक नहीं। इस सिलसिले को रोकना ही होगा।

response@jagran.com

प्याज बिना चैन कहां रे

हास्य-व्यंग्य

शैलेश त्रिपाठी

प्याज की फिल्मी कहानी में कई खास संवाद भी हैं जैसे कि तुम्हें जितना प्याज चाहिए ले लो, पर मेरे रास्ते से हट जाओ

जबरदस्त खबर है। एक जानेमाने निर्माता बड़ी जोरदार फिल्म बनाने जा रहे हैं। नाम है 'प्याज बिना चैन कहां' जिसे निर्देशित करने के लिए बाहर से किन्हीं विलियम ओनियन को बुलाया जा रहा है। चलिए इसकी कहानी की कुछ परतें खोलते हैं। कहानी नए जमाने की है, लेकिन उसमें एक स्वयंवर भी दिखाया गया है। यह स्वयंवर फिल्म की अहम कड़ी है। अपनी रूपवती राजकुमारी के विवाह के लिए प्याजगढ़ नरेश कांदाकुंवर स्वयंवर की घोषणा करते हैं। इसके मुताबिक जो नौजवान फलां तारीख तक सबसे ज्यादा प्याज लेकर हाजिर होगा तो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के साथ ही वह अपना आधा राजपाट उसे सौंपकर वनगमन को निकल जाएंगे।

स्वयंवर की मुनादी सुन ढेर सारे नौजवान अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। प्याज के लच्छों की तरह ही अपनी लच्छेदार बातों से सबको साधने में सिद्धहस्त नौजवान प्रेमपाल ने सोचा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात हुई। वह प्याज लादने के लिए गाड़ी लेकर सब्जी मंडी पहुंचा। वहां जाकर मालूम पड़ा कि महंगे भाव के चलते प्याज मंडी में नहीं, बल्कि सर्राफा बाजार से भी कड़ी सुरक्षा में बेचा जा रहा है। वह वहां से निकलने को ही था कि मंडी में घूम रहे तमाम सांडों में से एक ने उसे जोर से पटक दिया। वहां मौजूद लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाने में ही मशगूल रहे। फिर उन्हीं लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया कि देखिए आज का समाज कितना संवेदनहीन हो गया है।

अब स्वयंवर के दूसरे महारथी से मुलाकात की जाए। यह महाशय हैं छोटेलाल जो जुगाड़ लगाने में उतने ही बड़े उस्ताद माने जाते हैं। इसी सिलसिले में बैंक से लोन के लिए संपर्क साधा। बैंकों ने उससे आधार, पैन, पिछले बीस साल का आयकर रिटर्न और तमाम तरह की लिखित गारंटी लेने के बावजूद लोन इस बिना पर रद कर दिया गया कि वह बीते महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुका पाया था। छोटेलाल भी इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाए और अस्पताल पहुंच गए। खबर यह फैल गई कि प्याज सेहत के लिए हानिकारक है।

अब तीसरे महानुभाव मंगूराम की भी चर्चा हो जाए। उसने अपनी जमीन-जायदाद बेच और परिचितों को फंसाकर उनकी किडनी का सौदा करके मिली रकम बटोरने के बाद खरीदे गए प्याज को लेकर राजमहल की ओर कूच किया। वह राजमहल से लगी पुलिस चौकी तक पहुंचा ही था कि दो नकाबपोशों ने उसकी कनपटी पर तमंचा सटाकर सारा प्याज छीन लिया। पुलिस वालों ने उसे ही उल्टे प्याज चोर समझकर निपटा दिया। यहीं फिल्म की कहानी निर्णायक करवट लेती है।

पुनर्जन्म के बाद तीनों एक नेता के घर में जन्म लेते हैं जहां उन्हें 'अमर अकबर एंथोनी' नाम दिया जाता है। उनके पिता तीनों को कुंभ के मेले में ले जाते हैं। वहां एक गोदने वाले के यहां एक के हाथ पर प्याज, दूसरे के लहसुन और तीसरे के हाथ पर टमाटर गोदवा दिया। वे उस तंबू से निकले ही थे कि बाहर एक हाथी के उत्पात से मची भगदड़ में बिछड़ जाते हैं। एक भाई मंडी के एक बड़े जमाखोर के हाथ लगता है। वह बड़ा होकर बहुत बड़ा जमाखोर बनता है। दूसरा भाई जमाखोरी पर नियंत्रण रखने वाले विभाग का बेहद ईमानदार इंस्पेक्टर बनता है। तीसरा भाई फलों और सब्जियों के मूल्य पर निगरानी रखने वाले मंत्री के मातहत काम करता है। तीनों भाई वक्त-बेवक्त आपस में टकराते रहते हैं। क्या इन तीनों का मिलन हो पाएगा। इनमें कौन किस पर भारी पडता है। पूरी फिल्म का तानाबाना इसी पर बुना गया है। इसमें कई दमदार संवाद भी हैं। मसलन एक दृश्य में हीरोइन का बाप हीरो को बुलाकर कहता है कि तुम्हें जितना प्याज चाहिए ले लो, पर मेरी बेटी के रास्ते से हट जाओ। एक सीन में बताया जाता है कि कैसे नए प्याज में चिप लगाई जाएगी, जो खुद जमाखोर की पोल खोल देगी। फिल्म के गाने भी खूब धमाल मचा रहे हैं। 'प्याज बिना चैन कहां रे' जैसे टाइटल ट्रैक के अलावा 'प्याज मांगा है तुम्हीं से, न यूं इन्कार करो' और 'इक प्याज का नगमा है...' जैसे गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने वाले हैं। फिल्म के निर्माता का दावा है कि उनकी फिल्म दर्शकों को प्याज के रूप, रंग और रस से सराबोर करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | **अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों का निष्कासन**

(आंकड़े : वर्ष 2018 के)

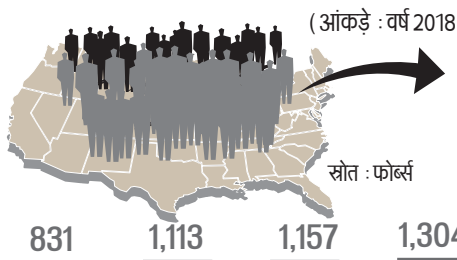

स्रोत : फोर्ब्स

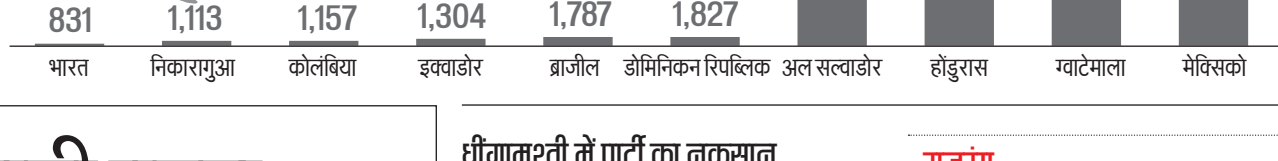

ऊर्जा

विचारों का प्रभाव

आदर्श विचार मनुष्य के जीवन की खराब दशा को सही दिशा देने का कार्य करते है। मनुष्य अपने जीवन में विचारों के बंधन से मुक्त नहीं रह सकता। वह किसी न किसी विचार के प्रति आकर्षित तो होता ही है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आकर्षण सुविचारों के प्रति है या कुविचारों के प्रति। सुविचारों को व्यवहार में स्थान देने से न सिर्फ व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि मनुष्य उन विचारों के आधार पर उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कुविचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले लोग पतन मार्ग के पथिक बनकर रह जाते हैं। इसलिए जीवन में विचारों की भूमिका को तय करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर सूक्तियां बहुत आकर्षित करती हैं। हालांकि ये कथन सिर्फ उन्हीं का आकर्षण बन पाते है जो उनके अर्थ तक पहुंच पाते हैं। यह केवल अमृत वचन मात्र नहीं होते, बल्कि जीवन का सार होते है। उन कथनों को अनुभव की भांति आत्मसात करने के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यदि वह दृष्टि हममें उपस्थित नहीं है तो हम उस विचार के मूल तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे।

यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक क्षमता भिन्न होती है। वह अपनी क्षमता के आधार पर ही विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण कर्म से होता है, किंतु कर्म में विचारों की बड़ी भूमिका रहती है। यदि सफलता गलत मार्ग पर चलने से प्राप्त हो रही हो तब मनुष्य क्या उस मार्ग का अनुसरण करेगा? इस प्रश्न का उत्तर उसकी वैचारिक स्थिति पर निर्भर करता है। आधुनिक जीवनशैली में प्रवेश के चलते अध्यात्म और आदर्श का स्थान व्यावहारिकता ने ले लिया है। ज्यादा व्यावहारिक बनने की लालसा ने सही और गलत के बीच सोचने की क्षमता को समाप्त करने में कोई कसर शेष नहीं रखी है। ऐसे विचारों के अनुयायियों के लिए कर्म में सही या गलत महत्वपूर्ण नहीं होता, वे सिर्फ परिणाम के अभिलाषी होते हैं। परिणाम की लालसा के चलते वे सही अथवा गलत में भेद ही नहीं कर पाते।

सौरभ जैन

पर्यावरण हित में बड़ी पहल

मुकुल व्यास

कार्बन डाईऑक्साइड को ईंधन और निर्माण सामग्री में बदलने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम किया जा सकता है

कार्बन डाईऑक्साइड को ईंधन या निर्माण सामग्री में बदलने का काम एक नया वैश्विक उद्योग बन सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड तथा पांच अन्य संस्थानों के एक नए अध्ययन में यह बात कही गई है। यदि ऐसा हुआ तो इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण को फायदा होगा। 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित यह शोध कार्बन डाईऑक्साइड के उपयोग के बारे में अब तक का सबसे विस्तृत अध्ययन है। कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग 10 विभिन्न तरीकों से हो सकता है। इनमें ईंधन, रसायन, प्लास्टिक, भवन निर्माण सामग्री, मृदा प्रबंधन तथा वानिकी शामिल हैं।

शोधकर्ताओं ने कार्बन डाईऑक्साइड के उपयोग की लागत का अध्ययन किया है। उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि खनिज तेलों के जलने से निकलने वाली गैसों या वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को कैसे पकड़ा जाए और इसके लिए कौन सी औद्योगिक प्रक्रिया इस्तेमाल की जाए। इस विषय पर पिछले अध्ययनों से आगे जाकर शोधकर्ताओं ने उन प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पकड़ी जाने वाली कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इसमें पता लगा कि गैस के उपयोग के हर तरीके से प्रति वर्ष करीब 0.5 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड का इस्तेमाल हो सकता है। एक गीगाटन एक अरब टन के बराबर होता है। सभी क्षेत्रों में संपूर्ण क्षमता का उपयोग होने पर 10 गीगाटन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग हो सकता है। प्रति टन कार्बन डाईऑक्साइड पर करीब 100 डॉलर की लागत आएगी।

कार्बन डाईऑक्साइड के उपयोग की लागत हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग हो सकती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एमिली कार्टर ने कहा कि हमारे विश्लेषण से साफ है कि कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने का समाधान हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब सभी सरकारें इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाएं, नीतियों में बदलाव करें, आवश्यक धन मुहैया कराएं और विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें तत्काल कार्य करने की दरकार है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल के अनुसार 21वीं सदी के शेष वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वायुमंडल से करीब 100 से 1,000 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड हटाने की आवश्यकता पड़ेगी।

इस समय जीवाश्म कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष करीब एक प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जो 2018 में 37 गीगाटन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने और जलवायु को स्थिर करने के लिए ग्रीनहाउस गैस को हटाना बेहद आवश्यक है। उनका कहना है कि हमने अभी तक अपने उत्सर्जनों को कम करने में तत्परता नहीं दिखाई है, अतः हमें जल्द ही वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को खींचना शुरू करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी कवायद की सफलता उद्योगों के रुख पर निर्भर करेगी।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

धींगामुश्ती में पार्टी का नुकसान

आजादी के बाद लंबे अरसे तक देश की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी में सत्ता से बाहर होने और देश में सिमटते जनाधार के बावजूद नेताओं की आपसी खींचतान कम नहीं हो रही है। जनता के बीच पार्टी के प्रति भरोसा कायम करने के लिए मिलजुलकर काम करने के बजाय नेता आज भी सिर्फ अपनी छवि को ही लेकर ज्यादा चिंतित दिखते हैं। राजस्थान में यह खींचतान बहुत ही स्पष्ट दिखती है जहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। प्रदेश में भविष्य की राजनीति को लेकर चिंतित दोनों ही नेताओं की कोशिश एक दूसरे से बड़ी लकीर खींचने की रहती है। हालांकि इसमें भी शह-मात का खेल जारी रहता है। कभी बाजी मुखिया के हाथ में तो कभी उनके नायब के हाथ लगती है, मगर इससे पार्टी का बंटाधार जरूर हो रहा है।

अपनों की नाराजगी

रेलवे में यूनियन नेताओं के पर कतरने के प्रयास कई वर्षों से चल रहे हैं। कई नेताओं के पर कतरे भी जा चुके हैं, परंतु हाल में हुई 'परिवर्तन संगोष्ठी' में जिस तरह रेलवे के 50 हजार यूनियन नेताओं की सुविधाएं कम करने अथवा वीआरएस देने का मुद्दा उठा, उससे रेलवे की तमाम यूनियनों के पदाधिकारियों को सांप सूंघा हुआ है। इन यूनियनों के नेता सार्वजनिक मंचों पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं, बड़ी-बड़ी प्रेस रिलीज जारी कर चक्का जाम की धमकी देते हैं, लेकिन दो-चार जगहों पर धरना-प्रदर्शन से आगे इनका विरोध नहीं बढ़ता। ऐसे में यूनियनों के प्रति रेलकर्मियों का मोह भंग होता जा रहा है और वे खुलकर अपना असंतोष जताने लगे हैं। इसे सोशल मीडिया पर बखूबी देखा जा सकता है जहां रेलकर्मी अक्सर यूनियन नेताओं का मजाक उड़ाते देखे जा सकते हैं। इनकी टिप्पणियों का लब्बोलुआब ये है कि एक वह दौर था जब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता रेलवे यूनियन के मुखिया थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया था, परंतु इस समय दोनों प्रमुख यूनियनों की कमान ऐसे पदाधिकारियों के हाथों में हैं जो हवाई बातों के अलावा कुछ नहीं करते। सरकार एक-एक करके कथित रूप से कर्मचारी विरोधी फैसले लेती जा रही है, परंतु ये पदाधिकारी चुप बैठे हैं। इन उम्रदराज और सुविधाभागी नेताओं में जोखिम लेने का साहस नहीं बचा है। लिहाजा यूनियनों की कमान अब युवा पदाधिकारियों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। सरकार और कर्मचारी दोनों के ऐसे तेवरों को भांपने के बाद यूनियन नेताओं की तंद्रा भंग हुई है और अब वे सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने की बात करने लगे हैं। अब देखना यही होगा कि इसमें वे कितनी धार दिखा पाते हैं।

हिमाचली कनेक्शन

नेताओं में वैचारिक मतभेद चाहे जितने अधिक हों, लेकिन अक्सर वे अपने आपसी रिश्तों की कड़ियां जोड़ने से नहीं चूकते। हाल में संसद सत्र के दौरान इसकी मिसाल देखने को मिली। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष-प्रतिपक्ष में बेहद गहमागहमी का माहौल बना हुआ था तब भी कांग्रेस के आनंद शर्मा और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हिमाचली कनेक्ट को सार्वजनिक करना नहीं भूले। चर्चा में आनंद शर्मा पहले बोले और उनके ठीक बाद नड्डा ने अपना भाषण दिया। नड्डा ने जब अपना भाषण खत्म कर लिया तो शर्मा ने खड़े होकर कहा कि यह संयोग ही है कि मेरे बाद नड्डा बोले और हम दोनों ही हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इस पर नड्डा भी अपनत्व दिखाने से नहीं चूके और बोले 'हम लोग एक यूनिवर्सिटी से भी हैं।'

अपनी फिक्र में लगे नेताजी

प्रधानमंत्री मोदी भले ही देश से वीआइपी कल्चर को खत्म करने में जुटे हों, लेकिन नेताओं की आदत में यह इतना रच बस गया है कि इससे वे इसके मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बीते दिनों संसद में दो ऐसे वाकये देखने को मिले। पहला मामला अपने लिए अलग से लेन की मांग से जुड़ा था जिस पर खूब चर्चा भी खूब हुई, लेकिन दूसरा मामला जो चर्चा में नहीं आया, वह अलग से कोर्ट के गठन को लेकर था। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नेताजी ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। उनका कहना था कि उन जैसे जनप्रतिनिधियों के मामलों का कोर्ट से जल्द निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर अलग कोर्ट गठित किया जाए। नेताजी जब यह मांग कर रहे थे तब उन्हें जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। या फिर वह जनता से एकदम कट चुके हैं। अन्यथा वह सभी के लिए कोर्ट बनाने की मांग करते। हालांकि उन्होंने जैसे ही मांग रखी, सदन में मौजूद साथियों के बीच उन्हें लेकर ही अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

28 मामलों में ही केवल अब तक दुष्कर्मियों को सुनाई जा सकी है सजा, पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में, पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) मध्य प्रदेश द्वारा हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार।

अनंत विजय

आजकल

साहित्य व सिनेमा की ओट में प्रपंच

नागरिकता संशोधन कानून के अस्तित्व में आने के बाद से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। साहित्य व सिनेमा जगत के भी कई लोग इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया है उस पर विचार करने की जरूरत है। एक मजेदार तथ्य यह भी है कि एक दौर में साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने की पेशकश कर चुके साहित्यकार अपने परिचय में इसे अब भी जरूर जोड़ते हैं

जाह्नू बरुआ

शिरीन दलवी

उदय प्रकाश

मंगलेश डबराल

एक फिल्मकार हैं जाह्नू बरुआ। वह असमिया में फिल्में बनाकर मशहूर हुए हैं। फिल्मों का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। तमाम सरकारी कमेटियों में उपस्थित रहते हैं। फिल्म आर्काइव से लेकर फिल्म हेरिटेज तक के प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविजन संस्थान से भी जुड़े रहे। केंद्र के अलावा राज्य सरकार की फिल्म नीतियां आदि से भी जुड़े रहते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे हैं। उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। जाह्नू बरुआ का ये परिचय इस वजह से ताकि पता चल सके के वह कितने प्रतिभाशाली हैं और लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि उनकी प्रतिभा किसी सरकार या किसी खास मंत्री की मोहताज नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार रहे वह समान रूप से मौजूद रहते हैं। कहना न होगा कि बरुआ में इतनी प्रतिभा है कि चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उनकी अहमियत बनी रहती है। हालांकि सिनेमा से जुड़े कई लोग उनकी इस प्रतिभा को जुगाड़ प्रतिभा भी कहते हैं, लेकिन अगर इसमें आंशिक सच्चाई भी है तो यह तो माना ही जा सकता है कि कम से कम इस तरह की प्रतिभा तो उनमें है कि वह खुद को अजातशत्रु बना चुके हैं।

पर इन दिनों बरुआ साहब मोदी सरकार से खफा हैं। उनकी नाराजगी की वजह है नागरिकता संशोधन कानून। वह इस कानून को असम की संस्कृति के खिलाफ मान रहे हैं, लिहाजा इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने असम फिल्म अवॉर्ड और असम सरकार के सहयोग से आयोजित फिल्म फेस्टिवल से अपनी फिल्म वापस लेने की घोषणा कर दी है। बरुआ की इस फिल्म- भोगा खिड़की (टूटी खिड़की) को मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। उनका गुस्सा और विरोध भी जायज हो सकता है, लेकिन अपने विरोध को जताते हुए उन्होंने जो कहा वो बेहद आपत्तिजनक है। बरुआ ने कहा कि राजनीति के लिए नेता उनकी 'मातृभूमि को निर्वस्त्र' कर रहे हैं। जब इतना प्रतिष्ठित कलाकार कुछ बोलता है तो उसको बेहद सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन कहा जाता है न कि क्रोध में विवेक समाप्त हो जाता है, बरुआ भी इसी दोष के शिकार हो गए और नेताओं को निशाने पर लेने के क्रोध में उन्होंने मातृभूमि को निर्वस्त्र करने जैसी उपमा का चयन कर लिया। इससे जाह्नू की पितृसत्तात्मक सोच का पता चलता है। विरोध के लिए वह किसी नारी के शरीर और उसको निर्वस्त्र करने की उपमा का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्या अभिव्यक्ति के लिए उनको कोई दूसरा शब्द नहीं मिला या यह मान लिया जाए कि उनकी मानसिकता क्रोध में सार्वजनिक हो गई है। अगर उनकी यही मानसिकता है तो उनकी तमाम कला पर उनके ये शब्द भारी पड़ रहे हैं। इससे तो ये भी साबित होता है कि एक संवेदनशील कलाकार की जो छवि उन्होंने गढ़ी वो वैसे हैं नहीं। अफसोस इस बात का है कि फिल्मों में नारी के चरित्र चित्रण को लेकर सवाल उठानेवाले सारे बयानवीर भी बरुआ के इन शब्दों पर खामोश हैं। दुख इस बात का भी है कि वे सारे कलाकार जिनको भारत में डर लगता है वे भी बरुआ के इस नारी विरोधी वक्तव्य पर खामोश हैं। लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बरुआ के इस बयान और फिल्म वापस लेने के फैसले पर सुर्खियां बनती हैं और मोदी सरकार को घेरने का एक मौका मिलता है कि देखो इतना बड़ा कलाकार भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है।

एक और उदाहरण देना चाहता हूं जिस पर देश का बौद्धिक वर्ग चुनी हुई चुप्पी का प्रदर्शन कर रहा है। वो भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध से ही जुड़ा हुआ है। एक उर्दू की लेखिका हैं शिरीन दलवी। इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। उनका मानना है कि यह कानून समाज के लिए विभाजनकारी है। उन्होंने अपने निर्णय की घोषणा के साथ-साथ अपने मित्रों को संदेश भी भेजा कि सीएए नहीं चलेगा। उनके निर्णय को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और समुदाय विशेष के पक्षकारों ने इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे किसी लेखक ने केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटा दिया हो, लेकिन ट्विटर पर ही यह बात भी साफ हो गई कि यह राज्य अकादमी का पुरस्कार था। यहां भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है उनको पुरस्कार मिला और अब वो उसको वापस करना चाहती हैं।

दरअसल पुरस्कार वापसी सिर्फ प्रचार हासिल करने का एक औजार है इससे कुछ होता नहीं है। वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी देश में सहिष्णुता के मुद्दे पर हिंदी के कई लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। हिंदी में पुरस्कार वापसी को सबसे पहले जादुई यथार्थवादी लेखक उदय प्रकाश ने शुरू किया था। तब उनको भारत में बहुत डर लग रहा था। अभी-अभी वाणी प्रकाशन से उदय प्रकाश की नई पुस्तक आई है- अम्बर में अबाबील। किताब को पलटते हुए मेरी नजर अंत में छपे उनके परिचय पर गई। वहां लिखा है- उदय प्रकाश को भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। देश और विदेश की लगभग समस्त भाषाओं में अनूदित और पुरस्कृत उनका साहित्य बदलते समय और यथार्थ का प्रामाणिक और साहसिक दस्तावेज है। साहित्य अकादमी, सार्क राइटर सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान आदि के अलावा उनकी रचनाओं के अनुवाद को भी कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। इस परिचय पर विचार कीजिए तो साफ हो जाता है कि अकादमी पुरस्कार लौटाना किसी विरोध का हिस्सा नहीं था। अगर होता तो वो आपके परिचय का हिस्सा नहीं होता। परिचय में सही लिखा है कि उदय प्रकाश के साहित्य में 'साहित्य के बदलते समय और यथार्थ का प्रामाणिक दस्तावेज' है। इससे ज्यादा बड़ा यथार्थ क्या हो सकता है जहां लेखक खुद को बेनकाब कर दे। उदय के इस परिचय में भी यही हुआ है।

यह सिर्फ उदय प्रकाश की ही बात नहीं है। एक और हिंदी के कवि हैं- मंगलेश डबराल। जब साहित्य अकादमी पर वामपंथियों का एकछत्र राज था तब इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह भी पुरस्कार वापसी का हिस्सा बने थे। अकादमी पुरस्कार लौटाकर उनको प्रचार मिला था, क्योंकि उन्हें पता था कि साहित्य अकादमी किसी भी कीमत पर एक बार दिए गए पुरस्कार की ना तो राशि स्वीकार कर सकती है और ना ही स्मृति चिन्ह आदि। इसकी पुष्टि कोर्ट ने भी की थी। यह सब जानते बूझते अकादमी पुरस्कार लौटाया गया था। बाद में मंगलेश जब भी मंच पर जाते रहे उनका परिचय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक के तौर पर दिया जाता रहा और वो वहां खुश होते रहे। एक बार भी उन्होंने टोकने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटा दिया है लिहाजा उनके परिचय में यह नहीं कहा जाए। अशोक वाजपेयी के साथ भी यही हो रहा है। जिन भी लेखकों ने पुरस्कार लौटाए, लगभग वो सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार को अपने सर पर कलगी की तरह लगाए घूम रहे हैं, लेकिन उस वक्त शहीद होने का जैसा प्रपंच करके पर्याप्त यश लूटा था, तो साहित्य पुरस्कार वापसी आदि को लेकर अब कोई स्पंदन हो नहीं पाता है।

दरअसल अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो एक बात और निकल कर आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की वजह भी समझ में नहीं आ रही है। ना तो जाह्नू बरुआ और ना ही शिरीन दलवी अपने विरोध की वजह साफ कर पा रही हैं। जाह्नू का कहना है कि ये उनकी मातृभूमि को निर्वस्त्र करने की कोशिश है, पर जब उनसे पूछा गया कि कैसे तो वो कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाए।

लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक है, लेकिन विरोध साहित्य, सिनेमा और कला की ओट में होता है तो आपकी मंशा साफ होती है और फिर वो विरोध का प्रपंच हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि जो साहित्य और कला जगत विरोध की भूमि बनती है, वो ऐसे प्रपंचों को बेनकाब करने की भूमि भी बने ताकि उसकी प्रतिष्ठा और लोगों का उसमें भरोसा कायम रह सके।

फिर से

आग से क्यों-कैसे होती है मौत

देश भर में वर्ष 2011 से 2015 के बीच आग लगने की वजह से 1.13 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसका मतलब रोजाना 48 लोगों ने अपनी जान आग की घटनाओं में गंवाई। मालूम हो कि अधिकतर घटनाओं में आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को बताया गया। जब भी आग लगने की वजह से मौत की बात होती है तो दो बातें सामने आती हैं। एक जलने से और दूसरा दम घुटने की वजह से। जलने से मौत होने में शरीर की त्वचा, रक्त और अंग आग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में अगर शरीर का बड़ा हिस्सा जल जाए तो मौत की आशंका होती है। दूसरा कारण दम घुटने की वजह से मौत का होता है। दम घुटने का मतलब जरूरी नहीं कि इंसान के शरीर में धुआं जाए तभी उसकी मौत हो। दम घुटने के कारण दूसरे भी हो सकते हैं। दम घुटने की वजह से तुरंत मौत हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आप किसी इमारत में हैं और इमारत के किसी दूसरे हिस्से में आग लगी है तब भी आप दम घुटने के शिकार हो सकते हैं।

सामान्य परिस्थितियों में हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाईऑक्साइड बाहर निकालता है। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और दूसरी गैसें भी सांस में जाती हैं, लेकिन वो सांस छोड़ने के साथ ही बाहर आ जाती हैं। शरीर में गई ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त के जरिये शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचती है। सांस लेने और छोड़ने का काम करने वाले सभी अंगों को मिलाकर श्वसन तंत्र कहा जाता है। जब कहीं आग लगती है तो बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है। धुएं की मात्रा और उसका जहरीलापन इस पर भी निर्भर करता है कि आग किस चीज में लगी है। इस धुएं का शरीर और श्वसन तंत्र पर चार तरह से असर होता है।

धुएं में मौजूद कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन जैसी दमघोंटू गैसें सांस में जाने वाली ऑक्सीजन की जगह शरीर में जाने लगती हैं। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। फेफड़े ऑक्सीजन की जगह आ रही इन गैसों को खून में पहुंचाने लगते हैं। इन गैसों के शरीर में पहुंचने से कोशिकाएं मरने लगती हैं और इंसान की मौत हो जाती है।

धुएं में मिलने वाली जहरीली गैसें शरीर में अंदर पहुंचने पर कई रासायनिक क्रियाएं करती हैं। इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और फार्मएल्डिहायड जैसे घातक कारक शरीर में बन जाते हैं। ये कारक श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही इनसे आंखों और श्वसन तंत्र को सीधा नुकसान होता है।

आग लगने पर आसपास के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। जब यह तापमान मनुष्य की त्वचा द्वारा बर्दाश्त किए जा सकने वाले तापमान की मात्रा से ज्यादा पहुंच जाता है तो शरीर की कोशिकाएं

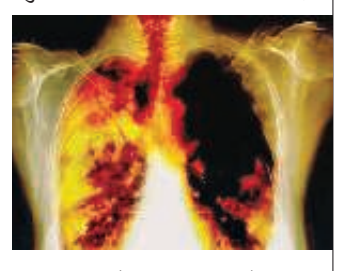

जलने लगती हैं। इससे त्वचा और फिर भीतरी शारीरिक अंग जलने लगते हैं। शरीर के परिचालन में सबसे जरूरी अंग जब आग की चपेट में आ जाते हैं तो मौत होना स्वभाविक है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ऐसे में जब किसी बंद जगह में आग लगती है तो आग वहां मौजूद सारी ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है। ऐसे में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाईऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें ले लेती हैं जो जानलेवा हैं।

कुछ पदार्थों में आग लगने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड भी बनते हैं। ये दोनों तत्व सबसे जहरीले होते हैं। जब सांस के जरिये ये दोनों कारक फेफड़ों में जाते हैं तो श्वसन तंत्र के साथ-साथ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। ये दोनों तत्व कोशिकाओं को तेजी से मारते हैं। अगर धुएं में ये दोनों कारक मौजूद होते हैं तो मौत निश्चित है।

(डीडब्ल्यू से संपादित अंश, साभार)

ट्वीट-ट्वीट

क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी खतरे में है? एक ओर राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि वह सावरकर की तरह नहीं हैं जो माफी मांग लें। इस पर संजय राउत का कहना है कि हम पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं तो कोई सावरकर का भी अपमान न करे।

संजय बरागटा@SanjayBragta

सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद संजय राउत की प्रतिक्रिया सिर्फ चेहरा बचाने की कवायद भर लगती है। जो पार्टी हाल में यह दर्शा चुकी हो कि उसके लिए विचारधारा के क्या मायने हैं, तो उससे इससे ज्यादा की उम्मीद रखना भी बेमानी होगा।

शिव अरूर@ShivAroor

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोग समझ लें कि दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर वे कुछ हासिल नहीं कर सकते। उन्हें धर्म को पीछे छोड़कर खुद को शिक्षित बनाना होगा ताकि वे वैज्ञानिक, कलाकार और मानवतावादी बनकर अन्य लोगों से भी प्रतिष्ठा अर्जित कर सकें।

तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

आखिरकार कुछ अवैध घुसपैठियों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात की कीमत अन्य नागरिकों को क्यों चुकानी चाहिए? कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है और उन्हें इसके लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

रचनाकर्म

सुरीले संसार के मिथक तोड़ती किताब

मालिनी अवस्थी

यह पुस्तक शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के बीच विभेद के प्रचलित भ्रमों को तोड़ती है...

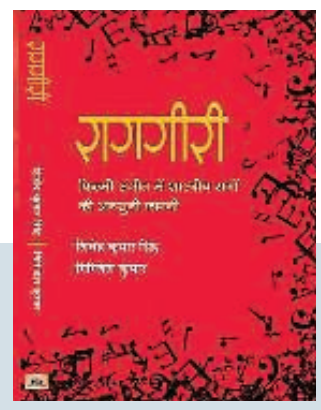

पुस्तक : रागगीरी
लेखकद्वय : शिवेंद्र कुमार सिंह व गिरिजेश कुमार
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 450 रुपये

'रागगीरी' के लेखक शिवेंद्र कुमार सिंह और गिरिजेश कुमार ने दरअसल एक विचार को पुस्तक का आकार दिया है। 'रागगीरी' के जरिये लेखकद्वय पिछले कई वर्षों से शास्त्रीय संगीत को सरल तरीके से आमजन, खास तौर पर बच्चों में ले जा रहे हैं। इस पुस्तक का स्वरूप भी ऐसा ही है, जिसमें 60 से ज्यादा प्रचलित शास्त्रीय रागों पर काम किया गया है। किसी एक शास्त्रीय राग की जमीन पर बने फिल्मी गाने के बनने की कहानी की दिलचस्प कहानी से हर अध्याय शुरू होता है, जो खत्म होता है शास्त्रीय संगीत के शुद्ध व्याकरण की जानकारी के साथ। राग क्या होता है? राग कैसे बनता है? कैसे पहचाना जाता है? कैसे गाया-बजाया जाता है? कुल कितने राग होते हैं? क्या सभी गीत किसी न किसी राग में होते हैं? क्या जितना भी संगीत है, सब रागों से ही बना है? क्या सचमुच राग गाने से दीपक जल जाते हैं, बारिश हो जाती है? ऐसे अनगिनत सवाल अक्सर पूछे जाते हैं।

सच्चाई यह है कि रागों की दुनिया से परिचित होने के लिए गुरु से ज्ञान लेना होता है, अध्ययन और अभ्यास करना होता है। ऐसी ढेरों किताबें बाजार में मौजूद हैं, जिनमें राग परिचय मिल जाएगा, बंदिशें मिल जाएंगी, यहां तक कि फिल्मी गानों की स्वर-लिपि भी मिल जाएगी, लेकिन अगर एक ही किताब में राग से जुड़े दिलचस्प किस्से हों, उस राग पर आधारित गीतों की फेहरिस्त हो, राग के आरोह-अवरोह और तमाम विशेषताओं का वर्णन हो, यह सुझाव भी हो कि इस राग का आनंद लेने के लिए आप कौन-सी रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह किताब गागर में सागर से कम नहीं।

जिस तरह हर इंसान एक ही ईश्वर की रचना है, उसी तरह हर तरह संगीत भी उन्हीं 12 स्वरों की उपज है। इसके बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन देखा जाए तो समाज की तरह संगीत में भी एक किस्म का वर्ग-भेद देखने को मिलता है। शास्त्रीय संगीत सर्वश्रेष्ठ, फिर उपशास्त्रीय, ठुमरी, भजन, गजल, फिल्मी, लोकगीत, रॉक, पॉप वगैरह। हो सकता है कि इस क्रम पर सभी सहमत न हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के बीच एक अभिजात्य का अंतर हमेशा देखा गया है। शास्त्रीय संगीत को अगर बौद्धिक वर्ग से जोड़कर देखा जाता है तो फिल्मी संगीत को सबका व सबके लिए माना गया है। ऐसे में यह किताब पढ़ते हुए एक आम पाठक को यह अनुभूति भी होगी कि शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत की दुनिया कैसे उन्हीं स्वरों के ताने-बाने से आपस में जुड़ी हुई है।

हिंदुस्तान में संगीत के जितने भी रूप हैं, उनमें फिल्म संगीत जैसा लोकप्रिय शायद ही कोई हो। इसलिए बेहद मशहूर फिल्मी गीतों का सिरा पकड़कर शास्त्रीय राग की बारीकियों की जानकारी देना अपने आप में विलक्षण है और दिलचस्प भी। जब मैंने शास्त्रीय संगीत अपने गुरुओं से सीखना शुरू किया, वह समय ऐसा था, जब रेडियो और गुरु की शिक्षा साथ ही चलती थी। फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों साथ चलते रहे। मैं सोचती थी कि जो बंदिशें मैंने गुरुओं से सुनीं वे फिल्मों में भी जाती हैं। लोग कहते रहे हैं कि फिल्मों और शास्त्रीय संगीत में एक ऐसी खाई है, जिसे कोई पाट नहीं सकता। यह बात मुझे विचलित करती थी। संगीत तो संगीत है। ऐसी भी बातें सुनते हैं, जहां बिस्मिल्लाह खान साहब ने जितने अमर गाने हैं, उनमें शहनाई बजाई। हरि जी ने, शिव जी ने, पंडित राम नारायण जी ने सबने फिल्मों में बजाया है। यानी कि कलाकारों के मन में खाई नहीं थी। समाज ने पूर्वाग्रह बना दिया था कि यह शास्त्रीय संगीत है, तो फिल्म में कोई भी कुछ भी कैसे भी गा सकता है। फिल्म संगीत की कला का आदर करना होगा। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर तो ऐसे थे, जो राग को बड़े सम्मानपूर्वक निर्वाह करते थे। जिनमें नौशाद साहब, गुलाम मुहम्मद साहब, मदन मोहन साहब, सलिल चौधरी साहब, जो कि फ्यूजन करते थे। सलिल चौधरी साहब ने वेस्टर्न का खूब फ्यूजन किया है। मैं बहुत खुश हूं कि यह किताब कहीं न कहीं उसी खाई को पाटेगी। यह किताब बहुत सारे उन भ्रमों को दूर करेगी, जो संगीत की दुनिया में प्रचलित हैं।

व्यंग्य के तीरों से विसंगतियों का शिकार

कन्हैया झा

'जब भी कवि कालिदास का जिक्र आता है, एक घटना जरूर सुनाई जाती है कि उन्होंने एक अंगुली दिखाई तो विद्योत्तमा ने यह व्याख्या की, जब मुक्का दिखाया तब उन्होंने वह बताया। यह केवल एक घटना नहीं है, इसमें पूरी सृष्टि का सार छिपा है। एक दर्शन है, जो बताता है कि हमें जो बूझा हमको वही सूझा, और वही हमने औरों को भी सुझवाया। लोकतंत्र के संदर्भ में भी यह लागू होता है। जैसे हाईकमान ने कुछ अबूझ-सा कहा। बस पार्टीजनों ने व्याख्याएं शुरू कर दीं। विपक्षियों ने हमले तेज किए। जनता कभी इधर देखे, कभी उधर। यह हुनर कमाल का है। चुनाव हुए। कोई जीता, कोई हारा। इसके बाद मतलब की खेती शुरू। हर दल में अनेक कालिदास हैं व अगणित विद्योत्तमा।' व्यंग्यकार व आलोचक रहे सुशील सिद्धार्थ ने अपने व्यंग्य संग्रह 'आखेट' में उपरोक्त पंक्तियों में सामाजिक-राजनीतिक तथ्यों की वास्तविकता को सरल शब्दों में रेखांकित करने का प्रयास किया है।

हालांकि सुशील सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे, पर हिंदी व्यंग्य परंपरा में वे अपना नाम जरूर दर्ज करा गए। यह व्यंग्य संग्रह पाठकों को ताजा हवा का झोंका जैसा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने बेहद सरल शब्दों में इसे लिखा है। 'भूख और भूख' में इन्होंने व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है, तो आजकल मनाए जाने वाले 'चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे' आदि जैसे तमाम दिवसों पर 'वेलेंटाइन अठवारा प्रवचन' में नए दृष्टांत दिए हैं।

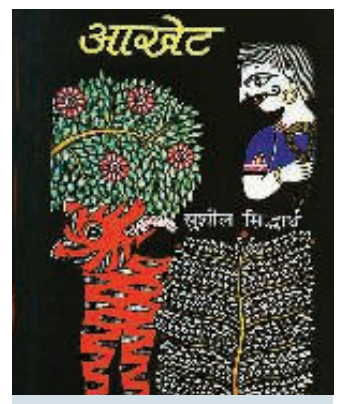

पुस्तक : आखेट
लेखक : सुशील सिद्धार्थ
प्रकाशक : किताबघर प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 450 रुपये

'भिखारीदास से भिखारी प्रसाद' में उन्होंने आज के कटु सत्य को उजागर किया है, 'लोकतंत्र में भिक्षुक होना एक योग्यता है। नेता वोट की भीख मांगता है। जनता जान की भीख मांगती है। कुछ सामाजिक उदाहरण भी शानदार हैं। माता-पिता पहले भगवान से औलाद की भीख मांगते हैं। फिर पता नहीं कितनी औलादें, कितने भगवानों से माता-पिता को वापस बुला लेने की भीख मांगती हैं।'

विभिन्न विषयों पर पुस्तक में 41 व्यंग्य हैं। इस व्यंग्य संग्रह की एक बड़ी खासियत यह है कि लेखक ने इसे व्यंग्य की पारंपरिक शैली के बजाय एक अलग अंदाज में लिखा है, जिसे अधिकांश पाठक पसंद कर सकते हैं।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर के कुछ लोगों का विरोध उचित है?

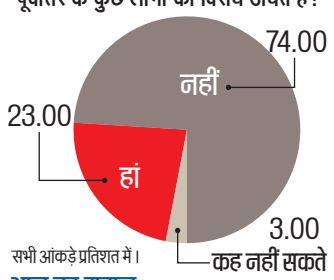

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या बोरिस जॉनसन की जीत से भारत-ब्रिटेन संबंध और मजबूत होंगे?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मुद्दा क्या है ना पता, नाहिं नफा-नुकसान,
आंदोलन कर हो रहे हैं फिर भी हलकान।
हैं फिर भी हलकान किसी ने जो भड़काया,
अपनी बुद्धि-दिमाग तनिक भी नहीं लगाया।
मुट्ठी बांधो बाद सोच लो पहले दद्दा,
बिला वजह ही 'कैब' बना भड़काऊ मुद्दा।

- ओमप्रकाश तिवारी

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

माफिया को कानूनी शिकंजे में लाने की तैयारी

मध्य प्रदेश को मिलावटखोरों, कालाबाजारियों, भूमि, रेत और शराब माफिया, हथियार तस्करों, नकली दवा माफिया और जमाखोरों से क्या मुक्ति मिलने वाली है? यह सवाल इन दिनों लगातार पूछा जा रहा है। सरकार कुछ बोले या नहीं, लेकिन लोग अब खुद ही प्रश्न पूछकर उत्तर भी दे रहे हैं। इस तर्क के साथ कि कमलनाथ सरकार के एक्शन-रिएक्शन में पहली बार सक्रियता है।

इंदौर के माफिया जीतू सोनी पर कार्रवाई के बाद अवैध धंधेबाजों में हड़कंप है। पुलिस- प्रशासन भी पिछले एक वर्ष में पहली बार उल्लेखनीय हरकत में दिखाई दे रहा है। यदि मुख्यमंत्री के इशारों को समझने की कोशिश करें तो भी कांग्रेस सरकार आने के बाद यह पहला अवसर होगा, जब पुलिस को फ्री-हैंड देने की बात कही जा रही है। इस बार इस सरकारी प्रस्ताव में थोड़ी गंभीरता इसलिए भी दिखाई दे रही है कि सरकार संगठित अपराध के खिलाफ कानून बनाने की बात भी कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ का मानना है- 'पुलिस को फ्री-हैंड दे दिया गया है, ताकि वह 'इधर-उधर' देखे बिना माफिया के खिलाफ सीधी कार्रवाई करे और संगठित अपराध करने वालों पर कहर बनकर टूट पड़े। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा न हो, सिर्फ खबरों की सुर्खियों में नहीं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई के परिणामों का प्रमाण-पत्र जनता से मिलना चाहिए। इंदौर का कारोबारी जीतू सोनी लंबे समय से लोगों की जमीन-जायदाद पर कब्जे और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा था। इसके बाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।'

बीते गुरुवार मुख्यमंत्री ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक में साफगोई से अपनी यह बात स्पष्ट कर दी। सरकार की इच्छाशक्ति को देखते हुए लग रहा है कि कानून के दायरे के बाहर काम कर रहे माफिया को अब कानून के शिकंजे में लाने की पूरी तैयारी हो रही है। सरकार अब कार्रवाई भी ऐसी करना चाहती है, जिसका संदेश प्रदेश के हर हिस्से तक जाए।

विशेष शाखा, विशेष कोर्ट : सरकार संगठित अपराध रोकने के लिए एक अलग शाखा तथा विशेष कोर्ट बनाने पर भी विचार कर रही है। योजना इस प्रकार बनाई जा रही है कि कपड़ों पर राजनीतिक बिल्ला देखकर कार्रवाई नहीं की जाए। शायद यही

वजह है कि अब मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) की तर्ज पर माफिया के खिलाफ कानून लाने की बात भी कही जा रही है। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में मकोका लाकर ही अंडरवर्ल्ड अपराध पर काबू पाया जा सका। दरअसल सरकार बनने के बाद से यह पहला मौका होगा, जब सरकार के इस कदम को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। पार्टी की खेमेबंदी, किसान कर्जमाफी को लेकर विपक्ष के हमले, तबादलों को उद्योग की संज्ञा जैसे कई आरोप हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस सरकार लगातार निशाने पर रही है। विपक्ष के हौसले इसलिए भी बुलंद रहे कि निर्दलियों और अल्पमत के समर्थन से चल रही सरकार को घेरना आसान था। इसी वजह से एक सोची-समझी रणनीति के तहत सरकार की नीति और नीयत पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। लेकिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने चुप्पी साध ली है।

दुष्कर्म के मामले बनाम सुधार की दरकार : निर्भया के जरिये देश-प्रदेश फिर गुस्से में है। दरिंदों को फांसी दिए जाने के सामूहिक स्वर में भी इस बार गहरा-गंभीर आग्रह है। असली-नकली मुठभेड़, फांसी, दया या पुनर्विचार याचिका पर देश भर में बहस चल ही रही है। ऐसे सभी घटनाक्रमों के बीच दुष्कर्म के मामलों के लिए सबसे ज्यादा कलंकित मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी सजा की मांग को लेकर बीते हफ्ते धरना दे चुके हैं। वे अपने ही कार्यकाल में देश में पहली बार बारह वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी देने का दंड विधेयक लेकर आए थे। लेकिन अब वे भी मान रहे हैं केवल कानूनी प्राविधान से ही हालात नहीं बदल सकते। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में दुष्कर्म के मामलों की पड़ताल करें तो पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) मध्य प्रदेश द्वारा इसी महीने जारी किए गए आंकड़ों को आधार बनाया जा सकता है। बीते दो वर्षों के 28 मामलों में दुष्कर्मियों को सजा सुनाई गई। सिर्फ वर्ष 2018 की बात करें तो दुष्कर्म कर हत्या के 19 मामले (इसमें 18 नाबालिगों के थे) सामने आए। सभी मामलों में फांसी की सजा दी गई है। लेकिन दुख और आश्चर्य का विषय यह है कि जब तक एक मामला हल होता है, तब तक कई मामले और दर्ज हो चुके होते हैं। मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर लगातार बहस होती रही है कि स्थानीय सामाजिक परिदृश्य को देखकर लगता नहीं है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या इतनी ज्यादा हो सकती है! तो क्या पुलिस में दर्ज होने वाले मामले झूठे हैं या फिर पुख्ता जांच के बगैर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं?

पुलिस रिफॉर्म के स्पेशल डीजी मैथिलीशरण गुप्त का मानना है- 'दुष्कर्म हो या अन्य अपराध, यदि आंकड़ों में हम आगे हैं तो यह उतनी चिंता का विषय नहीं है। दुष्कर्म जैसा अपराध रोकना है, तो सबसे पहले पुलिस को अपने भीतर सुधार करना होगा। यह पूरे विभाग के लिए चुनौती है कि कोई अपराधी कैसे उनकी नाक के नीचे इतना जघन्य अपराध कर सकता है? क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? दूसरा, सुधार न्यायिक प्रक्रिया में भी होना चाहिए। तकनीक के दौर में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि समन सीधे पुलिस-आरोपित सभी के मोबाइल पर पहुंचे। सौ फीसद तामिली हो। गवाह को कोर्ट क्यों आना पड़े? वे कियोस्क सेंटर्स की तरह गवाह सेंटर्स में जाकर कैमरे की निगरानी में बयान दर्ज करवा सकें। जब सिस्टम तेज होगा तो दो से तीन दिन के अंदर फैसले भी आने लगेंगे। सजा फांसी हो आजीवन कारावास, जल्दी होगी तो असर भी जल्दी और देर तक रहेगा।'

60 लाख रुपये में नीलाम हुई है एपल के दिवंगत को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की साइन की गई मैकिनटॉश फ्लॉपी। 1988 की बताई जा रही इस फ्लॉपी की कीमत का अनुमान शुरुआत में 5.35 लाख रुपये लगाया गया था।

50 पार भी शह और मात का आनंद

इनसे मिलिए

उमेश राजपूत, नई दिल्ली

शतरंज का नाम आते ही हर भारतीय के दिमाग में सबसे पहली छवि विश्वनाथन आनंद की ही उभर कर आती है। 'मद्रास टाइगर' और 'विशी' के नाम से मशहूर आनंद ना सिर्फ भारत के पहले ग्रैंडमास्टर हैं, बल्कि पांच बार के विश्व चैंपियन भी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आनंद और शतरंज एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही वजह है कि काले व सफेद मोहरों के इस खेल के सिवा आनंद को कुछ भाता भी नहीं है। आनंद ने बीते बुधवार (11 दिसंबर) को अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए। इस खेल के प्रति उनकी दीवानगी और जुनून का आलम यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी प्रतिस्पर्धियों को शह और मात देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।

पहली गुरु मां: 11 दिसंबर, 1969 को तमिलनाडु के छोटे से शहर मयिलाडुथराई में जन्मे आनंद के पिता कृष्णमूर्ति विश्वनाथन भारतीय रेलवे में कार्यरत थे, जबकि मां सुशीला गृहिणी थीं। हालांकि, मां को शतरंज का शौक था और आनंद को छह साल की उम्र में इस खेल का शुरुआती सबक उन्होंने ही सिखाया। जब आनंद आठ साल के थे तब उनके पिता तीन साल के लिए अनुबंध पर फिलीपींस रेलवे के काम से मनीला चले गए। आनंद और उनकी मां भी उनके साथ गईं। मनीला में आनंद को शतरंज की पेचीदगियां सीखने का सुनहरा मौका मिला। आनंद ने वहां शतरंज की कोचिंग लेनी शुरू की। इस दौरान उन्हें कोचिंग छोड़ने और वहां से लाने की जिम्मेदारी उनकी मां की होती थी।

जब टीवी कार्यक्रम वालों ने बुलाया: मनीला में टीवी पर शतरंज का एक कार्यक्रम आता था। घंटेभर के इस कार्यक्रम में शतरंज की बारीकियां बताई जाती थीं। कार्यक्रम के अंत में एक प्रतियोगिता होती थी। आनंद बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देखते थे और प्रतियोगिता में अपना जवाब भेजते और विजेता भी बनते। पुरस्कार में शतरंज की एक किताब मिलती थी। आनंद ने करीब आठ-नौ बार ऐसा किया। एक दिन उन्हें स्टूडियो से बुलावा आया। टीवी के लोग आनंद को अपनी लाइब्रेरी में ले गए और बोले, यहां से जितनी किताबें ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन कृपया आज के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे अलावा कोई और यह कार्यक्रम नहीं देखता है। आनंद से एक बार एक इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि यदि आप शतरंज के खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होते? इस पर आनंद कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, 'मैं इस बारे में सोच भी नहीं पाता हूं।'

18 साल की उम्र में बने ग्रैंडमास्टर: तीन साल मनीला में बिताने के बाद आनंद भारत लौटे तो चेन्नई में बस गए। यहीं उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ली और इसी दौरान वह जूनियर स्तर पर शतरंज में सफलता के झंडे गाड़ने लगे। 1984 में आनंद ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इंटरनेशनल मास्टर का नॉर्म हासिल किया। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बनने वाले वह सबसे युवा भारतीय थे। उन्होंने अगले साल अपना दूसरा इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया। 16 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। उन्होंने दो बार और यह खिताब जीता। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। 1988 में उन्हें 18 साल की उम्र में भारत का पहला ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल हुआ।

पांच बार विश्व चैंपियन: ग्रैंडमास्टर बनने के बाद से आनंद ने सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए और शतरंज की दुनिया में अपनी और भारत की धाक जमाते चले गए। 1988 में भारत का पहला ग्रैंडमास्टर बनना आनंद के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन 1991 में रेगिओ एमिलिआ टूर्नामेंट का खिताब जीतना उनके करियर का सबसे बड़ा लम्हा था। उन्होंने यहां काले मुहरों से खेलते हुए गैरी कास्परोव को हरा कर शतरंज की दुनिया को अपनी धमक दिखाई। आनंद पांच बार 2000, 2007, 2008, 2010, और 2012 में विश्व चैंपियन बने। 2000 में आनंद ने जब लातविया के एलेक्जेई शिरोव को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था तो वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके बाद आनंद ने 2007, 2008, 2010 और 2012 में लगातार चार बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

गिरावट का दौर: 2013 से विश्व स्तर पर आनंद के प्रदर्शन में गिरावट का दौर शुरू हुआ। 2013 व 2014 में उन्हें लगातार दो बार नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप में हार मिली। हालांकि, आनंद दूसरे प्रतिद्वंद्वियों को तो टक्कर दे रहे थे, लेकिन कार्लसन के खिलाफ उनकी बाजी सफल नहीं हो पा रही थी। आनंद दबाव के किस दौर से गुजरे इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल नवंबर में कोलकाता में हुए टाटा स्टील रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में ब्लिट्ज में बादशाह माने जाने वाले आनंद ने 15वें दौर में नीदरलैंड्स के अनीश गिरी से जीतने की स्थिति में पहुंच कर मैच गंवा दिया। तब उन्होंने हार के बाद कहा था, 'मुझे असफलता से कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं उम्मीदों के बोझ तले दबता जा रहा हूं। मैं आज यही कर रहा था। मैं खुद को लगातार मौके दे रहा था और फिर खुद को बर्बाद कर लिया। यह (अनीश के खिलाफ मुकाबला) ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। मैं जीत रहा था, लेकिन समय के बारे में भूल गया। अगर मैं यह मुकाबला जीत जाता तो दौड़ में बना रहता। मैं खुद का सबसे बड़ा दुश्मन हूं।'

वैसे तो विश्वनाथन आनंद आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन यह पल कुछ खास है। गत बुधवार को उन्होंने अपने जीवन के 50 बरस पूरे किए हैं और इसी के साथ शतरंज के इस सरताज की एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। इसलिए देश को शतरंज की दुनिया में पहचान दिलाने वाले इस खिलाड़ी के अब तक के सफर पर एक नजर तो बनती है...

गत 13 दिसंबर को चेन्नई में अपनी पुस्तक माइंड मास्टर के विमोचन अवसर पर शतरंज के सरताज विश्वनाथन आनंद। (फाइल फोटो) प्रेट्र

माइंड मास्टर

गत शुक्रवार को आनंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 'माइंड मास्टर' नामक किताब का विमोचन किया गया, जिसे इस दिग्गज खिलाड़ी ने खेल लेखिका सोसन नाइनन के साथ मिलकर लिखा है। इसमें आनंद ने कई खिलाड़ियों को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

आनंद से जुड़ीं पांच खास बातें

1. आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे। उसके बाद से भारत ने शतरंज में बहुत कुछ हासिल किया और आज भारत के पास कुल 65 ग्रैंडमास्टर हैं।
2. आनंद दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सभी प्रारूपों (नॉकआउट, राउंड रोबिन और मैच) में विश्व चैंपियनशिप जीती।
3. इन्होंने साल 2006 में 2800 रेटिंग अंक का जादुई आंकड़ा पार किया था। ऐसा करने वाले वह सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने थे। इसके साथ ही वह लगातार 21 महीने तक दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने रहे थे।
4. भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न पाने वाले आनंद पहले खिलाड़ी हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण से भी नवाजा जा चुका है।
5. आनंद भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम पर एक ग्रह (4538 विश्यानंद) का नाम रखा गया है।

पृथ्वी शॉ 2.0

मैन ऑफ द मोमेंट

निखिल शर्मा, नई दिल्ली

14 वर्ष की उम्र में 330 गेंदों में 546 रन की पारी। 85 चौके और पांच छक्के। ये आंकड़े बताते हैं कि मुंबई के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ कितने अनमोल खिलाड़ी हैं। 2018 में भारत की अंडर-19 टीम को विश्व कप खिताब दिलाना, आइपीएल में चयन और फिर पदार्पण टेस्ट में ही शतक। शॉ की जिंदगी में ये ऐसे लम्हे थे, जिन्होंने इस युवा बल्लेबाज की जिंदगी को बदलकर रख दिया और फिर इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद इस वर्ष डोपिंग में फंसना 20 वर्षीय पृथ्वी के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था, लेकिन पृथ्वी अनमोल हैं और परिपक्व भी। ऐसा उन्होंने दस महीने के प्रतिबंध के बाद मैदान पर वापसी करके दिखा दिया। यहीं से उनका 2.0 वर्जन भी सामने आया।

इंग्लैंड में संघर्ष भरे दिन: प्रतिबंध लगने के बाद पृथ्वी ना तो मैदान में जाकर अभ्यास कर सकते थे और ना ही किसी टीम में उनका चयन हो सकता था। यह दौर ऐसा था, जिसमें वह पूरी तरह से टूट गए थे। ऐसे में उन्होंने खुद को क्रिकेट से दूर और खुश रहने के लिए लंबा समय इंग्लैंड में बिताया। एक-एक दिन काटना पृथ्वी के लिए आसान नहीं था। मानसिक तौर पर यह खिलाड़ी कितना मजबूत है यह तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही टेस्ट में शतक लगाकर दिखा दिया था, लेकिन मुश्किल दौर में खुद को संभालना भी इतनी कम उम्र में कोई छोटी बात नहीं है।

सैयद मुश्ताक अली में दमदार प्रदर्शन: आखिरकार फिर वह समय आया जिसका पृथ्वी को बेसब्री से इंतजार था। 17 नवंबर, 2019 को पृथ्वी को सूरत में असम के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। पृथ्वी ने यहां सिर्फ 39 गेंद में 63 रन बनाकर दिखा दिया कि उनमें कितनी आग भरी हुई है। वह यहीं नहीं रुके, तमिलनाडु के खिलाफ 30 रन, झारखंड के खिलाफ 64 रन, कर्नाटक के खिलाफ 30 रन, पंजाब के खिलाफ 53 रनों की पारी खेलकर उन्होंने दिखा दिया कि वह अब थमने वाले नहीं हैं।

रणजी में लगा दिया दोहरा शतक: किसी भी खिलाड़ी के लिए दोहरा शतक खास अहसास होता है और वो भी तब जब वह बुरे दौर को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा हो। गत नौ दिसंबर से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी सत्र के पहले मैच में बड़ौदा के खिलाफ वडोदरा में पृथ्वी ने पहली पारी में 66 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में 202 रन बनाकर अपने मानसिक संतुलन की मजबूती का परिचय एक बार फिर दिया। 20 वर्ष की उम्र में इतना मजबूत मानसिक संतुलन दिखना बेहद बड़ी बात है।

अब टीम में वापसी के लिए जद्दोजहद: पृथ्वी के लिए पिछला वर्ष काफी खराब गया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद उनका चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुआ था, लेकिन फिर अभ्यास मैच में टखना मुड़ने के कारण सीरीज से बाहर हो गए और फिर उन्हें वापसी में काफी लंबा समय लग गया। आइपीएल में इस सत्र में 99 रन की पारी खेलकर उन्होंने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन पृथ्वी जानते थे कि टेस्ट टीम में वापसी अब इतनी आसान नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओपनिंग पर मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा अपनी जड़ मजबूत कर चुके हैं, जिसकी वजह से शिखर धवन, केएल राहुल और मुरली विजय जैसे बल्लेबाज अपनी जगह गंवा चुके हैं। पृथ्वी के सामने अब सुनहरा मौका है और चुनौती भी। अगर वह अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं तो न्यूजीलैंड दौरे पर तीसरे ओपनर के तौर पर उनका चुना जाना तय है।

किरन मोरे ने भी की तारीफ: पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरन मोरे ने भी पृथ्वी के शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी तारीफ की। मोरे ने कहा कि जब भी मैं पृथ्वी को देखता हूं तो मुझे युवा सचिन तेंदुलकर की याद आ जाती है। निडरता के साथ बल्लेबाजी करना दोनों को ही पसंद है। पृथ्वी, सचिन, ब्रायन लारा और वीरेंद्र सहवाग की तरह बेहद जल्दी गेंद की लाइन को भांप लेते हैं। मोरे ने आगे कहा कि पृथ्वी बिल्कुल परिपक्व खिलाड़ी हैं। साथ ही उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह 1990 के समय के दिग्गज गेंदबाजों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पिच उनके लिए मायने ही नहीं रखती है।

डोपिंग के कारण आठ महीने का प्रतिबंध झेलने के बाद मुंबई के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने जबरदस्त वापसी की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तीन अर्धशतक और रणजी में दोहरा शतक बताता है कि वह मानसिक रूप से कितने मजबूत खिलाड़ी हैं। जानते हैं 20 वर्षीय युवा क्रिकेटर के उतार-चढ़ाव से भरे अब तक के कॅरियर के बारे में...

मंगल पर पानी तलाशेंगे पढ़ाई से जी चुराने वाले अंशुमान

चर्चा में

मनोज उपाध्याय, गोपालगंज

इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं, जो बताते हैं कि बचपन में पढ़ाई में अरुचि रखने वाले व्यक्तियों ने बड़े होने पर कितने महान काम किए। गणित और विज्ञान की किताबों से जी चुराने वाले वैज्ञानिक बन गए। इस कड़ी में एक नाम बिहार के डॉ. अंशुमान भारद्वाज का भी जुड़ गया है। जिन्हें कभी डांटकर तो कभी दुलार कर पढ़ाई के लिए बैठाना पड़ता था, अब वह मंगल ग्रह पर शोध करने वाली यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टीम में शामिल किए गए हैं।

बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया प्रखंड के धरहरा मेला निवासी डॉ. अंशुमान भारद्वाज के माता-पिता दोनों शिक्षक हैं। मां डॉ. माया मिश्रा बताती हैं कि बचपन में अंशुमान बहुत नटखट था। पढ़ाई के लिए बैठाकर जाओ तो कुछ ही देर में दोस्तों के साथ खेलने के लिए भाग जाता था। कभी डांटकर तो कभी प्यार से किसी तरह पढ़ने को कहती थी। उनके पिता नरेंद्रधर द्विवेदी का कहना है कि पढ़ाई के प्रति उसकी अरुचि कक्षा आठ तक जारी रही, लेकिन नौवीं में पहुंचते ही उसका इंटरेस्ट जाग गया। अचानक अच्छे अंक लाने लगा। हां, ये सच है कि हम हमेशा उसकी हौसलाअफजाई करते थे और कम अंक आने पर कुछ बुरा-भला नहीं कहते थे, लेकिन नौवीं के बाद उसने अच्छे अंक लाने का जो सिलसिला शुरू किया फिर नहीं रुका। मां डॉ. माया बताती हैं कि उसके बाद कभी उसे पढ़ाई के लिए नहीं कहना पड़ा। मानो उसमें कुछ करने का जज्बा पैदा हो गया हो।

डॉ. अंशुमान का यह जज्बा ही उन्हें बिहार से पहले डीआरडीओ और फिर स्वीडन की लूलियॉ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ले गया, जहां वर्तमान में वह वायुमंडलीय अनुसंधान विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। बीते दिनों यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्श मिशन के तहत अगले साल मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले स्वीडन के हैबिट उपकरण की अनुसंधान टीम में उन्हें शामिल किया गया है। 15 वैज्ञानिकों के इस दल में डॉ. अंशुमान अकेले भारतीय और सबसे युवा हैं। यह टीम हैबिट उपकरण के माध्यम से मंगल ग्रह पर जल अपने तरल रूप में रह सकता है या नहीं, इस पर शोध करेगी। डॉ. अंशुमान बताते हैं अगर हैबिट उपकरण के माध्यम से वहां पानी को तरल रूप रखने का मिशन सफल रहा तो भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन का सपना सच हो सकता है। तरल अवस्था में पानी की उपस्थिति को मंगल पर सूक्ष्म जीवन की संभावना से भी जोड़ा जा रहा है। डॉ. अंशुमान की छोटी बहन आकांक्षा बीएचयू में शोध छात्रा हैं। भाई की उपलब्धि पर वह भी फूले नहीं समा रहीं।

डीआरडीओ में कर चुके हैं काम: डॉ. अंशुमान भारद्वाज की स्कूली शिक्षा बेतिया के जवाहर नवोदय विद्यालय वृंदावन में हुई। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से बायो मेडिकल से स्नातक तथा शोध किया। शोध पूरा होने के बाद इनका चयन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में हुआ। डेढ़ साल डीआरडीओ में काम करने के बाद स्वीडन की लूलियॉ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सेवाएं देने लगे। वह रिमोट सेंसिंग तथा ग्लासिओ हाइड्रोलोजिकल साइंस के भी विशेषज्ञ हैं। रिमोट सेंसिंग बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन तथा फील्ड डाटा कलेक्शन में प्रशिक्षित हैं। अपने अब तक के जीवन में मिली उपलब्धियों को वह अभिभावकों को समर्पित करते हुए कहते हैं कि माता-पिता के शिक्षक होने के कारण बचपन से ही सही मार्गदर्शन मिला।

डॉ. अंशुमान भारद्वाज के माता-पिता ने बचपन में उनकी पढ़ाई के प्रति अरुचि को देखते हुए शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा मंगल ग्रह पर खोज करने वाले वैज्ञानिकों के दल में शामिल होगा, लेकिन आज यह अनदेखा सपना सच होने जा रहा है। वर्तमान में स्वीडन की लूलियॉ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर सेवाएं दे रहे डॉ. अंशुमान को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उस दल में शामिल किया है, जो लाल ग्रह पर पानी तलाशेगा...

डॉ. अंशुमान भारद्वाज फाइल

कृत्रिम चांद का विचार कितना सही

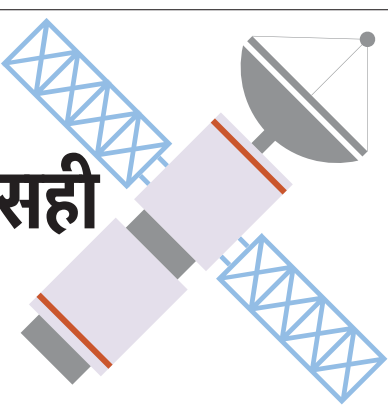

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली: 2018 में चीन ने पहली बार कृत्रिम चांद का विचार प्रस्तुत करते हुए दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। चीन के वैज्ञानिक वू चुनफेंग ने बताया था कि जल्द ही चेंगदू शहर के पास अपना चांद होगा, जिसके बाद वहां स्ट्रीटलाइटों की जरूरत नहीं होगी। अब यह बात सामने आ रही है कि इस योजना के तहत चीन अपना पहला उपग्रह 2020 में लांच कर सकता है। 2022 तक तीन और उपग्रह लांच किए जाएंगे, जिसके बाद यह विचार वास्तविकता का रूप ले लेगा। ऐसे में यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि विज्ञान को कुदरत पर हावी करते हुए चीन की कृत्रिम चांद की यह योजना कितनी सही है? जानते हैं, कैसे काम करेगी यह योजना और इससे क्या लाभ व नुकसान होंगे...

इस तरह करेगा काम

चीन के इस कृत्रिम चांद की सतह आईने की तरह होगी, जिससे यह सूरज की रोशनी को धरती की ओर मोड़ा जा सकेगा। चीन की योजना के मुताबिक, कृत्रिम चांद 10 से 80 किमी की परिधि में रोशनी कर सकेगा। इसके रोशनी असली चांद की तुलना में आठ गुना अधिक होगी।

यह होगा लाभ

इस विचार के पक्षधर वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि कृत्रिम चांद से स्ट्रीटलाइटों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरा लाभ आपदा के समय होगा। आपदा के दौरान जब किसी स्थान की बिजली चली जाएगी तो इसकी मदद से उस स्थान तक प्रकाश पहुंचाया जा सकेगा।

प्रकाश प्रदूषण का क्या

वर्तमान में प्रकाश प्रदूषण तेजी से बढ़ती समस्या है। रात में भी घरों, इमारतों में लाइट्स के जलने से सिर्फ लोग ही नहीं, उन घरों के बाहर मौजूद पशु, पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। चीन की कृत्रिम चांद योजना की खिलाफत करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा असर न केवल इंसानों, बल्कि पशु-पक्षियों के शरीर की आंतरिक घड़ी (सर्कडीअन) पर पड़ेगा।

क्या हैं अड़चनें

संभावना जताई जा रही है कि कृत्रिम चांद को पृथ्वी और अंरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आइएसएस) के बीच में स्थापित किया जाएगा। सबसे पहली अड़चन इसके आकार को लेकर बताई जा रही है। फुटबॉल के आकार के आइएसएस को तीन टुकड़ों में लांच करके अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। चीन का यह कृत्रिम चांद आइएसएस से भी बड़ा होगा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इसे स्थापित करने की होगी। दूसरी बड़ी चुनौती इसकी रफ्तार की होगी। इसे पृथ्वी पर गिरने से रोकने के लिए जरूरी है कि यह 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता रहे। ऐसे में ईंधन का खर्च भी विचार का विषय है।

दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी एशिया महाद्वीप के देशों की है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट भविष्य की तस्वीर इससे उलट रूप में प्रस्तुत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2100 तक सर्वाधिक आबादी वाले देश एशिया नहीं, बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप में होंगे। अभी दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से पांच एशिया में हैं, दो दक्षिण अमेरिका में और एक-एक उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप में हैं।

अफ्रीका में होंगे सर्वाधिक आबादी वाले देश

शीर्ष 10 में होंगे पांच अफ्रीकी देश

मौजूदा समय में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, लेकिन 2100 तक कई देशों को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीकी देश कांगो, इथियोपिया, तंजानिया, नाइजीरिया और मिस्र शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएंगे।

एशिया की स्थिति

आंकड़ों के मुताबिक, कम दर से कुछ एशियाई देशों की आबादी बढ़ती रहेगी। वहीं, चीन और बांग्लादेश की आबादी कम होने की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है।

भारत होगा सर्वाधिक आबादी वाला देश

संयुक्त राष्ट्र की ही द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉसपेक्ट्स 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2050 तक 27.30 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे। अभी भारत की आबादी करीब 137 करोड़ है। वहीं, चीन की जनसंख्या 143 करोड़ है। चीन में दुनिया की 19 और भारत में 18 फीसद आबादी रहती है। 32.90 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका तीसरे और 27.10 करोड़ के इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी में 200 करोड़ का इजाफा होगा और कुल आबादी बढ़कर 970 करोड़ हो जाएगी।

धरती पर सर्वाधिक आबादी वाले देश

एशिया | यूरोप | अफ्रीका | द. अमेरिका | उ. अमेरिका

1950 देश	(आबादी करोड़ में)	2020 देश	(आबादी करोड़ में)	2100 देश	(आबादी करोड़ में)
चीन	55.4	चीन	1.43 अरब	भारत	1.45 अरब
भारत	37.6	भारत	1.38 अरब	चीन	1.06 अरब
अमेरिका	15.9	अमेरिका	33.1	नाइजीरिया	73.3
रूस	10.3	इंडोनेशिया	27.4	अमेरिका	43.4
जापान	8.3	पाकिस्तान	22.1	पाकिस्तान	40.3
जर्मनी	7	ब्राजील	21.3	कांगो	36.2
इंडोनेशिया	7	नाइजीरिया	20.6	इंडोनेशिया	32.1
ब्राजील	5	बांग्लादेश	16.5	इथियोपिया	29.4
ब्रिटेन	5	रूस	14.6	तंजानिया	28.6
इटली	4.7	मेक्सिको	12.9	मिस्र	22.5

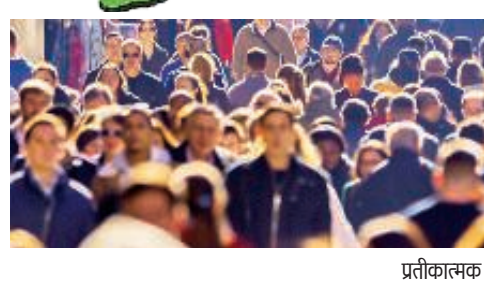

प्रतीकात्मक

सूची से गायब हो जाएंगे यूरोपीय देश

1950 में दस में से चार सर्वाधिक आबादी वाले देश यूरोप के थे। यह संख्या 2020 में घटकर एक रह जाएगी और 2100 तक इस सूची में यूरोप का एक भी देश नहीं रहेगा।

कम हो रही बच्चों की संख्या

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दुनियाभर में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पहले से कम हो रही है, लेकिन मौजूदा समय में प्रति महिला 2.5 बच्चे पैदा होने के साथ दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर वैश्विक प्रजनन दर मौजूदा दर पर गिरती रही, तो यह 2100 में प्रति महिला 1.9 बच्चों तक पहुंच जाएगी।

9.57 लाख रीट्वीट के साथ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड एग' वर्ष 2019 में सर्वाधिक रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट बन गया है। ट्विटर के मुताबिक, गेम्स ऑफ थ्रोंस सर्वाधिक ट्वीट किया गया शो रहा, जबकि फिल्मों में सबसे ज्यादा ट्वीट द एवेंजर्स : एंडगेम के लिए किए गए।

सुबह-ए-बनारस और गंगा आरती का दीदार करा रहा 'डिंगी'

डिंगी एप के संस्थापक, आइआइटी बीएचयू के पूर्व छात्र कपिल चावला। जागरण

हिमांशु अस्थाना, वाराणसी

दशाश्वमेध घाट पर खाली बैठे नाविक काशी साहनी के स्मार्टफोन पर डिंगी एप का अलर्ट आया कि कल उन्हें नीदरलैंड्स से आए ड्योडेट व सैरा पर्लीजिन नामक पर्यटकों को नौका विहार कराना है। एप कंपनी के एजेंट ने उन्हें फोन भी किया कि इन पर्यटकों को राजघाट से लेकर अस्सी घाट तक नौका विहार कराने के साथ ही दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी दिखानी है। साथ ही नाव पर ही पारंपरिक नाश्ते आदि का इंतजाम करना है, थोड़ी सजावट भी रहे तो बेहतर होगा। फिर क्या, काशी अपने मेहमानों को नौका विहार कराने की तैयारी में जुट गए।

अब अस्सी घाट का रुख करते हैं। यहां मौजूद नाविक अंगद साहनी के मोबाइल पर भी इसी तरह का मैसेज आया है। उन्हें अमेरिका से आने वाले एक पर्यटक को जनवरी के पहले सप्ताह में नौका विहार कराना है। अंगद इस पर्यटक को राजघाट से लेकर रामनगर किले तक नौका विहार कराएंगे। आइआइटी बीएचयू के पूर्व छात्र का स्टार्टअप 'डिंगी एप' इन दिनों काशी में चर्चा में है। देश-विदेश के सैलानियों को यहां गंगा में नौका विहार के लिए जहां बुकिंग का आसान प्लेटफार्म मुहैया हो गया है, वहीं स्थानीय नाविकों को बेहतर रोजगार।

डिंगी एप नामक स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले आइआइटी बीएचयू के पूर्व छात्र कपिल चावला बताते हैं कि काशी में पर्यटकों की आमद और गंगादर्शन को लेकर खास दिलचस्पी के ट्रेंड ने उन्हें इस स्टार्टअप का आइडिया दिया। कहते हैं, हालांकि इस बिजनेस में और भी खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमने स्थानीय नाविकों को साथ जोड़कर कुछ अलग और बेहतर करने का प्रयास किया है।

स्थानीय लोगों को भी पसंद आ रही यह सुविधा : इस सर्विस को न केवल टूरिस्ट बल्कि स्थानीय लोग भी बेहद पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे इसका किफायती किराया और बेहतरीन सर्विस है। कपिल बताते हैं कि पर्यटकों को अगर विकसित देशों जैसी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो उनकी काशी यात्रा बेहद खास हो जाती है। हमारा प्रयास यही होता है कि हम बुकिंग से लेकर सेवा प्रदान करने तक, पर्यटकों को उच्चस्तरीय सर्विस देकर उनकी यात्रा को यादगार बना सकें।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

रविवार विशेष

- काशी में नौका विहार हुआ किफायती और सुविधाजनक
- आइआइटी बीएचयू के पूर्व छात्र के स्टार्टअप से स्थानीय नाविकों को भी मिल रहा बेहतर रोजगार
- कई भाषाओं के जानकार नाविकों को अधिक फायदा

आप भी जुड़ें

अपने आस-पास के ऐसे ही किसी अभिनव, प्रेरक व सार्थक प्रयास की जानकारी आप भी हमें दे सकते हैं, जो व्यक्ति, देश व समाज को नवप्रेरणा से भर सकती हो। संक्षिप्त विवरण response.story@jagran.com पर भेजें।

इस तरह मिली सफलता

आइआइटी बीएचयू से 2013 में एमसीए करने और फिर पांच वर्षों तक विभिन्न कंपनियों में सेवाएं देने के बाद कपिल ने यह स्टार्टअप शुरू किया। उनके इस स्टार्टअप को आइआइटी, बीएचयू के इंक्यूबेशन से मदद मिली, जिसके बाद इस साल नवंबर में एप को लांच किया गया। मालवीय नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता केंद्र, आइआइटी, बीएचयू के समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि कपिल का स्टार्टअप हमें पसंद आया और एग्रीमेंट के बाद उन्हें काम करने के लिए यहां से उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

अंग्रेजी और फ्रेंच सीख रहे नाविक, नियमित रूप से मिलने लगा रोजगार

आंध्र प्रदेश से बनारस आए मुरली कृष्णा ने बताया कि वह डिंगी एप की सेवा लेकर नौका विहार करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। उन्हें नाव बुकिंग की यह सुविधा बेहद खास लगी। उन्होंने बताया कि इसने उनका बहुत समय बचाया। राणा महल घाट पर नाविकों के प्रबंधक विनोद यादव बताते हैं कि हमारे नाविक अंग्रेजी, फ्रेंच व दक्षिण भारत की कई भाषाओं के जानकार हैं। इससे वे गाइड का भी काम कर लेते हैं और किराए के अलावा अतिरिक्त भुगतान भी पाते हैं। घाट के गरीब नाविकों को इस स्टार्टअप से नियमित रोजगार मिल रहा है। पर्यटक खोजने के बजाय वह मेहमानों की सेवा व तैयारियों में लगे रहते हैं।

कहते हैं नंदलाल, बेटी तो बेटी ही होती है...

- दिल्ली अग्नि हादसे के दौरान अस्पताल परिसर में रिपोर्टिंग को तैनात महिला पत्रकारों से फल के बदले नहीं लिए थे पैसे
- दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर 45 साल से फलों की रेहड़ी लगाते हैं नंदलाल, सोशल मीडिया पर बने हीरो, जज्बे को सलाम कर रहे लोग

दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के सामने फल बेचते नंद लाल। जागरण

जीना इसी का नाम है

मनु त्यागी, नई दिल्ली

बीते दिनों दिल्ली में हुए अग्नि हादसे के दौरान अस्पताल परिसर में रिपोर्टिंग को डटीं महिला पत्रकारों ने जब वहां रेहड़ी लगाने वाले 70 वर्षीय फल विक्रेता नंदलाल से फल खरीदे तो नंद लाल ने पैसे लेने से इन्कार कर दिया। कहा, आप हमारी बेटी जैसी हो...। नंदलाल के इस जज्बे ने उन्हें सोशल मीडिया पर नायक बना दिया है।

नंदलाल बीते 45 सालों से तो दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल के सामने पेड़ की छांव में बैठकर फल बेचते हैं। 11 दिसंबर को नंदलाल तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने दो महिला पत्रकारों द्वारा फल खरीदने पर उनसे पैसे लेने से इन्कार कर दिया। उनकी इस भावना को ट्विटर पर साझा किया गया और देखते ही देखते नंदलाल सोशल मीडिया पर सराहे जाने लगे। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने उनके जज्बे को सलाम कर इसे शेयर करना शुरू कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे यह कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन थोड़ा ठहर कर सोचेंगे तो एहसास होगा कि आज कोई किसी को दो पैसे की चीज भी फ्री में देता है क्या? वह भी नंदलाल जैसा गरीब फल विक्रेता? यानी कुछ तो बात है नंदलाल में। इसीलिए वह सोशल मीडिया में किसी नायक की तरह सराहे जा रहे हैं।

नंदलाल ने बताया, 'वह बड़ा मनहूस दिन था। अनाज मंडी में हुई आगजनी की घटना से सभी की तरह मैं भी व्यथित था। अस्पताल पहुंचने वाले सैकड़ों पीड़ितों का दुख-दर्द सुन-देख रहा था। मैं हर दिन की तरह ही सुबह से अस्पताल के सामने वाली सड़क पर दुकान लगाए बैठा था। अस्पताल परिसर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया के लोग भी थे। उन्हीं में कई महिला पत्रकार भी थीं। देख रहा था कि इन बच्चियों ने बैग से टिफिन तक नहीं निकाला और लगातार अपना काम संभाल रही थीं। पता नहीं कि उनके पास टिफिन था भी या नहीं। मेरे पास आईं तो कुछ फल लिए और पैसे देने लगीं। मेरे जमीर ने यह गवाही नहीं दी कि मैं इन बच्चियों से पैसे लूं।' वह आगे कहते हैं, 'मेरी भी दो बेटियां हैं। अब भले ही उनकी शादी हो गई है, लेकिन बेटियों का बाप हूं, बेटी तो बेटी ही होती है। मैं अस्पताल के सामने फल बेचता हूं और आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में पीड़ा से भरे लोग ही पहुंचते हैं। 45 साल में ऐसी सैकड़ों बेटियां या जरूरतमंद आए, सभी को अपनी कुव्वत के हिसाब से सहयोग करता हूं। कोई घटना-दुर्घटना हो जाए या कोई मुसीबत में हो तो पुलिस को 100 नंबर पर फोन करने में देर नहीं लगाता, हर सूचना दे देता हूं, ताकि जरूरतमंद को मदद मिल सके। ऐसा भी हुआ, जब इधर सड़क चलते किसी बच्ची को कोई परेशानी आई या किसी ने परेशान किया, तब मैं बिना देर किए मदद को दौड़ पड़ा।' नंदलाल के बारे में हमने इलाके की पुलिस से भी पता किया। पीसीआर पर तैनात पुलिस कर्मी भी मानते हैं नंदलाल बेहद नेक इंसान हैं। जरूरत पड़ने पर खुद ही 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जरूरतमंद की मदद करने के लिए बुलाते आए हैं। कई बार तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर बच्चियों की मदद को हाथ बढ़ाया। झगड़े में उलझना पड़ा, लेकिन पीछे नहीं हटे। एक बार तो राह चलते एक युवती को छेड़कर भाग रहे आरोपित को नंदलाल ने मौके पर ही पकड़ा था और पुलिस के पहुंचने तक जोखिम उठाते हुए उसे पकड़े रखा।

रोशन किया प्रयागराज का नाम

नंदलाल मूलरूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बमरौली के रहने वाले हैं। बीते चार दशक से दिल्ली के इस अस्पताल के बाहर फल बेचने का काम कर रहे हैं। नंदलाल को आज लेडी हार्डिंग अस्पताल के छोटे-बड़े डॉक्टर, नर्स और अन्य सभी कर्मचारी जानते हैं, इज्जत देते हैं। नंदलाल के पास फल खरीदने आई अस्पताल में काम करने वाली फार्मासिस्ट रुचि ने बताया, 'अंकल हमेशा हमें बेटा कहकर ही संबोधित करते हैं, हमने इन्हें हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े देखा है। चाहे अस्पताल में किसी की मदद करनी हो या कभी हम लड़कियां भी अस्पताल के बाहर से गुजर रही हों, इत्मीनान रहता है कि अंकल वहां हैं।' दिल्ली में 'इंसानियत का नायक' बन बैठे अपने इस बुजुर्ग बेटे पर प्रयागराज निश्चित ही गर्व कर सकता है।

जहां कभी गरजती थीं बंदूकें, वहां अब लहलहाती है फसल

अर्पित अवस्थी, औरैया

उत्तर प्रदेश के औरैया का मई मानपुर गांव। जहां कभी बंदूकें गरजती थीं, वहां अब समृद्धि की फसल लहलहा रही है। शराब की जगह दूध की नदियां बह रही हैं। अब स्कूलों में सन्नाटा नहीं ककहरा गूंजता है। यह संभव हुआ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन से।

जनसंख्या नियोजन

यमुना के बीहड़ में बसे मई मानपुर में आज भी दिन ढल जाने के बाद जाने में डर लगता है। एक समय ऐसा था, जब यहां दस्यु लालाराम और निर्भर गुर्जर पनाह पाते थे। इसी ग्राम पंचायत के चंदन और गंभीर डकैत थे। एसपी दलजीत चौधरी यहां कई डकैतों का एनकाउंटर किया था। लिहाजा, गांव विकास की डगर नहीं पकड़ सका था।

वर्ष 2014 में केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 4500 की आबादी वाले इस गांव में 216 ग्रामीणों का 720 बीघा अनुपयोगी खेत समतल किया गया। 500 एकड़ बंजर भूमि में से 400 एकड़ को उपजाऊ बनाया गया। अब गांव में पशुपालन भी बढ़ा है, पांच हजार पशु हैं। स्वरोजगार के लिए मिले ऋण से डेयरी प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। दूध की सप्लाई हो रही है।

भूमि संरक्षण अधिकारी राजेश रावत ने बताया, एक हेक्टेयर से कम खेत वाले किसानों को दस हजार, भैंस खरीद पर 15 हजार और खाद-बीज पर 50 फीसद अनुदान दिया गया। दो परिषदीय स्कूलों में गांव के 30 फीसद बच्चे पढ़ते थे। अब एक राजकीय इंटर कॉलेज समेत पांच परिषदीय स्कूलों में 80 फीसद बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव में 450 इज्जतघर (शौचालय) बनाए गए। 700 परिवारों को उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि 90 फीसद घरों में बिजली कनेक्शन है। इसका सुपरिणाम आज सामने है। गांव के अभिलाख सिंह ने बताया, अब लोग निर्भय सिंह गुर्जर, अरविंद गुर्जर, रामवीर गुर्जर, फक्कड़, श्रीराम, लालाराम, फूलनदेवी, कुसुमा नाइन, विक्रम, श्याम जाटव, सीमा परिहार, मुस्तकीम जैसे दस्युओं की चर्चा भी नहीं करते, जिनका कभी यहां दबदबा रहता था। ग्राम प्रधान नरसिंह यादव कहते हैं, बीहड़ के कारण खेत किसी काम के नहीं थे, जिससे युवा दस्यु बनते गए। अब मिशन में शामिल हुए तो जिंदगी बदल गई।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत गोद लिए गए मई मानपुर में अब खेती और रोजगार के अवसर मुहैया
- कभी डकैतों को पनाह देने वाले गांव के बदल गए हालात, गांव से कई डाकू निकले, लालाराम, निर्भर गुर्जर का भी था ठिकाना

रामबाबू-दयाराम दस्यु दल की एक पुरानी तस्वीर। फाइल फोटो

नरसिंह, ग्राम प्रधान। जागरण

अभिलाख सिंह, किसान। जागरण

औरैया के मई मानपुर में सरसों के लहलहाते खेत के बीच किसान। जागरण

'चंबल के डाकुओं' का ऑनलाइन महिमा मंडन...

हरिओम गौड़, श्योपुर : जो दुर्दांत डकैत रामबाबू और दयाराम गड़रिया एक दशक तक चंबल में आतंक का पर्याय बन गए थे, जिन्होंने मुखबिरी के शक में लाइन में खड़ा कर 13 निर्दोष ग्रामीणों को गोलियों से भून दिया, लूट-पाट व अपहरण की कई घटनाएं कर पूरे सूबे को हिला दिया था, उन्हीं खूंखार दस्युओं का इंटरनेट पर खूब महिमा मंडन हो रहा है। गूगल और यू-ट्यूब पर ऐसे गीतों की भरमार है, जिनमें रामबाबू-दयाराम गड़रिया को चंबल की शान, गरीबों का मसीहा और गड़रिया समाज का अभिमान बताकर समाज के युवाओं को दयाराम-रामबाबू जैसा बनने की नसीहत दी जा रही है। इंटरनेट पर फैले इन वीडियो में सरकार और कानून की भूमिका दगाबाज की बताई जा रही है। इंटरनेट पर 'मैं रामबाबू' नाम से एक शॉर्ट फिल्म भी डाली गई है। रामबाबू-दयाराम पर 5-5 लाख का इनाम और पूरे गिरोह पर 15 लाख का इनाम था। अगस्त 2008 में दयाराम पुलिस के हाथों मारा गया तो जून 2007 को शिवपुरी के बक्सनपुर के जंगल में दयाराम भी एनकांउटर में मारा गया था। बहरहाल, इन डकैतों के इस तरह महिमा मंडन को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई है। एडीजी डीसी सागर ने कहा, जो लोग इनकी हैवानियत के शिकार हुए हैं, उनसे पूछिए कि यह कितने राक्षसी प्रवृत्ति के थे। जनता अमन-चैन चाहती है, लेकिन यह डकैत कानून को न मानने वाले दहशतगर्द थे।

इंटरनेट पर रामबाबू-दयाराम का गुणगान करने वाले वीडियो और गीतों की कतार लगी है। स्क्रीन शॉट

कानून की नजर में यह जघन्य अपराधी, बहशी और दुर्दात हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो लोग इंटरनेट पर इनका महिमा मंडन कर रहे हैं वह कतई सही नहीं हैं।

खेत में दबी यह तलवार आल्हा-ऊदल की!

अपना देस खुशबू माटी की

जोगेंद्र सेन, ग्वालियर

बड़े लड़ैया, महोबे वाले खनक-खनक बाजी तलवार
बड़े लड़ैया आल्हा-ऊदल जिनसे हार गईं तलवार...।।

बुंदेलखंड की लोकपरंपराओं में महायोद्धाओं के रूप में आल्हा-ऊदल का विशेष स्थान है। इनके अद्भुत साहस पर रचे गए साहित्य को गा और सुनाकर लोकगायक आज भी सुनने वालों को वीर रस से भर देते हैं। ग्वालियर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बेहट रोड पर बसे हस्तिनापुर गांव के एक खेत में दबी विशालकाय तलवार को इन्हीं आल्हा-ऊदल की निशानी माना जा रहा है।

आल्हा-ऊदल का ग्वालियर से नजदीकी रिश्ता होने के प्रमाण भी लोकपरंपरा और इतिहास में मिलते हैं। माना जाता है कि आल्हा-ऊदल भाइयों की मां देवल देवी ग्वालियर के राजा दलपत की पुत्री थीं। हस्तिनापुर के खेत में दबी उनकी तलवार को लेकर भी कई किंवदंतियां हैं। पुरात्व विभाग के अधिकारी हस्तिनापुर के पास एक तलवार के खेत में दबे होने की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन यह किसकी है, इसका प्रमाणिक इतिहास होने से इन्कार करते हैं। तलवार को न तो पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने के कोई प्रयास किए हैं और ना ही इसकी प्रमाणिकता के लिए कोई खोजबीन की है। ग्रामीणों ने खेत में लोहे के तार की घेराबंदी कर तलवार को संरक्षित किया है। तलवार का केवल हत्था ही जमीन से बाहर है, जबकि शेष भाग दबा हुआ है। हत्था इतना बड़ा है कि साधारण मानव के हाथ में आना आसान नहीं है। इसे देखने के लिए यहां जो लोग आते हैं, वे इसे घिसकर भी देखते हैं कि ये हत्था पत्थर का है या फिर धातु का। घिसने पर पता चलता है कि यह धातु का ही है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह तलवार महोबा के वीर आल्हा-ऊदल की ही है, वह अपने पूर्वजों से यह सुनते आए हैं, लेकिन यह यहां कैसे पहुंची, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। धारणा है कि आल्हा-ऊदल के आसमान से विचरण करते समय यह जमीन पर गिरी और यहां धंस कर रह गई। लोकपरंपराओं में उल्लेख है कि दोनों भाई आसमान में विचरण करने की विधा जानते थे। बता दें कि ओरछा के राजा हरदौल से लेकर महोबा के वीर भाई आल्हा-ऊदल की वीर गाथाएं पूरे बुंदेलखंड में बुंदेली काव्य के रूप में लय के साथ गाई जाती हैं। दोनों भाइयों की वीरगाथाएं 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती हैं। आल्हा खंड की रचना महोबा-कालिंजर के राजा परमाल के दरबारी कवि जगनिक ने की थी। कहा जाता है कि आल्हा-ऊदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच 52 बार युद्ध हुआ था, इसमें उसका विवरण है। ऊदल के युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त होने के बाद भाई आल्हा ने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर मां शारदा के सामने तलवार की नोक टेढ़ी कर दी थी।

ग्वालियर के हस्तिनापुर गांव के खेत में दबी विशालकाय तलवार का हत्था। नईदुनिया

- ग्वालियर के हस्तिनापुर गांव के एक खेत में दबी है तलवार, विशालकाय हत्था देख लोग हो जाते हैं अचंभित

प्रयागराज की धरती पर साइंस प्रैक्टिकल का नया रिकार्ड

4313 विद्यार्थियों ने 'लार्जेस्ट साइंस प्रैक्टिकल सेशन' में किया प्रतिभाग

- गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज कराया शहर का नाम, दो और संस्थाओं में रिकार्ड के लिए दावा

प्रयागराज में शनिवार को नैनी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में नया रिकार्ड बना। स्कूल के मैदान में जल आधारित प्रयोग करते विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राएं सतरंगी छटा बिखेरते नजर आए। इस दौरान एक छात्रा छत से इस यादगार पल को मोबाइल कैमरे में कैद करती हुई। मुकेश कनौजिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रयागराज की धरती शनिवार को साइंस प्रैक्टिकल के नया रिकार्ड की साक्षी बनी। नैनी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में कक्षा छह से 12 तक के 4313 छात्र-छात्राओं ने जल आधारित प्रयोग कर गिनीज वर्ल्ड रिकाड्र्स में प्रयागराज का नाम दर्ज कराया। करीब 50 स्कूलों के विद्यार्थी इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए जुटे थे। घोषणा होते ही आयोजकों के साथ छात्र-छात्राओं की बांछें खिल गईं।

आई साइंस वर्ल्ड, श्रीमहाप्रभु पब्लिक स्कूल और डीपीएस द्वारा यह आयोजन हुआ था। 'लार्जेस्ट साइंस प्रैक्टिकल सेशन' में 4313 छात्र-छात्राएं सम्मलित हुए। यह कवायद लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकाड्र्स और गोल्डेन बुक वर्ल्ड आफ रिकार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए भी भेजी गई है। विद्यार्थियों ने तीन चरणों में जल आधारित प्रयोग किए। विद्यार्थियों को (सालिबिलिटी, लिटमस और कैपिलरी राइस टेस्ट) के प्रयोग के लिए आधे-आधे घंटे का समय दिया गया था। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, रेणूकूट (सोनभद्र) जिलों के स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थियों ने किट और ट्रे में प्रयोग किया। बीच में उठने की वजह से 41 विद्यार्थी अयोग्य करार दिए गए। गिनीज वर्ल्ड रिकाड्र्स की एडजुडिकेटर शेफाली मिश्रा ने नया कीर्तिमान बनने की घोषणा कीं।

श्रीमहाप्रभु पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्रीभगवान पांडेय ने आइ साइंस वर्ल्ड के सेक्रेटरी रितांशु गुप्ता को नए विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के एशिया हेड डॉ. मनीष विश्नोई ने बताया कि प्रोविजिनल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। रिकार्डिंग की दोबारा जांच कर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 'मोस्ट पीपल परफार्मिंग इनफार्मल साइंस इक्सपेरीमेंट इनवाल्विंग वॉटर' का प्रोविजिनल सर्टिफिकेट दिया गया है। सहआयोजक श्रीमहाप्रभु पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या रबिंदर बिरदी ने बताया कि लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड के लिए वीडियो रिकार्डिंग भेजी गई है।

इसके पहले कब बना था रिकार्ड

गिनीज बुक में पिछला रिकार्ड 12 अगस्त, 2016 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में बना था। वहां चुंबक की सहायता से प्रयोग के लिए 53 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के 2895 बच्चे शामिल हुए थे।

वर्ष 2015 में दिल्ली में 2000 बच्चों ने एक साथ किया था प्रयोग।

हालात

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की एक बड़ी वजह पलायन भी, गांवों में खंडहर मकान और खेतों उग आई झाड़ियां बन रही जंगली जानवरों का सुरक्षित ठिकाना

वीरान गांवों में खंडहर बने गुलदार के सुरक्षित ठिकाने

गुरुवेंद्र नेगी, पौड़ी गढ़वाल

विषम भूगोल वाले उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की एक बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन भी माना जा रहा है। पलायन से वीरान हो चुके गांवों में खंडहर मकान और खेतों में उग आई घनी झाड़ियां जंगली जानवरों का सुरक्षित ठौर बन रहे हैं। वन विभाग भी मान रहा है कि कई गावों के वीरान होने से पैदा हुए हालात समस्या को और गंभीर बना रहे हैं।

15 ब्लॉकों वाले पौड़ी जिले में पिछले सात सालों में 186 गांव व तोक गांव वीरान हो गए। देखा जाए तो जिले का करीब-करीब हर ब्लॉक पलायन के दौर से गुजर रहा है। पलायन आयोग की ओर से जिले की 1212 ग्राम पंचायतों में किए गए सर्वे के अनुसार 1025 ग्राम पंचायतों में पलायन बढ़ा है। आजीविका, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क आदि की समस्या ने इसमें अहम भूमिका निभाई। सर्वे के अनुसार बीते दस सालों में 1025 ग्राम व तोकों से 47 हजार से अधिक लोगों ने पलायन किया। नतीजा इन क्षेत्रों में खेत बंजर हो गए और उनमें घनी घाड़ियां उग आईं। जो अब जंगली जानवरों, खासकर गुलदार का ठिकाना बनने लगी हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में गुलदार के हमले की बढ़ती घटनाएं इसकी तस्दीक करती हैं।

गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के प्रभागीय वनाधिकारी लक्ष्मण सिंह रावत कहते हैं कि पहले गांवों में लोग महीने में एक या दो बार सामूहिक श्रमदान कर गांव व आस-पास की झाड़ियों को काटते थे, लेकिन अब वीरान गांवों में यह संभव नहीं। डीएफओ के अनुसार, जिले के पौड़ी, पोखड़ा, पाबौ व खिर्सू ब्लॉक में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है।

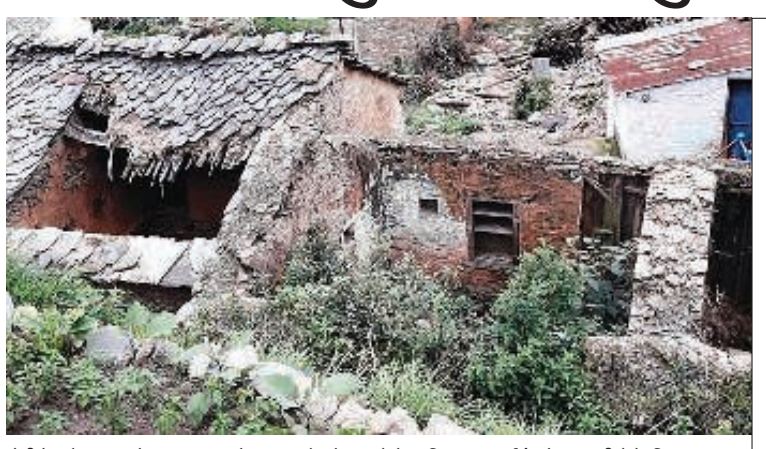
पौड़ी के कोट ब्लाक के धनकुर गांव में खंडहर हो चुके भवनों में झाड़ियां उग आईं हैं और वन्यजीवों के लिए यह ठौर बन गया है। ऐसी स्थिति पलायन से खाली हो चुके जिले के अन्य गांवों की भी है। जागरण

चार बने निवाला, दस हुए घायल

जिले में गढ़वाल वन प्रभाग के अंतर्गत देवकुंडई तल्ला, सरणा, कुलमोरी व बछेली गांव में इस वर्ष अभी तक गुलदार चार लोगों को निवाला बना चुका है। जबकि, दस लोग घायल हुए।

वीरान गांवों से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं

चकबंदी आंदोलन के प्रणेता गणेश सिंह गरीब, सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी व बुजुर्ग सुरेंद्र नौटियाल बताते हैं कि अब तो वीरान गांवों से गुजरने में भी डर लगता है। कब किस खंडहर या झाड़ी से गुलदार बाहर आ जाए, कहा नहीं जा सकता।

पीएनबी ने 2,617 करोड़ रुपये का एनपीए नहीं किया जाहिर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता पीएनबी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2,617 करोड़ रुपये का एनपीए जाहिर नहीं किया है। पीएनबी ने शेयर बाजारों को बताया कि आरबीआइ ने अपनी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। आरबीआइ ने पीएनबी के आंकड़ों में 2,617 करोड़ रुपये का डायवर्जेंस भी पाया है। पीएनबी के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में उसका एनपीए 78,472 .70 करोड़ रुपये रहा, जबकि आरबीआइ ने अपनी गणना में पाया कि इस दौरान पीएनबी का एनपीए 81,089 .70 करोड़ रुपये रहा था।

निवेश के लिए अब अमेरिकी कंपनियों की राय बदल चुकी है। वे चीन से अलग बाजार तलाश रही हैं। भारत इन कंपनियों के लिए बेहतरीन बाजार साबित हाने वाला है।

— अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

फास्टटैग: ऐसे करेगा काम, मुश्किलें होंगी आसान

राष्ट्रीय राजमार्गों पर भुगतान को बढ़ाने और कई तरह की परेशानियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज यानी 15 दिसंबर 2019 से फास्टटैग लेन लागू कर दिया है। लोगों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार ने फास्टटैग को लागू करने की समय सीमा को एक दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया था, जिससे लोगों को फास्टटैग खरीदने और लगवाने के लिए समय मिल सके।

ये है फास्टटैग

फास्टटैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान स्टिकर है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। यह टोल बूथों को वायरलेस और स्वचालित तरीके से शुल्क काटने की सुविधा देता है। इसके कारण वाहन को टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होती है। यह टैग एक दिसंबर 2017 के बाद बेची गई सभी कारों पर लगाना अनिवार्य है। नई कारों में फास्टटैग लगा हुआ ही आ रहा है आपको सिर्फ इसे रिचार्ज करवाना है।

इतना रख सकते हैं बैलेंस

आरबीआइ के नियमों के मुताबिक, जो उपभोक्ता केवाईसी प्रक्रिया से बाहर रहना चाहते हैं वे फास्टटैग प्रीपेड वॉलेट में 20 हजार से ज्यादा राशि नहीं रख सकते हैं। वहीं केवाईसी कराने वाले उपभोक्ता अपने फास्टटैग प्रीपेड वॉलेट में एक लाख रुपए से ज्यादा राशि नहीं रख सकते हैं।

ऐसे करें रिचार्ज

- किसी भी बैंक द्वारा जारी फास्टटैग को आप उस बैंक के वेब पोर्टल पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं। उपयोगकर्ता की जानकारी के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और फोन नंबर देना होगा। इसके बाद फास्टटैग के साथ संबंधित वॉलेट को नेटबैंकिंग, यूपीआइ या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं।
- बैंक के द्वारा जारी फास्टटैग को यूपीआइ द्वारा 'माई फास्टटैग एप' के जरिए भी रिचार्ज किया जा सकता है। यह एप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर ही उपलब्ध है।
- जो लोग फास्टटैग को अपने बैंक से लिंक कराने के इच्छुक नहीं हैं उनके लिए एनएचएआइ फास्टटैग है, जिसे आप एनएचएआइ प्रीपेड वॉलेट से जोड़ सकते हैं। यूपीआइ के जरिए माय फास्टटैग एप को नेट बैंकिंग, यूपीआइ या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं।
- बैंक अकाउंट से संबद्ध एनएचआइए फास्टटैग का बैलेंस एक निश्चित राशि से कम होते ही फास्टटैग एप के जरिए एक निश्चित राशि का रिचार्ज हो जाएगा। इसमें उपभोक्ता टॉप अप राशि का चुनाव कर सकता है।

फास्टटैग खरीदना है तो...

फास्टटैग खरीदने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और वाहन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज की एक कॉपी जो कि माय फास्टटैग एप में स्टोर होगी या फिर आप अपने बैंक से भी फास्टटैग खरीद सकते हैं।

क्या होगा यदि नहीं लिया फास्टटैग

15 दिसंबर के बाद भी यदि आपने फास्टटैग नहीं लिया और फास्टटैग लेन में प्रवेश किया तो आपको टोल राशि के लिए दोगुना शुल्क चुकाना होगा।

इतने बूथों पर फास्टटैग

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अब तक 537 टोल प्लाजा पर फास्टटैग के जरिए आप बिना गाड़ी रोके पार कर सकेंगे।

यह हैं फायदे

फास्टटैग को लेकर सरकार की ओर से कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। इनके मुताबिक फास्टटैग लगने से वाहन को टोल बूथों पर लाइन में लगने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही टोल बूथ के लिए कैश लेकर नहीं चलना होगा और ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा से डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल की बचत से प्रदूषण में कमी और पेपर के इस्तेमाल में कमी से पर्यावरण को भी फायदा होगा।

मदर डेयरी व अमूल दूध आज से तीन रुपये तक महंगा

जासं, नई दिल्ली : डेयरी कंपनी अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमत रविवार से तीन रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। अमूल ने दाम दो रुपये प्रति लीटर, जबकि मदर डेयरी ने तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अमूल का दूध दो रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब अमूल गोल्ड का आधा लीटर का पैकेट 28 और अमूल ताजा का 22 रुपये में मिलेगा। अमूल शक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके आधा लीटर पैकेट की कीमत 25 रुपये ही रहेगी। अमूल का कहना है कि पशु की खुराक के दाम सहित अन्य खर्च 35 फीसद तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। पिछले तीन साल में यह दूसरा मौका है, जब अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। इस दौरान दूध के दाम में चार रुपये की वृद्धि हुई है।

अमूल उपभोक्ताओं से मिलने वाले एक रुपये में से 80 प्रतिशत का भुगतान दुग्ध उत्पादकों को करता है। अमूल देशभर में प्रतिदिन 1.4 करोड़ लीटर दूध की सप्लाई करता है। दिल्ली-एनसीआर में ही इसकी खपत रोजाना 33 लाख लीटर है।

दूसरी तरफ, मदर डेयरी का भी कहना है कि उसने कम आपूर्ति और खरीद की लागत बढ़ने को कीमत बढ़ने का कारण बताया है। रविवार से मदर डेयरी का टोंड दूध 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि फुल क्रीम दूध 55 रुपये प्रति लीटर का मिलेगा। कंपनी के आधे लीटर फुल क्रीम दूध के पैकेट का नया दाम 28 रुपये होगा।

चुनौती ▶ राज्यों द्वारा कंपेंसेशन अवधि बढ़ाने की मांग संभव

जीएसटी कंपेंसेशन पर बढ़ रही राज्यों की नाराजगी

वर्तमान में मुताबिक राज्यों को 2021-22 तक कंपेंशेसन भुगतान की गारंटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जीएसटी कंपेंसेशन के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगले सप्ताह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथ ही राज्य अब कंपेंसेशन की अवधि को पांच साल और बढ़ाने का दबाव बना सकते हैं।

राज्यों का कहना है कि कंपेंसेशन की अवधि 2021-22 में समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब तक रेवेन्यू वृद्धि की अपेक्षित रफ्तार हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। उस पर मौजूदा कंपेंसेशन के भुगतान में भी देरी हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जल्द भुगतान का आग्रह किया था तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कंपेंसेशन की अवधि को बढ़ाकर 2026-27 करने की मांग की है। शनिवार को शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर कंपेंसेशन का जल्द भुगतान नहीं हुआ तो केंद्र और राज्य के संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार इस संबंध में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकी है। इससे 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की प्रस्तावित बैठक में इन मुद्दों पर गैर-भाजपा शासित प्रदेशों की तरफ से तल्ख रुख अपनाने के आसार बन रहे हैं।

प्रतीकात्मक

वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के वक्त केंद्र और राज्य के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को इसमें मिला दिया गया था। उस वक्त प्रति माह जीएसटी का रेवेन्यू एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। साथ ही राज्यों को जीएसटी लागू होने से पूर्व अर्जित रेवेन्यू में 14 परसेंट सालाना की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। राज्यों से वादा किया गया था कि प्रत्येक साल अर्जित रेवेन्यू में 14 परसेंट की अपेक्षित वृद्धि नहीं होने की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र करेगा। इसके लिए एक कंपेंसेशन सेस का प्रावधान भी किया गया।

जीएसटी रेवेन्यू के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई, 2017 के बाद से रेवेन्यू में अपेक्षित वृद्धि का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। यहां तक कि एक लाख करोड़ रुपये का मासिक रेवेन्यू भी गिनती के महीनों में प्राप्त हो पाया है। चालू वित्त वर्ष में ही केवल चार महीने ऐसे रहे हैं जब जीएसटी से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर गया है। यही वजह है कि राज्यों के रेवेन्यू और अपेक्षित वृद्धि के बाद अनुमानित रेवेन्यू का अंतर बढ़ता जा रहा है। यह अंतर बढ़ने से राज्यों को मिलने वाले कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति की भी दिक्कत होने लगी है। हाल ही में कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर कंपेंसेशन की राशि जारी करने का आग्रह किया। राज्यों का आरोप है कि बीते चार महीने से कंपेंसेशन की राशि का भुगतान केंद्र ने रोका हुआ है। राज्यों का कहना है कि केंद्र पर कंपेंसेशन का करीब 50,000 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि राज्यसभा में अनुदान की पूरक मांगों पर हुई चर्चा के दौरान हुए वित्त मंत्री ने भरोसा दिया था कि राज्यों को भुगतान को लेकर केंद्र वचनबद्ध है।

कार्वी के कर्जदाताओं को राहत से सेबी का इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कार्वी मामले में बजाज फाइनेंस समेत तीन अन्य कर्जदाताओं को राहत देने से इन्कार कर दिया है। इन कर्जदाताओं के पास कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केबीएल) से संबंधित शेयर गिरवी रखे थे। कार्वी द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद इन शेयरों को उनके मूल धारकों को लौटा दिया गया था। कर्जदाताओं ने इसके खिलाफ सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) में अपील की थी। सैट ने उन्हें यह मामला सेबी के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।

सेबी ने बजाज फाइनेंस, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक की अपील खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में निवेशकों की सिक्युरिटीज का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से शेयरों को गिरवी रखना वैध नहीं है। इस दौरान नियामक ने बताया कि बोक्रर किसी भी हालत में निवेशको के शेयर पांच कारोबारी सत्रों से अधिक अवधि के लिए अपने पास नहीं रखा सकता। इस दौरान इनका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी नहीं किया जा सकता।

इस मामले में कार्वी ने पावर ऑफ अटार्नी के जरिये निवेशकों के शेयरों का इस्तेमाल अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। अनियमितता सामने आने के बाद सेबी ने 83,000 से अधिक ग्राहकों को शेयर वापस लौटा दिए थे। इस दौरान नियामक ने कार्वी को नए ग्राहक जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके साथ ही बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज ने भी कार्वी को अपने प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने से प्रतिबंध लगा दिया था।

भारत में मौजूदगी बढ़ाना चाहती है आर्सेलरमित्तल

आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। जागरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन और सीईओ लक्ष्मी निवास मित्तल ने शनिवार को केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की। मुलाकात में प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने और इस्पात के क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई।

आर्सेलरमित्तल दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्माताओं में से एक है और भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। भारत के बड़े और विविध बाजार, बढ़ती मांग और निवेशकों के अनुकूल शासन का लाभ उठाने में मदद करने के लिए प्रधान ने उन्हें पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पिछले महीने एस्सार स्टील की खरीद के लिए आर्सेलरमित्तल की सभी बाधाओं को खत्म कर दिया था।

रंग लाएंगे बुनियादी सुधार के कदम : कांत

वाशिंगटन, प्रेट्र : नीति आयोग ने कहा है कि पिछले कुछ समय के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व सुधार आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करेंगे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि लंबे के समय के दौरान इन मौलिक सुधारों के परिणाम सामने आएंगे। यह इकोनॉमी को प्रतिस्पर्धी और उत्पादक बनाने में मददगार साबित होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स सुधार के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है।

नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि जीएसटी और बैंक्रप्सी कोड से क्रोनी कैपिटलिज्म का अंत करने में मदद मिलेगी। रियल एस्टेट में रेरा जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ेगी।

कांत ने कहा कि निवेश के मामले में अब अमेरिकी कारोबारियों की राय बदल चुकी है। वह निवेश के लिए चीन से इतर बाजार तलाश रहे हैं। भारत इन अमेरिकी निवेशकों के लिए मुफीद जगह साबित हो सकता है। इस बारे में वियतनाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि

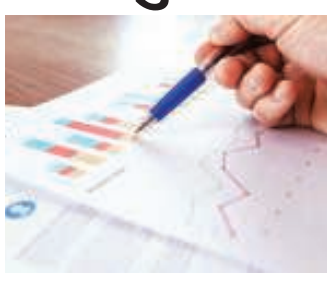
प्रतीकात्मक

वहां बाजार बहुत सीमित है, मानव संसाधन और स्किल के मामले में भी वह भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता।

सुधारों का जिक्र करते हुए कांत ने कहा कि यह भारतीय इकोनॉमी में सुधार की शुरुआत भर है। हम शहरीकरण, आधारभूत संरचना का निर्माण और तकनीकि के भरपूर प्रयोग की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले तीन दशकों में इसके परिणाम सामने होंगे। हाल के दिनों में इकोनॉमी में देखी गई सुस्ती के सवाल पर कांत ने कहा कि यह बहुत अल्प समय के संकेतक हैं। भारत पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

देश में कारोबारी माहौल में सुधार पर चर्चा करते हुए नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बेहतर कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची के शीर्ष 50 देशों में शामिल हो जाए। इसके बाद हमारा लक्ष्य अगले तीन वर्षो के भीतर शीर्ष 25 में जगह बनाने का है। श्रम सुधारों पर बात करते हुए कांत ने कहा कि हमने हाल में श्रम कानूनों का एकीकरण कर दिया है। इससे कंपनियों को भारत में उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में काफी सुधार किया है।

भारत में होने वाले शोध कार्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां बेंगलुरु और हैदराबाद में शोध कार्यों को अंजाम दे रही हैं। इस समय इन दोनों शहरों में करीब 1,400 कंपनियां शोध और विकास कार्य में लगी हुई हैं। कांत ने कहा कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली भारत के हैदराबाद से नजदीकी संबंध रखती है।

एनएमडीसी और आरआइएनएल को कोयला खदानें आवंटित

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उसने सरकारी कंपनियों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआइएनएल) को एक-एक कोयला खदान आवंटित कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि झारखंड स्थित इन खदानों में कोयला उत्पादन शुरू होने के बाद आयातित कोयले पर निर्भरता कम हो जाएगी। इन खदानों से प्रति वर्ष एक करोड़ टन कोकिंग कोल निकाला जाएगा। इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री द्वारा बहुतायत रूप में किया जाता है।

एनएमडीसी को आवंटित की गई रोहने स्थित खदान से उत्पादित कोयले को बेचा जाएगा। इसके अलावा एनएमडीसी इस कोयले का उपयोग अपने प्रस्तावित प्लांट में भी करेगी। इसके अलावा आरआइएनएल को दी गई रोबोडिह खदान से उत्पादित कोयले का प्रयोग आयरन और स्टील उद्योग में किया जाएगा।

आर्सेलरमित्तल ने शुरू की भुगतान प्रक्रिया

- आइबीसी कोड के तहत होगी सबसे बड़ी रिकवरी
- इस महीने के अंत तक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद
- एसबीआइ को मिलेंगे सबसे ज्यादा 12,161 करोड़ रुपये

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनिया की अग्रणी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण की ओर कदम बढ़ाते हुए भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्ज संकट से जूझ रही एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलरमित्तल 42,000 करोड़ रुपये चुकाएगी। एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली थी। भुगतान हो जाने के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत यह सबसे बड़ी रिकवरी होगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैंकिंग भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक-दो दिन के भीतर इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। हालांकि मामले से जुड़े कुछ अन्य जानकारों के मुताबिक आर्सेलर ने 42,000 करोड़ रुपये का बंदोबस्त कर लिया है और एसबीआइ को इसका भुगतान सोमवार को एकमुश्त रूप में किया जाएगा। हालांकि आर्सेलरमित्तल की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। गौरतलब है कि इन्सॉल्वेंसी कोड के तहत एस्सार स्टील के कर्जदाता समूह का नेतृत्व एसबीआइ कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आर्सेलरमित्तल ने 42,000 करोड़ रुपये की यह राशि एस्क्रो अकाउंट में रखी है। इस वजह से कर्जदाताओं को तुरंत इसका भुगतान संभव नहीं हो सकेगा। रिकवर की जाने वाली राशि में एसबीआइ को सबसे ज्यादा 12,161 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 3,493 करोड़ और आइसीआइसीआइ बैंक को 2,110 करोड़ रुपये मिलेंगे। अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

गौरतलब है कि आर्सेलरमित्तल और जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी निप्पों स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एस्सार के परिचालन को लेकर समझौता हुआ है। दोनों कंपनियां एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एस्सार स्टील का परिचालन करेंगी। इससे पहले इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में प्राथमिकता को लेकर कर्जदाताओं के बीच विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय कर्जदाताओं को परिचालन कर्जदाताओं पर प्राथमिकता दिए जाने का आदेश दिया था और कर्जदाताओं की कमेटी के फैसले को स्वीकार किए जाने की बात भी कही थी। इसके बाद आर्सेलरमित्तल द्वारा एस्सार के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया था।

निवेश पर बेहतर रिटर्न के लिए क्या सच में बहुत जानकारी की जरूरत है?

कुछ साल पहले एक अध्ययन में पता चला कि वित्तीय साक्षरता में अधिक अंक हासिल करने वालों ने कम अंक हासिल करने वालों की तुलना में निवेशक के तौर पर खराब प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमेरिका के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर/ब्रोकर के अध्ययन में पाया गया कि उनके पास सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अकाउंट उन लोगों के थे जिनकी मौत हो गई थी। एक और अध्ययन से पता चलता है कि अधिक आंकड़े होने से भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की क्षमता बेहतर नहीं होती है। यही नहीं, लगभग हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यह बात जानता है कि न्यूज और छोटी-बड़ी घटनाओं पर बारीक नजर रखने वाले निवेशक अक्सर निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में करते हैं और बाद में इसकी कीमत चुकाते हैं।

इन सभी विषयों पर मैं अलग-अलग समय पर लिख चुका हूं। हालांकि इन सब बातों से एक सोच उभरकर आती है जिसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लोगों की नजर में जो बातें किसी को एक स्मार्ट निवेशक बनाती हैं वे पूरी तरह से गलत भी हो सकती हैं। वास्तव में हो सकता है कि इन बातों का सच से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं हो। हम इस बात को मानते हैं कि निवेशक को वित्तीय रूप से साक्षर होना

धीरेंद्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च

बोनस

आम कहावत है कि ज्यादा जानकारी रखने वाला हमेशा नुकसान का शिकार होता है। कुछ मामलों को छोड़ दें तो यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। एक निवेशक के तौर पर लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा लेना और उसका उपयोग कर निवेश करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा जानकारी होने का मतलब यह नहीं है कि निवेश में आप सफल ही साबित होंगे। अमेरिका का एक अध्ययन तो यहां तक बताता है कि निवेश में सबसे अच्छा रिटर्न उनको मिला जो मर गए थे, क्योंकि वे अपनी जानकारी का उपयोग नहीं कर सकते थे। ऐसे में यह भी संभव है कि आपको जिन बातों की जानकारी है, उन सबका असल में निवेश से कोई लेनादेना ही नहीं हो।

चाहिए यानी उसे वित्तीय मामलों की कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। हम मानते हैं कि पूरे परिदृश्य को अच्छी तरह से समझने के लिए निवेशकों को यह जानना चाहिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हमें यह भी लगता है कि उनको इस जानकारी के आधार पर निवेश से जुड़े कदम उठाने चाहिए। पारंपरिक सोच और विश्वास के उलट यह भी हो सकता है कि इन सब बातों का निवेश में सफलता से कोई संबंध न हो और अगर कोई संबंध हो भी, तो यह नुकसान पहुंचाने वाला हो।

अब सवाल यह पैदा होता है कि वित्तीय साक्षरता और निवेश से जुड़ी जानकारी का मतलब क्या है? इन 'फूल्ड बाई रैंडमनेस' किताब में नासिम निकोलस तालेब ने ऑस्ट्रिया के दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन के हवाले से लिखा है कि जब आप पटरी का इस्तेमाल मेज को नापने के लिए करते हैं तो आप मेज का इस्तेमाल भी पटरी को नापने में कर रहे होते हैं। अगर इस नजरिये से उस अध्ययन को देखें जिसमें कहा गया है कि वित्तीय साक्षरता में अधिक अंक लाने वालों ने निवेशक के तौर पर खराब प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब है कि वित्तीय साक्षरता का पारंपरिक विचार गलत है। ऐसा नहीं है कि मेज गलत तरीके से बनी है बल्कि इसे नापने के लिए जिस पटरी का इस्तेमाल किया गया वही सही नहीं है।

कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले मानते हैं कि बेहतर जानकारी रखने वाले और इस जानकारी पर अमल करने वाले आपके निवेश के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। मरे हुए निवेशकों का उदाहरण इस विचार को गलत साबित करता है। मरे हुए लोग ज्यादा जानकारी न तो हासिल करते हैं और न ही इस जानकारी के आधार पर तेजी से निवेश से जुड़े फैसले करते हैं। और इसके बावजूद वे ज्यादा पैसा बनाते हैं। बहुत संभावना इस बात की है कि उन्होंने इसलिए ज्यादा पैसा बनाया क्योंकि वे कुछ नहीं कर रहे थे। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि वित्तीय साक्षरता का निवेश के प्रदर्शन से कोई लेनादेना नहीं है। यही नहीं, वित्तीय साक्षरता से निवेशकों को एक हद तक नुकसान ही होता है। यह संभव है कि वित्तीय तौर पर साक्षर निवेशकों को रिटर्न के लिहाज से नुकसान उठाना पड़े।

एक तीसरी स्टडी इफेक्ट्स ऑफ अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन जजमेंट एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस में कुछ दिलचस्प बातें बताई गईं हैं। स्टडी से पता चलता है कि जब लोगों के पास अधिक जानकारी होती है तो अपने फैसले में उनका भरोसा बढ़ता है। लेकिन इससे इस बात की संभावना नहीं बढ़ती है कि उनका फैसला ज्यादा सटीक होगा। यह एक रोचक बात है और अगर आप इस पर विचार करें तो आप पाएंगे कि खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होना इसे ही कहते हैं। मान लेते हैं कि आपने पांच जानकारी या इनपुट के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला। हो सकता है कि आपका निष्कर्ष सही हो, हो सकता है कि यह गलत हो।

हालांकि अगर आपको पांच और जानकारी मिल जाती है तो किसी भी हालात में बेहतर फैसला लेने की संभावना बहुत कम बढ़ती है लेकिन अपने फैसले में आपका भरोसा बहुत बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अति आत्मविश्वास के शिकार हो जाते हैं।

तो इस सीख के आधार पर हम निवेश करने वाले लोगों को देखने का प्रयास करें। कुछ लोग अच्छे फैसले लेते हैं और कुछ खराब। जिन निवेशकों के पास अधिक जानकारी होती है वे आम तौर पर निवेश से जुड़े ज्यादा कदम उठाते हैं। और वे ऐसा करने में इस बात पर खास ध्यान नहीं देते हैं कि उनका फैसला सही है या नहीं।

अगर हम इस हिसाब से देश के सभी निवेशकों को देखें तो पाएंगे कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाते हैं तो उसी अनुपात में निवेश से जुड़े गलत फैसले करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? हां मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। मैं यहां इस समस्या का कोई समाधान नहीं पेश कर रहा हूं। हालांकि एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि उसके पास निवेश से जुड़ी उचित जानकारी हो। लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी होना भी उसी तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है जैसे कम जानकारी होना।

कल से चौबीसों घंटे एनईएफटी सुविधा

प्रतीकात्मक

मुंबई, आइएएनएस : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा है कि 16 दिसंबर से बैंक उपभोक्ताओं को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की सुविधा 24 घंटे प्रदान करेंगे। इसके लिए वह बैंकों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त नकदी मुहैया कराएगा। एनईएफटी ऑनलाइन तरीके से दूसरे बैंकों के खाताधारकों को फंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। इसे लेकर आरबीआइ ने बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे हर वक्त अपने चालू खाते में पर्याप्त राशि रखें, ताकि फंड ट्रांसफर में किसी तरह की कोई समस्या न आए। साथ ही अपने यहां सुविधाओं पर भी ध्यान रखें ताकि फंड ट्रांसफर में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। आरबीआइ के नियमों के अनुसार एनईएफटी के जरिये फंड का ट्रांसफर विभिन्न बैच में होता है। अभी तक यह सुविधा सुबह आठ बजे से रात 6:30 बजे तक ही मिलती है। शनिवार को सुबह आठ बजे से दोहपर 12:30 बजे तक ही इसका फायदा उठाया जा सकता था।

भारत को 'फाइव आइ' में लाने के पक्ष में अमेरिका

- भारत के साथ जापान और दक्षिण कोरिया को भी लाने की तैयारी
- कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और कानून का राज कायम रखना जरूरी

वाशिंगटन, प्रेट्र : चीन पर नजर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं कानून का राज कायम रखने के तहत एक शीर्ष अमेरिकी कांग्रेस समिति क्षेत्र के तीन लोकतांत्रिक देशों भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को खुफिया साझेदारी के लिए 'फाइव आइ' के तहत लाना चाहती है। 'फाइव आइ' एक गठबंधन है जिसमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। गठबंधन के पांचों देश आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं।

खुफिया पर सदन की स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद एडम स्चीफ ने गुरुवार को प्रतिनिधि सभा को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के मामले को फाइव आइ के साथ लाया जाए ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और कानून का राज कायम रहे।

स्चीफ ने कहा, 'रक्षा मंत्री के तहत खुफिया मामलों की समिति ओडीएनआइ के साथ मिलकर कांग्रेस की खुफिया एवं रक्षा समितियों को कानून लागू होने के 60 दिन के अंदर भारत, जापान और कोरिया तथा फाइव आइ के सहयोगियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लाभ, चुनौतियां और सूचना-साझेदारी तंत्र के दायरे के विस्तार के जोखिम आदि से अवगत कराएगी।' पिछले हफ्ते तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया में व्यस्त रहे स्चीफ ने 2018, 2019 और 2020 के लिए खुफिया प्राधिकरण उपायों पर अपने बयान में यह बात कही है। रिपोर्ट में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया नामक एक उपखंड में समिति ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और साझेदारी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अहम है।

वकीलों की हड़ताल के चलते हाफिज सईद के खिलाफ नहीं हुई सुनवाई

लाहौर, प्रेट्र : वकीलों की देशव्यापी हड़ताल के चलते मुंबई हमले के मास्टरमांइड हाफिज सईद के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई नहीं हुई। एटीसी लाहौर ने सईद और अन्य के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में सईद सहित उसके तीन करीबी सहयोगियों पर आरोप तय किए गए हैं, लेकिन कोर्ट का कामकाज ठप होने की वजह से इन्हें आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश नहीं किया जा सका।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि तीन दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण किसी अन्य संदिग्ध या गवाह को पेश नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष को सईद के खिलाफ गवाह पेश करना था और अन्य आरोपितों को अदालत में लाया जाना था, लेकिन किसी को पेश नहीं किया जा सका। एटीसी ने बुधवार को जमात-उद-दावा प्रमुख और उसके सहयोगी हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में आरोप तय किया था और अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया था।

ब्रिटेन में जॉनसन की जीत से मुस्लिम समुदाय में भय

- प्रमुख मुस्लिम संगठन ने ओवन रेडी... वाले नारे का उल्लेख कर डर जताया
- लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कार्बिन ने खुद को मुस्लिम हितैषी बताया था

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी की जीत से वहां का मुस्लिम समुदाय डर महसूस कर रहा है। यह बात ब्रिटेन के एक प्रमुख संगठन ने बयान जारी कर कही है।

मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन (एमसीबी) ने चुनाव के दौरान कंजरवेटिव पार्टी की ओर से लगे इस्लामोफोबिया को भूनने के लिए ओवन तैयार के नारे की जांच की मांग की है। यह नारा चुनाव के प्रमुख नारों में शुमार रहा। अब जबकि कंजरवेटिव पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ सत्ता में फिर आई है तब मुस्लिमों को अपने भविष्य की चिंता हो रही है।

एमसीबी के महासचिव हारुन खान ने कहा है कि बोरिस जॉनसन को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला है लेकिन पूरे देश का मुस्लिम समुदाय इससे भयग्रस्त है। हम इस्लामोफोबिया के लिए ओवन रेडी वाले नारे को लेकर चिंतित हैं। हमारी प्रार्थना है कि जॉनसन अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल ब्रिटेन को जिम्मेदार बनाने में करें। कहा, ताजा चुनाव हाल के दशकों का सबसे ज्यादा विभाजनकारी चुनाव रहा। इसमें जीतने के लिए भेदभाव पैदा करने वाले नारे लगाए गए और अन्य कार्य किए गए। लेकिन अब जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं तब नए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकजुटता के लिए कार्य करना चाहिए। हारुन ने कहा, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री अब एकजुट राष्ट्र का नारा देंगे। वह सभी समुदायों को साथ लेकर चलेंगे।

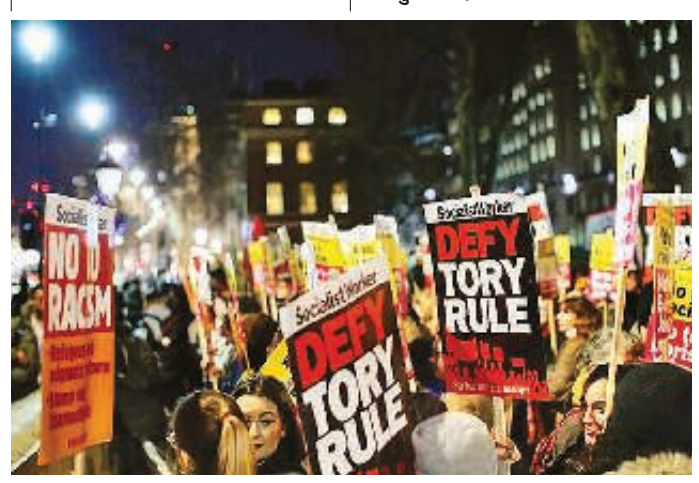

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली कंजरवेटिव पार्टी के चुनाव में भारी जीत के बाद लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट के समीप हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। रायटर

लेबर पार्टी को रहा है मुस्लिम समुदाय का समर्थन

चुनाव में मुस्लिम समुदाय का समर्थन लेबर पार्टी को रहा था। पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ब्रिटेन में खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश की थी। चुनावी चर्चा के दौरान ही लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमंस में जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रस्ताव पारित कराया था, जो बाद बाद सरकार ने खारिज कर दिया था। इस प्रस्ताव और अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में भारतीय उच्चायोग पर हुए प्रदर्शन ने ब्रिटिश- भारतीय समुदाय को लेबर पार्टी का विरोधी बना दिया। प्रदर्शन को लेबर पार्टी के नेताओं का समर्थन था। नतीजतन, भारतीय समुदाय एकजुट होकर कंजरवेटिव पार्टी के साथ आया और उसकी चुनावी जीत को प्रभावशाली बनाया।

न्यूज गैलरी

नेपाल में विस्फोट से पुलिस अधिकारी समेत तीन की मौत

काठमांडू : दक्षिण नेपाल के एक घर में हुए विस्फोट में गृहस्वामी और उसके पुत्र समेत एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। तीन अन्य घायल भी हुए हैं। यह घटना राजधानी काठमांडू से करीब दो सौ किलोमीटर दूर महेंद्रनगर में हुई। शुक्रवार रात अपने घर के गेट पर संदिग्ध वस्तु दिखने पर एक दवा कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी थी। जांच के दौरान विस्फोट हो गया था। (एपी)

हांगकांग में करोड़ों की नकली दवाएं बरामद, सात गिरफ्तार

हांगकांग : हांगकांग के सीमा शुल्क अधिकारियों ने नकली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी है। यह दस वर्ष में बड़ी सफलता बताई जा रही है। ऐसी दवाएं खरीदने के लिए चीनी तस्कर यहां आते हैं। बरामद दवाएं करीब 24 लाख टैबलेट और 470 लीटर लिक्विड के रूप में हैं। अधिकारियों ने बताया कि बरामद दवाएं गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के नाम पर बेची जाती थीं। (आइएएनएस)

सीरिया में बारूदी सुरंग फटने से तीन बच्चों की गई जान

दमिश्क : सीरिया के दक्षिणी प्रांत दारा में बारूदी सुरंग फटने से तीन बच्चों की मौत हो गई। चार अन्य घायल हो गए। घायल बच्चों में कुछ की हालत गंभीर बनी है। यह धमाका नसीब शहर में हुआ। इस शहर पर एक समय विद्रोहियों का कब्जा रहा। उनके द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में अब तक दर्जनों की जान जा चुकी है। (आइएएनएस)

ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

तैयारी ▶ अगले साल मार्च से शुरू करेगा सुनवाई, 30 जून से पहले सुनाएगा फैसला

टैक्स रिटर्न सार्वजनिक नहीं करने वाले निक्सन के बाद दूसरे राष्ट्रपति हैं ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसियां : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट टैक्स रिटर्न और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कंजरवेटिव न्यायाधीशों के बहुमत वाले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अगले साल मार्च में सुनवाई करेगा और 30 जून से पहले फैसला सुना देगा। ट्रंप, रिचर्ड निक्सन के बाद पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न सार्वजनिक नहीं किया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि वह आंतरिक राजस्व सेवा (आइआरएस) द्वारा की जाने वाली ऑडिट के तहत आते हैं।

ट्रंप के वकील जे सेकुलो ने एक बयान में कहा, 'हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से जुड़े तीन लंबित मामलों की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है। ये मामले महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों से जुड़े हैं। जब भी सुनवाई होगी हम अपने लिखित और मौखिक तर्क कोर्ट के सामने पेश करेंगे।'

वाशिंगटन स्थित ह्वाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ट्रंप के खिलाफ संपत्ति से जुड़े दो मामले दर्ज हैं। एक में, संसद की हाउस ओवरसाइट एंड रिफॉर्म कमेटी ने ट्रंप के वर्षों तक के व्यक्तिगत और कॉरपोरेट वित्तीय रिकॉर्ड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की अकाउंटिंग फर्म 'मजर्स यूएसए' को समन जारी किया है। दूसरे में, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके व्यवसाय से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों के लिए हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटेलिजेंस समितियों ने ड्यूश बैंक और कैपिटल वन को समन जारी किया है। वहीं, तीसरे मामले में ट्रंप के व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी जानकारी के लिए मजर्स यूएसए को एक समन जारी किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ महाभियोग को अनुचित बताया

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनके नेतृत्व में देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना अनुचित है। इससे पहले उन्होंने महाभियोग प्रक्रिया को धोखा और राजनीति से प्रेरित बताया था।

ट्रंप ने शुक्रवार रात को ट्वीट किया, 'मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसे में मेरे खिलाफ महाभियोग चलाया जाना अनुचित है।' ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अपने प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी। बता दें कि अमेरिकी सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दो आरोपों को मंजूरी दे दी। इस तरह कथित कदाचार के लिए प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद महाभियोग की कार्यवाही 100 सदस्यीय अमेरिकी सीनेट में जाएगी, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। ट्रंप ने ट्वीट किया, 'डेमोक्रेट नफरत की पार्टी बन गई है। ये हमारे देश के लिए बहुत खराब है।'

गुस्से में किया 123 बार ट्वीट

अपने खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की अनुमति दिए जाने से नाराज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 123 बार ट्वीट किया। अपने ट्विटर अकाउंट को टाइपराइटर कहने वाले ट्रंप ने ट्वीट, रीट्वीट मिलाकर महाभियोग चलाए जाने के खिलाफ 123 बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूर्व में सबसे अधिक ट्वीट करने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

'जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिबद्धता दिखाए विश्व समुदाय'

- ईयू ने कहा, संकेत दें कि उत्सर्जन में और कटौती के लिए सभी देश तैयार हैं
- पेरिस समझौते को लागू करने में विफल रहने पर कॉप 25 को आगे बढ़ाया गया

सम्मेलन को संबोधित करतीं कॉप-25 की अध्यक्ष कैरोलीन। रायटर

मैड्रिड, रायटर : मैड्रिड शिखर सम्मेलन में कायम गतिरोध के बीच यूरोपीय संघ (ईयू) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसने शनिवार को कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिबद्धता दिखाते हुए विश्व समुदाय को संकेत देना चाहिए कि सभी देश उत्सर्जन में और कटौती के लिए तैयार हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी आशंका है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बता दें कि विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार करने के लिए कॉप-25 नामक यह शिखर सम्मेलन दो दिसंबर को शुरू हुआ था और शुक्रवार को इसे समाप्त होना था, लेकिन चार साल पहले पेरिस में हुए समझौते को लागू करने में विफल रहने पर इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

ईयू की ओर से फिनलैंड की पर्यावरण मंत्री क्रिस्टा मिकोनेन ने शनिवार को हुए ताजा सत्र में कहा कि उत्सर्जन कटौती की आवश्यकता पर सहमत हुए बिना यहां से जाना ठीक नहीं होगा। इस पर हमें सहमत होना ही होगा क्योंकि बाहर का विश्व हमसे इसकी उम्मीद करता है और हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए। यूरोपीय संघ की इस मांग का नेपाल, स्विटजरलैंड, उरुग्वे और मार्शल आइसलैंड सहित कई देशों ने भी समर्थन किया। उधर, पर्यवेक्षकों का कहना है कि शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे चिली द्वारा तैयार किए गए नवीनतम मसौदा बयान में अगले साल से पेरिस समझौते को लागू करने के संबंध में कोई मजबूत प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए जोर दे रहे देशों का कहना है कि प्रदूषण फैलाने में अग्रणी रहने वाले देशों को अगले साल इससे निपटने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि इस समझौते को अमलीजामा पहनाया जा सके। सत्र के दौरान सबसे कम विकसित देशों की अध्यक्षता कर रहे भूटान के सोनम फुंटशो वांगडी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से निपटने के लिए नतीजे पर पहुंचे बिना हम सभी का अपने देश लौटना आसान नहीं होगा।

पाकिस्तान में पोलियो होना शर्म की बात : इमरान

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पोलियो मामलों के उभार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह मुल्क के लिए शर्म की बात है। उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे पोलियो रोधी अभियान में ना सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए बल्कि मुल्क की इज्जत के लिए भी शामिल हों।

प्रधानमंत्री इमरान ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रव्यापी पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, 'पाकिस्तान दुनिया के उन दो देशों में एक है, जहां पोलियो अब भी मौजूद है। यह शर्म की बात है। मैं माताओं से आग्रह करता हूं कि वे हेल्थ वर्करों के पास जाएं और अपने बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक दिलाएं। यह आपके बच्चे और मुल्क के लिए अहम है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजर में अभी तक पोलियो पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है।

इस साल पोलिया के 98 मामले : पाकिस्तान में इस साल पोलियो के 98 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 72 मामले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से हैं। 2018 में पोलियो के 12 मामलों का पता चला था। जबकि 2017 में महज आठ मामले पाए गए थे।

ब्रिटेन के साथ गोरखा भर्ती करार की समीक्षा चाहता है नेपाल

- भर्ती प्रक्रिया में नहीं है इस हिमालयी देश की कोई भूमिका

काठमांडू, रायटर : नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि उनका देश ब्रिटेन की सेना में गोरखा जवानों की भर्ती को लेकर हुए करार की समीक्षा करना चाहता है। उनके अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया में काठमांडू की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए इस करार की समीक्षा जरूरी है। नेपाल ने यह मांग ऐसे समय की है, जब ब्रिटिश सेना गोरखा ब्रिगेड में पहली बार नेपाली महिलाओं की भर्ती करने की तैयारी में है।

ब्रिटिश मीडिया में आई खबरों के अनुसार, अभी यह साफ नहीं है कि कितनी संख्या में गोरखा महिलाओं की भर्ती होगी, लेकिन यह तय है कि अगले साल ब्रिटिश सेना में गोरखा महिलाओं का प्रशिक्षण हो सकता है। ग्यावली ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि नेपाल इस 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा चाहता है। क्योंकि यह करार किसी विदेशी सेना में गोरखा युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में काठमांडू को कोई भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देता। उनके मुताबिक, 'इस समझौते के कुछ प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गए हैं। इसलिए हमने ब्रिटेन से कहा है कि हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए और इसे द्विपक्षीय समझौता बनाना चाहिए।' उन्होंने बताया कि नए समझौते में ब्रिटिश सेना के गोरखा जवानों की पेंशन समेत कई समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए।

1815 से गोरखा जवानों की भर्ती कर रहा ब्रिटेन : ब्रिटेन 1815 से अपनी सेना में गोरखा जवानों की भर्ती कर रहा है। 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद नई दिल्ली, लंदन और काठमांडू के बीच एक करार हुआ था। इस करार के तहत भारत और ब्रिटेन गोरखा जवानों की भर्ती अपनी-अपनी सेना में करते हैं। 2007 में ब्रिटेन ने अपने विशेष बल में गोरखा महिलाओं को भर्ती करने का एलान किया था।

गोरखा ब्रिगेड में 3 हजार नेपाली

ब्रिटिश सेना के गोरखा ब्रिगेड में इस समय करीब तीन हजार नेपाली जवान हैं। वर्तमान में इन जवानों की तैनाती इराक, अफगानिस्तान और बाल्कन में है।

महिला हिंसा के विरोध में प्रदर्शन

महिला हिंसा और दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोत्तरी के विरोध में ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन के दौरान नारीवादी गीत 'रेपिस्ट इन योअर पाथ' गाती महिलाएं। दुष्कर्म जैसे मामलों को लेकर यह गीत दुनियाभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और विरोध का प्रतीक बन गया है। इस गीत की शुरुआत चिली के आंदोलन के वक्त हुई थी। एपी

सूडान के पूर्व राष्ट्रपति को दो साल की कैद

खारतूम, एजेंसियां : भ्रष्टाचार और विदेशी मुद्रा रखने के आरोप में सूडान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर (75) को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें जेल में नहीं, बल्कि हिरासत शिविर में रखा जाएगा। कोर्ट ने बशीर के आवास से बरामद किए गए लाखों यूरो और सूडानी पाउंड को भी जब्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि बशीर के खिलाफ सूडान के विभिन्न अदालतों में मामले चल रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला है, जिसमें फैसला सुनाया गया है।

1989 में सैन्य तख्तापलट के बाद बशीर के हाथों में सूडान की सत्ता आई थी, लेकिन बढ़ती कीमतों और आवश्यक सामानों की कमी के चलते पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई और अंततः इसी साल अप्रैल में उन्हें सत्ता से हटना पड़ा था।

उसी समय से वह हिरासत में हैं। सफेद लबादा और पगड़ी पहने बशीर फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में बने धातु के बाड़े में चुपचाप खड़े थे। फैसला सुनाए जाने के पहले बशीर के समर्थकों ने कार्यवाही में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया।

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

वाशिंगटन, प्रेट्र : इराक के बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एक परिसर पर दो रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने शुक्रवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास जिस परिसर को निशाना बनाया गया वहां अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। सोमवार को हुई इस घटना में कई इराकी सैनिक घायल हुए थे।

अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगा।

एस्पर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (सीएफआर) थिंक टैंक में कहा, 'हम ईरान की आक्रामकता के जवाब में अपने सहयोगियों और साझेदारों के बीच बढ़े हुए बोझ को बांटकर उन्हें प्रोत्साहित कर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।' आरोप लगाया कि ईरान लगातार पश्चिम एशिया में अपना घातक प्रभाव और अस्थिरकारी गतिविधियां बढ़ा रहा है। उधर, 'एएफपी' की खबर के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपिओ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इराक में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

पोंपिओ ने एक बयान में कहा, 'हम निश्चित रूप से... इस मौके का इस्तेमाल कर ईरान के नेताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि अगर उन्होंने या उनसे संबंधित किसी ने भी हम पर (अमेरिकी सैनिकों पर), हमारे सहयोगियों या हमारे हितों पर हमला किया तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा।'

उन्होंने कहा, 'ईरान को निश्चित रूप से अपने पड़ोसी देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और इराक तथा समूचे क्षेत्र में तीसरे पक्ष को घातक सहायता और समर्थन देना बंद करना चाहिए।'

उ. कोरिया ने किया खास हथियार का परीक्षण

सियोल, एएफपी : उत्तर कोरिया ने फिर से घातक हथियार का परीक्षण किया है और उसे सफल करार दिया है। सोहाए सैटेलाइट लांच साइट पर किए गए इस परीक्षण में इस्तेमाल किए गए हथियार का विवरण उत्तर कोरिया ने नहीं दिया है लेकिन इसे महत्वपूर्ण परीक्षण का दर्जा दिया है।

परीक्षण का एलान उत्तर कोरिया के लिए नियुक्त अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बीगन के दक्षिण कोरिया दौरे से एक दिन पहले किया गया है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका प्रशांत महासागर के ऊपर से मध्यम दूरी के बैलेस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के मुताबिक महत्वपूर्ण परीक्षण 13 दिसंबर को रात 22.41 से 22.48 बजे तक किया गया। यह परीक्षण सफल रहा। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल का एक और परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया पूर्व में भी इस तरह के परीक्षण कर चुका है। लेकिन सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल पाक जोन चोन ने कहा है कि यह उत्तर कोरिया के नए रणनीतिक हथियार का सफल परीक्षण था जिसमें अनमोल जानकारियां हासिल हुईं। प्रवक्ता ने कहा कि यह परीक्षण उत्तर कोरिया को किसी हमले के खिलाफ सक्षम प्रतिरोधक क्षमता देगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया पर किसी भी तरह के मिसाइल और रॉकेट इंजन के परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगा रखी है, लेकिन वह सभी प्रतिबंधों को खारिज कर अक्सर परीक्षण करता रहता है। प्रतिबंधों से राहत की मांग पर उसके नेता किम जोंग उन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीन बार की वार्ता विफल रही है।

दक्षिण कोरिया के पाजू में एक प्रदर्शनी में उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल परीक्षण की फोटो प्रदर्शित की गई। उत्तर कोरिया ने शनिवार को भी एक और मिसाइल का परीक्षण किया है। एपी

भारतीय मूल के एमी बेरा अमेरिकी संसदीय समिति के अध्यक्ष नामित

- ब्रैड शर्मन की जगह लेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के चार बार के सांसद बेरा

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद एमी बेरा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अमेरिकी संसद की एशिया, प्रशांत और अप्रसार मामलों की उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वह ब्रैड शर्मन की जगह लेंगे।

कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के चार बार के सांसद बेरा ने कहा, 'मैं एशिया, प्रशांत और अप्रसार उप समिति का अध्यक्ष बनने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है और इस महाद्वीप में अमेरिका के गहरे और स्थायी संबंध हैं। मैं इस समिति के प्रमुख के तौर पर यह सुनिश्चित करूंगा कि अमेरिका अपने सभी राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक तंत्रों के उपयोग से अपने हितों को साधने के साथ ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं को भी बरकरार रखे।' 54 वर्षीय बेरा कोरियाई कॉकस के सह-अध्यक्ष भी हैं। वह भारत और भारतीय-अमेरिकी कॉकस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेरा 2013 से अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं।

भारतीय मूल के सांसद एमी बेरा। बेराडॉटहाउस

ये भी जानिए

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच धीमी रहने की उम्मीद है क्योंकि यहां पर पिछले दो दिनों से काफी बारिश हुई है। हालांकि रविवार को मौसम के साफ रहने की उम्मीद है।

गांगुली के लिए मेरे मन में काफी आदर : शास्त्री

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय कोच रवि शास्त्री ने कहा कि वह बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली की काफी इज्जत करते हैं और जो उनके रिश्तों पर सवाल उठाते हैं 'उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं'। पिछले सप्ताह गांगुली ने शास्त्री के साथ मतभेदों की अटकलों को कोरी अफवाह बताया था।

शास्त्री ने एक टीवी चैनल से कहा कि जहां तक सौरव-शास्त्री की बात है तो यह मीडिया के लिए चाट और भेलपुरी की तरह मिर्च मसाला है। भारतीय कोच ने कहा कि गांगुली ने क्रिकेटर के तौर पर जो कुछ किया है मैं उनका काफी सम्मान करता हूं। उन्होंने सट्टेबाजी प्रकरण के बाद भारतीय क्रिकेट की कमान सबसे मुश्किल समय में संभाली। आपको वापसी के लिए लोगों का भरोसा चाहिए होता है और मैं उसका सम्मान करता हूं। और अगर कोई इसका सम्मान नहीं करता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। शास्त्री और गांगुली के बीच मतभेद 2016 में सार्वजनिक हुए थे जब शास्त्री ने कोच के पद के लिये आवेदन किया था और गांगुली उस समय क्रिकेट सलाहकार समिति में थे जिसने अनिल कुंबले को चुना था। शास्त्री ने बिना किसी लोकतांत्रिक तरीके से तीन साल तक बोर्ड के संचालन के बाद गांगुली के अध्यक्ष बनने को 'शानदार' करार दिया। उन्होंने कहा कि गांगुली का अध्यक्ष बनना शानदार है। सबसे पहले मैं इस बात को लेकर रोमांचित हूं कि बीसीसीआइ फिर से अस्तित्व में है। हम तीन साल तक बीसीसीआइ के बिना खेले।

55 वर्षीय कोच शास्त्री को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता है। इस पर शास्त्री ने कहा कि सोशल मीडिया क्या है? ट्रोल तो नहीं है? मैं अपने प्रशंसकों के लिए पोस्ट करता हूं। वे पढ़ते हैं, धन्यवाद। उसके बाद भाड़ में गए सब। यह सिर्फ मेरे प्रशंसकों के लिए है कि मैं यहां हूं और यह कर रहा हूं। बोलने वाले बोलेंगे। हमारा देश 130 करोड़ आबादी वाला देश है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है वह ऐसी बातें करते हैं। शास्त्री ने कहा कि मैं भारतीय टीम का कोच हूं तो निश्चित तौर पर मुझ पर भी दबाव रहता है। यह ऐसा दबाव है जिसका आपको जवाब देना पड़ता है। आप एक जिम्मेदारी भरे पद पर हैं।

आलोचकों पर शास्त्री ने कहा कि आप एक अंगुली मेरी ओर उठाएंगे तो तीन अंगुली आपकी ओर उठेंगी, यह याद रखिए। यह भारतीय टीम हारना पसंद नहीं करती है। शास्त्री ने कहा कि लोगों को सवाल उठाने का हक है। मैं कहता भी हूं यह उनका काम है, लेकिन मैं जो कहता हूं मुझे कहने दीजिए, मुझे रोकिए मत।

देखते हैं धौनी का शरीर कैसा रहता है, विश्व कप में राहुल भी विकल्प : शास्त्री

नई दिल्ली : ऋषभ पंत अच्छा नहीं कर रहे हैं और धौनी की वापसी पर संशय है। ऐसे में शास्त्री ने विश्व कप में केएल राहुल को विकेटकीपर बनाने की बात से इन्कार नहीं किया। शास्त्री ने कहा कि यह अच्छा है धौनी ने ब्रेक लिया। मैं आइपीएल के वक्त देखना चाहूंगा जब वह दोबारा खेलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वह वनडे खेलना चाहते हैं। वह टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। टी-20 उनके लिए विकल्प है। यह ऐसा प्रारूप है जो उनके लिए ही बना है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या उनका शरीर इसके लिए तैयार है? इसका जवाब सिर्फ वही दे पाएंगे। बाकी चीजें जो जरूरत होगी वह अच्छी मानसिकता की। उन्होंने कहा कि अगर वह खेलने का फैसला करते हैं तो वह खेलेंगे क्योंकि वह आइपीएल खेलेंगे। इसके बाद वह स्वच्छ दिमाग के साथ टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। इसके बाद आपको उनकी फॉर्म देखनी होगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर एक दिग्गज खेलने का फैसला करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्री को लगता है कि राहुल भी विकेटकीपिंग का एक विकल्प हैं क्योंकि वह आइपीएल के साथ ही घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए भी सफेद गेंद की क्रिकेट में विकेटकीपिंग करते हैं। पंत पर शास्त्री ने कहा कि उन्हें शांत रहने की जरूरत है। आपको अपनी बल्लेबाजी पर मजबूती दिखानी होगी। यह खेल आपको सिखाता है। यहां तकनीक है और पागलपन भी। कई बार घरेलू क्रिकेट खेलना अच्छा रहता है। इससे खिलाड़ी को अपनी गलतियां पकड़ने का मौका मिलता है। वह खुशकिस्मत है कि उसके पास अभी उम्र है। शास्त्री ने यह इशारा किया है कि पंत को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए रिलीज किया जा सकता है। अगर वह तीन या छह महीने के लिए अपने खेल पर काम करेगा तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ बुरा हुआ है। वह मजबूती के साथ वापसी करेगा। उसे समय देने की जरूरत है। अगर वह पांच वर्ष में कुछ नहीं कर पाया तब लोगों को बोलने का हक है।

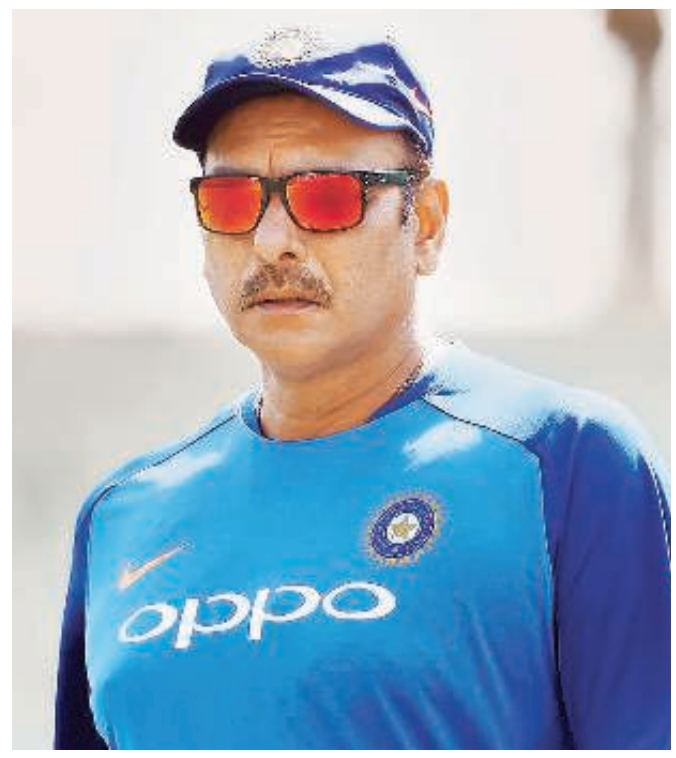

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री। फाइल फोटो, प्रेट्र

आगाज ▶ भारत और वेस्टइंडीज के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज

अब वनडे में विंडीज को पटखनी देने की बारी

टी-20 की लय को बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया

चेन्नई, प्रेट्र : भारत रविवार से यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा जिसमें मेजबान टीम की नजरें कैरेबियाई टीम के खिलाफ लगातार 10वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने पर टिकी होंगी। पिछले 24 घंटे से यहां बारिश हो रही है जिससे दोनों टीमों की नजरें मौसम पर भी टिकी होंगी। मेजबान टीम को तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की कमी खलेगी। भुवनेश्वर हाल ही में फिट होकर टी-20 टीम में आए थे लेकिन फिर चोटिल होकर बार हो गए जबकि धवन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान लगी चोट से अब तक नहीं उबर पाए हैं। आइपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलने वाले मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को चोटिल भुवनेश्वर के विकल्प के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

विराट की लय दिलाएगी जीत : मुंबई में सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के अलावा कप्तान विराट कोहली की शानदार पारियों से टी-20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम लय में है। धवन की गैरमौजूदगी में वनडे सीरीज में भी पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी रोहित और राहुल को सौंपी जा सकती है।

मयंक को मिल सकता है मौका : मयंक अग्रवाल को धवन के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है और देखना यह होगा कि उन्हें वनडे क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिलता है या नहीं। कर्नाटक का यह बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में था और डिंडीगुल में तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद टीम से जुड़ा है।

नंबर-चार पर श्रेयस अय्यर हिट : श्रेयस अय्यर मौकों का फायदा उठाने में सफल रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें चौथे नंबर पर बरकरार रखा जाएगा। यह स्थान पिछले कुछ समय से चर्चा का केंद्र रहा है। अंबाती रायुडू, रिषभ पंत और विजय शंकर सहित कई खिलाड़ियों को इस स्थान पर आजमाया गया जिसके बाद अय्यर इस क्रम पर अपनी जगह पक्की करने की कोशिश में जुटे हैं।

पंत को चाहिए आत्मविश्वास : सभी की नजरें विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत पर भी टिकी होंगी जो पिछले कुछ समय से बल्ले और दस्ताने के साथ प्रभावी प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पहले वनडे के जरिए उन्हें कोहली और टीम प्रबंधन के भरोसे पर खरा उतरने का मौका मिलेगा, जिसके लिए उन्हें आत्मविश्वास की जरूरत है।

कुलदीप-चहल को मिलेगा मौका : यह भी देखना होगा कि युजवेंद्रा सिंह चहल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी को चेपक की स्पिन की अनुकूल पिच पर एक बार फिर साथ खेलने का मौका मिलता है या नहीं। ये दोनों पिछली बार विश्व कप में एक साथ खेले थे। अनुभवी मुहम्मद शमी और दीपक चाहर का तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल होना तय है। दोनों ही तेज गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चुनौती देते दिखेंगे।

लुइस की चोट ने बढ़ाई मेहमानों की मुश्किल : वेस्टइंडीज को उम्मीद होगी कि मुंबई में अंतिम टी-20 के दौरान क्षेत्ररक्षण करते हुए चोटिल हुए आक्रामक सलामी बल्लेबाज इविन लुइस वनडे सीरीज में खेल पाएंगे। टीम अधिकारियों का कहना है कि पहले वनडे से पूर्व उनकी चोट का आकलन किया जाएगा। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को आक्रामक बल्लेबाजी करने के अलावा विकेट भी बचाने होंगे।

भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पहले चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार को बल्लेबाजी का अभ्यास करते वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड। प्रेट्र

130 वनडे अब तक दोनों टीम के बीच खेले जा चुके हैं। दोनों टीम ने 62-62 मुकाबले जीते हैं। दो मैच टाई रहे जबकि चार परिणाम रहित रहे

55 वनडे अब तक दोनों टीम के बीच भारतीय सरजमीं पर खेले गए हैं। कमाल की बात है कि यहां भी दोनों टीम 27-27 वनडे जीतकर बराबरी पर है। एक मुकाबला टाई रहा है

4 मुकाबले अब तक दोनों टीम के बीच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में हुए हैं। भारत ने यहां तीन मैच जीते जबकि एक मैच में हार मिली है

35 पारियों में 2146 रन बनाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं कोहली। पिछली नौ पारियों में कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 174 के औसत से 870 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक शामिल रहे

02 वर्ष वेस्टइंडीज के शाई होप के लिए वेहद शानदार रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 41 पारियों में 60.54 के औसत से रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और दस अर्धशतक शामिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 76 का रहा जो इन दिनों के हिसाब से वेहद कम है

हम वनडे में बेहतर प्रदर्शन करने के मिशन पर : पोलार्ड

चेन्नई, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने शनिवार को कहा कि उनकी टीम वनडे मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के 'मिशन' पर है लेकिन शायद अनुकूल नतीजे तुरंत नहीं मिले। पोलार्ड ने कहा कि उनकी टीम पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 3-0 की जीत की लय को आगे बढ़ाना चाहेगी।

पोलार्ड ने यहां वनडे मैच से पहले कहा कि हम एक मिशन पर हैं और हमारी रणनीति स्पष्ट है कि 50 ओवर के क्रिकेट में क्या रुख अपनाना है। इसके लिए एक प्रक्रिया है और हम असल में इसी से गुजर रहे हैं। नतीजे शायद तुरंत नहीं दिखाई दें। अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी सीरीज अच्छी रही। अब हम बेहतर टीम भारत के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। यह पूछने पर कि उनकी टीम ने वनडे मैचों में बीच के ओवरों में खेलने को लेकर क्या रणनीति बनाई है, पोलार्ड ने कहा कि इस पर चर्चा हुई है और खिलाड़ियों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी है। कप्तान ने कहा कि हमने चर्चा की है कि बीच के ओवरों में कैसे खेलना है, ये बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में और हम इस प्रारूप में कैसे खेलना चाहते हैं। बेशक हम यह नहीं बता सकते हैं कि हमारी रणनीति क्या है। खिलाड़ियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी है और अब सब इन्हें अमलीजामा पहनाने पर निर्भर करता है। पोलार्ड ने कहा कि वनडे टीम में रोस्टन चेस के शामिल होने से टीम संतुलित हुई है। उन्होंने कहा कि वह (चेस) हमारी टीम में अच्छा संतुलन लेकर आता है। वह टीम के लिए शानदार है, वह ऐसा खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट में मध्य क्रम में खेलता है और उसके नाम पर शतक भी दर्ज है। वह गेंदबाजी भी कर सकता है। उसके टीम में होने से हमें एक अन्य विशेषज्ञ खिलाड़ी को खिलाने का मौका मिलता है। कप्तान ने कहा कि वह हमारे लिए बेशकीमती है। वह हमारे लिए अहम भूमिका निभाएगा। ड्वेन ब्रावो के टी-20 अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी करने के बारे में पूछने पर पोलार्ड ने कहा कि एक कप्तान के रूप में मुझे यह जानकर खुशी है कि ब्रावो जैसा खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध है।

डायपर में क्रिकेटर, केविन ने विराट से पूछा, टीम में लोगे?

नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने डायपर में क्रिकेट खेलते एक बच्चे का वीडियो विलप शेयर किया। उन्होंने साथ ही टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को सवाल पूछा कि क्या वह इस बच्चे को अपनी टीम में शामिल करेंगे। वीडियो में एक छोटा बच्चा है जो घर में क्रिकेट का अभ्यास करते हुए नजर आ रहा है। डायपर पहने यह बच्चा फ्रंट फुट पर शॉट खेल रहा है। उससे पीटरसन खासे प्रभावित हुए और विराट को टैग करते हुए उनसे सवाल किया। पीटरसन ने लिखा कि विराट कोहली आप इसे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, क्या आप इसे टीम में चुनेंगे। इस पर विराट ने भी पीटरसन को जवाब देते हुए लिखा कि यह लड़का कहां से है, अविश्वसनीय। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं हो सकता।

वेस्टइंडीज को गेमप्लान के साथ उतरना होगा

के श्रीकांत

कलम से

वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती 50 ओवरों के क्रिकेट में रास्ता तलाशना है। जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, तो उनके पास इस काम के लिए अलग खिलाड़ी हैं, लेकिन वनडे में उनके सामने ढेरों सवाल खड़े हैं। वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वे अच्छी शुरुआत को आगे तक नहीं बढ़ा पाते हैं। उनके पास पावर हिटर हैं और उनके गेंदबाजों के पास हवा में गति के साथ विविधता भी है। इसके बावजूद खराब परिणाम इसलिए आता है क्योंकि उनके पास कोई गेम प्लान नहीं है।

अगर कोई टीम 50 और 20 ओवरों में एक जैसी योजना के साथ उतरेगी, तो उसे परेशानी होगी। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में मेहमान टीम अपना दिन होने पर किसी को भी हरा सकती है, लेकिन जब उनका दिन न हो तो कमजोर टीमें भी उन्हें हरा सकती हैं। ऐसा हम कई बार देख चुके हैं। उन्हें यहां अलग रणनीति के साथ खेलना होगा और मुश्किल समय में धैर्य से काम लेना होगा। दूसरी तरफ भारतीय टीम एक बढ़िया काम करने वाली मशीन की तरह दिख रही है, जो हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। इस टीम में शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह भी जुड़ जाएं, तो दुनिया की सबसे बेहतर संतुलित टीम बन जाएगी। हालांकि बुमराह चोट से जूझ रहे हैं और उनके विकल्प उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ टीम के सामने दिक्कत कर सकता है। खासतौर से विदेशी धरती पर।

भुवनेश्वर कुमार की कमी भारतीय टीम को खलेगी। टी-20 सीरीज में उनका अनुभव देखने को मिला है और उनका वनडे सीरीज न खेलना दुर्भाग्यजनक है। अगली सीरीज में बुमराह और हार्दिक पांड्या की वापसी की खबर खुशी देने वाली है। मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ संयोजन को नियमित तौर पर मैदान में देखना चाहता हूं। अगर यह टीम चोटों से दूर रहती है, तो 50 ओवरों के क्रिकेट पर राज कर सकती है। चेन्नई में पिछले दो दिन से बारिश हो रही है, जो प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस वजह से पिच और मैदान काफी धीमा हो सकता है। अगर मौसम मोहलत देता है, तो 250 रन का स्कोर भी काफी रहेगा।

आज के मैच में ACC KAMAAL KA MOMENT कौन जीतेगा?
वोट करने के लिए, लॉग ऑन करें facebook.com/accind
ACC OFFICIAL PARTNER

मुझे पता है कि अलग प्रारूप में कैसे ढलते हैं : मयंक

नजरिया

चेन्नई, प्रेट्र : टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल अब वनडे में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मयंक को चोटिल शिखर धवन की जगह वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार से यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू हो रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

बीसीसीआइ ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मयंक स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल के साथ बातचीत कर रहे हैं। मयंक ने कहा कि अगर मैं आगे भी इसी तरह से खेलता रहा तो यह मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मुझे खाली बैठने की जगह क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब प्रारूप में बदलाव के कारण मानसिकता बदलने की बात आती है तो आपका बेसिक्स (स्वाभाविक खेल) वही रहता है। अगर आपका गेम प्लान स्पष्ट है तो खुद को अलग-अलग प्रारूप के अनुरूप ढलना आसान होता है और खेल को लेकर आपकी समझ स्पष्ट होती है। मयंक ने अब तक नौ टेस्ट मैचों में तीन शतक लगाए हैं। इन तीन शतकों में दो दोहरे शतक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहीं पर भी खेलूं, हमेशा यही सोचता हूं कि अपनी टीम के लिए कैसे योगदान दे सकता हूं। अगर मैं रन नहीं भी बना पाऊं तो मैं क्षेत्ररक्षण में योगदान देने के बारे में सोचता हूं।

भारतीय वनडे टीम में शामिल किए गए युवा बल्लेबाज मयंक अग्रवाल। फाइल फोटो, एपी

रन बनाते ही पंत बड़े खिलाड़ी बनेंगे: राठौर

चेन्नई : भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत का समर्थन करते हुए कहा है कि उनमें ढेर सारी प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि पंत अगर एक बार रन बनाना शुरू कर देते हैं तो वह एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएंगे। राठौर ने मैच से पहले कहा कि हम पंत पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर काफी क्षमता है और हर किसी का मानना है कि वह किसी भी टीम के लिए एक्स-फैक्टर बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन ने उनका समर्थन किया है क्योंकि हम सभी का मानना है कि वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं। एक बार अगर वह रन बनाना शुरू कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि भारतीय टीम चेज करने में माहिर है। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 में टीम 171 रन का बचाव नहीं कर पाई थी। भारतीय बल्लेबाजी कोच ने कहा कि मुझे लगता है कि जब लक्ष्य का पीछा करने की बात आती है तब हम दुनिया की नंबर -1 टीम हैं।

मुश्किल

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी रीहैब के लिए एनसीए जाने से कर दिया है इन्कार

भुवनेश्वर की चोट ने खोली एनसीए की पोल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भुवनेश्वर कुमार की चोट ने एक बार फिर 'भानुमती के पिटारे' को खोल दिया है। इस चोट ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में काम कर रहे विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने भुवनेश्वर को क्लीन चिट दे दी थी। अब ऐसी खबरें हैं कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने भी रीहैब के लिए एनसीए जाने से इन्कार कर दिया है।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक अनुबंधित खिलाड़ियों को रीहैब के लिए एनसीए जाना पड़ता है लेकिन पांड्या और बुमराह ने साफ कर दिया है कि वह बेंगलुरु नहीं जाएंगे। अधिकारी ने कहा, 'पांड्या और बुमराह दोनों ने टीम प्रबंधन से साफ कह दिया है कि वह रीहैब के लिए अकादमी नहीं जाएंगे और इसलिए योगेश परमार पांड्या पर नजर बनाए हुए हैं जबकि नितिन पटेल ने बुमराह पर कड़ी नजर रखी है। हां, यह लोग अनुबंधित खिलाड़ी हैं और उन्हें एनसीए में होना चाहिए था, लेकिन जोखिम ज्यादा है और खिलाड़ी चोटों को लेकर गंभीर हैं इसलिए एक समय के बाद आपको खिलाड़ियों को आजादी देनी होती है कि वह अपने हित को लेकर फैसले ले सकें।'

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। फाइल फोटो, प्रेट्र

भुवनेश्वर को हार्निया की शिकायत है। यह गेंदबाज विश्व कप के बाद से एनसीए से अंदर-बाहर होता रहा है क्योंकि उनकी कोशिश 100 फीसद फिट होने की है लेकिन एनसीए की टीम उनकी चोट को समझ पाने में असफल रही है और राष्ट्रीय टीम से दो मैच खेलने के बाद ही एक बार फिर वह चोटिल हो गए हैं। अधिकारी ने कहा, 'वह तीन महीने तक एनसीए में थे और बेंगलुरु में उनके कितने टेस्ट हुए, इसमें जाने के बजाए मैं यह कह सकता हूं कि उनकी सभी तरह से जांच कर ली गई थी लेकिन उनका हार्निया ठीक नहीं हुआ। जैसे ही मुंबई में दोबारा उनकी जांच की गई यह सामने आ गया।' उन्होंने कहा, 'ऐसा पहली बार नहीं है कि खिलाड़ी को एनसीए में इस तरह की परेशानी हुई हो। रिद्धिमान साहा का भी एक उदाहरण हमारे सामने है। हम सब जानते हैं कि वह टीम में क्या लेकर आते हैं। उनके पास स्विंग और सीम है। वह सर्जरी कराएंगे और आईपीएल के समय तक वापसी करेंगे।' उन्होंने कहा, 'अच्छी बात यह है कि भुवनेश्वर ने टीम प्रबंधन को जल्दी बता दिया कि उन्हें परेशानी हो रही है और नितिन तथा सपोर्ट स्टाफ ने भी उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। हमने प्रोटोकॉल का पालन किया था और उन्हें तभी टीम में लाया गया था जब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया था।'

विकेटकीपिंग सुधारें रिषभ पंत

मोहिंदर अमरनाथ

रिवर्स स्वीप

निसंदेह वेस्टइंडीज की टीम के पास शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसे क्रिकेट का प्रारूप लंबा होता है वह कैरेबियाई टीम के लिए नुकसान से कम नहीं होता। भारतीय टीम इस वनडे सीरीज में दावेदार के साथ उतरेगी। 1980 में कैरेबियाई टीम सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार होती थी और तब से अब दोनों टीमों के बीच यह अंतर बदल गया है।

वर्तमान में कुछ होनहार खिलाड़ियों के साथ वेस्टइंडीज की टीम युवा है लेकिन उनके साथ स्थिरता और अनुभव के मुद्दे जुड़े हैं। भारतीय टीम अभी संतुलित है और टीम के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी फॉर्म में हैं जिसकी शुरुआत कप्तान विराट कोहली से होती है। मैं विशेष रूप से मुहम्मद शमी से प्रभावित हुआ हूं जो अच्छी लय में है और अच्छे से गति में बदलाव का प्रयोग कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में यह देखने में अच्छा है कि भारतीय टीम के पास पर्याप्त तेज गेंदबाज हैं। एक हिस्सा है जो चिंतित कर सकता है, वो विकेटकीपिंग है। रिषभ पंत को शांत रहने की जरूरत है। हर बार उन्हें बल्लेबाजी करते समय बड़े शॉट खेलने के दबाव को महसूस नहीं करना चाहिए।

#WhatDrivesYou EXIDE

प्रशंसक से अपील, टीम का सम्मान करें : टाइगर वुड्स

मेलबर्न : अमेरिकी टीम के कप्तान टाइगर वुड्स ने प्रशंसकों से प्रेसिडेंट्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उनकी टीम का सम्मान करने को कहा है। यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें पैट्रिक रीड के कैडी की एक दर्शक से झड़प हो गई थी। रीड के कैडी केसलर काराइन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं। केसलर की एक दर्शक से जमकर कहासुनी हुई थी। पीजीए टूर ने बाद कहा था कि केसलर अब रविवार को कैडी की भूमिका में नहीं होंगे।

ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से हमें अच्छी तरह से अभ्यास नहीं मिल पा रहा है।
– दुति चंद, भारतीय महिला धावक

न्यूज गैलरी

पाक–श्रीलंका टेस्ट के चौथे दिन नहीं हुआ खेल

रावलपिंडी : देर रात हुई बारिश और खराब रोशनी के कारण पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन कोई खेल नहीं हो सका। मैदानकर्मी पिच के बिछे कवर्स से पानी हटाने और सुपर–सॉपर से मैदान को सुखाने में जुटे थे लेकिन खराब रोशनी और मौसम को देखते हुए अंपायर माइकल गफ और रिचर्ड केटलबर्ग ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे दिन का खेल रद करने की घोषणा की। दोनों टीमें इस्लामाबाद के होटल में रुकी रहीं। अब तक श्रीलंका ने 91.5 ओवर में छह विकेट पर 282 रन बना लिए हैं। धनंजय 87 रन पर नाबाद हैं। (एएफपी)

ओलंपिक खेलों के मूल घोषणापत्र की होगी नीलामी

न्यूयॉर्क : दुनियाभर के खिलाड़ी जहां टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं 127 साल पुराना आधुनिक ओलंपिक खेलों के घोषणापत्र की नीलामी की तैयारी है। नीलामीकर्ता सोथबे के अनुसार ओलंपिक के मूल घोषणापत्र के लिए बोली अगले सप्ताह होगी। इसके लिए एक मिलियन डॉलर की बोली लगने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पिएरे डि काउबेर्टिन द्वारा 1892 में हस्ताक्षरित इस दस्तावेज में पुरातन यूनानी खेलों को नया रूप देने और एथलीटों के लिए मानक तय किए गए थे। सोथबे के प्रमुख रिचर्ड ऑस्टिन ने कहा कि पिछले 125 सालों में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें बदलाव न हुआ हो और शांति का संदेश देता हो। ओलंपिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश एक–दूसरे के खिलाफ स्पर्धा करते हैं, लेकिन यह युद्ध नहीं होता। मूल घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के चार साल बाद एथेंस (यूनान) में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पदार्पण हुआ था। (रायटर)

भारतीय अंडर–17 फुटबॉल टीम पराजित

मुंबई : भारतीय अंडर–17 बालिका फुटबॉल टीम को स्वीडन के खिलाफ 0–3 से हार का सामना करना पड़ा। यह नवनियुक्त कोच थॉमस डेनर्बी के मार्गदर्शन में भारतीय टीम का पहला मुकाबला था। मुंबई फुटबॉल एरीना में स्वीडिश टीम ने पहले हॉफ में दो गोल किए जबकि दूसरे हॉफ में एक गोल दागा। मेहमान टीम के लिए मातिल्दा लिव विनबर्ग, इडा नादिने एंडरसन और मोनिका बाह ने गेंद को जाली में डाला। अब स्वीडन का अगला मुकाबला थाइलैंड से होगा। भारतीय टीम मंगलवार को थाइलैंड के सामने होगी। तालिका में स्वीडन की टीम तीन अंकों के साथ शीर्ष पर है। (आइएएनएस)

डे–नाइट टेस्ट ▸ मेहमान टीम न्यूजीलैंड की पहली पारी 166 रनों पर सिमटी

ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 417 रनों की बढ़त

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट पर बनाए 167 रन

7000 टेस्ट रन बनाने वाले 12वें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में उन्होंने महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ा

पर्थ, एएफपी : मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले डे-नाइट टेस्ट में शिकंजा कस लिया है। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने टीम को जोस हेजलवुड की कमी नहीं खेलने दी और मेहमान टीम को पहली पारी में 55.2 ओवर में सिर्फ 166 रनों पर समेट दिया। पहली पारी में 250 रनों की बढ़त के बाद गर्मी और एक नियमित गेंदबाज की कमी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान टीम को फॉलोऑन नहीं दिया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 57 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए हैं। अब मेजबान टीम की कुल बढ़त 417 रनों की हो चुकी है जबकि उसके चार विकेट अभी शेष हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पैट कमिंस एक जबकि मैथ्यू वेड आठ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

दूसरी पारी के दौरान ओपनर डेविड वार्नर अपने अंदाज के विपरीत धीमे खेले। वार्नर और बर्न्स ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। इसके बाद बर्न्स और मार्नस लाबुशाने के बीच दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की भागीदारी हुई। फॉर्म में चल रहे लाबुशाने जब चार रनों के निजी स्कोर पर थे तो उन्हें जीवनदान मिला। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अर्धशतक बनाया। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट पर 131 रन था, लेकिन इसके बाद 29 रनों के भीतर टीम ने पांच विकेट गंवा दिए।

डार को लगी चोट : कीवी स्पिनर मिशेल सेंटनर दिन में कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन दिनभर चर्चा में रहे। वे अंपायर अलीम डार से ऐसे टकराए कि उन्हें घुटने में चोट लग गई। वे करियर के 129वें टेस्ट में अंपायरिंग कर रहे हैं। डार मैदान पर ही कुछ देर लेटे रहे और उपचार कराया। इसके बाद फिर अपनी जिम्मेदारी संभाली। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला खामोश रहा। 16 के निजी स्कोर पर वैगनर की शॉर्ट गेंद जीत रावल के हाथों में खेल गए। 71 टेस्ट मैचों के अपने करियर में पहली बार स्मिथ लगातार तीन मैचों में कोई अर्धशतक भी नहीं बना सके हैं। ट्रेविस हेड और कप्तान टिम पेन ने भी निराश किया।

सस्ते में सिमटी कीवी टीम : इससे पहले सुबह मेहमान टीम ने पांच विकेट पर 109 रनों से आगे पारी बढ़ाई। केवल रॉस टेलर (80) ही मेजबान गेंदबाजों का सामना कर सके। नाथन लियोन की गेंद के टर्न को टेलर समझ नहीं सके और गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए स्मिथ के सुरक्षित हाथों में समा गई। कोलिन डि ग्रैंडहोम को स्टार्क की गेंद पर स्मिथ के खूबसूरत कैच ने पवेलियन की राह दिखाई।

हेजलवुड पहले टेस्ट से बाहर : ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोस हेजलवुड मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। आइसीसी ने अपने बयान में इसकी घोषणा की। उन्हें दूसरे दिन के खेल के दौरान चोट लगी थी। मैच में वे सिर्फ आठ गेंद फेंक सके थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अर्धशतक लगाने के बाद जश्न मनाते लाबुशाने। एएफपी

अर्जेंटीना के लावेजी ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की

फुटबॉल डायरी

ब्यूनस आयर्स, आइएएनएस : अर्जेंटीना के पूर्व फॉरवर्ड एजेक्वेली लावेजी ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 34 वर्षीय लावेजी ने ट्विटर पर अपनी संन्यास की घोषणा की। उन्होंने करियर के दौरान मदद करने वाले लोगों को धन्यवाद भी दिया। लावेजी ने कहा कि इस कहानी के शानदार साल रहे थे। इन वर्षों के दौरान मैंने सीखना जारी रखा और इस दौरान कई यादें भी मेरे से जुड़ी, जोकि हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लावेजी ने 2007 में अर्जेंटीना के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण किया था। वह नापोली और पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के लिए भी खेल चुके हैं। लावेजी ने अर्जेंटीना के लिए 51 मैच खेले हैं।

एट्र्ज अमेरिका की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर

वाशिंगटन, रायटर : मिडफील्डर जूली एट्र्ज को इस साल की अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया। अमेरिकी फुटबॉल संघ ने इसकी पुष्टि की। एट्र्ज के लिए यह साल का दूसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार है। इससे पहले वह 2017 में यह पुरस्कार हासिल करने में सफल रही थीं। पुरस्कार हासिल करने के बाद जूली ने कहा कि अमेरिकी टीम के लिए 2015 और इस साल विश्व कप जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। मैं इस सफलता के लिए अपने साथ जुड़े हर एक शख्स का धन्यवाद करना चाहूंगी।

एजेक्वेली लावेजी। फाइल फोटो, एपी

उइगर मुस्लिमों के साथ खड़े हुए ओजिल

इस्तांबुल, एएफपी : इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल के मेसुट ओजिल ने चीन में उइगर मुस्लिमों की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि चीन में मस्जिदें गिराई जा रही हैं। वहां मौलवियों को मारा जा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इन सबके बावजूद दुनियाभर के मुसलमान और मुस्लिम देश खामोश हैं। तुर्की मूल के ओजिल 2010 में विश्व कप जीतने वाली जर्मन फुटबॉल टीम के सदस्य रहे थे। ओजिल आर्सेनल के लिए 173 मैचों में 32 गोल कर चुके हैं।

आइपीएल की नीलामी को समझना कठिन : पोंटिंग

▸ **दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच ने कहा, कमिंस और वोक्स के लिए नीलामी में लग सकती है मोटी बोली**

नई दिल्ली, आइएएनएस : आइपीएल की नीलामी अगले गुरुवार को होनी है और सभी फ्रेंचाइजी टीमें अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच, दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग का मानना है कि आइपीएल की नीलामी को समझना हमेशा ही कठिन रहा है।

पोंटिंग ने कहा, 'टीम प्रबंधन के साथ पिछले कुछ माह में हमारी कई बैठकें हुई हैं। नीलामी से पहले हमारी तैयारी बेहतर हो, इसके लिए हमने मेहनत की है। आप हमेशा तैयारी करते हैं, लेकिन नीलामी के समय क्या होगा, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तेज गेंदबाजों खासकर विदेशी तेज गेंदबाजों पर सभी का बहुत ज्यादा ध्यान होगा। पैट कमिंस के लिए मोटी बोली लग सकती है और ऐसा ही क्रिस वोक्स के लिए हो सकता है। ऑलराउंडर खिलाड़ियों की हमेशा ही मांग होती है। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल मार्श, जिमी नीशाम, कोलिन डि ग्रैंडहोम को टीमें महंगे दामों पर खरीद सकती हैं।' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा, 'नीलामी में जाते वक्त अपनी जरूरतों के हिसाब से आपका नजरिया बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास तीन ओपनर हैं, तो हम ओपनर की तलाश नहीं करेंगे। टीमों को अपनी प्रारंभिक एकादश में कमी तलाशना होती है और उसकी भरपाई करना होती है।' पोंटिंग ने 2019 के आइपीएल संस्करण की चर्चा करते हुए कहा, 'चेन्नई के खिलाफ सेमीफाइनल की हार निराशाजनक थी। मगर हमने अच्छा क्रिकेट खेला था। मैं अभी भी मानता हूं कि हम टूर्नामेंट की श्रेष्ठ टीम थे।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलेंगे शीर्ष खिलाड़ी

टेनिस : साल के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट की शुरुआत 20 जनवरी से होगी

मेलबर्न, एएफपी : टेनिस की दुनिया के तीन दिग्गज स्पेन के राफेल नडाल, सर्बिया के नोवाक जोकोविक और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर अगले साल जनवरी में होने वाले साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियन में खेलते दिखाई देंगे। तीनों खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपने खेलने की पुष्टि कर दी है। जोकोविक अगले साल रिकॉर्ड आठवीं बार यह खिताब जीतने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन 20 जनवरी से सात फरवरी तक होगा।

इन तीनों के अलावा कनाडा के डोमिनिक थिएम, रूस के डेनिल मेदवेदेव, ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास, एलेक्जेंडर ज्वेरेव, माटेयो बेरेटेनी, रॉबर्टो बातिस्ता आगुट, जुआन मार्टिन डेल पोत्रो और गेल मोनफिल्स भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वहीं, महिलाओं में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी, सात बार की विजेता अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स की नजरें 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब पर टिकी हैं जिससे वह मारग्रेट कोर्ट के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। दो बार की चैंपियन अजारेंका अस्पष्ट कारणों से शनिवार को प्रविष्टियों की समय सीमा खत्म होने से पहले टूर्नामेंट से हट गईं। सेरेना की बड़ी बहन 39 वर्षीय वीनस विलियम्स ने भी इस टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है। पुरुष एवं महिला वर्ग में कुल 104 खिलाड़ियों को सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में सीधा प्रवेश मिला है। आठ खिलाड़ियों को वाइल्ड कार्ड के जरिये शामिल किया है। 16 खिलाड़ी ऐसे होंगे, जो आठ से 11 जनवरी तक चलने वाले क्वालीफाइंग के माध्यम से मुख्य ड्रॉ में जगह बनाएंगे।

मैं अब कैंसर से पूरी तरह ठीक हूं : शिवोन

मिलान : फ्रेंच ओपन विजेता इटली की महिला टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस्का शिवोन ने कहा कि वह अब कैंसर से उबर चुकी हैं। 2010 में फ्रेंच ओपन जीतने वालीं 39 वर्षीय शिवोन ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं पिछले सात-आठ महीनों से सोशल मीडिया और इस दुनिया से दूर थी। मैं आप लोगों से यह साझा करना चाहती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कैंसर हो गया था। मैंने कीमोथेरेपी कराई थी। मैंने एक कठिन लड़ाई लड़ी और इसे जीतने में सफल रही। अब मैं वापसी करने के लिए तैयार हूं।' शिवोन इटली की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था और वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग पर रही थीं। 22 सत्रों में खेलने के बाद उन्होंने पिछले साल संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने करियर में आठ सिंगल्स खिताब जीते थे।

फ्रांसिस्का शिवोन। फाइल फोटो, एपी

विविध

पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार पर व्यापारी को पीटने का आरोप

जागरण संवाददाता, मेरठ

▸ **बच्चे के पिता ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने कराया मेडिकल**

मेरठ के बागपत रोड स्थित मुलतान नगर में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने सरेराह व्यापारी को पीटा। उनकी अंगुली तोड़ दी। आरोप है कि व्यापारी के बेटे को भी धक्का दिया। सड़क पर बच्चों को उतार रही बस से साइड नहीं मिलने पर कार सवार प्रवीण आगबबूला हो गए थे। व्यापारी ने टीपीनगर थाने में तहरीर दी है। व्यापारी का मेडिकल कराने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं, प्रवीण कुमार ने व्यापारी पर उनकी नाक तोड़ने का आरोप लगाया है।

मुल्ताननगर निवासी व्यापारी दीपक शर्मा का बेटा मेरठ पब्लिक स्कूल, वेदव्यासपुरी में पढ़ता है। स्कूल बस रोजाना की तरह शनिवार को यशवर्धन और अन्य बच्चों को छोड़ने मुल्ताननगर गई। दोपहर को दीपक अपने बेटे को लेने के लिए बागपत रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास आए। बच्चे उतर रहे थे तभी टीम इंडिया के मध्यम तेज गेंदबाज रहे प्रवीण कुमार कार से वहां पहुंचे। रास्ते में स्कूल बस खड़ी होने के कारण प्रवीण कुमार बार-बार कार का हॉर्न बजाने लगे। स्कूल बस हटने में थोड़ी देर हो गई, जिस पर वह भड़क गए।

पीड़ित दीपक के मुताबिक, प्रवीण शराब के नशे में धुत थे। वह स्कूल बस से साइड नहीं मिलने पर आपा खो बैठे। आरोप है कि प्रवीण ने बाइक को धक्का दिया जिससे बेटे को भी चोट लग गई। हमले में दीपक शर्मा की अंगुली भी टूट गई। दीपक के शोर मचाने के बाद प्रवीण वहां से निकल गए। टीपीनगर एसओ दिनेश चंद्र ने बताया कि दीपक का मेडिकल करा दिया गया है। उनकी तरफ से दी गई तहरीर पर जांच की जा रही है। जांच के लिए प्रवीण के घर गए थे, वह घर पर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दीपक शर्मा की तरफ से पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। व्यापारी का मेडिकल करा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
–अजय साहनी, एसएसपी

कालोनी में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। दीपक ने मारपीट करते हुए मेरी नाक तोड़ दी। हम मामले को तूल नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। हम आपस में ही मामले को निपटा लेंगे।
–प्रवीण कुमार, पूर्व क्रिकेटर

मणिपुर के सीएम के ममेरे भाई का कोलकाता में अपहरण

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन सिंह के कोलकाता में रह रहे ममेरे भाई टोंगब्राम लुखोई सिंह और उनके निजी सहायक का अपहरण कर लिया गया। हालांकि टोंगब्राम को शुक्रवार की रात 10.30 बजे पार्क बेनियापुकुर थाना इलाके के सर्कस इलाके से छुड़ा लिया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने पांच आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें मणिपुर और कोलकाता के दो-दो आरोपित हैं, जबकि पांचवां पंजाब का रहने वाला है।

पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10.30 बजे न्यूटाउन के एक्शन एरिया-वन के बीए-68 इलाके में स्थित फ्लैट में पांच संदिग्ध सीबीआइ अधिकारी बन कर पहुंचे थे। उनमें से एक ने कॉल बेल बजाई। टोंगब्राम लुखोई ने ही दरवाजा खोला। घर में टोंगब्राम का पीए और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आरोपितों ने कहा कि उक्त फ्लैट में काफी सोना और नकदी छिपा कर रखे हुए हैं। वे लोग तलाशी लेना चाहते हैं। इसके बाद आरोपितों ने घर की तलाशी ली। बाद में उनसे 15 लाख रुपये की मांग की। पैसे नहीं देने पर घर से कुछ नकदी जब्त की और हथियार का भय दिखा कर टोंगब्राम और उनके पीए को गाड़ी में लेकर चले गए। उनके जाने के बाद स्वजनों ने तुरंत न्यूटाउन थाने को सूचना दी। हरकत में आई पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और पार्क सर्कस इलाके से रात में टोंगब्राम और उनके पीए को छुड़ा लिया।

कार नहर में गिरी चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, सोनीपत : गांव महलाना के पास शुक्रवार देर रात एक कार नहर में गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों गोहाना की चोपड़ा कॉलोनी निवासी विजयपाल (45), उनकी पत्नी संध्या (42), बेटे हर्ष (17) और बेटी निकिता (14) की मौत हो गई। हादसे का उस वक्त पता चला जब शनिवार सुबह ग्रामीण नहर की ओर सैर के लिए गए। कार को नहर में गिरा देख मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार को नहर से निकलवाया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया।

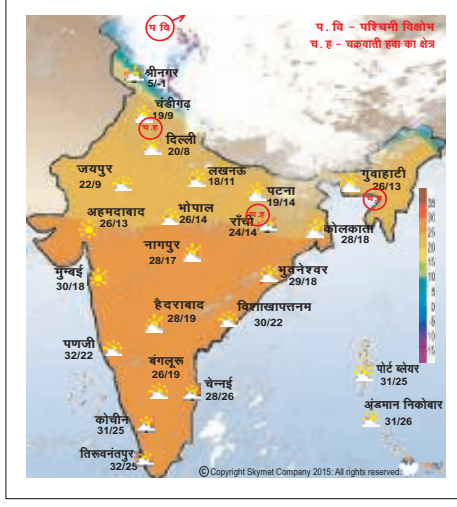

मौसम विशेष

पंजाब, उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर दिन सर्द बना रहेगा। सुबह कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा संभव है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में कमी आएगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। रात के तापमान में कमी जाएगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/17/व	अहमदाबाद	28/11/आंबा
कोलकाता	28/18/आंबा	बड़ौदा	30/15/सा
चेन्नई	30/23/आंबा	नागपुर	27/16/सा
हैदराबाद	28/19/सा	इन्दौर	27/11/सा
बंगलूरू	25/19/आंबा	राँची	24/11/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	24/12/आंबा
गुवाहाटी	22/12/सा	जमशेदपुर	25/15/आंबा
गंगटोक	05/-9/सा	पुणे	30/17/सा

श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए होगा माघ मेले में मंथन

अमरदीप भट्ट, प्रयागराज

▸ **संत समाज को एकजुट करने के लिए बनेगी रणनीति**

▸ **सरकार को सहयोग करने के तरीके पर होगा विमर्श**

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिहाज से प्रयागराज में जनवरी में होने वाला माघ मेला बेहद महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में केंद्र सरकार भले ही अब तक ट्रस्ट न बना सकी हो लेकिन, संत समाज संगम की रेती पर भविष्य की रणनीति जरूर बनाएगा।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि माघ मेले के दौरान धर्म संसद में श्रीराम मंदिर निर्माण पर चर्चा का संकेत पहले ही दे चुके हैं। उनका कहना था कि मंदिर तो अयोध्या में बनेगा लेकिन इसकी योजना प्रयागराज में बनेगी। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती कहते हैं कि ट्रस्ट के लिए सरकार के पास अभी काफी समय बचा है। इसलिए उस विषय में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, यह तय है कि श्रीराम मंदिर जैसे गंभीर विषय पर माघ मेले में चर्चा जरूर होगी। संत ऐसी रणनीति बनाएंगे ताकि मंदिर निर्माण में कोई अन्य प्रशासनिक बाधा न आ सके। मंदिर विरोधियों की घुसपैठ हर स्तर पर रोकी जाएगी।

खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री संतोषदास 'सतुआबाबा' का कहना है कि ट्रस्ट और मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर पहल कर रही है लेकिन माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। यहां तो संत श्रीराम मंदिर निर्माण पर चिंतन-मनन करेंगे ही। इसके लिए संत समाज को एकजुट करने की पहल भी की जाएगी।

ताकि विश्व कहे 'जय श्रीराम'

जितेंद्र शर्मा, लखनऊ : भगवान श्रीराम की यश गाथा तो कई ग्रंथ और पुस्तकें सुनाती हैं, लेकिन तमाम देश अभी उसे सहज स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या शोध संस्थान भी बड़ी भूमिका में आ रहा है। संस्थान दुनियाभर में अकादमिक गतिविधियां कर श्रीराम से जुड़े तथ्यों को जुटाएगा और उनके दस्तावेज तैयार करेगा। उन तथ्यों पर तार्किक संवाद भी होगा, ताकि विश्व उसे स्वीकार करे और कहे 'जय श्रीराम।'

भगवान राम का संबंध सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि उनके वनगमन और अन्य कार्यों के दायरे में कई देश आते हैं। अयोध्या पर फैसला आने के बाद से सरकार का यह प्रयास भी है कि श्रीराम का संबंध धरती के जिस-जिस भू-भाग से रहा है, वहां तक उनका यशगान होना चाहिए। इसी आधार पर अयोध्या शोध संस्थान ने विश्व को चार भागों में बांटा है। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्वी देश, कैरेबियन देश और यूरोप। संस्थान के निदेशक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक संस्थान विभिन्न माध्यमों से श्रीराम से संबंधित तथ्य जुटाकर सहेजता, प्रदर्शित करता था। अब तय किया गया है कि इन सभी देशों में शोध कर तथ्य जुटाए जाएंगे। उन तथ्यों के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही अकादमिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। वहां के विशेषज्ञ यहां बुलाए जाएंगे और यहां के वहां जाएंगे। तर्क-मंथन कर उन तथ्यों को बताया और समझाया जाएगा कि उस भूभाग या देश से भगवान श्रीराम का क्या संबंध था। अब तक अयोध्या शोध संस्थान इराक, इटली और होंडुरास से कुछ संदर्भ-तथ्य जुटा चुका है।

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 15 दिसंबर, 2019 से शनिवार 21 दिसंबर, 2019 तक — पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, धनागम में प्रगति, सामाजिक कार्य योग, नए कार्य न करें, परिवर्तन का योग प्रभावी, विदेश कार्य में सफलता, साथी के प्रति चिंता, भवन योग, संतान की प्रगति, चयन में सफलता, वाणी पर नियंत्रण, मांगलिक कार्य, व्यय अधिक, शुभ अंक 5।

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो) अर्थ साधन ठीक, पद प्रतिष्ठा वृद्धि योग, विशेष व्यक्ति से संपर्क, पारिवारिक चिंता, भवन–भूमि कार्य सफल, संतान से सहयोग, अध्ययन में रुचि, शत्रुपक्ष प्रभावी, संबंधों में सुधार, अनुबंध की प्राप्ति, अधिकारी से सहयोग, बैंक राज्य कार्य प्रगति, शुभ अंक 6।

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, धनागम में सुधार, नए संपर्क से सफलता, पारिवारिक जनों का सहयोग, संतान के प्रति योजना, अध्ययन में एकाग्रता, कूटनीति से कार्य करें, दांपत्य में मधुरता, भविष्य की चिंता, अधिकारी से सहयोग, स्थान परिवर्तन प्रभावी, शुभ अंक 7।

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो) धनागम में प्रगति, लक्ष्य का ध्यान रखें, परिवर्तन लाभकारी, भूमि–भवन कार्य में सफलता, संतान के प्रति योजना, अध्ययन में एकाग्रता, शत्रुपक्ष प्रभावी, खानपान का ध्यान रखें, दांपत्य में सुधार, रक्षा साधन कार्य में प्रगति, बहुप्रतीक्षा की इच्छापूर्ति, राज्य पक्ष से सावधान, शुभ अंक 8।

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में प्रगति, धनागम अच्छा, व्यस्तता का योग, दिनचर्या प्रभावी, चिंता समाधान, भूमि विवाद की समाप्ति, संतान से सहयोग, खानपान में सतर्क, संचार माध्यम से अच्छी खबर, प्रणय में मधुरता, राज्य पक्ष से दंड, सावधानीपूर्वक कार्य करें, शुभ अंक 9।

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,उ,पे,पो) धनागम में सुधार, सामाजिक क्षेत्र में कार्य, स्त्री पक्ष से लाभ, अच्छे अवसर का उपयोग करें, पारिवारिक सहयोग, भौतिक साधन योग, अध्ययन में एकाग्रता, व्यर्थ के कार्य से बचें, संबंधों में स्नेह, अधिकारी से सहयोग, मांगलिक कार्य, अनुबंध में देरी, शुभ अंक 10।

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, अर्थ साधन अच्छे, कार्यशैली में सुधार करें, स्त्री पक्ष से सहयोग, विदेश व्यापार में सफलता, भूमि–भवन सजावट योग, संतान के मंगल कार्य, शत्रु पक्ष प्रभावी, संबंध में मधुरता, यात्रा से लाभ, अधिकारी से सहयोग, यंत्र स्थापना योग, शुभ अंक 11।

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, धनागम में सफलता, व्यस्ततम दिनचर्या से बचें, अच्छे समाचार की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, समस्या समाधान, भूमि–भवन योग, संतान से सहयोग, अध्ययन में एकाग्रता, लक्ष्य का ध्यान रखें, वाहन में सावधानी, शुभ अंक 1।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, अर्थ साधन में सुधार, भावुकता से बचें, कार्य करने वालों से सतर्क, मन में शिथिलता, वाहन योग, संतान की सफलता, चयन में देरी, कुसंग से बचें, साथी का मिलन, एकाग्रता से कार्य करें, वाहन में सावधानी, निर्माण योजना की रूपरेखा, शुभ अंक 2।

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी) अर्थ साधन में अवरोध, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि, सलाह से कार्य करें, भावुकता का योग, मन में शिथिलता, संतान से सहयोग, शत्रु पक्ष प्रभावी, प्रणय में सुख, यात्रा से लाभ, वाहन में सावधानी, निश्चयता से योजना सफल, राज्य कार्य सफलता, व्यय अधिक, शुभ अंक 3।

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा) नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में सफलता, धनागम में सुधार, लेनदेन में सतर्कता, साझेदारी में तनाव, परिस्थिति विचलित कर सकती है, पिता से तनाव, अध्ययन में एकाग्रता, व्यर्थ की भागदौड़, विचारों का उतार–चढ़ाव, संबंधों में सुधार, वाहन में सावधानी, शुभ अंक 4।

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रयास से सफलता, धनागम ठीक, महिला से सहयोग, पारिवारिक साधन की पूर्ति, प्रतिस्पर्धा से तनाव, साधनों की पूर्ति, चयन में सफलता, वाद में विजय, दांपत्य में मधुरता, अनुबंध प्राप्ति में देरी, शासन का सहयोग, आय में सुधार, शुभ अंक 5।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

रविवार 15 दिसंबर 2019

16

www.jagran.com

पीसा की झुकी हुई मीनार को दोबारा खोला गया

2001 में आज ही इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार को ग्यारह साल तक चले मरम्मत कार्य के बाद दोबारा खोला गया था। मरम्मत में 170 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन यह झुकी हुई मीनार इसके बाद भी ठीक नहीं हो पाई थी।

एडोल्फ इचमैन की मिली मौत की सजा

1961 में आज ही इजरायल की एक अदालत ने जर्मनी में यहूदी नरसंहार के दोषी एडोल्फ इचमैन को मौत की सजा सुनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के राज में 60 लाख यहुदियों को कत्लेआम कर दिया गया था।

पहलवान गीता फोगाट को जन्मदिन मुबारक को

गीता फोगाट का जन्म 1988 में आज ही हरियाणा के भिवानी में हुआ था। 2009 में राष्ट्रमंडल कुश्ती प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के 55 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनीं। 2012 में उन्होंने एशियन ओलंपिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। 2012 में ही कनाडा में आयोजित हुई विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 2016 में आई फिल्म दंगल गीता और उनकी बहन बबिता फोगाट के जीवन पर आधारित है।

इधर-उधर की

अकेलापन दूर करने को लगाए होर्डिंग्स

टोक्यो, एजेंसी : अकेलापन दूर करने के लिए इंसान तरह-तरह के तरीके अपनाता है। इसी तरह एक महिला ने घर में खुद के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। इसकी वजह अजीब सी है। दरअसल, महिला का दावा है कि उसने अपने बच्चे के अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसा किया। जब वह घर से बाहर जाती है तो अपने कद के आकार के होर्डिंग को कमरे में लटका देती है। इससे बच्चे उसकी मौजूदगी का एहसास कराता है और बिना रोए खेलता रहता है। सेतो नेजी ने अपने ट्विटर पर इससे जुड़े वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। महिला के इस कदम की कई लोग तारीफ कर रहे हैं तो कई लोगों को महिला का यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया है।

शोध अनुसंधान

योग से बेहतर हो सकती है मस्तिष्क की कार्यक्षमता

योग करने से ना सिर्फ तन और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी हो सकता है। अब एक नए अध्ययन में योग करने का एक नया फायदा सामने आया है। इसमें पाया गया कि मस्तिष्क की संरचना और कार्यक्षमता को बेहतर करने में एरोबिक एक्सरसाइज के समान ही योग से भी फायदा हो सकता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष योगाभ्यास और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बीच संबंध को लेकर किए गए 11 अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर निकाला गया है। अमेरिका की इलिनोइस यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता नेहा गोथे ने कहा, 'योग से तनाव व अवसाद को कम करने में मदद मिलती है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है।' -एएनआइ

अल्जाइमर से बचाव कर सकता है ब्रेन प्रोटीन

शोधकर्ताओं को भूलने की बीमारी अल्जाइमर के इलाज की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने एक ऐसे ब्रेन प्रोटीन की पहचान की है, जो इस बीमारी से बचाव कर सकता है। यह प्रोटीन मस्तिष्क में ह्वाइट ब्लड सेल्स को नियंत्रित करने का काम करता है। कम्युनिकेशंस बायोलॉजी जर्नल में छपे अध्ययन के अनुसार, सीडी33 नामक प्रोटीन की अल्जाइमर रोग से मुकाबले में अहम भूमिका हो सकती है। यह प्रोटीन किसी व्यक्ति में इस रोग के खतरे को कम कर सकता है। कनाडा की अल्बर्ट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्यू मैकाले ने कहा, 'मस्तिष्क में माइक्रोग्लिया नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अल्जाइमर में अहम भूमिका होती है। ये नुकसानदेह या सुरक्षात्मक हो सकती हैं। माइक्रोग्लिया को नुकसानदेह से सुरक्षात्मक बनाना अल्जाइमर के इलाज के लिहाज से अहम हो सकता है।' उन्होंने बताया कि सीडी33 प्रोटीन की माइक्रोग्लिया की कार्यप्रणाली में बदलाव लाने में अहम भूमिका पाई गई है। -आइएएनएस

मंगल पर वायु प्रवाह का पैटर्न पता चला

मिलेगी मदद ▶ नए स्पेसक्राफ्ट पहुंचाने और उपकरण स्थापित करने में होगी आसानी

नासा के वैज्ञानिकों ने मावेन स्पेसक्राफ्ट से डाटा जुटाया

120 से 300 किलोमीटर मंगल की सतह से ऊपर के वायुमंडल में वायु परिसंचरण का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है

2016 से 2018 के बीच के हर महीने के केवल दो दिन के डाटा का इस्तेमाल किया गया है

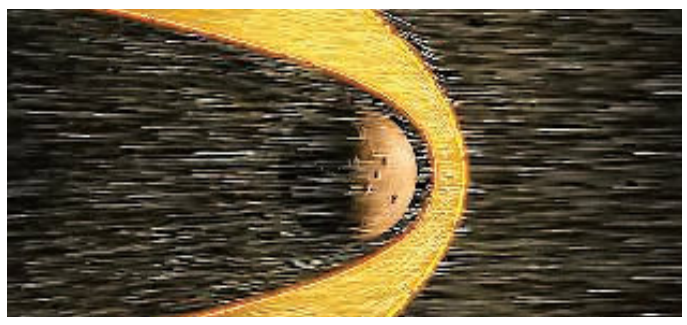

इस अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह से 120 से 300 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल में वैश्विक वायु परिसंचरण के पैटर्न का पता लगाया है।

अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, बाल्टीमोर काउंटी (यूएमबीसी) के शोधकर्ताओं सहित एक टीम ने लाल ग्रह पर हवा की माप को रिकॉर्ड करने के लिए नासा के मावेन (मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन) स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया। इसके लिए मावेन स्पेसक्राफ्ट में नेचुरल गैस एंड ऑयन मास स्पेक्ट्रोमीटर (एनजीआइएमएस) डिवाइस इस्तेमाल में लाई गई। यह डिवाइस स्पेसक्राफ्ट के बाहर लगी है और आगे-पीछे झूलती रहती है। इससे मंगल की सतह पर चलने वाली हवाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में 2016 से 2018 के बीच के प्रत्येक महीने के केवल दो दिन के डाटा का इस्तेमाल किया गया है।

नासा के गोडार्ड फ्लाइट सेंटर में कार्यरत और अध्ययन के सह लेखक मेहदी बेना ने कहा कि अंतरिक्ष यान और उसके उपकरण को किस तरह संचालित करना है यह भी एक चतुर इंजीनियरिंग है। क्योंकि, कुछ ऐसा ही करके वैज्ञानिकों ने उस स्पेसक्राफ्ट और उपकरण से हवा की माप को संभव बनाया जो इस काम के लिए बने ही नहीं थे। शोधकर्ताओं ने मंगल के ऊपरी वातावरण में पाए गए हवा के पैटर्न का मिलान सैद्धांतिक माडलों से की गई भविष्यवाणी से किया।

कहा गया कि मंगल पर हवा का औसतन परिसंचरण पैटर्न बहुत स्थिर है। हलांकि, कुछ समय के लिए हवा की परिवर्तनशीलता अनुमान से अधिक हो जाती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अभी इस क्षेत्र में और अधिक काम करने की जरूरत है।

एस्टेरॉयड बेन्नु में सैंपल लेने की साइट का चयन

ह्यूस्टन, प्रेट्र : नासा ने ओसिरिस-रेक्स मिशन के तहत एस्टेरॉयड बेन्नु की कंकड़ीली और बिखरी हुई सतह पर नमूने इकट्ठे करने की जगह का चयन कर लिया है। एक बयान में बताया कि एस्टेरॉयड के उत्तरी गोलार्ध के क्रेटर में स्थित इस साइट का नाम नाइटएंगल रखा गया है। यह जगह ओसिरिस-रेक्स स्पेसक्राफ्ट द्वारा नमूना जुटाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। नाइटएंगल साइट 140 किलोमीटर चौड़ी है। यहां की मिट्टी गहरी है, जिससे इसके चिकनी होने की संभावना है। यहां का तापमान बेन्नु के अन्य जगहों के अपेक्षा कम है।

वायु प्रवाह से नीचे के परिदृश्यों की मिलती है जानकारी : शोधकर्ताओं ने बताया कि लाल ग्रह की सतह से सौकड़ों किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा में नीचे के पहाड़ों और घाटियों की जानकारी रहती है। वायु दृव्यमान जब इन परिदृश्यों के ऊपर से बहता है तब इसमें लहरें बनतीं हैं जो ऊपरी वायुमंडल तक मौजूद रहती हैं।

अब बैक्टीरिया को खुद ही दूर भगाएगी सतह

- शोधकर्ताओं ने बताया कि नई खोज से सुपरबग्स से निपटने में मदद मिल सकती है
- कमल की पत्तियों की गुणवत्ता से प्रभावित होकर वैज्ञानिकों ने तैयार की है नई सामग्री

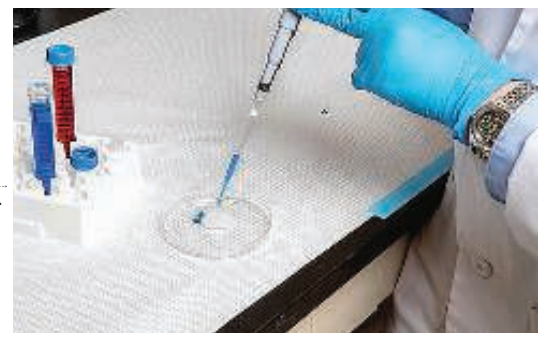

प्रति वर्ष हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं हानिकारक बैक्टीरिया। प्रतीकात्मक

टोरंटो, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने एक ऐसी स्वतः सफाई करने वाली प्लास्टिक सतह विकसित की है जो बैक्टीरिया को भी खुद ही साफ कर सकती है। इस खोज के जरिये अस्पतालों और किचन आदि में सुपरबग्स से निपटने में मदद मिल सकती है।

इस अध्ययन को 'एसीएस नैनो' नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि नई प्लास्टिक सामग्री को दरवाजों के हैंडल, रेलिंग और ट्राईपॉड में सिकोड़कर लपेटा जा सकता है। इस सामग्री को अन्य जगहों पर भी लगाया जा सकता है जहां बैक्टीरिया के इकट्ठा होने का खतरा रहता है।

पुराने अध्ययनों में यह बताया जा चुका है कि हर साल होने वाली हजारों मौतों के लिए सतह और अन्य जगहों पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। अगर इस खतरे से तत्काल नहीं निपटा जाता है तो आगे 2050 तक हर साल मरने वालों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो सकती है।

कमल से प्रेरित है यह खोज : कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित टीम ने बताया कि नई प्लास्टिक सामग्री कमल की पत्तियों से प्रेरित है। कमल की पत्तियां गंदगी को स्वतः ही साफ करती हैं। नई सामग्री को सरफेश (सतह) इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान के संयोजन के माध्यम से तैयार किया गया है।

बताया कि नई सतह में अतिसूक्ष्म सिकुड़न डाली गई है, जिसकी वजह से यह सभी बाहरी अणुओं को निकाल देती है। इसकी सतह पर पानी या रक्त की एक बूंद पड़ने पर उछल कर अलग हो जाती है, और यही हाल बैक्टीरिया के साथ होता है।

किया गया परीक्षण : शोधकर्ताओं ने इस सामग्री का परीक्षण करने के लिए एंटीबॉयोटिक रजिस्टेंट बैक्टीरिया के दो रूपों का उपयोग किया। जिसमें से एक मेथिसिलिन रजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस (एमआरएसए) और दूसरा स्यूडोमोनास था। इसके बाद इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके यह देखा कि वास्तव में कोई भी रोगाणु इस सतह पर नहीं टिक सकता है।

मनुष्य के दांतों से भी बनते थे आभूषण

लंदन, पेट्र : शोधकर्ताओं ने तुर्की के एक पुरातात्विक स्थल पर 8500 साल पुराने इंसानों के दांतों से बने हार का पता लगाया है। कोपेनहेगेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि खोज से इस बात पर बल मिलता है कि प्राचीन समय में यूरोप के कुछ स्थानों में सजावटी कामों के लिए इंसानों के दांतों का उपयोग किया जाता था।

आर्कियोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इंसानी दांतों से बने हारों को पहनने वालों के गहरे प्रतीकात्मक अर्थों के साथ बनाया गया था। 2013-15 के बीच तुर्की के कैटेलहुक में पुरातात्विक स्थल से खोदाई में इन दातों को निकाला गया था। अध्ययन करने के बाद शोधकर्ता अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बताया गाय कि दातों को गले में पहनने के लिए उनमें बारीकी से छेद भी किया गया था। इन दातों के साथ जानवरों की हड्डियां और पत्थरों को भी माले में गूंथा जाता था। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हो सकता है ये मानव दांत पुरातन काल के किसी अनुष्ठान और परंपरा का हिस्सा रहे हों।

फिल्म रिव्यू

थ्रिलर फिल्म से रोमांच गायब

द बॉडी

मुख्य कलाकार : ऋषि कपूर, इमरान हाशमी, शोभिता धूलिपाला, वेदिका कुमार
निर्देशक : जीतू जोसेफ
अवधि : 1 घंटा 43 मिनट

न दिनों कई विदेशी फिल्मों की हिंदी रीमेक बन रही हैं। 'द बॉडी' उन्हीं फिल्मों में शामिल है। यह फिल्म इसी नाम से वर्ष 2012 में बनी स्पेनिश फिल्म की हिंदी रीमेक है। ऋषि कपूर की यह इस वर्ष रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म होगी। न्यूयॉर्क में इलाज के चलते वह 'झूठा कहीं का' फिल्म का प्रमोशन नहीं कर पाए थे, लेकिन भारत लौटने के बाद उन्होंने 'द बॉडी' फिल्म का प्रमोशन जरूर किया।

फिल्म शुरू होती है मॉरीशस में हुए एक एक्सीडेंट के साथ। रात को एसपी जयराज रावल (ऋषि कपूर) के पास एक फोन आता है कि फॉरेंसिक लैब के मुर्दाघर से बॉडी गायब हो गई है। वह बॉडी माया वर्मा (शोभिता धूलिपाला) की है। माया के पति अजय पुरी (इमरान हाशमी) पर शक की सुई घूमती है। उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अजय कई झूठ बोलता है। उसका अफेयर रितु (वेदिका कुमार) के साथ चल रहा है। जिसकी जानकारी वह पुलिस को नहीं देता है। अजय के कई झूठ पुलिस के शक को बढ़ाते हैं। माया की बॉडी कैसे गायब हुई? उसकी मौत हुई है या उसका कत्ल हुआ? ऐसे कई सवालों से गुजरते हुए कहानी अंत तक पहुंचती है। कहानी काफी हद तक मूल स्पेनिश फिल्म से मिलती-जुलती है, लेकिन हिंदी दर्शकों के लिए निर्देशक जीतू जोसेफ ने इसमें और ड्रामा डालने की कोशिश की है। फिल्म का क्लाइमेक्स हूबहू मूल फिल्म की तरह फिल्माया गया है। जीतू क्राइम और मिस्ट्री थ्रिलर को पर्दे पर उतारने में माहिर हैं। मलयालम फिल्म 'दृश्यम' इसकी बानगी है। लेकिन अपनी पहली हिंदी फिल्म 'द बॉडी' में वह 'दृश्यम' का जादू नहीं ला पाए हैं। फिल्म में शुरू से ही कई घटनाओं से परतें खुलने लगती हैं, जो कहानी का रोमांच कम करती हैं। अंत चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन नया नहीं। लेखक फिल्म के किरदारों की गहराई में नहीं गए हैं। ऐसे में इमरान का किरदार अपनी पत्नी माया के सामने इतना बेबस क्यों है, इसका जवाब नहीं मिलता।

अपने किरदारों के साथ प्रयोग करते रहने वाले ऋषि कपूर सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में जंचे हैं। इमरान हाशमी पहले भी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में कर चुके हैं। ऐसे में उनका अभिनय सहज लगता है। शोभिता धूलिपाला अमीर और सनकी बिजनेस वूमन माया के किरदार के साथ न्याय करती दिखीं। दक्षिण भारतीय फिल्मों से हिंदी में डेब्यू करने वाली वेदिका कुमार को रितु के किरदार में स्क्रीन स्पेस कम मिला है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कहानी को संभालता है। बीच-बीच में आते गाने फिल्म की कहानी में खलल डालते हैं। कोई भी गाना थियेटर से बाहर निकलने पर याद नहीं रह पाता है।

-प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

फेसबुक के 29000 कर्मियों की हार्डड्राइव चोरी

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : फेसबुक के करीब 29,000 कर्मचारियों के बैंकिंग डाटा से भरे अनएनक्रिप्टेड हार्डड्राइव को चोर ने एक कर्मचारी की कार से चुरा लिया। हार्डड्राइव में कर्मचारियों के बैंक अकाउंट नंबर, उनके नाम, सोशल सिक्योरिटी के चार आखिरी डिजिट, उनका वेतन, बोनस और इक्विटी से संबंधित जानकारी शामिल है। हालांकि, चोरी हुए हार्डड्राइव में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं का डाटा शामिल नहीं है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक ने कहा कि हार्डड्राइव में वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों का व्यक्तिगत अनएनक्रिप्टेड डाटा था और उन कर्मचारियों को सचेत कर दिया गया है। हार्डड्राइव के गायब होने के बारे में फेसबुक को 20 नवंबर को पता चला, और 29 नवंबर को इस बात की पुष्टि की गई कि ड्राइव में कर्मचारियों की जानकारी शामिल थी।

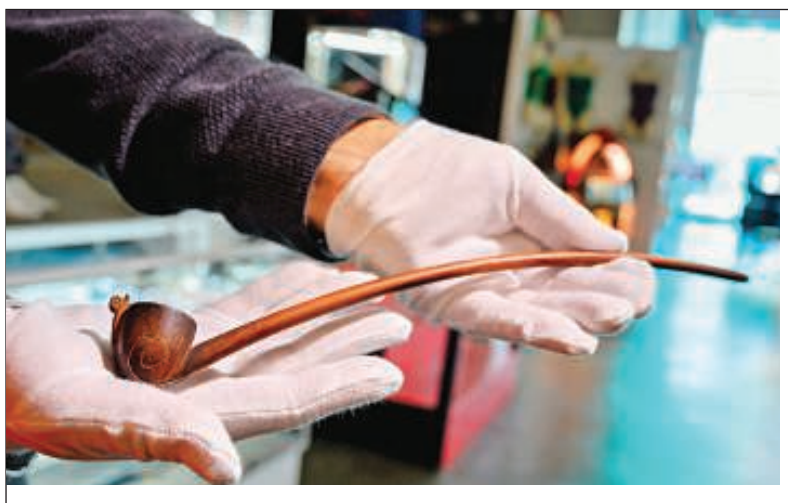

70 लाख का पाइप

अमेरिका के कैलिफोर्निया में जूलियंस नीलामी घर में हॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'द लॉर्ड ऑफ रिंग्स' में इस्तेमाल पाइप की नीलामी की जाएगी। इसका मूल्य एक लाख अमेरिकी डालर (करीब 70 लाख रुपये) है। इसका इस्तेमाल अभिनेता इयान होल्म ने किया था। पाइप पीने के उनके अंदाज को लोगों ने काफी सराहा था। यहां हॉलीवुड के सामानों की नीलामी की जाएगी। एएफपी

रूस का परमाणु ऊर्जा संचालित आइसब्रेकर 'आर्कटिका'...

यह रूस का परमाणु ऊर्जा संचालित आइसब्रेकर (रास्ते से बर्फ हटाने वाला जहाज) जहाज 'आर्कटिका' है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आइसब्रेकर जहाज बताया जा रहा है। बीते दिनों इसका दो दिवसीय समुद्री ट्रायल पूरा हुआ है और इसके बाद शनिवार को सेंट पीटर्सबर्ग लौटा। परीक्षण में इसके संचालन, कार्यपद्धति, कुशलता, गतिशीलता आदि पर जोर रहा। इसका फाइनल टेस्ट मार्च व अप्रैल में और इस्तेमाल मई से होना है। इसी तरह के दो और जहाज यूराल और सिबिर निर्माणाधीन हैं। 173 मीटर लंबे और 15 मीटर ऊंचे इस जहाज को आर्कटिक में वाणिज्यिक संभावनाएं तलाशने में रूस की महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जा रहा है। यह तीन मीटर मोटी बर्फ तोड़ने में सक्षम है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

सशक्त महिला का किरदार निभाकर खुश हैं सोनाक्षी सिन्हा

फिल्म 'दबंग' से करियर का आगाज करने वाली सोनाक्षी सिन्हा कमर्शियल और छोटी बजट की फिल्मों में संतुलन साधकर चल रही हैं। इस साल वह 'खानदानी शफाखाना' में नजर आई थीं। वहीं दूसरी ओर 'दबंग 3' में एक बार फिर रज्जो की भूमिका में दिखेंगी। सोनाक्षी का कहना है कि कमर्शियल फिल्मों की सफलता ने ही उन्हें छोटे बजट की फिल्में करने का साहस दिया है। उसकी वजह से ही 'नूर', 'अकीरा', 'खानदानी शफाखाना' जैसी फिल्में कर पाई, जिनका भार पूरी तरह से उनके कंधों पर था। फिल्मों को बड़ी सफलता भले न मिली हो, लेकिन उनका काम सराहा गया। सोनाक्षी का कहना है कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से फिल्म बुरी नहीं बनती है। 'लुटेरा' भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन वह यादगार फिल्म है। सोनाक्षी इन दिनों फिल्म 'भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया' को लेकर उत्साहित हैं। संजय दत्त व अजय देवगन स्टारर यह फिल्म वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में हैं। यह भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की कहानी है, जो उस समय भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। उन्होंने तीन सौ स्थानीय लोगों की मदद से वायुसेना के एयरबेस का पुनर्निर्माण किया था। इस फिल्म में सोनाक्षी सुंदरबेन जेठा के किरदार में हैं, जिन्होंने अपने गांव की तीन सौ महिलाओं को एकत्रित किया था। इन महिलाओं ने रातोंरात रनवे का निर्माण किया था, ताकि भारतीय विमान भुज में लैंड कर सकें। सोनाक्षी के मुताबिक, 'यह बहुत जरूरी कहानी है। मुझे खुशी है कि मैं सशक्त महिला का किरदार स्क्रीन पर निभा पा रही हूं।'

लंदन से मंगवाया गया करीना का 'बेबी बंप'

फिल्मों में किरदार के मुताबिक लुक पाने के लिए कलाकार घंटों बैठकर मेकअप करवाने के लिए तैयार रहते हैं। अब शारीरिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए भी अब पेशेवरों की मदद ली जाती है। पहले की फिल्मों में गर्भावस्था को अक्सर पेट पर कुशन वगैरह लगाकर दिखा जाता था, लेकिन 'गुड न्यूज' फिल्म में करीना कपूर खान और कियारा आडवाणी को गर्भवती दिखाने के लिए कृत्रिम पेट लंदन से मंगवाया गया। करीना की मानें तो यह दोबारा मां बनने की उस अवस्था को जीने जैसा था, जो वह पहले वास्तविक जीवन में जी चुकी हैं। करीना ने बताया कि गर्भवती लगने के लिए तीन, छह और नौ महीने के लिए अलग तरह का सूट बनवाया गया था। बेबी बंप दिखाने के लिए जो पेट था, वह स्विम सूट की तरह बनाया गया था, जिसे पहनकर रोजाना शूट करना मुश्किल काम था। करीना का कहना है कि प्रॉस्थेटिक से बना वह पेट दिखने में वास्तविक था। उस पर नाभि भी बनी हुई थी। ऐसे में वह नेचुरल लगेगा।

खोला राज

वैज्ञानिकों ने पोलीनेशिया में ईस्टर द्वीप पर बनीं विशाल प्रतिमाओं के निर्माण के पीछे की वजह बताई, कहा- पत्थर तराशने से निकले चूर्ण ने मिट्टी में प्राकृतिक तत्वों की भरमार ला दी

मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने को बनी थीं विशाल प्रतिमाएं

यूनेस्को ने ईस्टर द्वीप को 1995 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। प्रतीकात्मक

लास एंजिलिस, प्रेट्र : 1250 और 1500 के बीच पूर्वी पोलीनेशिया में ईस्टर द्वीप पर रेपा नुई में नक्काशी कर विशाल मानव आकृतियों के बनाने के वजह के बारे में पहली बार वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पता लगाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विशाल मूर्तियों के बनने के पीछे की वजह यह है कि उस समय के लोग यह सोचते थे कि इन मोनोलिथ (मूर्तियों) से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, जिससे फसलों आदि की पैदावार अच्छी होगी।

यूनेस्को ने ईस्टर द्वीप को 1995 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस द्वीप के अधिकतर संरक्षित क्षेत्र रेपा नुई नेशनल पार्क में हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया लासएंजिलिस (यूसीएलए) के शोधकर्ताओं के अनुसार यह पहला अध्ययन है जो मिट्टी की उर्वरता, कृषि, उत्खनन आदि के बारे में बताता है। इसमें उस साइट की मिट्टी का अध्ययन किया गया है, जहां के पत्थरों से इन मोनोलिथ का निर्माण हुआ। 'आर्कियोलॉजिकल साइंस' नामक जर्नल में अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इन मोनोलिथ की खोज पोलीनेशियन आइलैंड के पूर्व में रैनो राकू नामक जगह पर हुई थी। विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि रैनो राकू आदमकद प्रतिमाओं के अलावा कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में भी अग्रणी है। इस अध्ययन के सह लेखक जो ऐनी वैन टिलबर्ग ने कहा कि हमारा अध्ययन मोनोलिथ के बारे में हमारी समझ को और व्यापक करता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि रैनो राकू की मिट्टी के रासायनिक परीक्षण से पता चलता है कि संभवतः इस मिट्टी पर लंबे समय तक सबसे अमीर खनिज मौजूद रहे हैं। अध्ययन के अनुसार बताया गया कि इन लंबी आदमकद प्रतिमाओं को तराशने के दौरान चट्टानों का चूरा फैला उससे वहां की जगह उपजाऊ हो गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि यहां की मिट्टी में बड़ी उच्च मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया गया। मृदा रसायन में उच्च स्तर में वह तत्व पाए गए जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि द्वीप पर हर जगह मिट्टी खराब हो रही है, पौधों की बढ़ोतरी में काम आने वाले तत्वों का क्षरण हो रहा है, लेकिन साइट में प्राकृतिक उर्वरक और पोषक तत्वों की एक सही प्रतिक्रिया प्रणाली थी। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि रापा नुई के प्राचीन लोग कृषि करने में बहुत होशियार थे।

जन्मदिन पर फिल्म इंडस्ट्री को याद आए राज कपूर

शनिवार को हिंदी सिनेमा के पहले शो मैन राज कपूर के 95वें जन्मदिन पर सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियों ने उन्हें याद किया। 14 दिसंबर 1924 को अविभाजित भारत में जन्मे राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को 'श्री 420', 'बरसात', 'मेरा नाम जोकर', 'बॉबी', 'प्रेम रोग' जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। राज कपूर को याद करते हुए उनके बेटे ऋषि कपूर ने फिल्म 'मेरा नाम जोकर' की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा- 'जन्मदिन मुबारक डैड, हम आपको हमेशा याद करेंगे।' फिल्म 'प्रेम रोग' के निर्देशन में राज कपूर को असिस्ट कर चुके निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्हें याद किया। अनीस ने लिखा, 'फिल्म 'प्रेम रोग' के सेट से एक तस्वीर। कैमरामैन राधू कर्माकर, ऋषि कपूर, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट और राज कपूर जैसे दिग्गजों के बीच मेरी यह तस्वीर मेरे दिल के करीब है। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे महान फिल्मकार राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। 95वें जन्मदिन पर इस दिग्गज अभिनेता की याद में...'। अनिल कपूर ने भी राज कपूर के मुंबई में चेंबूर स्थित घर में उनके जन्मदिन की पार्टियों को सबसे यादगार बताकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की।

सनी की फिल्म में होगा कार्तिक का कैमियो

कार्तिक आर्यन और सनी सिंह अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हाल ही में सनी ने कार्तिक की फिल्म 'पति पत्नी और वो' में गेस्ट अपीरियेंस किया था। कार्तिक और सनी ने 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी को लोगों ने भी काफी पसंद किया था। अब खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन अपने दोस्त सनी की आगामी फिल्म 'जय मम्मी दी' में एक छोटा रोल निभाएंगे। दोनों को बड़े पर्दे पर फिर एक साथ देखना दर्शकों के लिए अच्छा अनुभव हो सकता है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। नवजोत गुलाटी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 17 जनवरी 2020 को रिलीज होगी।